रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 11, 1971 (अग्रहायण 20, 1893)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 11, 1971 (AGRAHAYANA 20, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

(PART III—SECTION 4)

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

सूचना

बम्बई, दिनांक 3 नवम्बर 1971

—स्टेट बैंक आफ इंडिया, सामान्य नियमावली 1955 के नियम 76(1) के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति ने कार्यभारी अधिकारी, विदेशी मुद्रा अनुभाग, मोरादाबाद, को हस्ताक्षर करने की निम्नलिखित शक्तियों के उपयोग का अधिकार दिया है:—

"स्टेट बैंक के चालू और अधिकृत कारोबार के दौरान स्टेट बैंक के नाम से या उसके पास रखे माल के कब्जे के दस्तावेजों का पृष्ठांकन और अन्तरण करना, विनिमय पत्रों और चेकों को आहरित करना, सकारना और पृष्ठांकित करना, सारव-पत्रों को जारी करना, उनकी पुष्टि करना और उनका अन्तरण करना तथा ऐसे कारोबार से संबंधित अन्य सभी पत्रों, सूचनाओं, रवातों, रसीदों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना"

केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति के आदेश से

टी० आर० वरदाचारी,

प्रबन्ध-निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 1971

सं० इन्स० 1.22(1)1/71(8)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) जोकि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित है, के अनुसरण में शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने जैसा कि उक्त विनियम 95-क तथा मद्रास कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम, 1954 में निर्दिष्ट है, बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर चिकित्सा हितलाभ को तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तार करने के लिये 28-11-1971 की तिथि नियत की है, अर्थात्:—

I. थन्जावुर जिले के कुम्बाकोनम तालुक में राजस्व ग्राम पनडारावडाई पेरुमण्डी की सीमा के भीतर का क्षेत्र।

II. तिरुनेवेलि जिले के तिरुनेवेलि तालुक में राजस्व ग्राम मेला थिरुवेन्गाडानाथापुरम, थिरुवेन्गाडानाथापुरम, सुथामल्लि, कन्नाथुर, थेन्पाथु, कन्डियापेरि, विलागाम, कीला थिरुवेन्गाडानाथापुरम, थारुवई, मुन्नीरपल्लम, करुंगाडु तथा करुप्पन्थुरई के भीतर का क्षेत्र।

सं० इन्स० 1·22(1)1/71(9)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) जोकि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95क के साथ पठित है, के अनुसरण में शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने जैसा कि उक्त विनियम 95-क तथा मैसूर कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम, 1958 में निर्दिष्ट है, बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर चिकित्सा हितलाभ को मैसूर राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तार करने के लिये 26-12-1971 की तिथि नियत की है, अर्थात्:—

क्र सं०	जिला	तालुक	होबली	ग्राम का नाम
1.	बंगलौर	बंगलौर दक्षिणी तालुक	कृष्णा राजापुरम	ह्वाइट फील्ड
2.	बंगलौर	बंगलौर दक्षिणी तालुक	कृष्णा राजापुरम	सदरमंगला
3.	बंगलौर	हॉसकोटे	बिदाराहाल्ली	काडुगेडी
4.	बंगलौर	हॉसकोटे	बिदाराहाल्ली	बेलथुर

सं० इन्स० 1.22(1)1/71(10)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) जोकि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित है, के अनुसरण में शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने जैसा कि उक्त विनियम 95-क तथा असम कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1958 में निर्दिष्ट है, बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर चिकित्सा हितलाभ को असम राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तार करने के लिये 26-12-1971 की तिथि नियत की है, अर्थात्:—

निम्नलिखित राजस्व ग्रामों द्वारा समाविष्ट क्षेत्र:—

I. लखीमपुर जिले के टिपलिंग मौजा में छोटाटिंगराय टी० ई० अपर असम टी० कम्पनी लि०, ग्रान्ट नं० 54 एफ० एस०

II. लखीमपुर जिले के रामपगार मौजा में हेंगालुगुरी तथा बजालटोली गांव।

वी० एन० कौल
उप बीमा आयुक्त

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 (1948 का 15) की धारा 35 के अन्तर्गत 30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड की रिपोर्ट

तेईसवीं वार्षिक रिपोर्ट

1970-71

नई दिल्ली

सूचना

सूचना दी जाती है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंशधारियों (शेयर होल्डरों) की तेईसवीं वार्षिक साधारण सभा, सोमवार, तारीख 27 सितम्बर, 1971 को सायंकाल 4.00 बजें (मानक समय) होटल इम्पीरियल, जनपथ नई दिल्ली में होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर कार्यवाही की जायेगी:—

1. 30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष का निगम का तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा, वर्ष के दौरान निगम के कार्य के सम्बन्ध में बोर्ड की रिपोर्ट और उक्त तुलन-पत्र और लेखों के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार।

2. श्री एन० रामानन्द राव के कार्यनिवृत होने से औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अंशधारियों के प्रतिनिधि के रूप में एक संचालक चुनना। इस अधिनियम की धारा 11 के अनुसार ये फिर से चुने जा सकते हैं।

3. श्री एन० वी० नायुडू के कार्यनिवृत्त होने से औद्योगिक वित्त निगम अधिनिमय, 1948 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट अंशधारियों के प्रतिनिधि के रूप में एक संचालक चुनना, परन्तु इस अधिनियम की धारा 11 के अनुसार ये फिर से चुने जा सकते हैं।

4. श्री पी०एस० राजगोपाल नायडू के कार्यनिवृत्त होने से औद्योगिक वित्त निगम अधिनमिय, 1948 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट अंशधारियों के प्रतिनिधि के रूप में एक संचालक चुनना। इन्होंने लगातार चार वर्ष की दो अवधियां पूरी कर ली हैं, अतः इस अधिनमिय की धारा 11 की उपधारा (2) के तीसरे परन्तुक के अनुसार पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं हैं।

5. औद्योगिक वित्त निगम की धारा 4 की उपधारा (3) में उल्लिखित पार्टियों अर्थात अनुसूचित बैंकों, बीमा कम्पनियों, निवेशन्यासों और ऐसी ही अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा सहकारी बैंकों द्वारा मैसर्स एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी, बम्बई के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का पहला) की धारा 226 के अन्तर्गत कम्पनियों के लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् अर्हता प्राप्त एक लेखा परीक्षक को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अन्तर्गत चुनना। मैसर्स एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी इस वर्ष के अन्त में कार्यनिवृत्त हुए हैं पर वे फिर से चुने जा सकते हैं।

14 जुलाई, 1971

बलदेव पसरीचा
महाप्रबन्धक

संचालक बोर्ड

श्री चरन दास खन्ना	अध्यक्ष
श्री जी० रामानुजम् श्री एफ० के० एफ० नारीमन् डा० सैम्युल पाल डा० बी० बी० भट्ट	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित
श्री बी० बी० लाल श्री एम०के० वेंकटाचलम्	केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित
श्री एन० रामानन्दन राव श्री एस० जे० उत्तमसिंग	अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित
सरदार संतोख सिंह श्री एन० बी० नायडु	बीमा कम्पनियों, निवेशों न्यासों और ऐसी ही अन्य वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित
श्री पी०एस० राजगोपाल नायडू श्री एन०ए० कल्याणी	सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित

केन्द्रीय समिति

श्री चरन दास खन्ना	अध्यक्ष
श्री बी०बी० लाल श्री एम०के० वेंकटाचलम्	नामित संचालकों द्वारा निर्वाचित
श्री एन०ए० कल्याणी सरदार संतोख सिंह	निर्वाचित संचालकों द्वारा निर्वाचित

बैंकर्स

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी	सनदी लेखापाल
मैसर्स वाकर चन्डयोक एण्ड कम्पनी	सनदी लेखापाल

सलाहकार समितियों के सदस्य

रासायनिक प्रक्रिया और समवर्गीय उद्योग

श्री चरन दास खन्ना — अध्यक्ष
श्री एन०ए० कल्याणी
सरदार सन्तोख सिंह
श्री डी०एस० सेठ
श्री एस० के० मुखर्जी
श्री सी०जे० दादचन्जी
श्री जी०पी० कणे
श्री जयन्त जे० मेहता
श्री आर०वी० रमानी
श्री ए०सीतारामैया
श्री एल० कुमार
श्री वी०एन० कस्तूरीरंगन

चीनी उद्योग

श्री चरन दास खन्ना — अध्यक्ष
श्री पी०एस० राजगोपाल नायडु
श्री एन० ए० कल्याणी
श्री एस०एन० गुंडुराव
श्री जे०के० भौसले
श्री ए० दास
श्री एस०वी० सम्पत
श्री एम०एम०के० वाली
श्री एन०एस० जैन

इंजीनियरिंग उद्योग

श्री चरन दास खन्ना — अध्यक्ष
श्री एन०ए० कल्याणी
श्री एस० जे० उत्तमसिंग
श्री के०सी० मैत्र
श्री प्राणलाल पटेल
श्री पी० आर० देशपांडे
श्री बी० एन० खोसला
श्री ए० के०सेन
श्री वी० डी० कालेलकर
श्री के० बी० राव
श्री हरिभूषण

विविध उद्योग

श्री चरन दास खन्ना — अध्यक्ष
श्री एस० जे० उत्तमसिंग
श्री एफ०के०एफ० नारीमन्
श्री के०सी० मैत्र
श्री आर० चक्रवर्ती
श्री जी०पी० कणे
श्री बी०एन० रमन
श्री ए० सीतारामैया

वस्त्र उद्योग

श्री चरन दास खन्ना — अध्यक्ष
श्री पी०एस० राजगोपाल नायडू
श्री जी० रामानुजम
सरदार संतोख सिंह
श्री एन० मजुमदार
श्री बी० राहा
श्री के० सुन्दरम्
श्री सी०एस० रामाचारी
श्री एस० ए० खेर
श्री के० किशोर
श्री आई०बी० दत्त
श्री ए० दास
श्री एम०एम०के० वाली

पटसन उद्योग

श्री चरन दास खन्ना — अध्यक्ष
श्री एन० रामानन्द राव
श्री एस० जे० उत्तमसिंग
श्री एस० पाल
श्री हरिशंकर सिंघानियां
श्री एस० एल० मेहता
श्री एस० पी० मुकर्जी
श्री बी०डी० कुमार
श्री आर० महादेवन

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की रूपरेखा

निगमन और प्रयोजन

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना भारतीय संसद् के एक अधिनियम के अन्तर्गत 1948 में हुई । इसका उद्देश्य भारत में औद्योगिक संस्थाओं को मध्यम और दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ।

पूंजी

इस समय इसकी प्रदत्त पूंजी (पेडअप कैपिटल) 8.35 करोड़ रुपये है, जिसका 50 प्रतिशत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया) द्वारा लगाया गया है। यह बैंक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पूर्ण स्वामित्व में है और उसके द्वारा नियंत्रित भी है । शेष 50 प्रतिशत रुपया अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा संस्थाओं और निवेश-न्यासों आदि के द्वारा लगाया गया है।

प्रबन्ध

संचालक बोर्ड में एक पूर्णकालिक (होल-टाइम) अध्यक्ष और बारह संचालक हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करके, केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। छः संचालक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न अंशधारियों द्वारा चुने जाते हैं और चार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और दो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित होते हैं।

कार्य और उधार नीतियां

भारत में पंजीकृत ऐसी कोई भी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या सहकारी समिति, जो माल के निर्माण, परिरक्षण या अभिसंस्कार (प्रोसेसिंग) में, अथवा नौपरिवहन खनन या होटल उद्योग में अथवा बिजली या अन्य किसी प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण में लगी हुई हो या लगने का विचार करती हो, निगम से वित्तीय सहायता कर प्राप्त करने की पात्र है। सरकारी क्षेत्र में परियोजनायें भी, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां हैं, गैर-सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के समान ही सहायता प्राप्त कर सकती हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कम विकसित राज्यों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाएं लगाने के लिए वित्तीय सहायता रियायती दर पर भी उपलब्ध है। यह सहायता विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे रुपये और विदेशी मुद्रा दोनों का ही दीर्घकालीन ऋण, जारी किए गए साधारण (इक्विटी) और अधिमान शेयरों या डिबेंचरों की हामीदारी (अंडर राइटिंग), साधारण अधिमान और डिबेंचर पूंजी का अभिदान, विदेशों से आयात की गयी या भारत में ही खरीदी गई मशीनरी के लिए आस्थगित अदायगी (डेफर्डपेमेंट) गारंटी और विदेशी वित्तीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा के रूप में और अनुसूचित बैंकों या राज्य सहकारी बैंकों या सार्वजनिक बाजार से भारतीय मुद्रा के रूप में लिए गए ऋणों की गारंटी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का उद्देश्य नई औद्योगिक परियोजानएं स्थापिता करना और वर्तमान परियोजनाओं का नवीकरण, आधुनिकीकरण, विस्तार या विशाखन (डाइवर्सिफिकेशन) करना है ।

निधियों के स्रोत

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की निधियों के मुख्य स्रोत उसकी अपनी पूंजी, संचित आय, दिये गए ऋणों की वापसी (रिपेमेंट) और निवेशों की बिक्री के अतिरिक्त बांड जारी करके बाजार से रुपया उधार लेना और केन्द्रीय सरकार से ऋण लेन एवं विदेशी ऋण हैं।

निगम के कार्यों की उल्लेखनीय बातें

	30-6-1970 को	30-6-1971	
	रुपये (करोड़ों में)	रुपये (करोड़ों में)	उनके ब के अमर डाल (दस लाख
पूंजी और आरक्षित निधियां			
प्रदत्त पूंजी	8.35	8.35	11.[illegible]
आरक्षित निधियां	12.65	14.24	19.[illegible]
जोड़	21.00	22.59	30.[illegible]

मंजूरियां (निवल)			
—रुपया ऋण	213.30	238.67	318.23
—विदेशी मुद्रा ऋण	37.97	34.58	58.11
—हामीदारियां	25.68	29.01	38.68
—प्रत्यक्ष अभिदान	2.01	2.48	3.31
—आस्थगित अदायगियों के लिए दी गई गारंटियां	28.04	28.46	37.94
—विदेशी ऋणों के लिए दी गई गारंटियां	32.47	32.47	31.29
जोड़	330.47	356.67	487.56
संवितरण (डिस्बर्समेंट्स)			
—रुपया ऋण	196.43	209.61	279.48
—विदेशी मुद्रा ऋण	32.37	35.37	47.29
—हामीदारियां	19.84	20.57	27.42
—प्रत्यक्ष अभिदान	1.99	2.13	2.84
—आरक्षित अदायगियों के लिए दी गई गारंटियां	27.45	27.65	36.87
—विदेशी ऋणों के लिए दी गई गारंटियां	23.33	23.33	31.11
जोड़	301.41	318.76	425.01
बकाया (आउटस्टैंडिंग्स)			
—रुपया ऋण	128.06	133.32	177.76
—विदेशी मुद्रा ऋण	25.17	26.09	34.79
—हामीदारियां	15.29	15.61	20.81
—प्रत्यक्ष अभिदान	2.48	2.41	3.21
—आरक्षित अदायगियों के लिए दी गई गारंटियां	8.24	7.05	9.40
—विदेशी ऋणों के लिए दी गारंटियां	16.15	13.65	18.20
जोड़	195.38	198.13	264.17
वित्तपोषित इकाइयों की संख्या	499	527	
स वर्ष का उपार्जन			
—सकल आय	12.82	13.46	17.95
—कर लगाने से पहले सकल लाभ	4.33	4.47	5.96
—करों के लिए व्यवस्था	2.37	2.37	3.16
—निवल लाभ	1.96	2.10	2.80

टिप्पणियां:—तारीख 30-6-1970 को जो निवल मंजूरियों के आंकड़े और वित्तपोषित औद्योगिक इकाइयों की संख्या दिखाई गई ह उस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में दिखाए गए आंकड़ों से पूरी तरह मेल नहीं खाती, क्योंकि 30-6-1970 तक मंजूर की गई य सहायता में से चालू वर्ष के दौरान कुछ वित्तीय मंजूरियां बाद में वापिस ले ली गई/समंजित कर दी गयीं । 2—वित्तीपोषित ेक इकाइयों की संख्या उन इकाइयों की बोधक है जिन्हें एक या अधिक अवसरों पर एक या एक से अधिक प्रकार की वित्तीय ा मंजूर की गई है। तथ्य यह है कि इसमें से बहुत सी औद्योगिक इकाइयों सी ने निगम से अधिक प्रकार की सहायता की है और इकाइयों ने एक से अधिक बार सहायता प्राप्त की है।

वित्तीय कार्यों का संक्षिप्त विवरण

(रुपये, करोड़ों में)

	30-6-1970 तक			30-6-1971 तक को समाप्त हुए वर्ष तक			30-6-1971 का जोड़			
	मंजूरियां (निवल)		संवितरित	मंजूरियां (निवल)		संवितरित	मंजूरियां (निवल)		संवितरित	30-6-1961 की बाकया
	संख्या	रकम	रकम	संख्या	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम
1. ऋण										
—रुपया	639	213.30	196.43	45	25.37	13.18	684	238.67	209.61	133.32
—विदेशी मुद्रा	135	37.97	32.37	22	5.61	3.10	157	43.58	35.47	26.09
जोड़	774	251.27	228.80	67	30.98	16.28	841	282.25	245.08	159.41
2. हामीदारियां										
—साधारण शेयर	121	10.31	7.68	9	0.91	0.11	130	11.22	7.79	6.64
—अधिमान शेयर	96	6.64	4.58	7	0.42	0.62	103	7.06	5.20	4.24
—डिबेंचर	20	8.73	7.58	1	2.00	—	21	10.73	7.58	4.73
जोड़	237	25.68	19.84	17(क)	3.33	0.73	254(ग)	29.01	20.57	15.61
3 प्रत्यक्ष अभिदान										
—साधारण	5	0.17	0.15	8	0.37	0.11	13	0.54.	0.26	0.75(घ)
—अधिमान शेयर	1	0.02	0. 02	3	0.,10	0. 03	0.4	0 .12	0.05	0.29(घ)
—डिबेंचर	1	1.82	1. 82	—	—	—	1	1.82	1.82	1.37
जोड़	7	2·01	1.99	11(ख)	0.47	0.14	18	2. 48	2.13	2.41
1 से 3 तक का जोड़	1018	278.96	250.63	95	34.38	17.15	1113	313.74	267.78	177.43
4. आस्थगित अदायगी गारंटियां	41	28.04	27.45	1	0.42	0.20	42	28.46	27.65	7.05
5. विदेशी ऋण के लिये गारंटियां	5	23.47	23.33	—	—	—	5	23.47	23.33	13.65
1 से 5 तक का जोड़	1064	330.47	301.41	96	35.20	17.35	1160	365 67	318 76	198.13

(क) 7 मामले साधारण और अधिमान दोनों प्रकार के शेयरों से सम्बन्धित हैं।

(ख) 2 मामले साधारण और अधिमान दोनों प्रकार के शेयरों से सम्बन्धित हैं।

(ग) 75 मामले साधारण और अधिमान दोनों प्रकार के शेयरों से सम्बन्धित हैं।

(घ) इसमें 0.67 करोड़ रुपये के बकाया ऋण भी सम्मिलित हैं, जिन्हें शेयरों में बदल दिया गया और दूसरी कम्पनी के 0.06 करोड़ रुपयें के डिबेंचरं भी सम्मिलित हैं, जिन्हें साधारण शेयरों में बदल दिया गया ।

टिप्पणी:—30-6-1970 को निवल मंजूरियां के जो आंकड़े दिखाये गये हैं वे वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये आंकड़े से मेल नहीं खाते, क्योंकि उनमें से 30-6-1970 तक वित्तीय सहायता की कुछ मंजूरियां बाद में या तो वापस ले ली गयीं या समंजित कर दी गई।

यह वर्ष—संक्षेप में

30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निगम ने 61 औद्योगिक परियोजनाओं को 35.32 करोड़ रुपयें की सकल सहायता मंजूर की, जबकि पिछले वर्ष 49 परियोजनाओं को 19.38 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई ।

1970-71 के दौरान ऋण प्राप्त करने वाली इन 61 परियोजनाओं की लागत का अनुमान 190 करोड़ रुपये लगाया गया। सहायता प्राप्त करने वाली इन परियोजनाओं में से 24 नई परियोजनाओं को कुल मंजूरियों का 59 प्रतिशत (20.87 करोड़ रुपयें) भाग प्राप्त हुआ ।

1970-71 के दौरान कई प्रकार के उद्योगों को सहायता दी गई, जिसमें प्राथमिक-उद्योग जैसे धातु इस्पात, कटर, सीमेंट, अलमोनियम भी शामिल हैं। ये 61 परियोजनायें 13 प्रांतो में व्याप्त हैं। इसमें 7 प्रांतों में व्याप्त परियोजनायें भी शामिल हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अविकसित अथवा औद्योगिक रूप से कम विकसित जिलों में लगाई जायेंगी। इस प्रकार की परियोजनाओं को कुल 8.32 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई । यह वर्ष के दौरान मंजूर सहायता का 24 प्रतिशत है।

पिछले वर्ष की भांति 1970-71 में भी चीनी तथा सूती सहकारिताओं को काफी मात्रा में सहायता प्राप्त हुई, यह 9.15 करोड़ रुपये थी, जो कुल मंजूरियों का 26 प्रतिशत के लगभग है। निगम ने 8 चीनी सहकारिताओं तथा दो सूती सहकारिताओं को ये ऋण मंजूर किये, इनमें 4 चीनी सहकारितायें तथा एक सूती सहकारिता औद्योगिक रूप से कम विकसित जिलों में स्थित है।

नई नीति के अनुरूप सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने के पात्र हो जाने के फलस्वरूप दो सरकारी-क्षेत्र परियोजनाओं को दूर संचार तारें बनाने के लिए ऋण मंजूर किये गये।

इस साल के कार्य परिणाम से 13.46 करोड़ रुपये की आय हुई, 1969-70 में यह आय 12.82 करोड़ रुपये थी। पिछले वर्ष के सकल लाभ में 14 लाख रुपये की वृद्धि होने से सकल लाभ 4.47 करोड़ रुपये हुआ, कराधान के लिए 2.37 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के बाद निवल लाभ 2.10 करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष से यह 14 लाख रुपये ज्यादा है। आरक्षित निधि में 1.69 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी गई, इससे निगम की आरक्षित निधि 14.24 करोड़ रुपये कर दी गई, जो प्रदत्त पूंजी से 5.90 करोड़ रुपये अधिक है।

रुपया ऋणों के वर्तमान तथा भावी वायदे पूरे करने की दृष्टि से तथा केन्द्रीय सरकार से उधार लेने की निर्भरता को कम करने के लिए नवम्बर, 1970 में 4.50 करोड़ रुपये के बांड जारी किये । जारी की गई राशि में अनुज्ञेय 10 प्रतिशत रकम को मिलाकर निगम को 4.95 करोड़ रुपये का अभिदान प्राप्त हुआ ।

वर्ष के दौरान पश्चिमी जर्मनी के ऋदितांस्तल द्वारा निगम को 100 लाख जर्मनी मार्क का ऋण स्वीकार किया गया। संयुक्त राज्य/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1969 के अन्तर्गत निगम को 10 लाख पौंड का ऋण उपलब्ध किया गया। संयुक्त राज्य भारत पूंजी विशेष ऋण, 1971 के अन्तर्गत 10 लाख पौंड का ऋण सम्बन्धी दस्तावेज के शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है।

इस वर्ष के दौरान निगम ने ब्याज की दर बढ़ा दी। 5 दिसम्बर, 1970 से रुपया ऋणों पर ब्याज की दर 8 प्रतिशत से 8½ प्रतिशत लागू हो गई। 27 फरवरी, 1971 से विदेशी मुद्राओं के उपऋणों पर ब्याज की दर 8½ प्रतिशत से 9 प्रतिशत कर दी गई ।

17 मई, 1971 से गौहाटी में निगम के उप-कार्यालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है। 18 अगस्त, 1971 को अहमदाबाद में निगम की एक शाखा खोली गई। निगम के हैदराबाद, बैंगलोर, कानपुर पटना भुवनेश्वर तथा भोपाल में अन्य कार्यालय खोलने के लिए तैयारियां जारी हैं। आशा की जाती है कि निगम के अतिरिक्त कार्यालय खुल जाने से निगम ऋण प्राप्त करने वाली वर्तमान तथा भावी संस्थाओं की उत्तम सेवा प्रदान करने में समर्थ रहेगा।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 35 के अन्तर्गत, 30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड की रिपोर्ट

संचालक बोर्ड 30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के परीक्षित लेखा विवरण के साथ निगम के कार्य संचालन के बारे में अपनी तेईसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

निगम के कार्यों की समीक्षा

2. इस वर्ष के दौरान, मंजूर और संवितरित वित्तीय सहायता का संक्षिप्त विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है

सारणी 1

(रुपये, करोड़ों में)

	मंजूर की गई सहायता (सकल)			संवितरित सहायता
	आवेदन-पत्रों की संख्या	रकम		रकम
(1) रुपया ऋण	46(45)	25.49	(25.37)	13.18
(2) विदेशी मुद्रा ऋण	22	5-61		3.10
(3) हामीदारियां	10(क)	3.33		0.73(ग)
(4) प्रत्यक्ष अभिदान	9(ख)	0.47		0.14
(1) से (4) तक का जोड़:	87.(86)	34.90	(34.78)	17.15
(5) अस्थगित आदयगियों की गारंटियां	1	0.42		0.20(घ)
(1) से (5) तक का जोड़:	88(87)	35.32	(35.20)	17.35

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दी गई संख्याएं निवल प्रभावी मंजूरियों अर्थात् सकल मंजूरियों में से वर्ष के दौरान रद्द की गई मंजूरियों को घटाने पर शेष रही मंजूरियों की सूचक हैं।

(क) 7 मामले साधारण और अधिमान दोनों प्रकार के शेयरों से सम्बन्धित हैं।

(ख) 2 मामले साधारण और अधिमान दोनों प्रकार के शेयरों से सम्बन्धित हैं।

(ग) उन शेयरों के लिए मांगी गई रकम जो निगम को लेने पड़े थे।

(घ) वास्तव में दी गई गारंटियां।

30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान मंजूर और संवितरित वित्तीय सहायता का आलेख

मंजूरियां रूपये 35.32 करोड़

संवितरण रूपये 17.35 करोड़

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

3. पहले की भांति वर्ष के दौरान 25.49 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता रुपया ऋणों के रूप में मंजूर की गई। इस वर्ष 35.32 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई जो पिछले वर्ष 19.38 करोड़ रुपये की सहायता से लगभग 82 प्रतिशत अधिक थी।

इस वर्ष 17.35 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई, यह राशि पिछले वर्ष 18.05 करोड़ रुपये के संवितरिणों की तुलना में कुछ कम थी। इस वर्ष संवितरणों के थोड़ा कम होने का कारण पिछले वर्ष की कम मंजूरियों में खोजा जा सकता है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संवितरणों में भी वास्तव में वृद्धि हुई। पिछले वर्ष 1.69 करोड़ रुपये के संवितरणों की तुलना में इस वर्ष 3.10 करोड़ रुपये के संवितरण हुए।

इस वर्ष के दौरान नकद संवितरणों की राशि 17.15 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष यह रकम 17.71 करोड़ रुपये थी। इन नकद संवितरणों का ब्यौरा इस प्रकार से है :—

	(रुपये, करोड़ों में)
(1) रुपया ऋण	13.18
(2) विदेशी मुद्रा ऋण	3.10
(3) शेयरो में विनियोग/औद्योगिक इकाईयों को डिबेंचरों के रूप में हामीदारियां/प्रत्यक्ष अभिदान	0.87
जोड़:	17.15

4. 30 जून, 1970 को 34 संस्थाओं से प्राप्त कुल 127.99 करोड़ रुपये के लिए 51 आवेदन पत्र विचाराधीन थे। इनमें से 113.29 करोड़ रुपये के लिए 9 संस्थाओं से प्राप्त 17 आवेदन पत्र ऐसे थे जिनमें अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से वित्त व्यवस्था की जानी थी। इस वर्ष के दौरान 70 संस्थाओं से 96 नये आवेदन पत्र प्राप्त हुए जो रुपया तथा विदेशी मुद्रा ऋणों, शेयरों तथा डिबेंचरों की हामीदारी और आस्थगित अदायगी की गारंटियों के लिए थे। कुल मिला कर 35.32 करोड़ रुपये के 61 संस्थाओं से 88 आवेदन पत्र मंजूर किये गये, 4 आवेदनों को मंजूर नहीं किया गया। 16 संस्थाओं से 20 आवेदन पत्र वापिस ले लिये गये, क्योंकि आवेदकों ने अपनी योजनायें बदल दी अथवा स्थगित कर दी अथवा वे वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए आवश्यक शर्तों का पालन नहीं कर सकें। 29 संस्थाओं से 29 आवेदनों पर इस लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि आवेदक आवश्यक सूचना तथा आंकड़ें उपलब्ध नहीं करा सके।

वर्ष के अन्त में 28 संस्थाओं से कुल 94.40 करोड़ रुपये के 41 आवेदन पत्र विचारार्थ बाकी थे। इन आवेदन पत्रों में 77.88 करोड़ रुपये की कुल सहायता के लिए 4 संस्थाओं से 9 आवेदन पत्र ऐसे भी थे जो संयुक्त रूप से अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित किये जाने थे। इनमें से 2 उर्वरक परियोजनाओं से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों की राशि ही कुल मिला कर 73.23 करोड़ रूपये थी। इन आवेदनों पर इस लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि परियोजनाओं से सम्बन्धित आधार-भूत पहलू स्पष्ट नहीं थे। विचारार्थ पड़े हुए आवेदनों में से 10.27 करोड़ रुपये के 10 मामले सहकारी चीनी मिलों तथा एक करोड़ रुपये का एक मामला सहकारी कताई मिल का था। चीनी सहकारी मिलों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि वे काफी पूंजी एकत्र नहीं कर सकें, इनके मामले में पूंजी एकत्र करना एक क्रमिक प्रक्रिया है।

एक विवरण रिपोर्ट के परिशिष्ट "क" में दिया गया है, जिसमें वर्ष के आरम्भ में विचारार्थ पड़े तथा वर्ष के दौरान प्राप्त, रद्द किये गए, वापिस लिये गये और मंजूर किये गये आवेदन पत्रों की रकम और संख्या तथा विभिन्न राज्यों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को संवितरित की गई रकम दिखाई गई है।

वर्ष के दौरान में मंजूर किया गया रुपया ऋण

5. वर्ष के दौरान कुल 25.49 करोड़ रुपये के 46 रुपया ऋण मंजूर किये गये। 2 आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये और 13 आवेदन पत्रों को वापिस लिया मान लिया गया। वर्ष के दौरान संवितरित रकम 13.18 करोड़ रुपये थी।

वर्ष के दौरान मंजूर किए गए विदेशी मुद्रा ऋण

6. वर्ष के दौरान कुल 5.61 करोड़ रुपये के 22 आवेदन मंजूर किये गए। इन ऋणों का मुद्रावार वितरण नीचे सारणी 2 में दिखाया गया है।

सारणी 2

मुद्रा	उपऋणों की संख्या	विदेशी मुद्रा (दस लाख में)	(रुपये, लाखों में)
पश्चिमी जर्मन मार्क	21	25.90	530.78
पौंड स्टर्लिंग	3	0.12	21.51
फ्रांसीसी फ्रांक	2	0.65	8.81
जोड़ :	26		561.10

इस वर्ष के दौरान विदेशी मशीनरी पूर्तिकर्ताओं को कुल 2.40 करोड़ रुपये के साख-पत्र प्रेषित किये गये। निगम के पास उपलब्ध फ्रांसीसी ऋण के अन्तर्गत 2 उपस्कर संविदाओं के सम्बन्ध में 17.83 लाख रुपये (फ्रा० फ्रा० 13.2 लाख) के वचन-पत्र बैंक फ्रांसेस डु फामर्स एकसटीरियर के नाम जारी किये गये।

वर्ष के दौरान कुल 121.8 लाख जर्मनी मार्क (249.49 लाख रुपये), अमरीकी डालर 5.7 लाख (42.79 लाख रुपये, और 12.9 फ्रांसीसी फ्रांक (17.48 लाख रूपये) की रकम संवितरित की गई।

वर्ष के दौरान किए गए हामीदारी कार्य

7. इस वर्ष के दौरान हामीदारी के 10 आवेदन पत्र मंजूर किये गये जिनकी कुल राशि 333.15 लाख रुपये थी इसमें 91 लाख रुपये के साधारण शेयर, 42.15 लाख रुपये के अभिमान शेयर और 200 लाख रुपये के डिबेंचर शामिल थे।

इस वर्ष के दौरान निगम 10 शेयर निर्गमों (पिछले वर्ष में अनुमोदित दो निर्गमों सहित) के लिए हामीदारी के करारों पर हस्ताक्षर किये । ये क्रमश: 79.00 लाख रुपये तथा 39.90 लाख रुपये के साधारण और अधिमान शेयरों के लिए थे। इनमें से 10.28 लाख रुपये के साधारण शेयर और 34.89 लाख रुपये के अधिमान शेयर निगम को लेने पड़े । इन 10 इजराओं में से साधारण शेयरों के 20 लाख रुपये के एक मामले में निगम ने हामीदारी ली थी, इसका पूरा अभिदान किया गया। शेष 3 मामलों में जिनमें साधारण और अधिमान शेयरों के लिए क्रमश: 47.50 लाख रुपये तथा 17.65 लाख रुपये की हामीदारी थी, साधारण शेयरों का पूरा अभिदान हो गया । इस वर्ष पूरे हुए हामीदारी के दस मामलों के सम्बन्ध में हामीदारी की राशि और निगम को प्राप्त शेयरों का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :

सारणी 3

(रुपये, लाखों में)

	हामीदारी की राशि	वह राशि जो निगम को देनी पड़ी
साधारण शेयर	79.00	10.28
अधिमान शेयर	39.90	34.89
जोड़	118.90	45.17

इस वर्ष के दौरान निगम ने 9 कम्पनियों के मामलों में साधारण और अधिमान शेयरो के क्रमश: 37.01 लाख रुपये तथा 9.99 लाख रुपये हामीदारी सहित प्रत्यक्ष अभिदान का भी अनुमोदन कर दिया ।

वर्ष के दौरान संयन्त्रों और मशीनों की आस्थगित अदायगियों के लिए गारंटियां

8. इस वर्ष के दौरान कुल 42.35 लाख रुपये का एक आवेदन पत्र मंजूर किया गया। वास्तव में दी गई गारंटियों की कुल रकम 19.79 लाख रुपये थी।

मंजूर की गई वित्तीय सहायता का उद्योगवार विवरण

9. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान की गई वित्तीय सहायता का उद्योगवार वितरण सारणी 4 में दिया गया है। जैसा कि स्पष्ट है कि निगम की वित्तीय सहायता का लाभ उद्योगों के एक विस्तृत समूह को मिला है और उनमें से कई उद्योग राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में आधारभूत महत्व के हैं। आकार की दृष्टि से निगम की वित्तीय सहायता का लाभ प्रमुख रूप से चीनी उद्योग, कृत्रिम रेशे, लोहा और इस्पात, बिजली मशीनरी, सूती वस्त्र, धातु उत्पाद, मोटर गाड़ियों और अलौह धातु उद्योगों को मिला है।

चीनी उद्योग को मंजूर की गई 8.29 करोड़ रुपये की सारी सहायता सहकारी क्षेत्र की 8 इकाईयों की प्राप्त हुई। सूती वस्त्र उद्योग में 2.73 करोड़ रुपये की मंजूर की गई वित्तीय सहायता में से 2 सहकारी कताई मिलों को 85.50 लाख रुपये (अर्थात 31.5 प्रतिशत) प्राप्त हुए। यह पहली दोनो इकाइयों ऐसी हैं जोकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई हैं। इनमें से राजस्थान की इकाई औद्योगिक रुप से कम विकसित जिले में स्थित है। सहकारी चीनी तथा वस्त्र उद्योग को कुल 9.15 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो कुल मंजूर की गई सहायता का 26 प्रतिशत है।

जिन उद्योगों को वर्ष के दौरान सहायता मिली है उनमें अलौह धातुओं में अलमोनियम तथा कृत्रिम रेशों में नाइलोन उद्योग, उल्लेखनीय है। निगम से सहायता प्राप्त करने वाले उद्योगों में धातु इस्पात, ट्रांसफार्मर तथा दूर संचार यन्त्र, धातु उत्पाद, ट्रैक्टर और शक्ति हल विशेष उल्लेखनीय हैं। निगम से सहायता प्राप्त करने वाले अन्य उद्योग मशीनरी, सीमेंट, रसायन, वनस्पति तेल, कोयला, वनस्पति निर्जलीकरण, कागज, होटल, लकड़ी, और कार्क आदि हैं ।

सारणी 4

(रुपये, लाखों में)

उद्योग	ऋण	हामीदारियां	गारंटियां	जोड़	कुल का प्रतिशत	औद्योगिक इकाइयों की संख्या
चीनी	829.00	—	—	829.00	20.5	8
कृत्रिम रेशे	435.00	55.00	42.35	532.35	15.1	5
लोहा और इस्पात	211.50	267.25	—	478.75	10.6	4
बिजली मशीनरी	289.39	9.40	—	298.79	8.5	6
सूती वस्त्र	268.06	5.00	—	273.06	7.7	9
धातु उत्पाद	233.80	10.60	—	244.40	6.9	7
मोटर गाड़ियां	229.54	10.00	—	239.54	6.8	3
अलौह धातुएं	170.00	—	—	170.00	4.8	1
मशीनरी	83.15	12.00	—	95.15	2.7	3
कागज	70.22	—	—	70.00	2.0	1
विविध रसायन	70.00	—	—	56.78	2.0	2
बुनियादी औद्योगिक रसायन	56.78	—	—	56.78	0.6	3
सीमेंट	50.00	—	—	50.00	0.4	1
वनस्पति और पशुजन्य तेल तथा स्नेह	25.00	7.00	—	32.00	9.0	1
कोयला	32.00	—	—	32.00	9.0	2
खाद्य निर्माण उद्योग वनस्पति तथा फलों का	12.00					
परिरक्षण	15.10	3.90	—	15.90	0.4	1
होटल	15.00	—	—	15.00	0.4	1
लकड़ी और कार्क	10.00	—	—	10.00	0.3	1
बिजली गैस तथा भाप	8.99*	—	—	8.99	0.2	—
उर्वरक	5.60	—	—	5.68	0.2	1
साईकल	4.58	—	—	4.58	0.1	1
जोड़	3109.61	380.15	42.35	3532.11	100.0	61

*पहले से मंजूर विदेशी मुद्रा ऋण के एक भाग के संपरिवर्तन की राशि।

20.87 करोड़ रुपए (कुल का लगभग 59 प्रतिशत) की वित्तीय सहायता 24 नई इकाइयों को दी गई, जबकि 14.45 करोड़ रुपए चालू उपक्रमों के विस्तार, और आधुनिकीकरण के लिए मंजूर किए गए। जिन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी गई उनको कुल प्राक्कलित पूंजीगत लागत 190.42 करोड़ रुपए थी। इस कुल प्राक्कलित लागत का लगभग 18.6 प्रतिशत राशि निगम ने वित्तीय सहायता के रूप में मंजूर की।

वित्तीय सहायता का राज्यवार वितरण

10. आगेसारणी 5 में निगम के द्वारा वर्ष के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार वितरण दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान मंजूर की गई कुल 35.32 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता 13 राज्यों में व्याप्त 61 परियोजनाओं को उपलब्ध हुई। तीन राज्यों को छोड़कर शेष सभी को वित्तीय सहायता का काफी भाग प्राप्त हुआ। 6 कम विकसित राज्यों अर्थात्, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को 15.22 करोड़ रुपए की सहायता मिली, जो कुल मंजूरियों का 43 प्रतिशत है। इन राज्यों की परियोजनाएं, चीनी, सूती वस्त्र, कागज, कृत्रिम रेशे तथा धागे, शक्ति अल्कोहल, धातु इस्पात, अलमोनियम, शक्ति टिलरों तथा हैंड ट्रैक्टरों, आटोसाइकिलों आदि से संबंधित है।

वित्तीय सहायता का सर्वाधिक भाग (21.8 प्रतिशत) महाराष्ट्र को मिला, क्योंकि 3 चीनी सहकारिताओं को 3.24 करोड़ रुपए तथा 3 अन्य इकाइयों को 3 करोड़ रुपए रोलर बियरिंगों, सूखे बैटरी सेल तथा नाइलोन तन्तु धागे बनाने के लिए मंजूर किए गए। गुजरात को 4.49 करोड़ रुपए की सहायता नाइलोन धागे, चीनी तथा बाल बियरिंग की परियोजनाओं को मंजूर किए गए। मैसूर को 2.60 करोड़ रुपए (7.4 प्रतिशत)

की सहायता चीनी, सूती वस्त्र तथा बिजली मशीनरी को प्राप्त हुए। तमिल नाडु की परियोजनाएं सूती वस्त्र, चीनी और रसायन उद्योगों से संबंधित है। हरियाणा में सहायता का मुख्य लाभ एक ट्रैक्टर बनाने वाली परियोजना को मिला। शेष 1.56 करोड़ रुपए (4.4 प्रतिशत) की सहायता अन्य राज्यों की परियोजनाओं को प्राप्त हुई।

इस वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में जिन संस्थाओं को वित्तीय सहायता मंजूर की गई, उनके नाम और उनकी परियोजनाओं का विवरण रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है।

सारणी 5

(रुपए, लाखों में)

राज्य	ऋण	कुल ऋणों का प्रतिशत	हामीदारियां	आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	कुल का प्रतिशत	औद्योगिक इकाइयों की संख्या
महाराष्ट्र	752.09	24.2	17.02	—	769.10	21.8	14
बिहार	225.00	7.2	260.00	—	485.00	13.7	4
गुजरात	383.61	12.3	23.00	42.35	448.96	12.7	3
उत्तर प्रदेश	397.94	12.8	44.25	—	442.19	12.5	7
उड़ीसा	269.05	8.7	10.00	—	279.05	7.9	3
मैसूर	260.28	8.4	—	—	260.28	7.4	3
तमिलनाडु	216.78	7.0	5.00	—	221.78	6.3	8
आन्ध्र प्रदेश	185.00	5.9	5.00	—	190.00	5.4	3
हरियाणा	143.57	4.6	10.88	—	154.45	4.4	6
केरल	105.00	3.4	—	—	105.00	3.0	1
राजस्थान	81.10	2.6	—	—	81.10	2.2	3
पश्चिमी बंगाल	49.40	1.6	—	—	49.50	1.4	4
मध्य प्रदेश	40.00	1.3	5.00	—	45.00	1.3	2
पंजाब	0.70*	—	—	—	0.70	—	—
जोड़	3109.61	100.0	380.15	42.35	3532.11	100.0	61

*पहले से मंजूर जर्मनी मार्क उप-ऋण में वृद्धि।

प्राथमिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं

धातु इस्पात

यह सर्वविदित है कि राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए धातु इस्पात सर्वोपरि महत्व का है। ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात्, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं साख निगम, जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के साथ संयुक्त रूप से निगम ने बिहार अलाय स्टील्ज लि० को 150 लाख रुपए का ऋण तथा शेयर पूंजी में 60 लाख रुपए की हामीदारी एवं प्रत्यक्ष अभिदान करना मंजूर किया। बिहार में रांची के समीप पतरातू के स्थान पर फ्रांस के स्नीडर ग्रुप से संबंधित दो कंपनियों के तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग से लगने वाला यह कारखाना कार्बन और धातु निर्माण इस्पात, बाल बियरिंग इस्पात, धातु यंत्र तथा तीव्र गति इस्पात का निर्माण करेगा।

इंजीनियरिंग

एन्टीफ्रिक्सन बियरिंगज कारपोरेशन लि० को 100 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया गया। यह कारपोरेशन शुण्डक तथा बेलनाकार रोलर बियरिंग और बाल नोद बियरिंग के उत्पादन में लगी है। महाराष्ट्र में लोनवला के स्थान पर कम्पनी के वर्तमान संयंत्र में बेलनाकार तथा शुण्डक

रोलर बियरिंग को 4.6 लाख से 10 लाख वार्षिक की दर से क्षमता बढ़ाने के लिए निगम ने वित्तीय सहायता प्रदान की। इंजीनियरिंग और परिवहन उद्योग के विकसित होने से रोलर बियरिंगों की मांग बढ़ रही है, कम्पनी का उत्पाद इस कमी को पूरा करने में सहायक होगा।

बाल बियरिंग उद्योग में प्रिसिज़न बियरिंगज़ इण्डिया लि० अन्य इकाई है जिसे वित्तीय सहायता मंजूर की गई। कम्पनी को 85 लाख रुपए का ऋण तथा 5.61 लाख रुपए के बराबर पश्चिमी जर्मनी मार्क में उप-ऋण मंजूर किया गया। यह सहायता कम्पनी में बड़ौदा में लगे संयन्त्र को बाल और रोलर बियरिंग की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए मंजूर की गई। पहले से ही कम्पनी 67 प्रकार के बाल और रोलर बियरिंगों का निर्माण कर रही है। कम्पनी द्वारा एक विस्तार योजना के अधीन संस्कारित प्रकृति के अन्य 28 प्रकार के बाल और रोलर बियरिंगों के बनाने का प्रस्ताव है, आजकल इनका आयात किया जाता है।

कृषि मशीनरी

ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है, जिनका अब तक काफी मात्रा में आयात किया जाता रहा है। निगम ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं साख निगम तथा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंन्सी के साथ मिलकर एस्कोर्टस् ट्रैक्टर लि० को 60 लाख रुपए का रुपया ऋण तथा 63.85 लाख रुपए के बराबर पश्चिमी जर्मनी मार्क उप-ऋण मंजूर किया। यह ऋण फरीदाबाद, हरियाणा में 46 हार्स पावर के 6,000 वार्षिक की दर से ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए नई परियोजना को मंजूर किए। इस कंपनी का प्रवर्तन अमेरिका की फोर्ड मोटर कम्पनी की तकनीकी तथा वित्तीय सहायता से एस्कोर्टस् लि० ने किया, यह कम्पनी पहले से ही निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है। अमेरिका की इस कम्पनी ने भारत में इस प्रकार के उद्यम में पहली बार प्रवेश किया है। कम्पनी का उत्पाद अर्थव्यवस्था की भारी कमी को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। इस परियोजना का विशेष पहलू यह होगा कि कम्पनी ट्रैक्टरों की सर्विस तथा मरम्मत के लिए केंद्र स्थापित करेगी जिससे प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त कम्पनी 60 प्रतिशत कल पुर्जे छोटे तथा सहायक उद्योगों से प्राप्त करेगी, फलस्वरूप तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।

कृषि क्षेत्र में निगम द्वारा वित्तपोषित अन्य महत्वपूर्ण परियोजना कानपुर की जे० के० सातोह एग्रीकल्चरल मशीन्ज़ लि० है, जिसका लक्ष्य प्रतिवर्ष 6,000 पावर टिलर बनाने का है। निगम ने कंपनी को 50 लाख रुपए का रुपया ऋण तथा 5 लाख रुपए के साधारण तथा अधिमान शेयरों में हामीदारी दी है। इस परियोजना की स्थापना जापान की ख्याति प्राप्त सातोह एग्रीकल्चरल मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि० तथा सुमितोमो शोजी केशा लि० फर्मों के तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग से हुई है। कंपनी कम हार्स पावर (7.5 हार्स पावर और 8 से 11 हार्स पावर) के पावर टिलरों/हैंड ट्रैक्टरों का निर्माण करेगी जिनके साथ सालांगो तथा उपसाधनों का विविध रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इन टिलरों का प्रयोग खुश्क तथा गीली भूमि को जोतने, हल चलाने, समतल करने और ढलाई करने के लिए किया जा सकता है। इस परियोजना द्वारा विविध प्रकार के यंत्र बनाने के लिए सहायक उद्योग लगाने का भी विचार है। छोटे पैमाने के उद्योग का विकास करने की योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है और काफी प्रशिक्षित बेरोज़गार इंजीनियरों को रोजगार मिलने की संभावना है। कंपनी ने बिक्री के बाद सर्विस करने के लिए कारीगर तथा तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण पाठशाला की स्थापना भी की है।

कृत्रिम रेशे

उपभोक्ताओं की रुचि तथा आदतों में परिवर्तन होने के कारण और देश में कपास का उत्पादन कम होने से मानवनिर्मित रेशे की मांग बढ़ी है। कृत्रिम रेशे का उत्पादन कपास के आयात को कम करने के लिए आवश्यक समझा गया है। वर्ष के दौरान निगम ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर स्वदेशी पलीटेक्स लि०, गाजियाबाद को वित्तीय सहायता प्रदान की। इस परियोजना की स्थापना पश्चिमी जर्मनी के विकरज़-जिम्मर की तकनीकी सहायता से हुई। इसका लक्ष्य 6,100 टन वार्षिक दर से कृत्रिम रेशे का उत्पादन करना है। इस परियोजना के लिए निगम ने 50 लाख रुपए का रुपया ऋण और 100 लाख रुपए के बराबर पश्चिमी जर्मनी मार्क उपऋण तथा 20 लाख रुपए की हामीदारी का अनुमोदन किया है।

नाईलोन-6 के उत्पादन क्षेत्र में निगम ने दो परियोजनाओं को सहायता दी, इनमें से एक नई है। गारवारे नाइलोन्स लि० को विस्तार योजना के लिए निगम ने 50 लाख रुपए का ऋण, 100 लाख रुपए के बराबर पश्चिमी जर्मनी मार्क उप-ऋण तथा 8 लाख और 15 लाख रूपए के क्रमशः साधारण और अधिमान शेयरों में हामीदारी का अनुमोदन किया। यह नई नायलोन परियोजना गुजरात में सूरत के पास उधाना के स्थान पर गुजरात पोलियामिड्ज़ लि० द्वारा चालू की गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजना ट्रैको केबल कं० लि०, केरल सरकार का उपक्रम है। यह इकाई 1,000 किलो मीटर वार्षिक की दर से कागज की मढी हुई दूर-संचार तारों का निर्माण करेगी। 1965 से यह कंपनी कवचित तथा गैर-कवचित पी० वी० सी० तारों का निर्माण कर रही है। इसमें तांबे तथा अलमोनियम पर संवाहक 1.1 किलो वोल्ट तक की लोच और लोचक तथा अनावृत तांबा अलमोनियम संवाहक जैसे ए० ए० सी० एवं ए० सी० एस०आर० भी शामिल हैं। उपरोक्त उल्लेख के अनुसार जिला एरनाकुलम के इरीम-पनम स्थान पर लगने वाली यह परियोजना विशालन के लिए है। इससे देश में टेलीफोन तारों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी तथा सरकार को अधिक टेलीफोन लगाने में सुविधा रहेगी, इससे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं को विकसित करने में आसानी होगी।

निगम ने एन० जी० इ० एफ० लि०, बैंगलोर को 75 लाख रुपए मंजूर किए। इस कंपनी ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से 250 लाख रुपए के लिए आवेदन पत्र दिया था। इस कंपनी का प्रवर्तन मैसूर सरकार ने स्विच गियरों, बोर्डों, ट्रांसफारमरों, बिजली की मीटरों का उत्पादन

करने के लिए किया। कंपनी का लक्ष्य प्रतिवर्ष 10,000 सिलीकोन डयोड्स (रेक्टीफायर के लिए) उत्पादन के लिए संयंत्र लगाने तथा आंतरिक उपभोग के लिए प्रतिवर्ष 1,300 मीट्रिक टन ट्रांसफार्मर पत्तियों का निर्माण करने और प्रतिवर्ष 600 मीट्रिक टन तांबा तार रेखणों के उत्पादन करने का है। कंपनी का लक्ष्य वर्तमान उत्पादन को मजबूत बनाने के लिए कुछ संतुलन उपस्कर उपलब्ध करना भी है। यह राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, इसकी स्थापना पश्चिमी जर्मनी की ए० ई० जी-टेलेफुन्कन की तकनीकी सहायता से हुई है। इन्होंने कंपनी के साधारण शेयरों में भी ऋदितांस्तल ऋण में से भी कंपनी को काफी सहायता मिली है। यह कंपनी अपने उत्पादों अर्थात् स्विच गियरों, ट्रांसफार्मरों और बिजली की मोटरों का पश्चिमी जर्मनी सहित कई देशों को निर्यात कर रही है और भारी निर्यात आदेश पूरे किए जाने बाकी हैं। योजना के कार्यान्वित होने से बिजली उद्योग में उच्च दरीय पावर डयोड्स के उत्पादन की भारी कमी को पूरा करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही कंपनी के उत्पाद का उपभोग करने वाले विभिन्न उद्योग भी लाभान्वित होंगे।

औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाएं

वर्ष के दौरान जिस उच्च प्राथमिक राष्ट्रीय परियोजना को वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया गया वह उड़ीसा के पिछड़े हुए जिले कोरापुट में जैपोर के स्थान पर लगेगी। यह परियोजना अलमोनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (कंपनी पहले से ही वित्तपोषित) ने स्थापित की है। निगम ने इस कंपनी को 170 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया। कंपनी का प्रस्ताव प्रतिवर्ष 15,000 टन धातु उत्पादन करने के लिए एक नई संकलित अलमोनियम परियोजना लगाने का है, इसमें से 7,000 टन को अलमोनियम छड़ों में बदला जाएगा। कोरापुट में इस कारखाने के लगने से न केवल कम विकसित क्षेत्र के 2,400 लोगों को रोजगार मिलेगा, अपितु अवस्थापना सुविधाओं के विकास में भी सहायता मिलेगी। परियोजना के चालू हो जाने से कई सहायक उद्योगों के विकसित होने में मदद मिलेगी।

एक और अन्य उल्लेखनीय परियोजना लक्ष्मी आटो साइकलज लि० है, निगम ने इसके लिए 75 लाख रुपए का ऋण तथा 10 लाख रुपए के साधारण शेयरों में हामीदारी का अनुमोदन किया। परियोजना का लक्ष्य पिछड़े हुए जिले कोरापुट में 50,000 वार्षिक विस्थापित क्षमता से आटो साइकलों का निर्माण करना है। परियोजना का प्रवर्तन दो व्यावसायिक इंजीनियरों ने किया है, जो कारखाने की दैनिक कार्रवाई की देखभाल करेंगे। इस परियोजना की उल्लेखनीय बात यह है कि आटो साइकलों (मोपेड) के निर्माण के लिए किसी विदेशी जानकारी पर निर्भर नहीं रहेगी तथा उत्पाद का मूल्य इतना कम होगा कि जिससे निम्न मध्य वर्गीय लोग उसे खरीद सकेंगे। परियोजना का लक्ष्य कई सहायक उद्योग स्थापित करना भी है, जो आटो साइकलों के पुर्जों का निर्माण करेंगे। इस प्रकार योजना रोजगार प्रधान है।

वर्ष के दौरान राजस्थान के कम विकसित जिले भीलवाड़ा के सहकारी कताई उद्योग को निगम द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता भी उल्लेखनीय है। निगम ने राजस्थान कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० को 45.50 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया। इस सहकारिता का प्रवर्तन भीलवाड़ा तथा निकटवर्ती जिलों के कपास उत्पादकों ने किया है। परियोजना का अनुमान 12,960 पूरक तकुओं वाला मिल लगाने का है। इस सहकारी समिति का प्रवर्तन राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग तथा मार्ग दर्शन से हुआ है, ताकि उस क्षेत्र के उत्पादक अपनी उपज के लिए उपयुक्त प्रतिफल प्राप्त कर सकें तथा उन्हें कपास का उत्पादन तथा उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने का प्रोत्साहन मिल सके।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिक वित्तीय सहायता मंजूर करने के फलस्वरूप टैक्सटाइल कारपोरेशन आफ मराठवाड़ा लिमिटेड को 26.63 लाख रुपए का रुपया ऋण, 3.37 लाख रुपए के बराबर पश्चिमी जर्मनी मार्क उप-ऋण और 5 लाख रुपए के साधारण शेयरों में प्रत्यक्ष अभिदान का अनुमोदन किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने इस उद्यम का प्रवर्तन राज्य के कम विकसित खण्ड मराठवाड़ा के आर्थिक विकास के लिए किया है। मराठवाड़ा विकास निगम लि० ने विरंजक, रंगे और छपे हुए विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्र बनाने के लिए संयुक्त संयंत्र लगाया है। इसमें 2,304 शक्ति करघे, एक पूर्व-बुनाई इकाई तथा एक अभिसंस्कार इकाई होगी। इन इकाइयों की स्थापना अविकसित जिले नान्देद में की जाएगी। शक्ति करघों का संचालन पांच जिलों (औरंगाबाद, परभानी, नान्देद, भीड़ और उस्मानाबाद) की 24 सहकारी समितियों (प्रत्येक समिति के 96 शक्ति करघे) द्वारा किया जाएगा।

नए उद्यमकर्ताओं तथा व्यावसायिकों द्वारा स्थापित परियोजनाएं

वर्ष के दौरान सूती विशेषज्ञ व्यावसायिक द्वारा स्थापित परिमियर सिन्थेटिक प्रोसैसर्स लि० बंबई को मंजूर की गई वित्तीय सहायता का भी उल्लेख किया जा सकता है। परियोजना का अनुमान 8,200 मीटर दैनिक की दर से कृत्रिम बुने हुए वस्त्र उत्पादन के लिए बंबई के समीप अभिसंस्करण तथा रंगाई इकाई की स्थापना करने का है। बंबई जैसे वस्त्र केंद्र में इस प्रकार की इकाई की स्थापना एक उचित कदम है।

निगम ने एकसेल्सियर प्लांट्स कारपोरेशन लि० को 10 लाख रुपए का रुपया ऋण, 4.71 लाख रुपए की आस्थगित अदायगी गारंटी 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए क्रमशः साधारण और अधिमान शेयरों के लिए मंजूर किए। इस कंपनी का प्रवर्तन कुछ युवा तकनिकियों ने फरीदाबाद (हरियाणा) में 25 संयंत्र वार्षिक की क्षमता से यांत्रिक ईंटों, मृतिकाशिल्प तथा विशेष प्रकार की टाइलों को बनाने के लिए किया है। इन्डस्ट्रीयल एक्सपोर्ट, रूमानिया के तकनीकी सहयोग से इसकी स्थापना हुई है। इस कंपनी द्वारा बनाए गए संयंत्रों से भवन बनाने तथा अन्य औद्योगिक उपयोगों के लिए आधुनिक तरीकों से उत्तम कोटि की ईंटें तथा टाइलें बनाने में मदद मिलेगी। कंपनी इन संयंत्रों के लगाने का काम भी करेगी और कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षित तकनीकी अमले की सेवाएं भी प्रदान करेगी। इस प्रकार यह योजना रोजगार प्रधान भी है।

पहली जुलाई, 1948 से 30 जून, 1971 तक की अवधि में किए गए कुल कार्य

11 निगम द्वारा 1 जुलाई, 1948 से 30 जून, 1971 तक मंजूर और संवितरित वित्तीय सहायता का संक्षिप्त विवरण पृष्ठ 9 पर दिया गया है। 30 जून, 1971 तक 1160 आवेदन पत्रों पर 527 औद्योगिक परियोजनाओं को कुल 365.67 करोड़ रुपए की निवल वित्तीय सहायता मंजूर की गई। कुल 318.76 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई जिसमें कनद संवितरित राशि 267.78 करोड़ रुपए थी। वर्ष के अंत में 198.13 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

पिछले तेईस वर्षों में मंजूर किए गए आवेदन, निवल मंजूरियां तथा संवितरित राशि और 30 जून, 1971 की बकाया राशि का सार नीचे की सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 6

(रुपए, करोड़ों में)

	मंजूरियां (निवल)		संवितरित सहायता	बकाया सहायता
	संख्या	रकम	रकम	रकम
1. ऋण				
—रुपया	684	238.67	209.61	133.32
—विदेशी मुद्रा	157	43.58	35.47	26.09
जोड़	841	282.25	245.08	159.41
2. हामीदारियां				
—साधारण शेयर	130	11.22	7.79	6.64
—अधिमान शेयर	103	7.06	5.20	4.24
—डिबेंचर	21	10.73	7.58	4.73
जोड़	254(क)	29.01	20.57	15.61
3. प्रत्यक्ष अभिदान				
—साधारण शेयर	13	0.54	0.26	0.75 (ख)
—अधिमान शेयर	4	0.12	0.05	0.29 (ख)
—डिबेंचर	1	1.82	1.82	1.37
जोड़	18	2.48	2.13	2.41
1 से 3 तक का जोड़	1113	313.74	267.78	177.43
4. आस्थगित अदायगी गारन्टियां	42	28.46	27.65(ग)	7.05
5. विदेशी ऋण के लिए गारन्टियां	5	23.47	23.33(ग)	13.65
1 से 5 तक का जोड़	1160	365.67	318.76	198.13

(क) 75 मामले साधारण और अधिमान दोनों प्रकार के शेयरों से संबंधित हैं।

(ख) इसमें चार कंपनियों का 0.67 करोड़ रुपए के बकाया ऋण भी सम्मिलित हैं, जिन्हें शेयरों में बदल दिया गया और एक दूसरी कंपनी के 0.06 करोड़ रुपए के डिबेंचर भी सम्मिलित हैं, जिन्हें साधारण शेयरों में बदल दिया गया।

(ग) वास्तव में जारी की गई गारंटियां।

पहली जुलाई 1948 से 30 जून, 1971 तक की अवधि में प्रत्येक वर्ष मंजूर और संवितरित की गई निवल वित्तीय सहायता

12. पिछले तेईस वर्षों की अवधि में निगम ने प्रत्येक वर्ष जो कुल निवल वित्तीय सहायता मंजूर और संवितरित की है, उसका पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार किया गया वर्गीकरण निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 7

(रुपये, करोड़ों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के दौरान मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता				इस वर्ष के दौरान संवितरित रकम			
	ऋण	हामीदारियां	मशीनरी की आस्थगित अदायगियां/ गारंटियां	जोड़	ऋण	हामिदारियां	गारंटियां	जोड़
पहली पंचवर्षीय योजना से पहले की अवधि								
1949	3.25	–	–	3.25	1.33	–	–	1.33
1950	2.90	–	–	2.90	2.08	–	–	2.08
1951	1.98	–	–	1.98	2.38	–	–	2.38
जोड़	8.13	–	–	8.13	5.79	–	–	5.79
पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि								
1952	3.20	–	–	3.20	1.78	–	–	1.78
1953	0.53	–	–	0.53	2.50	–	–	2.50
1954	4.10	–	–	4.10	2.82	–	–	2.82
1955	5.13	–	–	5.13	1.64	–	–	1.64
1956	14.06	–	–	14.06	2.20	–	–	2.20
जोड़	27.02	–	–	27.02	10.94	–	–	10.94
दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि								
1957	9.15	–	–	9.15	9.78	–	–	9.78
1958	5.93	0.75	1.82	8.50	8.33	–	–	8.33
1959	2.77	0.87	0.27	3.91	7.48	0.66	–	8.14
1960	12.62	0.10	6.06	18.78	8.41	0.17	2.09	10.67
1961	18.58	1.84	8.29	28.71	6.62	0.48	13.02	20.12
जोड़	49.05	3.56	16.44	69.05	40.62	1.31	15.11	57.04
तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि								
1962	17.84	0.73	0.48	19.05	10.92	0.24	0.41	11.57
1963	19.82	4.63	10.62	35.07	15.05	3.99	3.18	22.22
1964	23.61	4.30	13.16	41.07	16.94	1.96	6.39	25.29
1965	19.61	3.55	3.92	27.08	19.79	3.36	14.65	37.80
1966	21.60	3.96	1.35	26.91	23.99	4.48	2.17	30.64
जोड़	102.48	17.17	29.53	149.18	86.69	14.03	26.80	127.52

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
वार्षिक योजना की अवधि								
1967	12.35	1.87	4.00	18.22	29.52	2.90	5.64	38.06
1968	15.86	1.48	0.85	18.19	23.35	1.06	2.61	27.02
1969	23.93	2.42	0.40	26.75	15.03	1.68	0.28	16.99
जोड़	52.14	5.77	5.25	63.16	67.90	5.64	8.53	82.07
चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि								
1970	12.46	1.19	0.29	13.94	16.86	0.85	0.34	18.05
1971	30.97	3.80	0.42	35.19	16.28	0.87	0.20	17.35
जोड़	43.43	4.99	0.71	49.13	33.14	1.72	0.54	35.40
कुल जोड़	282.25	31.49*	51.93	365.67	245.08	22.70	50.98	318.76

*इसमें 2.48 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष अभिदान भी शामिल है।

टिप्पणी : सारणी में दिए गए आंकड़े पिछले वर्षों की रिपोर्टों में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते क्योंकि इनमें से कुछ मंजूरियां बाद में या तो वापिस ले ली गईं या समंजित कर दी गईं।

30 जून, 1971 तक मंजूर की गई वित्तीय सहायता की सुविधावार समीक्षा

रुपया ऋण

13. 30 जून, 1971 तक रुपए की कुल प्रभावी मंजूरियां 238.67 करोड़ रुपए थीं जबकि संवितरित राशि 209.61 करोड़ रुपए थी जो कुल का 87.8 प्रतिशत है।

विदेशी मुद्रा ऋण

14. निगम ने 30 जून, 1971 तक 43.58 करोड़ रुपए की राशि के विदेशी मुद्रा ऋण मंजूर किए। निगम ने उक्त तारीख तक विदेशी मशीनरी पूर्तिकर्ताओं के हक में जो साख पत्र खोले उनकी कुल रकम 767.7 लाख जर्मन मार्क और 268.6 लाख अमरीकी डालर (कुल 35.32 करोड़ रुपए) थी। इसके अतिरिक्त बी० एफ० सी० ई० पैरिस को कुल 1.9 लाख फ्रांसीसी फ्रांक (2.76 लाख रुपए) की नकद अदायगी की गई और 121.1 लाख फ्रांसीसी फ्रांक (1.66 करोड़ रुपए) के 13 बचंत पत्र उनके नाम जारी किए गए। 30 जून, 1971 तक संवितरणों की कुल रकम 702.7 लाख जर्मन मार्क, 267.6 लाख अमरीकी डालर और 113.3 लाख फ्रांसीसी फ्रांक (कुल 35.47 करोड़ रुपए) थी।

30 जून, 1971 तक विदेशी ऋण से संबंधित स्थिति संक्षेप में नीचे की सारणी में बताई गई है :

सारणी 8

मुद्रा	निवल मंजूरियां			जारी किए गए साख वचन-पत्र		संवितरित रकम	
	ऋणों की संख्या	विदेशी मुद्रा (दस लाख में)	रुपए (लाखों में)	विदेशी मुद्रा (दस लाख में)	रुपए (लाखों में)	विदेशी मुद्रा (दस लाख में)	रुपए (लाखों में)
पश्चिमी जर्मन मार्क	103	105.04	2139.48	76.77	1560.15	70.27	1426.97
अमरीकी डालर	57	26.92	1976.52	26.86	1971.55	26.76	1964.72
फ्रांसीसी फ्रांक	11	12.97	177.48	12.11	165.60	11.33	155.18
पौंड स्टर्लिंग	3	0.12	21.50	—	—	—	
जोड़	174*		4314.98**		3697.30		3546.87

टिप्पणियां :

*157 आवेदन-पत्रों के संबंध में उप-ऋण मंजूर किए गए।

**इसमें वो इकाइयों से संबंधित 43.05 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है जिसका उपयोग नहीं किया जाना है अथवा अन्य सुविधा में संपरिवर्तित कर दिया जाएगा।

हामीदारी के कार्य और पूंजी के लिए प्रत्यक्ष अभिदान

15. निगम ने 30 जून, 1971 तक साधारण और अधिमान शेयरों तथा डिबेंचरों के लिए हामीदारी के 179 आवेदन-पत्र मंजूर किए जिनकी कुल निवल रकम 29.01 करोड़ रुपए थी। इसमें साधारण शेयरों की रकम 11.22 करोड़ रुपए, अधिमान शेयरों की रकम 7.06 करोड़ रुपए तथा डिबेंचरों की रकम 10.73 करोड़ रुपए थी। इसके अतिरिक्त 14 आवेदन पत्रों में 66.09 लाख रुपए (53.60 लाख रुपए के साधारण शेयर तथा 12.49 लाख रुपए के अधिमान शेयर) के लिए निगम ने जो हामीदारी ली थी उसके शेयर निगम को लेने पड़े और 30 जून, 1971 तक उसकी मंजूरी दे दी गई।

निगम ने 174 मामलों में कुल 26.67 करोड़ रुपए के हामीदारी करारों पर हस्ताक्षर किए 30 जून, 1971 तक 173 मामले संपन्न हो गए जिनकी कुल रकम 26.44 करोड़ रुपए थी। जिन 12 निर्गमों के लिए निगम ने 2.36 करोड़ रुपए की हामीदारी ली थी, जनता ने उनमें पूरा-पूरा अभिदान कर दिया। शेष 161 निर्गमों के लिए जिनकी कुल बचनबद्धता 24.08 करोड़ रुपए थी, निगम ने 20.65 करोड़ रुपए के शेयर और डिबेंचर लिए जो कुल का 78 प्रतिशत थे।

30 जून, 1971 तक पूरे किए निर्गमों से संबंधित स्थिति सारणी 9 में दिखाई गई है।

30 जून, 1971 तक निगम ने एक डिबेंचर निर्गम के लिए प्रत्यक्ष अभिदान भी मंजर किया जिसकी कुल रकम 1.82 करोड़ रुपए थी।

सारणी 9

(रुपए, लाखों में)

	हामीदारी की रकम	रकम जो निगम को देनी पड़ी	(3) का (2) से प्रतिशत
1	2	3	4
साधारण शेयर	1089.05	776.22	71.3
अधिमान शेयर	682.29	531.03	77.8
डिबेंचर	873.00	758.20	86.8
	2644.34	2065.45	78.1

आस्थगित अदायगी के लिए गारंटियां

16. 30 जून, 1971 तक मंजूर की गई आस्थगित अदायगियों की गारंटियों की निवल रकम 28.46 करोड़ रुपए थी, जो 42 आवेदन-पत्रों के लिए दी गई थी। 30 जून, 1971 तक वास्तव में जारी की गई गारंटियों की कुल रकम 27·65 करोड़ रुपये थी।

विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए गारंटियां

17. रद्द किए गए और वापिस लिए गए आवेदन पत्रों को निकाल देने के बाद, 5 आवेदन-पत्रों पर कुल 23.47 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 30 जून 1971 तक वास्तव में दी गई गारंटियों की कुल रकम 23.33 करोड़ रुपए थी।

30 जून, 1971 तक मंजूर की गई वित्तीय सहायता का प्रयोजनवार वितरण

18. 30 जून, 1971 तक मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का प्रयोजनवार वर्गीकरण तथा निगम द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की कुल लागत का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है।

सारणी 10

(रुपये, करोड़ों में)

उपक्रम का स्वरूप	परियोजनाओं की कुल लागत	मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता				प्रतिशत (2) से (6) का
		ऋण	हामीदारियां और प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटियां	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
नये उपक्रम	1003.43	169.88	21.14	42.26	233.28	23.3
वर्तमान उपक्रम						
(1) उत्पादन की वर्तमान दिशाओं में विस्तार के लिए	474.65	87.25	7.17	7.07	101.49	21.4
(2) आधुनिकीकरण और पुनःस्थापन के लिए	103.59	11.55	2·76	0.53	14.84	14.3
(3) उत्पादन की नई दिशाओं में विशाखन के लिए	30.82	11.34	0.42	2.07	13.83	44.9
जोड़	1612.49	280.02	31.49	51.93	363.44	22.5
कार्यकारी पूंजी आदि जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए मंजूर किए गए ऋण	—	2.23	—	—	2.23	—
कुल जोड़	1612.49	282.25	31.49	51.93	365.67	—

30 जून, 1971 तक मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का उद्योगवार और राज्यवार वितरण इस रिपोर्ट के क्रमश: 'ग' (i) और 'ग' (ii) परिशिष्टों में दिया गया है। निवल वित्तीय सहायता और प्रत्येक औद्योगिक संस्था को मंजूर की गई राशि के अनुसार उनकी सहायता का वर्गीकरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है। प्रत्येक राज्य में मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का उद्योगवार वितरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ङ' में दिया गया है।

निगम ने 30 जून, 1971 तक जो कुल 365·67 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की थी उसमें से 233.28 करोड़ रुपये नये उपक्रमों के लिए और शेष 132.39 करोड़ रुपये की रकम वर्तमान इकाइयों के विस्तार, आधुनिकीकरण अथवा उत्पादन की नई दिशाओं में विशाखन के लिए थे। जिन 527 परियोजनाओं में निगम ने रुपया लगया है उनकी कुल लागत 1612 करोड़ रुपये है, समग्र साधनों का सूचक है जो परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जुटाया गया है।

सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता

19. पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों तथा केन्द्रीय सरकार की नीतियों के अनुरूप निगम सहकारी क्षेत्र की परियोजनाओं विशेषकर चीनी तथा वस्त्र उद्योग को काफी सहायता देता रहा है।

30 जून, 1971 तक 77.31 करोड़ रुपये की सहायता 98 औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को मंजूर की, जिनमें 74 चीनी मिलें (65.87 करोड़ रुपये), 22 सूती कताई कारखाने (10.43 करोड़ रुपये), एक पटसन मिल (78.50 लाख रूपये) और एक तेल निकालने वाली मिल (22.50 लाख रुपये) थी। कुल संवितरण 65.59 करोड़ रुपये था।

निगम द्वारा वित्त पोषित सहकारी इकाइयों का राज्यवार और उद्योगवार वितरण नीचे सारणी में दिखाया गया है। जहां तक औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र का स्थान सर्वोपरि रहा है। इसके पश्चात् मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश हैं।

यह बात उल्लेखनीय कि निगम द्वारा औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर किये गये ऋण कुल रुपया ऋणों का 32 प्रतिशत है।

सारणी 11

(रुपये लाखों में)

राज्य	चीनी		सूत-कताई		अन्य		कुल मंजूरियां		कुल संवितरण	बकाया ऋण
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	राशि	राशि
आंध्र प्रदेश	6	635.00	3	110.00	–	–	9	745.00	557.00	362.07
असम	1	60.00	–	–	*	78.50	2	138.50	138.50	85.00
बिहार	1	115.00	1	24.70	–	–	2	139.70	114.70	131.55
गुजरात	6	405.50	2	170.00	–	–	8	575.50	425.50	324.08
हरियाणा	2	106.00	–	–	–	–	2	106.00	106.00	–
केरल	2	180.00	–	–	–	–	2	180.00	180.00	232.69
मध्य प्रदेश	1	80.00	1	40.00	–	–	2	120.00	60.00	60.00
महाराष्ट्र	28	2794.70	8	382.50	–	–	36	3177.20	2806.70	1604.20
मैसूर	8	677.75	2	79.00	1**	22.50	11	779.25	608.75	442.38
उड़ीसा	2	175.00	1	31.00	–	–	3	206.00	181.00	149.57
पंजाब	4	315.00	–	–	–	–	4	315.00	315.00	217.03
राजस्थान	1	80.00	1	45.50	–	–	2	125.50	79.00	82.25
तमिलनाडु	7	583.00	1	35.00	–	–	8	618.00	576.00	364.26
उत्तर प्रदेश	5	380.00	2	125.00	–	–	7	505.00	411.00	191.84
जोड़	74	6586.95	22	1042.70	2	101.00	98	7730.65	6559.15	4226.92

* पटसन का सहकारी कारखाना

** वनस्पति तेल निकालने वाली मिल

सहकारी क्षेत्र को दी गई गई वित्तीय सहायता का अवलोकन औद्योगिक सहायता को प्रोत्साहन देने की स्वीकृति राष्ट्रीय नीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में करना होगा। औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को निगम की वित्तीय सहायता का समग्र समय रूप से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव इस तथ्य से जांचा जा सकता है कि निगम ने 98 सहकारी इकाइयों के लिए कुल 160.74 करोड़ रुपया जुटाया है, विभिन्न स्त्रोतों से इकट्ठा करने में सहायता दी है। कृषि क्षेत्र की बचत को उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने का प्रमाण यह है कि 74 सहकारी चीनी कारखानों के लिए उत्पादक सदस्यों ने शेयर पूंजी के रूप में 34.51 करोड़ रुपये दिये, जबकि अन्यों का योगदान (अर्थात् सहकारी संस्थाओं के अनुत्पादक और अन्य) 3.52 करोड़ रुपये रहा। राज्य सरकारों का शेयर पूंजी में योगदान 17.09 करोड़ रुपये के बराबर रहा। इसके अतिरिक्त चीनी के सहकारी कारखानों ने 19.78 करोड़ रुपये एकत्र किये जो अप्रतिदेय जमा तथा उत्पादकों को गन्ने के मूल्य के रुप में देय है। औद्योगिक सहकारी क्षेत्र में तीव्र विकास की संभावनाओं को देखते हुए, निगम अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र के विकास में अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करके महत्वपूर्ण योगदान देने की आशा करता है।

औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों/क्षेत्रों को सहायता

20. कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था से प्रादेशिक असन्तुलन समाप्त करने और कम विकसित राज्यों/क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को तीव्र करने की जरूरत पर बल दिया गया है। निगम के इस अभाव को हमेशा जाना है और कम विकसित राज्यों को काफी मात्रा में वित्तीय सहायता दी है। वर्ष के अन्त तक 527 परियोजनाओं को मंजूर की गई 365.67 करोड़ रुपये की सहायता में से लगभग 33.3 प्रतिशत अर्थात् 121.80 करोड़ रुपये की सहायता कम विकसित प्रदेशों/क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा गोआ की 149 औद्योगिक इकाइयों को मंजूर की है।

यह स्वीकार कर लिया गया है कि सन्तुलित प्रादेशिक विकास करने के लिए पूर्ण राज्य के स्थान पर कुछ चुने हुए जिलों/क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक है। तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा योजना आयोग से परामर्श करने के बाद कुछ राज्य/क्षेत्र अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से रियायती दरों पर सहायता प्राप्त करने के लिए घोषित किए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा 30 जून, 1971 तक घोषित जिले/क्षेत्र परिशिष्ट 'ज' में दिखाये गए हैं। निगम ने केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित जिलों/क्षेत्रों में लगी हुई अथवा लगने वाली 57 जिलों तथा 3 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की 103 औद्योगिक परियोजनाओं को 74.33 करोड़ रुपये मंजूर किए यह भी स्पष्ट किया जाता हैकि निगम द्वारा दी गई रियायतें घोषित जिलों/क्षेत्रों में लगने वाली नई परियोजनाओं पर ही लागू होंगी। 23 जुलाई, 1970 को घोषित रियायतें परिशिष्ट 'झ' में दर्शाई गई हैं।

नये उद्यमकर्ताओं और व्यावसायिकों को वित्तीय सहायता

21. निगम नये व्यावसायिकों तथा पेशेवर योग्य व्यक्तियों स्थापित परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन दे रहा है। निगम ने नये उद्यमकर्ताओं तथा व्यावसायिकों द्वारा स्थापित इंजीनियरिंग, वस्त्र, रसायन, चीनी, सीमेंट, कागज और कागज बोर्ड, रबर उत्पादन, कांच, होटल आदि औद्योगिक परियोजनाओं को काफी मात्रा में सहायता दी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता

22. जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि केन्द्रीय सरकार ने निगम को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया था। निगम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (चाहे उनमें सरकारी शेयरों की संख्या कुछ भी हो) से निजी क्षेत्र की संस्थाओं के समान ही वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां हैं, अपने विस्तार, आधुनिकीकरण अथवा विशाखन व अन्य नई परियोजनाओं के लिए निगम को निवेदन करने के पात्र हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 1.80 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की। सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को पिछले वर्ष दी गई सहायता को ध्यान में रखते हुए (प्रत्येक मामले में सरकार की स्वीकृति सहित) 5 संस्थाओं को जिनमें केन्द्र/राज्य सरकारों का साधारण शेयरों में 51 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, 30 जून, 1971 तक 6.42 करोड़ रुपये मंजूर किए गये।

वित्तीय सहायता देने के लिए अपनाई गई कसौटी तथा कार्य प्रणाली

23. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अनुसार निगम के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना काम करते हुए व्यावसायिक सिद्धान्तों पर अमल करे और उद्योग, वाणिज्य तथा सामान्य जनता के हितों का विशेष ध्यान रखे।

क्योंकि वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं की परियोजनाओं में कारोबारी जोखिम होती है, अतः निगम इन परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं की जांच करता है, ये पहलु हैं, देश की अर्थव्यवस्था में परियोजना की अपेक्षाकृत औद्योगिक राष्ट्रीय दृष्टि से प्राथमिकता, उसकी तकनीकी, वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता, प्रवर्तकों का अनुभव और ईमानदारी तथा परियोजनाओं की लागत में उनका वित्तीय अंशदान, प्रबन्ध का स्तर और परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान सक्षम तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना।

निगम परियोजना के गुणावगुणों पर ही विशेष ध्यान रखती है, अतः परियोजना के तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक पहलुओं का विस्तृत मूल्यांकन करना जरूरी होता है।

उदाहरण के तौर पर तकनीकी पहलुओं की जांच करते समय प्रयोग में लाई गई तकनीकी प्रक्रिया की व्यवहार्यता, परियोजना की स्थिति, सयन्त्र और उपस्कर का आकार, तथा मशीनी पूर्तिकारों की ख्याति और अनुभव, तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करने का प्रबन्ध तथा कार्मिक और श्रमिकों का प्रशिक्षण, संयन्त्र की रूपरेखा, आवश्यक उपयोगिताओं के लिए व्यवस्था, परियोजना के निर्माण की अवधि पर विशेष ध्यान रखा जाता है। परियोजना के वित्तीय पहलुओं की जांच में उसकी लागत का अनुमान, आवश्यक कार्यकारी पूंजी का मूल्यांकन, वित्तीय साधनों जैसे शेयर पूंजी, दीर्घकालीन ऋण, विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने के लिए व्यवस्था, वर्तमान संस्थाओं के लिए संयन्त्र और मशीनरी के लिए आस्थगित अदायगियों तथा आन्तरिक साधन आदि। यह भी आश्वस्त करना जरूरी है कि परियोजना की इक्विटी और ऋण का अनुपात संतोषजनक है, परियोजना लागत में प्रवर्तकों का योगदान उपयुक्त है तथा लाभ का अनुमान व्यावहारिक है ताकि दीर्घकालीन ऋण उचित प्रकार से लौटाया जा सके और शेयरधारियों को भी उचित मात्रा में लाभ मिलता रहे।

प्रबंधकीय पहलू के अध्ययन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि संस्था का प्रबंधकीय ढांचा उपयुक्त है तथा संस्था का संचालक-मंडल समर्थ है और तकनीकी तथा प्रशासनिक कार्मिक योग्य एवं अनुभवी हैं। परियोजना के आर्थिक तथा सामाजिकक पहलुओं जैसे बाजार दृष्टिकोण, रोजगार क्षमता तथा अविकसित अथवा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक वातावरण स्थापित रकने की क्षमता पर भी ध्यान दिया जाता है।

24. निगम के वित्तीय और तकनीकी कर्मचारियों द्वारा परियोजना का वित्तीय और तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन कर लिए जाने के बाद सलाहकार समिति से सलाह ली जाती है। इस समिति में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उन विशेषज्ञों को बुलाया जाता है जिनको उस विशिष्ट उद्योग की विशेष जानकारी होती है। इसके बाद निगम का बोर्ड सलाहकार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मामले पर निर्णय करता है। किन्तु सलाहकार समिति की सलाह नहीं ली जाती, यदि परियोजना नई न हो अथवा सहायता की विदेशी मुद्रा उप-ऋण के रूप में संतुलनकारी उपस्कर का आयात करने, आधुनिकीकरण के लिए संयन्त्र और मशीनरी प्राप्त करने अथवा सीमान्तिक विस्तार करने के लिए जरूरी हों। जिन बड़ी परियोजनाओं को अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं साख निगम, जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता दी जाती है, उनके मामलों में समय-समय पर इन संस्थाओं की सम्मिलित बैठकें या विशेष सम्मेलन बुलाए जाते हैं। उपयुक्त मामलों में फैक्टरी स्थल पर जाकर और आवेदकों से विचार-विमर्श करके एक संयुक्त तकनीकी तथा वित्तीय दल द्वारा जांच की जाती है। इस दल में वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं।

25. यह ज्ञात होगा कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्रीय सरकार ने फरवरी, 1970 में लोक वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ परिवर्तन करने का निर्णय किया। संयुक्त क्षेत्र विकल्प के सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लेने से यह निर्णय किया गया है कि बड़ी परियोजनाएं जो लोक वित्तीय संस्थाओं से काफी वित्तीय सहयता प्राप्त करती हैं, विशेषकर नीति स्तर पर उनके प्रबंध में सहयोग की मात्रा अधिक होनी चाहिए।

सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि वित्तीय संस्थाओं को अपने ऋणों तथा भविष्य में निर्गमित डिबेंचरों के पूरे अथवा कुछ भाग को निश्चित अवधि के भीतर संपरिवर्तन करने के अधिकार का वित्तीय सहायता की एक व्यवस्था के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। पिछले ऋणों तथा डिबेंचरों के लिए वित्तीय संस्थाएं अपनी स्वेच्छा से चूकों के मामले में बातचीत कर सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच कमेटी की सिफारिशों पर सरकारी निर्णय के विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों के साधारण शेयरों में बदलने तथा वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में संचालक नामित करने की नीतियों से सम्बंधित है। ये निर्देश अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं साख निगम जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को जारी किए गए हैं।

इन निर्देशों की शर्तों के अनुसार सभी मामलों में जहां पर कुल वित्तीय सहायता 50 लाख रुपये से बढ़ जाती है, ऋण के एक भाग को साधारण शेयरों में बदलना जरूरी हो गया है। उन सभी मामलों में जब एक औद्योगिक इकाई को कुल वित्तीय सहायता 25 लाख रुपये से बढ़ जाती है परन्तु 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ती, तो वित्तीय संस्थाओं की स्वेच्छा से संपरिवर्तन धारा अनुबंधित की जा सकती है। स्वेच्छा का प्रयोग करते हुए सभी भौतिक तथा वाणिज्यिक तथ्यों जैसे उद्योग केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्गीकृत 'कोर सैक्टर' का हिस्सा है अथवा सुरक्षा प्रधान है अथवा उद्योग सामान्य उपभोग की आवश्यक वस्तु के उत्पादन में लगा है, को ध्यान में रखना चाहिए। जिन मामलों में एक औद्योगिक इकाई को वित्तीय सहायता 25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ती तो ऋणों के एक भाग को साधारण शेयरों में बदलने से सम्बंधित धारा को अनुबन्धित करना जरूरी नहीं है जब तक कि वित्तीय संस्थाएं वाणिज्यिक आधार पर ऐसा फैसला न कर लें।

ऋणों के साधारण शेयरों में बदलने से सम्बन्धित शर्तें उन विदेशी मुद्रा उप-ऋणों पर लागू नहीं होंगी जो ऋण भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋणों में से मंजूर किए हैं। फिर भी यह संपरिवर्तन धारा उन सभी रुपया ऋण संविदाओं/डिबेंचर निर्गमों पर लागू होगी जो वित्तीय संस्थाओं ने औद्योगिक इकाइयों को सरकार के पास तथा किसी अन्य स्रोत से उपलब्ध ऋण में उन इकाइयों को विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए मंजूर किए हैं।

ऋणों/डिबेंचरों का साधारण पूंजी में संपरिवर्तन की शर्तें, ऋण की संपरिवर्तित राशि, शेयर का इजरा मूल्य, संपरिवर्तन के विकल्प अधिकार का प्रयोग करने की अवस्था अथवा अवस्थाएं, विकल्प प्रयोग किए जाने की अवधि, यदि सूचना दी जाती है तो उसकी अवधि, आदि प्रत्येक मामले में तय करके ऋण करार में अनुबंधित कर दिए जाएंगे।

शर्तों को तय करते समय, उद्योग की प्रकृति तथा महत्व, परियोजना के चालू होने की संभव अवधि, ऋण-इक्विटी अनुपात, परियोजना की लाभ क्षमता, विस्तार की संभावनाएं, आदि को भी आवश्यक महत्व दिया जाएगा। ऐसी वर्तमान कम्पनियों के मामले में जिन्हें-पिछले लाभों में से आरक्षित निधियां कायम की है, इनके शेयर की इजरा कीमत तय करते समय, शेयर का बाजार मूल्य, विसर्जन मूल्य, अधिलाभांश रिकार्ड, वर्तमान तथा भावी लाभ, आदि बातों पर भी ध्यान रखा जायेगा।

संपरिवर्तन धारा को बंधित करते समय संबंधित कम्पनी को संपरिवर्तन की शर्तों के अनुसार कम्पनी अधिनियम के खण्ड 81 (3) के अधीन अपने शेयर धारियों तथा, केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति ले लेनी चाहिये।

निगम ने 30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान स्वेच्छा से 21 कम्पनियों के सम्बन्ध में संपरिवर्तन की शर्तों को अनुबंधित किया है, इन संस्थाओं को वर्ष के दौरान रुपया ऋण मंजूर किए गए थे। जिन 21 कम्पनियों का ऊपर उल्लेख किया गया है, इनमें से 16 के संपरिवर्तन मामलों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार निगम सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए सभी भारी मात्रा में सहायता प्राप्त करने वाली कम्पनियों के बोर्डों में अपने सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिनिधियों को नामित करना आवश्यक है, जिन मामलों में वित्तीय सहायता के लिए समझौता करारों में संपरिवर्तन धारा का निर्गमन किया गया है।

26. जब निगम का संचालक बोर्ड वित्तीय सहायता मंजूर कर देता है तो आवेदक को सिद्धांत रूप में मंजूरी की सूचना भेज दी जाती है, साथ ही मंजूरी की मुख्य शर्तें भी स्पष्ट कर दी जाती हैं। इसके पश्चात् उधार लेने वाले को मानकीकृत तथा मुद्रित ऋण करार तथा प्रतिभूति के अन्य दस्तावेज निष्पादित करने होते हैं।

विधिक औपचारिकताओं तथा ऋण करार में उल्लिखित शर्तों के पूरा हो जाने के पश्चात् संवितरण शुरू हो जाते हैं। संवितरण में देरी को कम से कम करने के लिए विधिक औपचारिकताओं को बेहद सरल कर दिया गया है। परियोजना की प्रगति तथा पहले दिये गए ऋणों के उपयोग आदि को देखते हुए आगे संवितरण किए जाते हैं।

परियोजना की निर्माण अवधि में तथा उसके बाद भी निगम अनुवर्ती कार्रवाई करता है। सहायता-प्राप्त संस्था को नियमित रूप से निर्धारित प्रपत्रों में अपनी प्रगति रिपोर्ट तथा लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र निगम को भेजने पड़ते हैं। जब कारखाना उत्पादन शुरू कर देता है तो निगम के तकनीकी तथा वित्तीय अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते रहते हैं। जरूरत पड़ने पर निगम सहायता-प्राप्त संस्थाओं के बोर्डों में अपने द्वारा नामित व्यक्तियों की नियुक्ति करके सहायता-प्राप्त संस्थाओं को गतिविधियों से निकट संपर्क बनाए रखता है।

निधि स्रोत

बांड

27. नवम्बर, 1970 में निगम ने अपने निधि स्रोतों को बढ़ाने के लिए 4.50 करोड़ रुपये के बांड जारी किए जिनकी परिपक्वता अवधि 12 वर्ष है। बांड सम-मूल्य पर जारी किए गए और ब्याज की दर 5¾ प्रतिशत वार्षिक तय की गई। जारी की गई राशि में अनुज्ञेय 10 प्रतिशत रकम को मिलाकर 4.95 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया। वर्ष के अन्त में बकाया बांडों की कुल राशि 57.69 करोड़ रुपये थी।

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण

28. 30 जून, 1970 को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों की बकाया राशि 79.61 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन वर्ष में कोई राशि नहीं ली गई अपितु 2.29 करोड़ रुपये के ऋण की राशि चुकाई गई। इस वर्ष के अन्त में ऋणों की बकाया राशि 77.32 करोड़ रुपये थी। यह राशि केन्द्रीय सरकार से वर्ष 1959-60 और 1968-69 के मध्य में लिए गए ऋणों का सूचक है। पिछले वर्ष की भांति, 1970-71 में भी निगम के लिए केन्द्रीयय बजट में कोई व्यवस्था की गई।

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त ऋण

29. समीक्षाधीन वर्ष में भी पिछले वर्षों की भांति रिज़र्व बैंक से ऋण उसी अवस्था में लिए गए जबकि ऋण लेना अनिवार्य हो गया था। 30 जून, 1971 को इस शीर्षक के अन्तर्गत 1.24 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी, जो अदा कर दी गई। 8 जनवरी, 1971 से ब्याज दर 5 से 6 प्रतिशत हो जाने से इन ऋणों पर ब्याज की दर 6 प्रतिशत वार्षिक हो गई है।

विदेशी मुद्रा ऋण

30. अक्तूबर, 1970 में भारत सरकार तथा जर्मन संघीय गणराज्य सरकार के बीच 19 नवम्बर, 1970 को हुए एक अन्तर-सरकारी करार के अनुसार निगम को और 100 लाख मार्क का ऋण दिया। तदनुसार निगम और क्रेदितांस्तल के बीच भी 22 जून, 1971 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। करार के सम्पन्न हो जाने से वर्ष के अन्त में निगम के पास क्रेदितांस्तल का कुल ऋण

1125 लाख मार्क हो गया। निगम ने इसमें से 1050.4 लाख मार्क के उप-ऋण मंजूर किए। अब यह ऋण पूर्ण संपरिवर्तनीय है, अर्थात् यह कुछ विशेष देशों को छोड़ कर पश्चिमी जर्मनी के अतिरिक्त अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क जापान आदि देशों से पूंजीगत माल, इंजीनियरिंग जानकारी और सेवाओं आदि के आयात के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

संयुक्त राज्य/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1969 के अन्तर्गत भारत सरकार ने निगम को सितम्बर, 1970 में पात्र संस्थाओं द्वारा संयुक्त राज्य से पूंजीगत माल का आयात करने के लिए 10 लाख पौंड का ऋण उपलब्ध किया। इस ऋण में से 1.2 लाख पौंड (21.50 लाख रुपये) के उप-ऋण मंजूर किए गए। संयुक्त राज्य/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1971 के अन्तर्गत 10 लाख पौंड का ऋण सम्बन्धि दस्तावेज के शीघ्र ही पूरा होने की आशा है।

बैंक फ्रांसिस डु कामर्स एकसटिरिए, द्वारा निगम को दिये गये फ्रांसिसी ऋण का कुल मूल्य 150.0 लाख फ्रांसिसी फ्रांक था, जिसमें से 129.7 लाख फ्रांसिसी फ्रांक के उप-ऋण मंजूर किए गए। अन्तराष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा दिये गये 268.8 लाख अमरीकी डालर के दोनों ऋण पूरे होने से एजेन्सी पूर्णत: दायित्वमुक्त हो गई।

30 जून, 1971 तक निगम अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से प्राप्त दो ऋणों में से 143.5 लाख अमरीकी डालर क्रेदितांस्तल से प्राप्त 150.0 लाख और 250.0 लाख मार्क के दो ऋणों में से 105.8 लाख मार्क और बी०एफ०सी०ई० से प्राप्त ऋण की राशि में से 33.2 लाख फ्रांक अदा कर चुका है।

उद्योगों को दी जाने वाली सहायता के स्रोत

31. जैसा कि पैरा 11 में उल्लेख किया जा चुका है, 30 जून, 1971 तक निगम ने जो रकमें संवितरित की हैं और हामीदारी लेने के कारण उसे जो शेयर और डिबेंचर लेने पड़े हैं उनकी कुल राशि 267.78 करोड़ रुपये है। ये निम्नलिखित स्रोतों से पूरे किये गये हैं :

	(रुपये, करोड़ों में)
प्रदत्त पूंजी	8.35
आरक्षित निधियां	14.24
बांड जारी करके बाजार से प्राप्त ऋण	57.69
केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण	77.32
रिजर्व बैंक से लिया गया ऋण	1.24
विदेशी ऋण	35.47
रुपया ऋणों की वापसी और निवेशों की बिक्री	73.47
जोड़ :	267.78

पिछले तीन वर्षों में निधियों के स्रोत तथा उपयोग

32. 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के वर्षों में निधियों के स्रोत तथा उपयोग नीचे की सारणी में दिखायें गयें हैं :

(रुपये, करोड़ों में)

	1968-69	1969-70	1970-71
क—निधियों का स्रोत			
1—प्रारम्भ में नकदी और बैंक शेष	2.67	8.42	6.89
2—वर्ष का सकल लाभ	3.92	4.33	4.47
3—केन्द्रीय सरकार से उधार	10.00	—	—
4—रिजर्व बैंक आफ इंडिया से निवल उधार	—	—	1.24
5—बांड जारी करके बाजार से उधार	8.33	5.50	4.95
6—विदेशी संस्थाओं से उधार	1.41	1.69	3.10
7—निवेशों की बिक्री	0.73	0.10	0.16
8—सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों की बिक्री	—	1.30	2.01
9—डिबेंचरों और अधिमान शेयरों का विमोचन	0.50	0.01	0.70
10—उधार लेने वालों द्वारा ऋणों की वापसी			
(क) रुपया ऋण	7.55	10.34	9.48
(ख) विदेशी मुद्रा ऋण	1.25	1.97	2.46
11—हामीदारी दायित्वों के रूप में वसूली	0.03	0.04	—
जोड़	**36.39**	**33.70**	**35.46**

	1968-69	1969-70	1970-71
ख—निधियों का उपयोग			
1—सहायता संवितरणों के रूप में			
(क) ऋण—			
(i) रुपया ऋण	12.91	15.01	13.16
(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	1.41	1.69	3.10
(ख) हामीदारी दायित्वों के रूप में औद्योगिक इकाइयों के शेयर/डिबेंचरों में अभिदान	1.62	0.82	0.73
(ग) प्रत्यक्ष अभिदान	0.05	0.03	0.14
(घ) निगम द्वारा दी गई हामीदारियां	0.76	0.16	0.02
	16.75	17.71	17.15
2—सरकार से प्राप्त ऋणों की अदायगी	0.86	1.77	2.29
3—विदेशी संस्थाओं से प्राप्त ऋणों की अदायगी	2.15	2.09	2.26
4—बांडों का विमोचन	4.38	—	—
5—कर के लिये व्यवस्था	2.22	2.37	2.37
6—अधिलाभांश	0.21*	2.25	0.42
7—सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	0.80	2.51	—
8—अन्य	0.60	0.11	1.79
9—अन्य में नकदी और बैंक शेष	8.42	6.89	9.18
जोड़	36.39	33.70	35.46

टिप्पणी* यह राशि वह नकद अदायगी की रकम है जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32क के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अन्तरित की गई थी, इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को देय अधिलाभांश शामिल नहीं है।

जैसा कि पीछे दी गई सारिणी से स्पष्ट है, 1970-71 में वित्तीय सहायता का संवितरण 17.15 करोड़ रुपये था जो पिछले वर्ष 17.71 करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष 19.38 करोड़ रुपये की कम मंजूरियों के बावजूद भी संवितरण पिछले वर्ष के स्तर पर कायम रखे गये। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 2.37 करोड़ रुपये की कर व्यवस्था की गई। निगम नें इस वर्ष भी अपने वित्तीय कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई ऋण नहीं लिया, अपितु बांड जारी करके बाजार से 4.95 करोड़ रुपये का ऋण लिया।

ऋणों की वापसी अदायगी की प्रगति

33. सारणी 12 और 13 में वे रकमें दिखाई गई हैं जो पिछले पांच वर्ष के अन्त में ब्याज और मूलधन की अदायगी के रूप में लेनी थी और जो रकमें वसूल हुई थीं। इसमें प्रत्येक वर्ष में बाकीदारी की रकमों का ब्यौरा दिया गया है। 30 जून, 1971 को 159.41 करोड़ रुपये के कुल बकाया ऋणों में ब्याज की 550.75 लाख रुपये की बाकीदारी तथा मूलधन 498.03 लाख रुपये की बाकीदारी थी जो कुल बकाया ऋणों का क्रमशः 3.45 प्रतिशत तथा 3.13 प्रतिशत है।

सारणी 12

ब्याज

(रुपये, लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया ऋण*	वर्ष के प्रारम्भ में ब्याज की देय रकम	वर्ष के दौरान ब्याज की देय रकम	खाना 3 और 4 का जोड़	वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त रकम	वर्ष के दौरान ब्याज की अदायगी में चूक होने से बकाया रकम**
1	2	3	4	5	6	7
1967	9960.69	61.42	801.69	863.11	721.98	116.82
1968	12120.37	116.82	940.19	1057.01	830.57	202.81
1969	13553.04	202.81	1026.64	1229.45	917.78	311.67
1970	14207.50	311.67	1084.89	1396.56	1023.84	372.72
1971	14998.54	372.72	1161.08	1533.80	983.05	550.75

*इसमें वह रकम शामिल नहीं है जिनकी किस्तें, अदायगी में चूक होने के कारण अस्थगित कर दी गई हैं और जिनकी गारंटी निगम ने दी थी और निगम को उन्हें अदा करना पड़ा। इसमें उन ऋणों पर लगने वाला ब्याज शामिल नहीं है। ये ऋण और उनके ब्याज का ब्यौरा सारणी 15 में दिखाया गया है।

**इसमें वे राशियां शामिल नहीं हैं, जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। तकनीकी रूप से ऐसे मामलों को चूकें नहीं माना जाता।

सारणी 13

मूलधन

(रुपये, लाखों में)

30 जून की समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया रकम*	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया मूलधन	वर्ष के दौरान मूलधन की देय रकम	खाना 3 और 4 का जोड़	वर्ष के दौरान मूलधन की प्राप्त रकम	वर्ष के दौरान मूलधन की अदायगी में चूक होने से बकाया रकम**
1	2	3	4	5	6	7
1967	9960.69	38.83	784.13	822.96	723.24	80.02
1968	12120.37	80.02	928.16	1008.18	801.11	149.32
1969	13553.04	149.32	944.90	1094.22	811.99	256.51
1970	14207.50	256.51	1163.86	1420.27	1004.27	313.21
1971	14998.54	313.21	1354.43	1667.64	1151.66	498.03

*इसमें वे बकाया ऋण शामिल नहीं है जिनकी किस्तें अदायगी में चूक होने के कारण अस्थगित कर दी गई हैं और जिनकी गारंटी निगम ने दी थी और इसलिए निगम को उन्हें अदा करना पड़ा। इसमें उन ऋणों पर लगने वाला ब्याज भी शामिल नहीं है। ये ऋण और उनके ब्याज का ब्यौरा सारणी 15 में दिया गया है।

**इसमें वे राशियां शामिल नहीं हैं जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। तकनीकी रूप से ऐसे मामलों को चूकें नहीं माना जाता।

34. 30 जून, 1971 तक बाकीदारी का उद्योगवार ब्यौरा और पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दिये गये हैं :—

सारणी 14

(रुपये, लाखों में)

उद्योग	30-6-1970 तक की बाकीदारियां			30-6-1971 तक की बाकीदारियां		
	संस्थाओं की संख्या	मूलधन	ब्याज	संस्थाओं की संख्या	मूलधन	ब्याज
चीनी	5	24.50	56.40	7	39.00	82.05
वस्त्र	14	115.66	138.62	21	180.33	186.88
कागज	3	12.45	62.35	3	15.65	87.86
बुनियादी औद्योगिक रसायन	1	15.00	17.95	2	19.73	22.53
मृतिका शिल्प और भट्टी में लगाने की ईंटें	4	37.18	46.74	5	54.48	62.30
लोहा और इस्पात	1	2.45	0.01	—	—	—
लकड़ी और कार्क	1	56.25	13.10	1	75.00	23.09
धातु उत्पाद	9	14.62	17.91	10	15.17	19.53
मशीनरी	3	9.60	5.25	5	31.85	10.57
बिजली मशीनरी और उपस्कर	3	14.91	7.88	2	19.23	22.30
मोटर गाड़ियां और उनके पुर्जे	1	2.12	2.48	1	5.30	8.88
विविध वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योग	2	3.42	0.98	2	8.63	1.06
विविध रसायन	2	4.00	1.06	2	23.06	12.16
होटल	1	1.05	1.80	1	3.15	4.23
साईकल	1	—	0.19	1	2.00	—
कांच	—	—	—	2	3.92	1.24
रबर	—	—	—	2	1.53	5.97
जोड़	51	313.21	372.72	67	498.03	550.75

35. वर्ष के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में बाकीदारी संस्थाओं की संख्या 14 से बढ़कर 21 हो गई। बाकीदारी की रकमों में और भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इस वर्ष उन्हीं संस्थाओं ने फिर समय पर रकमें नहीं चुकाई हैं जो पहले नहीं चुका सकी थीं। इन संस्थाओं का कार्य लाभ में कमी होने के कारण इस वर्ष भी संतोषप्रद नहीं रहा। यह सर्वविदित है कि कुछ वर्षों से सूती वस्त्र उद्योग में कार्य परिणाम असन्तोषप्रद रहा, जिसका कारण था, कच्चे माल की लागत में वृद्धि होना, विक्रय मूल्य की वसूली कम होना और उसकी अपेक्षा विनिर्माण लागत में वृद्धि होना। कुछ अन्य कठिनाइयां भी थीं, जैसे परियोजना के कार्यान्वित होने में विलम्ब हो जाने से लागत में अतिव्यय, कार्यकर पूंजी का अभाव, अकुशल प्रबन्ध और मजदूरों की हड़तालें आदि, कुछ इकाइयों के कार्य पर बिजली की उचित मात्रा में पूर्ति के अभाव का भी दुष्प्रभाव पड़ा। कुछ इकाइयों के मामले में निगम ने अदायगियों के कार्यक्रम में उचित परिवर्तन तथा आस्थगन करके राहत प्रदान की। इसके साथ ही इन संस्थाओं की कमियों तथा कठिनाइयों को भली प्रकार से समझने के लिये अधिक निरीक्षण तथा प्रवर्तकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों के साथ विचार विमर्श को तीव्र कर दिया है। कुछ मामलों में, निगम को बाध्य होकर अपनी बकाया को वसूल करने के लिये कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी।

36. चीनी उद्योग में पिछले वर्ष 42.62 लाख टन के उच्चतम उत्पादन की तुलना में 1970-71 के गन्ना पेरने के मौसम में 37 लाख टन के लगभग उत्पादन किया गया। चीनी के भारी भंडार इकट्ठा हो जाने के कारण कार्यकर पूंजी की कमी हो जाने से कठिनाई में रहीं। बाकीदारी संस्थाओं की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो गई, ब्याज की बाकीदारी की रकम 65.40 लाख रुपये से बढ़कर 82.05 लाख रुपये और मूलधन की बाकीदारी 24.05 लाख रुपये से बढ़कर 39.00 लाख रुपये हो गई।

37. 1968 तथा 1969 में कागज की कीमतों का विनियन्त्रण हो जाने से कागज उद्योग में समग्र रूप से लाभ की स्थिति ठीक रही है। फिर भी, निगम द्वारा वित्तपोषित कुछ इकाइयां उनकी अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण देय रकमें समय पर नहीं चुका सकीं। पिछली

वार्षिक रिपोर्ट में एक इकाई के पुनरप्रवर्तन का उल्लेख किया गया था जिसमें निगम का भारी जोखिम था। तब से इस संस्था ने विस्तार योजना के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सहायता के लिए पहुंच की है, जो इन संस्थाओं के विचाराधीन है। एक अन्य मामले में जहां निगम को अपनी वसूली करने के लिए बाध्य होकर कानूनी कार्रवाई के फलस्वरूप बन्धक परिसम्पत्तियों के लिए आयुक्त की नियुक्ति की गई तथा निगम के बकाया को वसूल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

38. इस्पात तथा अन्य उद्योगों से मृत्तिका शिल्प तथा भट्टी में लगने वाली ईंटों की मांग बढ़ जाने से, इस उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है। यद्यपि निगम द्वारा वित्तपोषित इकाइयों के कार्यपरिणामों में कुछ सुधार हुआ है, फिर भी वे ब्याज तथा मूलधन की बकया रकमों को अदा करने में असमर्थ रहें। यद्यपि एक इकाई ने बाकीदारी की कुछ रकम निगम को अदा की फिर भी इसे मन्दी के प्रभाव से पूर्णत: मुक्ति पाने के लिये कुछ समय लगेगा। एक अन्य मामले में कम्पनी का परिसमापन कर दिया गया है और न्यायालय के आदेश से बंधक मे रखी गई परिसम्पत्तियों को बिक्री के लिये लगा दिया गया है।

39. हार्डबोर्ड के उत्पादन में लगी इकाई जिसका उल्लेख पिछली वार्षिक रिपोर्ट में किया गया था इस वर्ष भी बाकीदारी की रकम को अदा करने में असमर्थ रही, यद्यपि इसके घरेलू तथा आयात बिक्री में सुधार हुआ है। कम्पनी को परिवहन की कठिनाइओं के कारण अपने उत्पाद को बेचने में कठिनाइओं का सामना करना पड़ा। कम्पनी की स्थिति सुधारने के लिये कुछ अन्य राहत देने पर विचार करना होगा।

40. इंजीनियरिंग उद्योग में बाकीदारी संस्थाओं की संख्या 10 से बढ़ कर 12 हो गई। यद्यपि इंजीनियरिंग उद्योग में कुछ सुधार हुआ है। फिर भी मशीनरी निर्माता, मशीन औजरों, इस्पात के ढ़ांचों और छोटे औजारों के उत्पादक मन्दी से पीड़ित रहे। पूर्वी क्षेत्र के बड़े कुछ उत्पादक सहित इनमें से कुछ अन्य ने श्रम संकट, उच्च उत्पादन लागत, कार्यकर पूंजी के अभाव के कारण उत्पादन बन्द कर दिया। इन इकाइयों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखी जा रही है और इनके पुनरस्थापन अथवा निगम की बकाया वसूल करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

41. 30 जून 1971 को निगम द्वारा गारंटी की हुई। अस्थगित अदायगी की बकाया राशि 316.83 लाख रुपये था जो कि पिछले वर्ष 293.84 लाख रुपये थी। अस्थगित अदायगी की ज्यादातर बकाया राशि कागज उद्योग की 3 परियोजनाओं तथा सूती वस्त्र उद्योग की 2 परियोजनाओं से सम्बन्धित है। इनमें से एक इकाई के पुनरप्रवर्तन की योजना का उल्ले पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था इस इकाई में निगम का भारी वित्तीय जोखिम था। इस वर्ष के दौरान इस दिशा में कुछ प्रगति हुई, आशा की जाती है कि वित्तीय पुनर्रचना तथा पुनस्थापना की योजना के पूरा हो जाने से निगम अपनी बकाया रकमों को प्राप्त करने में समर्थ रहेगा। एक अन्य कागज उद्योग की इकाई को जिसमें निगम का काफी जोखिम रहे, उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित पुनर्रस्थापना की योजना को भी अन्तिम दिया जा चुका है। कम्पनी ने अब एक विस्तार योजना के लिये निगम सहित अन्य अखिल भारतीय वित्तीय सस्थाओं से वित्तीय सहायता के लिये आवेदन किया है। कम्पनी के आवेदन-पत्र पर तेजी से गौर किया जा रहा है। कागज उद्योग की तीसरी इकाई जो आस्थगित अदायगी की बकाया रकम नहीं चुका सकी, यद्यपि इकाई उत्पादन कर रहीं है तथा तथा इस वर्ष इसका कार्यपरिणाम भी अच्छा रहा है। कम्पनी ने बाकीदारी को अभी चुकाना है, अत: ऋण के शोधन कार्यक्रम में परिवर्तन तथा कम्पनी के प्रबन्ध वर्ग में तबदीली करने पर विचार किया जा रहा रहा है।

सूती वस्त्र की एक इकाई जो बाकीदारी की रकमों को अदा करने में असमर्थ रही, इसकी पुनर्रस्थपना, तथा वित्तीय पुनर्रचना की योजना न्यायालय के विचाराधीन है। आशा है, योजना के अनुमोदित हो जाने से तथा प्रबन्ध वर्ग में परिवर्तन होने से कम्पनी की स्थिति में सुधार हो जायेगा।

कुछ चूकें करने वाली संस्थाओं के बारे में ऊपर के अवतरणों में की गई समीक्षा से यह पता चलेगा कि निगम ने हमेशा बाकीदारी के ऐसे मामलों में मूल कारण को खोजने की कोशिश की है और उसका रचनात्मक हल खोजने का प्रयत्न किया है। निगम ने हमेशा ऐसे उपक्रमों को स्वस्थ धरातल पर खड़ा करने तथा उनको वित्तीय क्षमता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से संस्थाओं के वर्तमान प्रबन्ध में सुधार करके तथा वित्तीय पुनर्रचना द्वारा और वर्तमान ऋण के शोधन कार्यक्रम में परिवतन लाकर अल्पकालीन देयताओं को दीर्घकालीन देयताओं में परिवर्तित करके अथवा उचित मामलों में बकाया को इक्विटी में परिवर्तित करके, रचनात्मक उपायों, द्वारा सुधार करने की कोशिश की है।

42. जिन अस्थगित अदायगियों के लिये निगम ने गारंटी दी थी उनकी किस्तों में जक होने के कारण निगम द्वारा पिछले पांच वर्षों में अदा की गई बाकीदारी की रकम और उस पर देय ब्याज आदि सारणी 15 में दिया गया है।

सारणी 15

जिन आस्थगित अदायगियों के लिए निगम ने गारंटी दी थी उनकी किस्तों की अदायगी में चूक होने के कारण निगम द्वारा अदा की गई बाकीदारी की रकम और उस पर देय ब्याज आदि

(रुपये, लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बाकीदारी की रकम	वर्ष के दौरान बाकीदारी की रकम	खाना 2 और 3 का जोड़	वर्ष के दौरान वसूलियां	वर्ष के अन्त में देय बाकीदारी की रकम
1	2	3	4	5	6
1967	239.34	95.77	335.11	—	335.11
1968	335.11	80.41	415.52	0.47	415.05
1969	415.05	116.27	531.32	3.89	527.43
1970	527.43	52.24	579.67	285.83*	293.84
1971	293.84	25.71	319.55	2.72	816.33

*इसमें 279.44 लाख रुपए की वह राशि शामिल है, जिसे नये ऋणों में परिवर्तित करके मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है।

उद्योग, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के उद्योगों की समीक्षा जिन्हें निगम से सहायता दी है।

43. निगम ने जिन उद्योगों को सहायता दी है, उनमें से बहुत से उद्योगों में वर्तमान क्षमता के उपयोग करने की दिशा में काफी सुधार हुआ है। बिजली के सामान बनाने वाले उद्योगों, जैसे ट्रांसफार्मरों, बिजली मोटरों, बैटरियों, घरेलू सर्विस मीटरों, बिजली मापक यन्त्रों तथा उच्च बोल्ट इन्सुलेटरों और बिजली मशीनरी से अन्य समूह में बाल और रोलर बियरिंगों, पेचदार बरमों आदि के निर्माण में लगे उद्योगों में क्षमता का पूर्ण उपयोग किया गया। तारों, मशीनी यन्त्रों तथा उपयोगों, सिलाई पहियों आदि के निर्माण में लगे उद्योगों में भी क्षमता के उपयोग की प्रगति देखी गई। अलमोनियम, कास्टिक सोडा ऐश, कृत्रिम रेशों, कागज और कागज बोर्ड, आटोमोबाइल टायरों एवं ट्यूबों के उद्योगों ने भी क्षमता के उपयोग में अच्छी क्षमता दिखाई। कोयले के मामले में मांग में स्थिरता आने तथा परिवहन की कठिनाइयों के कारण क्षमता का कम उपयोग किया गया।

वस्त्र उद्योगों की स्थिति कई विपरीत प्रभावों जैसे कपास के मूल्य बढ़ जाने से लाभ की मात्रा कम होना, मजदूरी में वृद्धि, उचित मात्रा में बिजली पूर्ति का अभाव, कार्यकर पूंजी का अभाव आदि के कारण स्थिति संतोषप्रद नहीं रही। सरकार ने कपास के अभाव को पूरा करने के लिए तन्तुक रेशे सहित 10 लाख कपास की गांठें आयात करने की व्यवस्था की। आयात को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिये कपास निगम की स्थापना की, ताकि वह जरूरत पड़ने पर मूल्य स्तर को रोकने तथा उचित वितरण के लिये आन्तरिक बाजार में प्रवेश कर सके। हाल ही में उद्योग को रियायतें प्रदान करने के लिये सैलूलोसिक तन्तुक रेशे पर यथा-मूल्य चुंगी कर 100 प्रतिशत से 30 प्रतिशत करने की घोषणा की है। सरकार ने निर्यात करने वाली इकाइयों के आधुनिकीकरण की जरूरत के महत्व को भी स्वीकार कर लिया है। सरकार की एक योजना के अनुसार वस्त्र उद्योग की इकाइयों को निगम द्वारा रियायती दर पर वित्तीय सहायता दी जायेगी। आशा है, इन उपायों से इस उद्योग में लाभ की स्थिति में सुधार होगा तथा निर्यात में वृद्धि होगी।

जहां तक पटसन उद्योग का संबन्ध है, यद्यपि कुछ महीने पहले कालीनों के अस्तर के कपड़ों की मांग अमेरिकी बाजार में गिर गई थी। इस दिशा में 1970 के अन्त से कुछ सुधार हुआ है। हाल ही में राजनैतिक घटनाओं के कारण पाकिस्तान से निर्यात तेजी से गिरने तथा भारत में पटसन की उपलब्धता के कारण आशा है कि इस उद्योग में अच्छी प्रगति होगी। फिर भी, निसन्देह इस उद्योग को बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण की जरूरत है।

समग्र रूप से चीनी उद्योग की स्थिति सन्तोषप्रद कही जा सकती है, फिर भी चीनी के भारी भण्डार एकत्र होने से उद्योग कार्यकारी पूंजी के अभाव का सामना कर रहा है, बाद में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। वर्ष के दौरान चीनी का उत्पादन बढ़ जाने से उगाही चीनी की मात्रा 70 से 60 प्रतिशत कर दी गई है। मई, 1971 के अन्त में केन्द्रीय सरकार ने चीनी मूल्य के विनियन्त्रण, वितरण, संचलन से रोक हटाने की घोषणा की। फिर भी थोक व्यापारियों को चीनी नियमित रूप से दी जायेगी ताकि, कीमतें उचित रहे तथा चीनी सारा वर्ष उपलब्ध होती रहे। उगाही चीनी के लिये यथामूल्य 25 प्रतिशत और 37.5 प्रतिशत दो दरों के स्थान पर सरकार ने यह दर यथामूल्य 30 प्रतिशत कर दी है।

इंजीनियरिंग उद्योग पर 1965-68 के दौरान मन्दी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, अब स्थिति कुछ सुधरी है। यद्यपि इस उद्योग के कुछ उत्पादों जैसे तन्तु नलों, ढांचों, सांचों, मशीनी यन्त्रों की मांग में वृद्धि हुई है, इस्पात की कमी से पूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकी। तुरन्त राहत प्रदान करने के लिये सरकार ने इस्पात के आयात की व्यवस्था की, सरकार देश में इस्पात की कमी दूर करने की जरूरत से पूर्णतः अवगत है। बोकारो इस्पात कारखाने के चालू होने तथा भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार होने से स्थिति में सुधार हो जायेगा, फिर भी इसमें कुछ समय लगेगा। दीर्घकालीन योजना के अनसार दक्षिण में 3 नये इस्पात कारखाने तथा कई 'छोटे संयन्त्रों' की योजना के पूरा होने से इस्पात तथा सम्बन्धित उत्पादों की कमी पूरा होने की आशा है। इस्पात के उत्पादन बढ़ने से रिफ्रेक्टरी उद्योग का भविष्य भी उज्जवल हो गया है।

कागज उद्योग में 1968 तथा 1969 के दौरान कीमतों तथा वितरण से विनियन्त्रण हट जाने से इस उद्योग के लाभ तथा उत्पादन दोनों में सुधार हुआ है। फिर भी देश में कागज की भारी कमी है। चौथी योजना के 10.20 लाख टन की विस्थापित क्षमता को प्राप्त करने के लिये 2.32 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता पैदा करनी होगी। कुछ वर्तमान कागज इकाइयों की विस्तार योजना का विस्तृत कार्यक्रम विचाराधीन है, जिसके पूरा होने से उत्पादन बढ़ने की आशा है। कागज उद्योग अत्याधिक पूंजी प्रधान है। कागज उद्योग की प्रगति तथा विकास कच्चे माल जैसे बांस, खोई, नरम तथा ठोस लकड़ी की भारी मात्रा में उपलब्धता पर निर्भर करता है।

इस वर्ष उर्वरकों का उत्पादन लगभग पिछले वर्ष जितना ही हुआ। फिर भी उर्वरकों का उत्पादन मांग से कम रहा है। सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम, इस्पात की कमी, देशी संकलित यन्त्रों की पूर्ति में देरी होना, बिजली पूर्ति में रुकावटें तथा श्रम संकटों के कारण रुके रहें। गैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में विदेशी मुद्रा साधनों/विदेशी सहायता के कारण समस्या खड़ी हुई। उर्वरक उद्योग भी अत्याधिक पूंजी प्रधान उद्योग है। यद्यपि कुछ नई परियोजनाओं की योजना है, इनके चालू होने में कुछ अवधि लगेगी और मांग तथा पूर्ति का अन्तर दूर हो जायेगा।

इस वर्ष के दौरान सीमेन्ट उद्योग ने कुछ प्रगति दिखाई, फिर भी मजदूरी बढ़ जाने तथा बिजली की लगातार पूर्ति में बाधा पड़ने से लाभ पर दुष्प्रभाव पड़ा।

मानव निर्मित रेशा उद्योग ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है इसके महत्व का कारण इसके विविध प्रयोगों तथा देश में कपास की कमी है। देश में कृत्रिम रेशों का उत्पादन मांग से बहुत कम है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में नाइलोन तन्तु धागे (औद्योगिक धागे सहित) की मांग का अनुमान 29,000 टन लगाया गया है जबकि उत्पादन 16,750 टन के बराबर होगा। कृतिम रेशों की मांग और पूर्ति के अन्तराल को कम करने तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिये अतिरिक्त क्षमता को पैदा करना आवश्यक है।

रिपोर्ट के परिशिष्ट 'च' में एक सारणी दी गई है जिसमें कुछ चुने हुए उद्योगों के सम्बन्ध में जिन्हें निगम ने वित्तीय सहायता दी है तथा ऐसों के सम्बन्ध में भी जिन्हें निगम द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के अंशदान दिया है, संस्थापित क्षमता और 1970 में देश में हुए औद्योगिक उत्पादन का एक विवरण दिया गया है।

ब्याज की दर

44. निगम ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन से रुपया ऋणों पर 5 दिसम्बर, 1971 से ब्याज की दर 8½ प्रतिशत वार्षिक से 9 प्रतिशत वार्षिक कर दी। इसके साथ मूलधन और ब्याज के समय पर अदा किये जाने के लिये आधा प्रतिशत की वार्षिक सामान्य छूट भी मिलेगी। फिर भी, यह संशोधित ब्याज दर केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित कम विकसित जिलों/क्षत्रों में लगने वाली परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी। विदेशी मुद्रा के उपऋणों पर भी 27 फरवरी 1971 से ब्याज की दर 9 से 9½ प्रतिशत वार्षिक कर दी गई, आधा प्रतिशत वार्षिक की सामान्य छूट भी मिलती रहेगी।

शेयरों का वितरण

45. विभिन्न वर्गों के अंशधारियों के पास निगम के जो शेयर थे, समीक्षाधीन वर्ष के उनके वितरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 30 जून, 1971 को शेयरों का वितरण निचे लिखे अनुसार था।

	शेयरों की संख्या	कुल का प्रै प्रतिशत
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	8346	50
अनुसूचित बैंक	3405	20
बीमा संस्थायें आदि	3586	22
सहकारी बैंक	1355	8
	16692	100

लेखे

इस वर्ष का लाभ-हानि विवरण :—

(रुपये, लाखों में)

	इस वर्ष	पिछले वर्ष
46. इस वर्ष के कारोबार की सकल आय	1345.95	1281.57
सकल आय में से निम्नलिखित घटाने के बाद :-		
बांडों और अन्य ऋणों पर अदा किया गया ब्याज	820.34	793.56
अन्य खर्चे	78.35	55.19
और कर के लिए व्यवस्था:-		
कर	237.00	237.00
इस वर्ष का निवल लाभ	210.26	195.82
210.26 लाख रुपये के निवल लाभ को इस प्रकार विनियोजित किया गया:-		
(i) सामान्य आरक्षित निधि को अन्तरित	74.54	96.19
(ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधि को अन्तरित	50.00	45.00
(iii) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये आरक्षित निधि को अन्तरित	42.99	30.00
(iv) स्टाफ कल्याण निधि को अन्तरित	1.00	
(v) 8.35 करोड़ रुपयों की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 5 प्रतिशत वार्षिक दर से अधिलाभांश की अदायगी	41.73	24.63
	210.26	195.82

सामान्य आरक्षित निधि

47. चालू वर्ष के लाभों में से 74.54 लाख रुपये की रकम सामान्य आरक्षित निधि में अन्तरित कर दी गई है, जो अब 834.60 लाख रुपये हो गई है ।

सामान्य आरक्षित निधि के अतिरिक्त कुल 435.78 लाख रुपये की निम्नलिखित विशेष आरक्षित निधियां हैं :

(रुपये, लाखों में)

(1) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32 क के अधीन विशेष आरक्षित निधि	100.00
(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	335.78
	435.78

सामान्य और आरक्षित निधियों की कुल रकमों का जोड़ 1270.38 लाख रुपये है ।

इसके अतिरिक्त संदिग्ध ऋणों के लिये कुल 153.82 लाख रुपये की रकम आरक्षित है । इस प्रकार निगम के पास आरक्षित निधियों की कुल रकम 1424.20 लाख रुपये हैं जो प्रदत्त पूंजी से 589.60 लाख रुपये अधिक है ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि

48. आयकर अधिनियम, की धारा 36 (1) (viii) के अधीन चालू वर्ष के लाभों में से 50.00 लाख रुपये की राशि विशेष आरक्षित निधि को अन्तरित कर दी गई । यह राशि चालू वर्ष की करनिर्धार्य आय के 10 प्रतिशत के बराबर है । इस प्रकार इस निधि की जमा रकम 335.78 लाख रुपये हो गई है ।

अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था :

49. वर्ष के अन्त में ऋण खाते की जो समीक्षा की गई, उसमें अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की स्थिति संतोषजनक पाई गई । निगम के कार्यक्षेत्र के विस्तार, कुछ संस्थाओं के पुनः स्थापना की योजनाओं के परिपक्व होने में लगने वाले अधिक समय को ध्यान में रखते हुए, संचालकों ने दूर दर्शिता से काम लेकर समीक्षाधीन वर्ष के लाभ में से 42.99 लाख रुपये संदिग्ध ऋणों की आरक्षित निधि को अन्तरित करने का निर्णय किया है।

आयकर के लिए व्यवस्था

50. 30 जून, 1970 को समाप्त हुए लेखा वर्ष (कर निर्धारण वर्ष 1971-72) को कर निर्धारण की कार्यवाही को वार्षिक लेखा बन्द होने से पहले अन्तिम रूप नहीं दिया गया था, अतः 30 जून, 1971 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के लिए कर लेखें में 237.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

51. निगम के पिछले पांच वर्षों के लाभहानि लेखे का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है :

सारणी 16

(रुपये, लाखों में)

	पिछले पांच वर्षों का कार्य परिणाम				
(1)	1967 (2)	1968 (3)	1969 (4)	1970 (5)	1971 (6)
उपार्जित ब्याज	858.33	1009.90	1086.78	1200.34	1257.84
अन्य आय	103.68	71.24	107.03	81.23	88.11
कुल आय	962.01	1081.14	1193.81	1281.57	1345.95

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अदा किया गया ब्याज	569.55	670.63	739.24	793.56	820.34
बांडों पर बट्टा और दलाली	12.60	16.97	17.87	1.37	1.17
स्थापना खर्च जिसमें चिकित्सा फीस तथा खर्च और कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज भी शामिल है	22.72	23.49	29.35	35.03	48.24
अन्य खर्चे	11.65	13.63	15.24	18.79	28.94
कुल खर्चे	616.52	724.72	801.70	848.75	898.69
सकल लाभ	345.49	356.42	392.11	432.82	447.26
कर के लिये व्यवस्था	180.69	198.25	221.79	237.00	237.00
निवल लाभ	164.80	158.17	170.32	195.82	210.26
आरक्षित निधियों में	140.17	133.54	145.69	171.19	168.53
अधिलाभांश	24.63	24.63	24.63	24.63	41.73

पिछले वर्ष को 1281.57 लाख रुपये की आय की तुलना में निगम को इस वर्ष कुल 1345.95 लाख रुपये की आय हुई । सकल लाभ 432.82 लाख रुपये से 447.26 लाख रुपये हो गया । 237.00 लाख रुपये की कर व्यवस्था करने के बाद (पिछले साल के बराबर) निवल लाभ 195.82 लाख रुपये से 210.26 लाख हो गया । पिछले वर्ष के 171.19 लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष आरक्षित निधियों में 168.53 लाख रुपये का विनियोजन किया गया ।

इस वर्ष के लाभ में से 74.54 लाख रुपये की राशि सामान्य आरक्षित निधि की अन्तरित कर देने से यह निधि 30 जून, 1971 को निगम की प्रदत्त पूंजी के बराबर हो गई । इसलिये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32 के अनुसार 30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम ने अपनी प्रदत्त पूंजी पर 5 प्रतिशत का अधिलाभांश देने की घोषणा की । अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार यह पहला अवसर है कि सर्वाधिक दर से अधिलाभांश घोषित करना संभव हुआ है । पिछले वर्ष 24.63 लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष का कुल अधिलाभांश 41.73 लाख रुपये है ।

तुलनपत्र से संलग्न अनुसूची :

52. 30 जून, 1971 तक दिए गए ऋणों और पेशगियों का विवरण बताने वाली एक अनुसूची तुलन-पत्र के साथ लगी है।

केवल न्यायालय को डिक्री द्वारा रक्षित ऋण :

अनुसूची की मद (ङ) से यह पता चलेगा कि इस वर्ग के अधीन एक संस्था पर 0.67 लाख रुपये का ऋण है।

ऋणी संस्थाओं में संचालकों के हित :

तुलन-पत्र के साथ लगी अनुसूची की मद (ध) में दिए गए आंकड़ों के विश्लेषण को दिखाने वाला विवरण परिशिष्ट 'छ' में दिया गया है। ऐसी कोई भी संस्था नहीं है (देखिये विवरण का खण्ड 'क') जिसमें निगम के किसी संचालक का राज्य सरकार या सहकारी बैंक या सहकारी समितियों के नामित संचालक के रूप में कोई हित हो।

उन संस्थाओं पर कुल 1113.34 लाख रुपये के ऋण बकाया हैं जिनमें निगम के कुछ संचालक केवल शेयरधारी के नाते हितबद्ध हैं। 681.81 लाख रुपये के ऋण सम्बन्धित संचालकों के निगम का संचालक बनने से पूर्व या ऋणी संस्था से हितबद्ध होने से पूर्व मंजूर किए गए थे। जिन संस्थाओं में संचालकों का हित संचालकों के नाते है, और जिनको वित्तीय सहायता उन व्यक्तियों के निगम के संचालक बनने के बाद मंजूर हुई है, उन संस्थाओं पर बकाया ऋण की राशि कुल राशि 84 लाख रुपये है। यह राशि निगम को प्राप्त होने वाले कुल बकाया ऋणों की 159.42 करोड़ रुपये की रकम का लगभग 0.5% है (देखिये विवरण का खण्ड 'ग')।

1365.61 लाख रुपये का मूलधन और ब्याज की किस्तों के रूप में बकाया में से एक संस्था से 98.09 लाख रुपये की राशि बकाया थी, जिसमें निगम का संचालक ऋणी संस्था के शेयरधारी के रूप में हितबद्ध था।

बोर्ड और केन्द्रीय समिति की बैठकें

53. इस वर्ष के दौरान बोर्ड की ग्यारह बैठकें हुई। जिनमें से सात नई दिल्ली में और एक-एक बैठक बम्बई, बंगलौर, चंडीगढ़ और शिलांग में हुई। केन्द्रीय समिति की कोई बैठक नहीं हुई। इस वर्ष केन्द्रीय समिति की दो बैठकें तथा बोर्ड की अन्य समितियों की 9 बैठकें हुई।

सलाहकार समितियां

54. छः सलाहकार समितियों के सदस्यों के नाम रिपोर्ट में अन्य स्थान पर दिए गए है। वर्ष के दौरान विभिन्न सलाहकार समितियों द्वारा की गई बैठकों की संख्या नीचे दी गई है :

सलाहकार समिति का नाम	बैठकों की संख्या
रसायन प्रक्रिया और समवर्गी उद्योग	8
इंजीनियरिंग	8
चीनी	8
वस्त्र	5
पटसन	कोई नहीं
विविध	कोई नहीं

इन बैठकों में कुल 44 संस्थाओं से विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार किया गया।

निगम ने पहले की तरह विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञों और सलाहकारों की एक नामिका रखी ताकि विभिन्न उद्योगों के लिए उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके और अवसर की आवश्यकतानुसार विचारार्थ मामलों की जटिलता और उनके स्वरूप और संबन्धित विशेषज्ञ के विशेषज्ञता-प्राप्त क्षेत्र के अनुसार नामिका में से कुछ विशेषज्ञों को संबन्धित समिति का सदस्य सहयोजित किया जा सके।

संचालक बोर्ड

55. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संचालक बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :—

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10(1) (कक) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने श्री चरत राम, डा० आर० एन० भार्गव और श्री एस० एल० एन० सिम्हा के स्थान पर क्रमशः श्री एफ० के० एफ० नारीमन्, डा० सैम्युल पाल और डा० वी०वी० भट्ट, संचालकों के रूप में नामित किये।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10(1) (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने श्री टी० स्वामीनाथन् के स्थान पर औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री बी० डी० पाण्डे को नामित किया। औद्योगिक विकास मन्त्रालय से बदली हो जाने के कारण श्री बी० डी० पाण्डे ने निगम के संचालक बोर्ड से त्याग पत्र दे दिया। उनके स्थान पर 17 अगस्त, 1971 से औद्योगिक विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री बी० बी० लाल नामित किए गये।

निगम की 30 सितम्बर, 1970 को हुई साधारण वार्षिक बैठक में श्री एस० डी० श्रीनिवासन् के त्याग पत्र देने के कारण हुए आकस्मिक रिक्त स्थान पर बीमा कम्पनियां निवेश न्यासों और ऐसी ही अन्य वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए जीवन बीमा निगम के महाप्रबन्धक श्री एन० वी० नायुडु चुने गये।

बोर्ड श्री चरत राम, श्री आर० एन० भार्गव, श्री एस० एल० एन० सिन्हा, श्री टी० स्वामीनाथन्, श्री बी० डी० पाण्डे और श्री एस० डी० श्रीनिवासन द्वारा की गई अमूल्य सेवाओं की सराहना करता है।

अन्य समितियां

56. जहां पर भी निगम के कार्यालय हैं, वहां पर निगम ने हाल ही में स्थानीय सलाहकार समितियों की स्थापना की है ताकि निगम सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं की प्रभावशाली ढंग से मदद कर सकें। उस क्षेत्र के औद्योगिक वातावरण की जानकारी, निवेश अवसरों, निगम के बारे में जनता की सामान्य धारणा, निगम के कार्य को जनता में लोकप्रिय बनाने आदि के उद्देश्य से इन समितियों की स्थापना की गई है। समितियों के सदस्य निगम का एक अथवा दो संचालकों के अतिरिक्त, राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, वाणिज्य और उद्योग के महत्वपूर्ण चैम्बर्स, समिति के क्षेत्राधिकार के राष्ट्रीयकृत बैंक तथा सम्बन्धित राज्य सरकार और प्रख्यात उद्योगपति होंगे।

निगम द्वारा नए कार्यालयों का खोलना

57. निगम के संचालक बोर्ड ने निगम के वर्तमान कार्यालयों, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के अतिरिक्त अहमदाबाद, हैदराबाद और बंगलौर में शाखाएं तथा कानपुर, पटना, भूवनेश्वर और गोहाटी में उप-कार्यालय खोलने का अनुमोदन कर दिया। गौहाटी के उप-कार्यालय ने 17 मई, 1971 से कार्य करना शुरू कर दिया है। यह कार्यालय असम, नागालैंड, मेघालय के राज्यों तथा मणिपुर, नेफा और त्रिपुरा के केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करेगा। 18 अगस्त, 1971 को अहमदाबाद में एक शाखा खोली गई। हैदराबाद और बंगलौर में शाखाएं तथा अन्य स्थानों पर उप-कार्यालय खोलने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

लेखा परीक्षक

58. 30 जून, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मैसर्स वाकर चन्डयोक एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली को निगम के लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया। 30 सितम्बर, 1970 को निगम के शेयर-धारियों की वार्षिक साधारण बैठक में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को छोड़कर अन्य शेयर-धारियों की ओर से उक्त अवधि के लिए मैसर्स एम० बी० बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी, बम्बई को फिर से लेखा परीक्षक चुना गया। मैसर्स एम० बी० बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी कार्यनिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन उनका फिर से चुनाव किया जा सकता है।

प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रदर्शन

59. बोर्ड को भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से जो सहयोग और सहायता मिली है उसके लिए वह उनकी प्रशंसा करता है। जिन सदस्यों ने निगम की विभिन्न सलाहकार समितियों में काम किया है बोर्ड उनकी अमूल्य सहायता और सलाह के लिए उनके प्रति कृतज्ञ है और वह उन गैर-सरकारी व्यक्तियों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रगट करता है जिन्होंने विभिन्न ऋणी संस्थाओं के संचालक बोर्डों में निगम के द्वारा नामित किए गए संचालकों के रूप में कार्य किया है। वर्ष के दौरान निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वफादारी और निष्ठापूर्वक की गई सेवा के लिए भी बोर्ड उनकी सराहना करता है।

संचालकों की ओर से

चरन दास खन्ना

अध्यक्ष

भारतीय औद्योगिक

30 जून 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष का
तुलन-पत्र और लाभ हानि लेखा

पिछले वर्ष	पूंजी और देयतायें			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
	1. अधिकृत पूंजी			
10,00,00,000	पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर			10,00,00,000
	जारी, स्वीकृत और प्रदत्त पूंजी			
5,00,00,000	पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपए के 10,000 शेयर (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की वापसी, अदायगी और 2½ प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारंटी प्राप्त)		5,00,00,000	
2,00,00,000	पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय श्रेणी) (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की वापसी, अदायगी और 4 प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारंटी प्राप्त)		2,00,00,000	
1,34,60,000	पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय श्रेणी) (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की वापसी, अदायगी और 4 प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारंटी प्राप्त)		1,34,60,000	8,34,60,000
8,34,60,000				
	2. रिजर्व और आरक्षित निधि			
	(i) सामान्य आरक्षित निधि (धारा 32 के अन्तर्गत)			
6,63,87,453	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	7,60,05,737		
96,18,284	लाभ हानि लेखे से अंतरित	74,54,263	8,34,60,000	
7,60,05,737				
	(ii) विशेष आरक्षित निधि (धारा 32 के अन्तर्गत)			
1,00,00,000	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		1,00,00,000	
	(iii) विशेष आरक्षित निधि (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अन्तर्गत)			
2,40,78,362	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	2,85,78,362		
45,00,000	लाभ हानि लेखे से अंतरित	50,00,000	3,35,78,362	
2,85,78,362				
11,45,84,099				
8,34,60,000	आगे ले जाया गया		12,70,38,362	8,34,60,000

विस्त निगम दिल्ली

तुलन-पत्र

पिछले वर्ष	सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां			इस वर्ष
रु०		रु०	रु.	रु०
	1. **नकद और बैंक शेष**			
9,177	(i) प्रधान कार्यालय और शाखाओं में		38,769	
	(ii) (धारा 19 के अन्तर्गत) नीचे लिखे बकों में—			
85,82,307	(क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया में	49,15,209		
5,92,86,840	(ख) अनसूचित बैंकों में	8,42,86,407		
10,00,000	(ग) राज्य सहकारी बैंकों में	26,00,000		
20,466	(घ) भारत के बाहर के बैंकों में	8,811	9,18,10,427	9,18,49,196
6,88,89,613				
6,88,98,790				
	2. **निवेश लागत मूल्य**			
	(i) धारा 20 के अन्तर्गत			
2,00,70,000	(क) भारत सरकार की अनभूतियों में	---		
---	(ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	---		
21,00,000	(ग) भारत यूनिट ट्रस्ट की आरंभिक पूंजी	21,00,000	21,00,000	
2,21,70,000				
	(ii) धारा 23 (1) (च) के अन्तर्गत शेयर			
65,91,150	(क) शेयर	94,80,693		
---	(ख) शेयरों की आवेदन राशि	8,75,000	1,03,55,693	
65,91,150				
	(iii) धारा 23 (1) (ज) के अन्तर्गत			
---	(क) स्टाक	---		
10,33,16,613	(ख) शेयर	10,85,49,285		
9,73,250	(ग) शेयरों और डिबेंचरों की आवेदन राशि	2,17,750		
---	(घ) बांड	---		
4,86,29,600	(ङ) डिबेंचर	4,73,14,600	15,60,81,635	
15,29,19,463				
1,82,00,000	(iv) धारा 23 (1) (झ) के अन्तर्गत डिबेंचर		1,37,35,000	18,22,72,328
19,98,80,613				
	[रु० 13,33,86,090 (कथित) रु० 12,99,08,245 (बाजार मूल्य), रु० 4,88,86,238 (अकथित)]			
	3. **ऋण और पेशगियां**			
1,53,22,17,265	कुल बकाया ऋण (संलग्न अनसूची के अनुसार)			1,59,41,19,564
1,80,09,96,668	आगे ले जाया गया			1,86,82,41,088

पिछले वर्ष	पूंजी और देयताएं			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
8,34,60,000	आगे लाया गया			8,34,60,000
11,45,84,099	**रिजर्व और आरक्षित निधि (जारी)**		12,70,38,362	
	(iv) संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित			
89,45,478	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	1,19,45,478		
——	घटाइये : बट्टे खाते डाले गये संदिग्ध ऋण	8,63,019		
89,45,478		1,10,82,459		
30,00,000	लाभ हानि लेखे से अंतरित	42,99,175	1,53,81,634	
1,19,45,478				
	(v) स्टाफ कल्याण निधि			
——	लाभ हानि लेखे से अंतरित		1,00,000	14,25,19,996
12,65,29,577				
	3. **कराधान के लिए व्यवस्था**			
5,98,60,717	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		4,56,78,698	
2,37,00,000	जोड़िये : वर्ष के लिए व्यवस्था		2,37,00,000	
8,35,70,717			6,93,78,698	
3,78,82,019	घटाइये : वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)		2,15,91,727	
4,56,78,698			4,77,86,971	
61,07,118	घटाइये : स्रोत पर काटा गया कर	61,40,537		
2,08,14,602	पेशगी दिया गया कर	2,38,12,581	2,99,53,118	1,78,33,853
2,69,21,720				
1,87,56,978				
4. बांड और डिबेंचर				
	(i) 4 प्रतिशत बांड (अरक्षित) जो 1971 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत गारन्टी दी है)			
5,48,86,900			5,48,86,900	
	(ii) 4½ प्रतिशत बांड (अरक्षित) जो 1974 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत गारन्टी दी है)			
6,00,33,100			6,00,33,100	
	(iii) 4¾ प्रतिशत बांड (आरक्षित) जो 1976 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत गारन्टी दी है)			
4,45,50,000			4,45,50,000	
	(iv) 4¾ प्रतिशत बांड (अरक्षित) जो 1976 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत गारन्टी दी है)			
6,58,48,100			6,58,48,100	
22,53,18,100				
22,87,46,555	आगे ले जाया गया		22,53,18,100	24,38,13,849

पत्र (जारी)

पिछले वर्ष	सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
1,80,09,96,668	आगे लाया गया			1,86,82,41,088
1,05,90,811				1,08,16,648
	4. स्थगित फ्रांसीसी ऋण के मूलधन के लिए उप-ऋणियों के वायदे			
	5. अधिलाभांश घाटा लेखा			
----	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		----	
----	घटाइए : लाभ हानि लेखे से अंतरित बकाया		----	----
	6. भवन आदि—लागत मूल्य			
----	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		----	
----	वर्ष के दौरान वृद्धियां		----	
----			----	
----	घटाइये : पिछले वर्ष तक का ह्रास मूल्य	----		
----	इस वर्ष का ह्रास मूल्य	----	----	----
----				
	7. मोटर-कारें, साइकलें, फर्नीचर, जुड़नार, फिटिंग इत्यादि लागत मूल्य पर			
7,68,879	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		8,63,576	
1,05,749	वर्ष के दौरान वृद्धियां		**4,96,869**	
8,74,628			**13,60,445**	
11,052	घटाइये : बेची गई/फैंकी गई परिसम्पत्तियों की लागत		6,725	
8,63,576			13,53,720	
2,97,306	घटाइये : पिछले वर्ष तक का ह्रास मूल्य	3,54,367		
67,274	इस वर्ष का ह्रास मूल्य	1,13,870		
3,64,580		4,68,237		
10,213	घटाइये: बेची गई/फैंकी गई परिसम्पत्तियों का ह्रास मूल्य	3,239	4,64,998	8,88,722
3,54,367				
5,09,209				
	8. अन्य परिसम्पत्तियां			
प्रोद्भूत ब्याज				
1,19,02,283	(i) ऋणों और पेशगियों पर	1,42,76,886		
15,96,814	(ii) डिबेंचरों पर	15,47,802		
18,97,876	(iii) बैंकों में जमा रकमों पर	20,05,095		
1,53,96,973				
1,81,20,96,688	**आगे ले जाया गया**	**1,78,29,783**		**1,87,99,46,458**

पिछले वर्ष	पूंजी और देयतायें			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
22,87,46,555	आगे लाया गया			24,38,13,849
22,53,18,100	**बाड और डिबेंचर (जारी)**		22,53,18,100	
2,00,00,000	(v) 5½ प्रतिशत बांड (अरक्षित) जो 1977 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के अंतर्गत गारन्टी दी है)		2,00,00,000	
6,12,90,000	(vi) 5½ प्रतिशत बांड (अरक्षित) जो 1978 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत गारन्टी दी है)		6,12,90,000	
8,24,86,700	(vii) 5¾ प्रतिशत बांड (अरक्षित) जो 1979 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत गारन्टी दी है)		8,24,86,700	
8,33,30,800	(viii) 5¾ प्रतिशत बांड (अरक्षित) जो 1980 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत गारन्टी दी है)		8,33,30,800	
5,50,00,000	(ix) 5¾ प्रतिशत बांड (अरक्षित) जो 1981 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत गारन्टी दी है)		5,50,00,000	
---	(x) 5¾ प्रतिशत डिबेंचर (अरक्षित) जो 1982 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत गारन्टी दी है)		4,95,00,000	
---	(xi) प्रतिशत डिबेंचर (अरक्षित) जो में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत गारन्टी दी है)		---	57,69,25,600
52,74,25,600				
---	**5. सावधि जमा** (धारा 22 के अन्तर्गत)			
	6. लिए गए ऋण			
	(i) रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से—			
---	(क) रु० अंकित मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्राप्त ऋण [धारा 21(3) (क) के अन्तर्गत]	---		
---	(ख) 3.25 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के निगम द्वारा जारी किये गये बांडों और डिबेंचरों द्वारा प्राप्त ऋण [धारा 21 (3) (ख) के अन्तर्गत]	1,24,10,000	1,24,10,000	
---	(ii) धारा 21 (4) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	---		
---	(iii) धारा 21 (4) के अन्तर्गत भारत सरकार से		77,32,05,415	
79,61,48,180				
20,62,91,583	(iv) विदेशी मुद्रा में		21,47,49,369	1,00,03,64,784
100,24,39,763				
1,05,90,811	**7. आस्थगित फ़ांसिसी ऋण मूलधन के लिए**			1,08,16,648.
176,92,02,729	आगे ले जाया गया			1,83,19,20,881

पत्र (जारी)

पिछले वर्ष	सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
1,81,20,96,688	आगे लाया गया			1,87,99,46,458
1,53,96,973	**अन्य परिसम्पत्तियां (जारी)**	1,78,29,783		
1,86,389	(iv) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर	—		
39,124	(v) कर्मचारियों को दी गई पेशगी रकमों पर	68,871		
288	(vi) किराए के लिए जमा पर	288	1,78,98,942	
1,56,22,774				
11,23,906	वचनबद्धता और अन्य प्रोद्भूत प्रभार		8,46,232	
2,839	प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता तथा अन्य प्रोद्भूत प्रभार		—	
38,71,934	फुटकर ऋण		42,82,422	
4,66,624	कर्मचारियों को दी गई पेशगी रकमें		7,70,395	
90,501	लेखन सामग्री के स्टाक		95,673	
55,186	टेलीफोन जमा (डिपाजिट)		72,019	
93,16,304	भुनाने के लिए किए गए चैक अथवा अपने पास मौजूद चैक जो भुनाये जाने हैं, दुतरफा (पर कन्ट्रा)		97,99,110	
51,689	पूर्वदत्त खर्च		53,844	
3,28,746	विनिमयजन्य अन्तर		2,58,344	
18	पास में मौजूद टिकटें		18	
3,09,30,521				3,40,76,999
24,39,66,816	9. **गारंटियां दुतरफा (पर-कन्ट्रा)**			20,70,51,508
12,50,000	10. हामीदारी संविदा दुतरफा (पर कन्ट्रा)			23,00,000
2,08,82,44,025	आगे ले जाया गया			2,12,33,74,965

तुलन-पत्र

पिछले वर्ष	पूंजी और देयतायें			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
1,76,92,02,729	आगे लाया गया			1,83,19,20,881
	8. भारत सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता			
	धारा 32 के साथ पढ़ी गई धारा 5 के अन्तर्गत अधिलाभांश के लिए			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष राशि	—		
	घटाइए : भारत सरकार को अदा की गई	—	—	—
	9. अन्य देयतायें			
	प्रोद्भूत हुआ और प्रोद्भूत होने वाला ब्याज—			
1,52,82,212	(क) धारा 21(4) के अन्तर्गत भारत सरकार से लिए गए ऋणों पर	1,48,88,796		
69,14,830	(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बांडों पर	73,25,956		
13,01,429	(ग) विदेशी मुद्रा ऋणों पर	11,94,169		
447	(घ) फुटकर जमा राशियों पर	487	2,34,09,408	
2,34,98,918				
10,12,797	पेशगी गारंटी कमीशन		8,94,204	
1,02,05,992	फुटकर लेनदार		1,03,62,206	
2,34,52,773	उचंत ब्याज		2,91,68,158	
5,32,414	उचंत वचनबद्धता प्रभार		4,33,270	
24,717	उचंत प्रासंगिक प्रभार		38,681	
4,20,572	गारंटी का उचंत कमीशन		4,20,572	
68,900	उचंत विधि प्रभार		74,200	
28,27,255	औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि लेखा		33,23,363	
438	दावा न किया गया अधिलाभांश		614	
93,16,304	वसूली के लिए प्राप्त चैक दुतरफा		97,99,110	
—	विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार		5,790	7,79,29,576
7,13,61,080				
	10. आकस्मिक देयतायें			
8,24,21,131	(क) धारा 23 (1) (ख) के अन्तर्गत दी गई गारंटियां — दुतरफा	7,05,29,601		
16,15,45,685	(ख) धारा 23(1) (ग) के अधीन विदेशी ऋण के लिए दी गई गारंटियां—दुतरफा	13,65,21,907	20,70,51,508	
24,39,66,816				
12,50,000	(ग) धारा 23 (1) (घ) के अन्तर्गत हामीदारी संविदा— दुतरफा		23,00,000	20,93,51,508
24,52,16,816				
2,08,57,80,625	आगे ले जाया गया			2,11,92,01,965

पत्र (जारी)

पिछले वर्ष	सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
2,08,82,44,025	आगे लाया गया			2,12,33,74,965
2,08,82,44,025	आगे ले जाया गया			2,12,33,74,965

तुलन-

पिछले वर्ष	पूंजी और देयतायें			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
2,08,57,80,625	आगे लाया गया			2,11,92,01,965
	11. **लाभ-हानि लेखा**			
24,63,400	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	24,63,400		
24,63,400	घटाइये : 1969-80 का अधिलाभांश	24,63,400	—	
—				
1,95,81,684	जोड़िये : लाभ हानि लेखे के अनुसार इस वर्ष का लाभ		2,10,26,438	
	घटाइये : (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (VIII) के (अन्तर्गत) विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	50,00,000		
45,00,000	संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि को अंतरित	42,99,175		
30,00,000	सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित	74,54,263		
96,18,284	स्टाफ कल्याण निधि को अंतरित	1,00,000	1,68,53,438	41,73,000
—				
1,71,18,284				
24,63,400				
2,08,82,44,025				2,12,33,74,965

आकस्मिक देयतायें : (क) धारा 23 (1) (च) और धारा 23 (1) (ज) के अन्तर्गत निवेश के रूप में अंशत: प्रदत्त शेयरों के लिए आकस्मिक देयतायें रु० 34,19,593

(ख) आस्थगित फ्रांसिसी ऋण पर ब्याज रु० 25,74,787

बलदेव पसरीचा
महाप्रबन्धक

चरन दास खन्ना
अध्यक्ष

एम० बी० बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी
बाकर, चन्डयोक एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

श्री एन० रामानन्द राव
श्री जी० रामानुजम
डा० वी० वी० भट्ट
डा० सैम्युल पाल
} संचालक

श्री एस० जे० उत्तमसिंग
सरदार सन्तोख सिंह
श्री पी० एस० राजगोपाल नायडु
} संचालक

पत्रक (जारी)

पिछले वर्ष	सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
2,08,82,44,025	आगे लाया गया			2,12,33,74,965
2,08,82,44,025				2,12,33,74,965

टिप्पणियां :—

1. धारा 23(1) (ज) के अन्तर्गत एक कम्पनी की साधारण शेयर पूंजी में नियोजित 1,97,900 रुपये शामिल हैं, कम्पनी ने ऐच्छिक परिसमापन कर दिया है। सम्भवतः निगम की नियोजित पूर्ण राशि वसूल न की जा सके।
2. ऋण और अग्रिम शामिल हैं—एक औद्योगिक इकाई से 81,63,841 रुपये शामिल हैं जिनकी वसूली संदिग्ध है। इस राशि के लिए विशेष व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि 'उचंत में डाला गया ब्याज' और 'संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि' खातों में उचित व्यवस्था है।
3. एक इकाई से ऋणों और अग्रिम राशियों में ब्याज की किश्तों के बकाया 23,75,000 रुपए शामिल हैं। निगम ने वर्ष के दौरान कम्पनी के एक भाग के पुर्नस्थापन होने से ब्याज की बकाया रकम के बराबर रकम वास्तविक मूल्य के साधारण और अधिमान शेयर स्वीकार करके समायोजन कर दिया, इन शेयरों का बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य से कम आंका गया है ।
4. वचनबद्धता और अन्य प्रभारों में शामिल हैं : (क) दो इकाइयों से 1,41,567 रुपए बकाया हैं, जिनकी अदायगी विवादग्रस्त है। इस संदिग्ध राशि के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई। (ख) एक इकाई से 4,33,270 रुपये बकाया हैं, जिनकी अदायगी संदिग्ध है और उचंत खाते में डाले गये।
5. फुटकर ऋणों में निम्नलिखित शामिल हैं : (क) एक कम्पनी की परिसम्पत्तियां जो अन्य कम्पनी को बेची गयीं उनके मूल्य के रूप में वसूल की जाने वाली, पूर्णतः रक्षित शेष राशि के 9,87,641 रुपए। (ख) एक कम्पनी की परिसम्पत्तियां जो अन्य कम्पनी को बेची गयीं उनके मूल्य तथा उस पर ब्याज के रूप में वसूल की जाने वाली शेष राशि के 2,76,729 रुपए (प्रतिभूति 2,58,000) बकाया हैं। (ग) कुछ उप-देनदारों की अतिरिक्त देयता के 7,87,975 रुपए जो उन्होंने रुपए के अवमूल्यन से पहले मूलधन की किस्तों के रूप में जमा किये हैं और जो विवादग्रस्त हैं, तथा जिनको वसूली संदिग्ध है। (घ) एक ऐसी कम्पनी में निवेशित आवेदन और आवंटन की 1,97,525 रुपए की रकम जिसके विरुद्ध निगम ने अदा की गई रकम की वापसी के लिए मुकदमा दायर किया हुआ है। निगम ने इस कम्पनी के शेयरों के आवंटन को अवैध माना है क्योंकि कुछ शेयर बाजारों ने शेयरों को सचीबद्ध करने से इन्कार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आवंटन को विधिमान्य करार दे दिया है, फिर भी कुछ मामले उच्च न्यायालय के सामने फैसले के लिये पड़े हुये हैं, राशि फुटकर ऋण खाते में रखी गई है।
6. कर्मचारियों को निवृत्ति उत्पादन अदायगी विनियम 1968 के अधीन भाविषय में अदा की जाने वाली निवृत्ति उत्पादन देयता (अनिश्चेय राशि) के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

30 जून, 1971 के तुलन-पत्र में उल्लिखित ऋणों और पेशगियों के ब्योरे को दर्शाने वाली अनुसूची

	रु०
(क) शोध्य समझे गये ऋण जो निगम के लिए पूर्णरूप से रक्षित हैं	1,30,81,66,142
इसमें से—	
(i) कुल 65,61,31,075 रुपए के ऋण उधार लेने वाली संस्थाओं के संचालकों और/या पूर्व प्रबन्ध एजेंटों और/या पूर्व सचिवों तथा कोषाध्यक्षों की व्यक्तिगत गारन्टी द्वारा भी रक्षित हैं। (इनमें से कुल 82,00,000 रुपयों के ऋण केन्द्रीय और/या राज्य सरकारों की गारन्टी द्वारा और भी रक्षित हैं तथा कुल शून्य रुपए के ऋण अनुसूचित या सहकारी बैंकों द्वारा रक्षित हैं)	
(ii) कुल 40,23,99,322 रुपयों के ऋण केन्द्रीय और/या राज्य सरकारों की गारन्टी द्वारा भी रक्षित हैं।	
(iii) कुल शून्य रुपयों के ऋण अनुसूचित और/या राज्य सहकारी बैंकों की गारन्टी द्वारा भी रक्षित हैं।	
(ख) ऋण जो पहले पूरी तरह रक्षित थे लेकिन अब केवल 10,52,99,000 रुपयों की सीमा तक ही रक्षित हैं। (15,45,71,894 रुपयों में से 2,65,28,146 रुपयों के ऋण केन्द्रीय और राज्य सरकारों की गारंटियों द्वारा रक्षित हैं)।	15,45,71,894
(ग) केवल केन्द्रीय और/या राज्य सरकारों की गारन्टी द्वारा रक्षित ऋण	4,52,32,197
(घ) केवल अनुसूचित और/या सहकारी बैंकों की गारन्टी द्वारा रक्षित ऋण	8,60,82,584
(ङ) केवल व्यक्तिगत गारन्टी या वाद प्राप्य वस्तुओं द्वारा रक्षित ऋण	66,747
(क), (ख), (ग), (घ), और (ङ) का जोड़	159,51,19,564
(च) जिन औद्योगिक संस्थाओं से निगम के संचालक उनके संचालक और अंशधारी के रूप में हितबद्ध हैं, उनके द्वारा देय ऋण	13,01,68,028
इसमें से—	
(i) उन सहकारी समितियों द्वारा कुल शून्य रुपये के ऋण देय हैं, जिनके निगम के संचालक राज्य सरकार या उन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के नामित व्यक्ति के रूप में हितबद्ध हैं।	
(ii) कुल 11,13,74,147 रुपयों के ऋण उन संस्थाओं द्वारा देय हैं जिनसे निगम के संचालक केवल अंशधारियों के रूप में हतबद्ध हैं।	
(iii) कुल 1,87,93,881 रुपयों के ऋण उन संस्थाओं द्वारा देय हैं जिनसे निगम के संचालक केवल संचालक के रूप में हितबद्ध हैं।	
(छ) जिन संस्थाओं से निगम के संचालक उनके संचालक और अंशधारी के रूप में हितबद्ध हैं, उनको वर्ष के दौरान संवितरित किये जाने गए ऋणों की रकम।	1,13,48,901

	रु०
(ज) (i) मूलधन या ब्याज की ऐसी किस्तों की रकम जिनको चुकाने में वर्ष के दौरान किसी समय चूक हुई हो।	5,44,59,234
(ii) मूलधन या ब्याज की ऐसी किस्तों की कुल रकम जो वर्ष का अन्त होने के बाद भी देय हों।	13,65,60,680
(iii) ऐसी संस्थाओं द्वारा देय मूलधन या ब्याज की किस्तों की कुल रकम जिससे निगम के संचालक केवल अंशधारी के नाते हितबद्ध हैं।	98,08,886

टिप्पणी :—इस अनुसूची में छः संस्थाओं द्वारा मशीनरी पूर्तिकारों की आस्थगित अदायगियों की किस्तों में की जाने वाली चूकें शामिल हैं। इन चूकों के लिए निगम ने आस्थगित अदायगी गारन्टी के अधीन अदायगी की है और इन अदायगियों को ऋण माना गया है।

बलदेव पसरीचा
महाप्रबन्धक

चरन दास खन्ना
अध्यक्ष

एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी
बाकर, चण्डयोक एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

भारतीय औद्योगिक नई

30 जून, 1971 को समाप्त हुए

पिछले वर्ष			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०
7,93,55,581	बाबत बांड, डिबेंचरों आदि पर ब्याज		8,20,34,017
	बाबत वेतन, भत्तों, भविष्यनिधि अंशदान और उपदान		
50,622	(क) अध्यक्ष	46,457	
36,719	(ख) महाप्रबन्धक	29,325	
32,27,364	(ग) अन्य	46,06,686	
1,79,733	(घ) भविष्य निधि अंशदान	2,10,110	
39,735	(ङ) उपदान	2,250	
53,34,173		48,94,828	
2,11,050	घटाइये : निगम द्वारा किये गये कानूनी कार्य के लिए ऋण लेने वाली संस्थाओं से ली गई रकम।	2,81,700	46,13,128
33,23,123			
11,750	बाबत संचालकों की फीस		11,350
3,250	बाबत समिति के सदस्यों की फीस (संचालकों से अन्य)		4,350
91,989	बाबत संचालकों के यात्रा और अन्य भत्ते		1,00,711
48,314	बाबत समिति के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते (संचालकों को छोड़कर)		44,988
8,71,785	बाबत किराया, कर, बीमा और रोशनी		11,16,601
1,41,764	बाबत डाक, तार, टिकटें और टेलीफोन		1,62,185
1,70,006	बाबत छपाई, लेखन सामग्री और विज्ञापन		2,67,020
7,764	बाबत मरम्मत		6,187
39,785	बाबत विधि प्रभार		32,854
20,000	बाबत लेखा परीक्षा फीस		20,000
67,274	बाबत मूल्य ह्रास		1,13,870
	बाबत दूसरे खर्च :—		
5,500	बाबत एजेंसी प्रभार	4,950	
15,000	बाबत पुस्तकें और समाचार पत्र	19,047	
37,091	बाबत डाक्टरी फीस और खर्चे	42,749	
1,46,658	बाबत यात्रा फीस	1,79,650	
11,985	बाबत विराम भत्ते	16,739	
20,083	बाबत मोटरकारों का रखरखाव	25,587	
2,36,317			
8,41,52,385	आगे ले जाया गया	2,88,722	8,85,27,261

विद्युत निगम
दिल्ली
वर्ष का लाभ हानि लेखा

पिछले वर्ष		इस वर्ष
रु०		रु०
12,00,33,727	द्वारा ब्याज	12,57,83,668
28,37,627	द्वारा कमीशन	25,81,615
----	द्वारा किराया	---
5,53,835	द्वारा निवेशों की बिक्री से लाभ	12,22,356
5,233	द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	1,132
26,29,767	द्वारा शेयरों पर अधिलाभांश	34,39,754
18,45,351	द्वारा वचनबद्धता प्रभार	13,26,487
---	द्वारा समय पूर्व वापसी अदायगी के लिए प्रीमियम	---
--	द्वारा अशोध्य ऋण की वसूली	---
2,51,062	द्वारा विविध आय	2,40,015
12,81,56,062	आगे ले जाया गया	13,45,95,027

लाभ और

पिछले वर्ष				इस वर्ष
रु०			रु०	रु०
8,41,52,385		आगे लाया गया		8,85,27,261
2,36,317	बाबत दूसरे खर्च (आरी)		2,88,722	
4,800	बाबत सूचीकरण फीस		6,000	
20,253	बाबत बैंक प्रभार		28,648	
97,610	बाबत न गिनाए गए खर्च		1,81,773	
1,43,151	बाबत कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज		1,67,672	6,72,815
5,02,131				
83,105	बाबत विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार			1,41,091
1,37,091	बाबत बांडों पर दलाली			1,16,756
—	बाबत बांडों पर बट्टा			—
—	बाबत बट्टेखाते डाले गये अशोध्य ऋण			—
—	बाबत प्रतिभूतियों की बिक्री पर काटा गया आयकर			—
—	बाबत संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था			—
—	बाबत निवेशों की बिक्री से हानि			4,10,000
206	बाबत बट्टेखाते डाली गई परिसम्पत्तियां			482
—	बाबत परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि			184
2,37,00,000	बाबत करोधान के लिए व्यवस्था			2,37,00,000
1,95,81,684	बाबत तुलन पत्र में ले जाया गया लाभ शेष			2,10,26,438
12,81,56,602				13,45,95,027

बलदेव पसरीचा
महाप्रबन्धक

चरन दास खन्ना
अध्यक्ष

एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी
बाकर, चन्दयोक एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

श्री एन० रामानन्द राव
श्री जी० रामानुजम
डा० वी० बी० भट्ट
डा० सैम्युल पाल
} संचालक

श्री एस० जे० उत्तमसिंग
सरदार संतोख सिंह
श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू
} संचालक

हानि लेखा (जारी)

पिछले वर्ष			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०
12,81,56,602	आगे लाया गया		13,45,95,027
12,81,56,602			13,45,95,027

टिप्पणी : (1) 'ब्याज' में बकाया प्राप्त हुए 3,123 रुपये शामिल हैं जो पहले उचंत लेखे में डाले गये थे।

(2) 'ब्याज' में 57,92,340 रुपये नहीं दिखाये गये हैं जिनकी वसूली संदिग्ध समझी गई है, यह उचंत लेखें में डाले गये हैं।

(3) एक लेखे पर ब्याज आभारित नहीं किया गया है क्योंकि इनकी वसूली संदिग्ध समझी गई है।

(4) 'कमीशन' में बकाया रकमों की वसूली के 1,73,493 रुपये शामिल नहीं हैं, क्योंकि समझौते में परिगणन से सम्बन्धित खण्ड के स्पष्टीकरण के लिए पत्र-व्यवहार चल रहा है।

(5) 'बचनबद्धता प्रभारों' में 68,240 रुपये शामिल नहीं हैं जो संदिग्ध वसूली समझे गये तथा उचंत लेखे में डाले गये।

(6) 'विविध आय' में 13,965 रुपये शामिल नहीं हैं जो प्रासंगिक प्रभार होने से वसूली में संदिग्ध समझे गये तथा उचंत लेखे में डाले गये।

(7) वेतन तथा भत्ते में 3,75,293 रुपये शामिल हैं, जो अधिकारियों के समायोजन भत्ते तथा कार्मिक कर्मचारियों के वेतनमान के पुनरीक्षण के कारण पिछले वर्ष से सम्बन्धित हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंशधारी,

हम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के, नीचे हस्ताक्षर करने वाले लेखा-परीक्षक निगम के 30 जून 1971 के तुलन-पत्र और लेखों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने सम्बन्धित वाउचरों और लेखों तथा शाखा-कार्यालयों से प्राप्त परीक्षित विवरणों के साथ ऊपर दिये गये तुलन-पत्र की जांच कर ली है। ये विवरणियां ऊपर के तुलन-पत्र में शामिल कर ली गई हैं। हम इस बात की रिपोर्ट देते हैं कि हमने जहां कहीं भी कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी है, वहां हमें सम्बन्धित स्पष्टीकरण या जानकारी दी गई है और वह संतोषप्रद रही है। हमारी राय में प्रस्तुत तुलन-पत्र पूर्ण और निष्कपट है और जहां तक हमें जानकारी और स्पष्टीकरण दिये गये हैं और जैसा कि निगम के बही-खातों में पता चलता है, यह तुलन-पत्र निगम के अधिनियम और नियमावली के अनुसार इस प्रकार उचित रीति से बनाया गया है कि इससे निगम के कार्यों का सच्चा और सही चित्र सामने आ जाता है।

त्रिवेन्द्रम,
दिनांक 26 अगस्त, 1971

एस० बी० बिर्ला मोरिया एण्ड कम्पनी
वाकर, चन्डयोक एण्ड कम्पनी
मनद्दी लेखापाल

परिशिष्ट

	परिशिष्ट
1-7-1970 तक विचाराधीन आवेदनपत्रों की संख्या और उनकी राशि तथा 30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्राप्त, अस्वीकृत, वापस लिए गए और मंजूर किए गए आवेदन पत्रों की संख्या और संवितरित राशि तथा 30 जून, 1971 को विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या और उनकी राशि के राज्यवार वितरण को दर्शाने वाला विवरण	'क'
1-7-1970 से 30-6-1971 तक मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण	'ख'
30 जून, 1971 तक समस्त आर्थिक कार्यकलापों के अन्तर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विश्लेषण	'ग' (i)
30 जून, 1971 तक मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का राज्य प्रदेशवार वितरण	'ग' (ii)
30 जून, 1971 तक प्रत्येक औद्योगिक संस्था को मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का धन राशि के अनुसार वर्गीकरण	'घ'
30 जून, 1971 तक प्रत्येक राज्य में मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का उद्योगवार वितरण	'ङ'
वर्ष 1970 के दौरान देश के चुने हुए उद्योगों की कुल स्थापित क्षमता और औद्योगिक उत्पादन और उसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त औद्योगिक संस्थाओं के योगदान को दर्शाने वाला विवरण	'च'
उन औद्योगिक संस्थाओं द्वारा देय ऋण जिनसे निगम के संचालक हितबद्ध हैं	'छ'
लोक वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पात्र जिलों/क्षेत्रों की समेकित सूची	'ज'
औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं को रियायती दर पर उपलब्ध वित्तीय सहायता का विवरण	'झ'

1-7-70 को विचाराधीन, आवेदनपत्रों की संख्या और उनकी राशि तथा
गए और मंजूर किए गए आवेदन पत्रों की संख्या और
आवेदन पत्रों की संख्या और उनकी राशि के

परिशिष्ट 'क' (जारी)

(क) ऋणों का बोधक है ।

(ख) हामीदारियों का बोधक है ।

(ग) मशीनरियों की आस्थगित अदायगियों और विदेशी मुद्रा ऋणों की गारंटियों का बोधक है ।

(रुपये लाखों में)

राज्य/क्षेत्र		वर्ष के आरम्भ में (1-7-70 को) विचाराधीन आवेदन पत्र*		वर्ष के दौरान (1-7-70 से 30-6-71 तक) प्राप्त आवेदन पत्र		वर्ष के दौरान (1-7-70 से 30-6-71 तक) अस्वीकृत आवेदन पत्र	
		सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आंध्र प्रदेश	(क)	1	60.00	2	340.00	—	—
	(ख)	—	—	1	5.00	—	—
असम	(क)	—	—	—	—	—	—
बिहार	(क)	2	221.46	3	475.00	—	—
	(ख)	1	2000.00	2	500.00	—	—
गुजरात	(क)	2	3823.00	8	699.60	—	—
	(ख)	—	—	1	23.00	—	—
	(ग)	—	—	1	64.40	—	—
हरियाणा	(क)	6	643.00	6	121.73	—	—
	(ख)	1	3.90	4	23.48	—	—
केरल	(क)	1	20.00	5	390.00	—	—
	(ख)	1	7.50	2	110.00	—	—
	(ग)	1	10.00	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	(क)	1	40.00	—	—	—	—
	(ख)	—	—	—	—	—	—
महाराष्ट्र	(क)	11	921.10	18	1067.39	1	200.00
	(ख)	3	195.00	3	21.42	1	120.00
मैसूर	(क)	2	3050.00	4	382.28	—	—
	(ख)	1	700.00	—	—	—	—
उड़ीसा	(क)	—	—	4	1109.05	—	—
	(ख)	—	—	2	15.50	—	—
पंजाब	(क)	2	311.68	1	60.00	1	275.68
	(ख)	2	226.80	—	—	1	220.00
राजस्थान	(क)	—	—	4	122.10	—	—
तमिलनाडु	(क)	1	55.00	9	370.78	—	—
	(ख)	—	—	2	15.00	—	—
	(ग)	—	—	—	—	—	—

30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्राप्त, अस्वीकृत, वापस लिए संवितरित राशि तथा 30 जून, 1971 को विचाराधीन राज्यवार वितरण को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

वर्ष के दौरान (1-7-70 से 30-6-71 तक) वापस लिए गए आवेदन पत्र		वर्ष के दौरान (1-7-70 से 30-6-71 तक) स्वीकृत आवेदन पत्र		वर्ष के दौरान (1-7-70 से 30-6-71 तक) संवितरित राशि	30-6-71 को विचाराधीन आवेदन पत्र	
सं० (8)	राशि (9)	सं० (10)	राशि (11)	राशि (12)	सं० (13)	राशि (14)
1	60.00	2	185.00	80.00	—	—
—	—	1	5.00	9.95	—	—
—	—	—	—	18.50	—	—
2	221.46	3	225.00	66.45	—	—
—	—	3	260.00	5.93	—	—
1	43.99	6	383.61	44.52	4	4098.00
—	—	1	23.00	—	—	—
—	—	1	42.35	—	—	—
3	135.25	5	143.57	52.02	4	114.00
—	—	3	10.88	8.62	3	18.50
1	20.00	1	105.00	36.46	4	285.00
1	7.50	—	—	—	2	110.00
1	10.00	—	—	—	—	—
—	—	1	40.00	21.46	—	—
—	—	1	5.00	4.24	—	—
3	71.10	18	752.08	584.93	9	761.00
1	5.00	4	17.02	6.24	—	—
—	—	4	260.28	121.32	2	2972.00
—	—	—	—	0.76	1	700.00
—	—	4	269.05	123.73	—	—
—	—	1	10.00	—	1	5.50
1	60.00	—	0.70	9.02	1	36.00
—	—	—	—	—	1	6.80
—	—	3	81.10	4.00	1	36.00
1	9.00	7	216.78	139.77	2	85.00
—	—	1	5.00	7.24	1	10.00
—	—	—	—	19.79	—	—

परिशिष्ट 'क'—जारी

(रुपये, लाखों में)

राज्य/क्षेत्र		वर्ष के आरम्भ में (1-7-70 को) विचाराधीन आवेदन पत्र		वर्ष के दौरान (1-7-70 से 30-6-71 तक) प्राप्त आवेदन पत्र		वर्ष के दौरान (1-7-70 से 30-6-71 तक) अस्वीकृत आवेदन पत्र	
		सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उत्तर प्रदेश	(क)	7	418.90	7	297.12	—	—
	(ख)	3	37.25	4	50.00	—	—
पश्चिमी बंगाल	(क)	2	54.72	3	37.50	—	—
	(ख)	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	(क)	—	—	—	—	—	—
	(ख)	—	—	—	—	—	—
गोआ, दमन और दिउ	(ख)	—	—	—	—	—	—
जोड़	(क)	38	9618.86	74	5472.55	2	475.68
	(ख)	12	3170.45	21	763.40	2	340.00
	(ग)	1	10.00	1	64.40	—	—
कुल जोड़		51	12799.31	96	6300.35	4	815.68
		(34)		(70)		(2)	
अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से सहायता**		17	11328.89	17	3226.90	4	815.68
		(9)		(8)		(2)	

*वर्ष के प्रारम्भ में विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में दिखाई गई संख्या से मेल नहीं खाती, क्योंकि बाद में आवेदकों द्वारा कुछ परिवर्तन किए गये।

**कोष्ठों में दी गई संख्याएं इकाइयों की संख्या का बोधक हैं।

†इसमें पिछले वर्षों में आवंटित 27.35 लाख रुपये के 6 मामले शामिल हैं।

(रुपये, लाखों में)

वर्ष के दौरान (1-7-70 से 30-6-71 तक) वापस लिए गए आवेदन पत्र		वर्ष के दौरान (1-7-70 से 30-6-71 तक) स्वीकृत आवेदन पत्र		वर्ष के दौरान (1-7-70 से 30-7-71तक) संवितरित राशि	30-6-71 को विचाराधीन आवेदन पत्र	
सं० (8)	राशि (9)	सं० (10)	राशि (11)	राशि (12)	सं० (13)	राशि (14)
2	156.28	10	397.94	135.35	3	165.50
1	6.00	4	44.25	7.84	2	37.00
1	42.72	4	49.50	160.06	—	—
—	—	—	—	0.92	—	—
—	—	—	—	30.00	—	—
—	—	—	—	5.78	—	—
—	—	—	—	29.20	—	—
16	819.80	68†	3109.61	1628.19	30	8552.50
3	18.50	19†	380.15	86.72	11	887.80
1	10.00	1	42.35	19.79	—	—
20	848.30	88	3532.11	1734.70	41	9440.30
(16)		(61)			(28)	
2	221.46	19	1269.19		9	7787.50
(1)		(10)			(4)	

परिशिष्ट 'ख'

1 जुलाई, 1970 से 30 जून, 1971 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	संस्था का नाम और फैक्टरी का स्थान	प्रबन्धक संचालकों/ संचालक बोर्ड के अध्यक्ष/ सचिवों और कोषाध्यक्षों के नाम	परियोजना की पूंजी लागत	मंजूर की गई वित्तीय सहायता						परयोजना विवरण
				रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा ऋण (रुपये के बराबर)	हामीदारी			मशीनों की आस्थगित अदायगी के लिए गारंटी	
						साधारण शेयर	अधिमान शेयर	डिबेंचर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			आंध्र प्रदेश							
1.	मै० आन्ध्रा फाउन्ड्री एण्ड मशीन कं० लि०, मौला अली, हैदराबाद।	श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद, प्रस्तावित प्रबंध संचालक	30.00	–	–	2.50@	2.50@	–	–	कुछ संतुलन उपस्कर को उपलब्ध करके लगाना तथा कार्यकारी पूंजी को संपूर्ति एवं अन्य जरूरी देयाताओं को पूरा करने के लिए।
2.	मै० हिन्दुस्तान पोलेमर्स लि०, विशाखापट्नम्।	श्री कस्तूरभाई लाल भाई, अध्यक्ष	249.17 (अति० व्यय)	35.00 (अति०)	–	–	–	–	–	10,000 टन स्टाइरीन मोनोमर, 7,500 टन पोली स्टीइरीन वार्षिक की दर से उत्पादन करने के लिए 22 लाख गैलन वार्षिक की क्षमता वाली एलकोहल डिस्टीलरी के लिए दूसरे अति० व्यय के कुछ भाग को पूरा करने के लिमे।

3.	मैं० वेस्ट गोदावरी कोपरेटिव शुगर्स लि०, सुरापागुडम जि० पश्चिमी गोदावरी	सहकारी इकाई	260.00	51.00*	—	—	—	—	—	1,250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाले कारखाने को लगाने के के लिए।
				बिहार						
4.	मैं० बिहार अलाय स्टील्स लि०, पतारतू रांची	डा० बी० सी० जैन, [प्रस्ताविक प्रबन्ध] संचालक (बिरला ग्रुप)	2431.58	150.00	—	50.00	10.00	—	—	40,000 टन की वार्षिक क्षमता से कार्बन धातु, संरचनात्मक इस्पात, लोचक इस्पात, कठोर तथा ताप रोधक इस्पात, औजार और तीव्र गति इस्पात बनाने के लिये कारखाना लगाने हेतु।
5.	मैं० कल्यापुर लाईम एण्ड सीमेन्ट वर्क्स लि०, बंजारी जिला शाहबाद	श्री एस० पी० सिन्हा [प्रबन्ध संचालक]	101.40	50.00 (अति०)	—	—	—	—	—	4 लाख टन वार्षिक की दर से सीमेन्ट का उत्पादन करने के लिए नवीकरण तथा सन्तुलन योजना हेतु।
6.	मैं० पुरणिया कोपरेटिव शुगर फैक्टरी लि,० बनमान्खी, जिला पुरणिया [	सहकारी इकाई	59.60 (अति०व्यय)	25.00 (अति०)	—	—	—	—	—	1,000 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाले चीणी कारखाने के लिए निर्माण में अति०व्यय को पूरा करने के लिए।
7.	मैं० टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० जमशेदपुर, जिला सिंघभूम [	श्री जे० आर० डी० टाटा, अध्यक्ष और श्री एस० के० नानावती, प्रबन्ध संचालक (टाटा ग्रुप)	5800.00	—	—	—	—	200.00	—	कम्पनी की ऐक पूर्न-स्थापना आधुनिकीकरण तथा विशाखन योजना को वित्तोपोषित करने के लिये।

परिशिष्ट 'ख' (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					गुजरात					
8.	मै० अमरेली सहकारी कृषि खण्ड उद्योग लि० गोवद्का, जिला, अमरेली	सहकारी इकाई	249.95	140.00*	—	—	—	—	—	1,250, टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाले चीनी कारखाने की स्थापना के लिए।
9.	मै० गुजरात पोलियामिड्स लि०, उधाना, जिला सूरत	महामान्य फत्तेसिंह राव पी० गायकवाड़, अध्यक्ष	100.00	50.00	100.00 ज०मा०में	8.00	15.00	—	42.35	1,800 टन वार्षिक की दर से नाइलोन-6 सूती धागे का निर्माण करने के लिए संयन्त्र लगाना।
10.	मै० परिसीजन बियरिंगज इण्डिया लि०, मनेजा, जिला बड़ौदा	श्री के० जी०० कृष्णा-मूर्ति उपाध्यक्ष (तकनीकी) श्री के० एम० एस० वाडिया, उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक)	168.89	85.00	5.61 ज० मा में०	—	—	—	—	23.53 लाख वार्षिक से 28.82 वार्षिक बाल और रोलर बियरिंगों का उत्पादन बढ़ाने के लिए संयन्त्र के विस्तार तथा सन्तुलन हेतु।
					हरियाणा					
11.	मै० एटलस साइकल इंडस्ट्रीज लि०, सोनीपत जिला रोहतक	श्री बी०बी० कपूर तथा श्री जे० डी० कपूर, मुख्य प्रबन्ध अधिकारी	6.45	—	4.15 ज०मा०में० (अति०) 0.43 (पौंड में)	—	—	—	—	साइकलों के पुर्जे बनाने के लिए कुछ पुरानी मशीनें बदलने तथा अर्ध स्वचालित प्रक्रिया को लागू करने के लिए।
12.	मै० वैको इंजीनियरिंग कम्पनी लि०, वल्लभगढ़ जिला गुड़गांव	श्री. जयन्त एच० शाह प्रबंध संचालक (वजाज ग्रुप)	*	—	3.15 ज०मा०में (अति०)	—	—	—	—	पश्चिम जर्मनी से सिलाई करने वाली मशीन के आयात के लिये।
13.	मै० डैल्रोफ्ड्स लि०, राई, सोनीपत के समीप, जिला रोहतक	श्री एम० पी० मित्तल, प्रबन्ध संचालक	36.88	12.00*	—	2.50	1.40	—	—	12 से 15 टन दैनिक की दर से तैयार वनस्पति

14.	मै० एस्कोर्टस ट्रैक्टर्स लि०, फरीदाबाद, जिला गुड़गांव	श्री एच० पी० नन्दा अध्यक्ष	991.82	60.00	63.84 (ज०मा० में)	—	—	—	—	अभिसंस्करण करने के लिए वनस्पति निर्जलीकरण संयंत्र लगाना 6,000 वार्षिक की दर से 46 हार्स पावर के ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए आवश्यक कलपुर्जों तथा सहायक यन्त्रों का प्रतिस्थापन ।
15.	मै० एक्सेल्सियर प्लांटस कारपोरेशन लि०, जिला गुड़गांव	श्री जे० एन० रेना, प्रबन्ध संचालक	—	—	—	2.00@	—	—	—	25 संयन्त्र वार्षिक की दर से यांत्रिक ईंटों तथा मृत्तिकाशिल्प और विशेष प्रकार की टायलें बनाने के लिये कारखाना लगाने हेतु ।
16.	मै० टेलिफुंकन (इण्डिया) लि०, बल्लभगढ़, जिला गुड़गांव	मि० फेलिक्स हेरिगर, अध्यक्ष तथा श्री रवि पी० गुप्ता, प्रबन्ध संचालक	25.00	—	—	2.49*	2.49*	—	—	3 लाख वार्षिक रेडियो उत्पादन बढ़ाने तथा 40,000 वार्षिक दर से रिकार्ड प्लेयरों का निर्माण करने के लिए ।
					केरल					
17.	मै० ट्रैको केबल कम्पनी लि०, इरिम्पनम, जिला एर्नाकुलम (केरल सरकार का उपक्रम)	श्री के०पी० विश्वनाथन् नायर, अध्यक्ष	149.10	£105.00	—	—	—	—	—	1,000 कि मीटर वार्षिक की दर से कागज मढ़ी हुई दूर-संचार तारें बनाने के लिये विशाखन योजना ।

@प्रत्यक्ष अभिदान

*जीवन बीमा निगम द्वारा मंजूर की गई राशि कम कर दी जायेगी ।

परिशिष्ट 'ख' (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				मध्य प्रदेश						
18.	मै०कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, बुरहानपुर, जिला खण्डवा	सहकारी इकाई	110.09	40.00	—	—	—	—	—	12,312 पूरक तकुओं वाले कताई मिल की स्थापना के लिए।
19.	श्री सिन्थेटिक्स लि०, उज्जैन	मै० बंगुर ब्रादर्स लि०, सचिव (बंगुर ग्रुप)	—	—	—	5.00@@	—	—	—	1,100 टन वार्षिक की क्षमता से नाइलोन-6 धागे बनाने के लिए सयन्त्र लगाना।
				महाराष्ट्र						
20.	मै० एन्टीफ्रिकशन बियरिंगज कारपोरेशन लि०, लोनावला, पूना	श्री० सी० सी० देसाई, अध्यक्ष	323.86	100.00	—	—	—	—	—	4.64 लाख वार्षिक से 10 लाख वार्षिक रोलर बियरिंगों का उत्पादन बढ़ाने की विस्तार योजना।
21.	मै० अशोक एस० एस०के० लि०, अशोक नगर, जिला अहमदनगर	सहकारी इकाई	163.90	100.00 (अति०)	—	—	—	—	—	1500 से 2600 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार योजना।
22.	मै० बम्बई मलेबल आयरन कास्टिंगज़ एण्ड अलायड इंडिस्ट्रीज लि०, अम्बेरनाथ, बम्बई	श्री एच० एम० पटेल, अध्यक्ष	20.00	10.00 (अति०)	—	0.60‡	—	—	—	अतिरिक्त यन्त्रों को प्राप्त करने, भूमि खरीदने तथा भवन बनाने तथा कार्यकारी पूंजी के भाग को पूरा करने के लिए।
23.	मै० एम्को ट्रांसफार्मरस लि०, थाना	श्री एच० वी० गांधी, अध्यक्ष	8.00	7.40 (अति०)	—	—	—	—	—	ट्रांसफार्मरों के उत्पादन में उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त यन्त्रों को उपलब्ध करना।

24. मै० एस्ट्रेला बैटरीज लि०, बम्बई	श्री शांति लाल चुन्नी लाल तथा श्री हर्षद चुन्नीलाल, संचालक	179.06	91.62	8.38 (ज०मा० में)	–	–	–	–	700 लाख से 1300 लाख वार्षिक की दर से सूखे सैल बनाने तथा 100 टन वार्षिक की क्षमता से विशेष प्रकार के जैकट बनाने के लिए विस्तार योजना।
25. मै० गंगापुर एस० एस० के० लि०, रघुनाथ नगर, जिला औरंगाबाद	सहकारी इकाई	150.57	74.00	–	–	–	–	–	मै० गंगापुर शुगर मिल्स लि० की 1000 टन की दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली चीनी फैक्टरी खरीदने के लिए।
26. मै० गारवारे नाइलोन्स लि०, पिम्परी, पूना	श्री बी० डी० गारवारे, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक	583.63	–	100.00 (ज०मा० में)	–	–	–	–	756 से 2000 टन वार्षिक दर से नाइलोन-6 तन्तु धागे तथा 330 टन वार्षिक प्लास्टिक की पर्तें बनाने के लिए विस्तार योजना।
27. मै० महेन्द्रा यूगाइन स्टील कम्पनी लि०, खोपोली, जिला कोलाबा	श्री के० रामाचन्द्रन, प्रबन्ध संचालक (महिन्द्रा एण्ड महिंद्रा ग्रुप)	87.00	–	22.00 (ज०मा० में)	–	–	–	–	इस्पात पिघलाने वाली, कूटने वाली, गर्मी पहुंचाकर, तैयार पत्तियां निकालने वाली शाखाओं तथा प्रयोगशाला के कुछ सन्तुलन उपस्कर उपलब्ध करना।

*परियोजना की लागत का गणन पहले किया जा चुका है।

**बाद में मंजूरी रद्द कर दी गई।

@भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के हामीदारी वायदे के अधीन प्रत्यक्ष अभिदान। परियोजना लागत का गणन 1969-70 में किया गया।

†बाद में 55.00 लाख रुपये कम कर दिए गए, क्योंकि 50.00 लाख रुपये का ऋण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देना मंजूर किया।

@@हामीदारी सुविधा के बदले में पहले से मंजूर 50.00 लाख रुपये के ऋण के 10 प्रतिशत का फर्म अभिदान।

‡साधारण शेयरों में प्रत्यक्ष अभिदान।

परिशिष्ट 'ख' (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	मै० पूना इंडस्ट्रियल होटल लि०, पूना।	श्री एस० एल० किर्लोस्कर, अध्यक्ष (किर्लोस्कर ग्रुप)	29.05 (अति व्यय)	15.00 (अति०)	–	–	–	–	–	पूना में चार स्टार होटल लगाने के लिए अति व्यय को पूरा करने के हेतु।
29.	मै० परीमियर सिन्थेटिक प्रोसेसर्ज लि०, थाना, बम्बई	श्री बी० के० झुनझुनवाला, प्रवर्तक संचालक	60.00	33.34	1.66 (ज०मा० में)	5.00	2.00	–	–	8,200 मीटर दैनिक की दर से भरे कृत्रिम बने कपड़े को रंगने के लिए अभिसंस्करण संयन्त्र लगाना।
30.	मै० रूबी मिल्स लि०, बम्बई	श्री एम० सी० शाह, प्रबन्ध संचालक	2.40	–	2.40 ज०मा०में (अति०)	–	–	–	–	कपड़े को बढ़िया बनाने के लिए एक पियरलैस शियरिंग मशीन के आयात हेतु।
31.	मै० श्री दत्ता शेतकारी एस० एस० के० लि०, शिरोल, जिला कोल्हापुर	सहकारी इकाई	250.00	150.00*	–	–	–	–	–	1,250 टन दैनिक गन्ना पेरने के लिए चीनी कारखाना स्थापित करना।
32.	मै० टाटा मरलिन एण्ड जेरिन लि०, थाना, बम्बई	श्री आर० एफ० एस० तल्यारखां, अध्यक्ष (टाटा ग्रुप)	68.21	–	1.99 फा०फा० में	4.42@	–	–	–	66 किलोवाट के ट्रांसफार्मरों का निर्माण करने तथा वर्तमान उत्पादकों के संयन्त्र के संतुलन के लिए विस्तार योजना।
33.	मै० टैक्सटाइल कारपोरेशन आफ मराठवाड़ा लि०, जिला नान्देद	श्री अरविन्द एन० मफतलाल, अध्यक्ष मराठवाड़ा विकास निगम लि० द्वारा प्रवर्तित (पूर्णतः महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम)	383.00	26.63	3.37 ज०मा० में	–	5.00 (प्रत्यक्ष अभिदान)	–	–	नान्देद में विरंजक छपे तथा विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाने के लिए औरंगाबाद, परभानी, नान्देद, भीड़ तथा उस्मानाबाद जिलों की 24 सहकारी समितियों द्वारा 2,304 शक्ति करघे लगाने की योजना चालू करने हेतु।

				मैसूर					
34. मै० दावनगिरि काटन मिल्स लि०, दावनगिरि, जिला चित्रदुर्गा	श्री आर० आर० श्रीनिवासमूर्ति और श्री आर० एल० श्रीनिवास गुप्त, प्रबंध संचालक।	108.21	29.00	6.28 ज०मा०में	–	–	–	–	दावनगिरि इकाई में सूती मानवनिर्मित तथा मिश्रित वस्त्रों के विशाखन के लिए आधुनिकीकरण तथा नवीकरण।
35. श्री दूधगंगा कृष्णा एस० एस० के० नियमित, ननदी, जिला बेलगांव	सहकारी इकाई	260.00	150.00*	–	–	–	–	–	1,250 टन दैनिक की दर से गन्ना पेरने के लिए कारखाना लगाना।
36. मै० एन० जी० ई० एफ० लि०, बंगलौर (मैसूर सरकार का उपक्रम)	श्री सच्चिदानन्द मूर्ति, आई०ए०एस०, प्रबंध, संचालक	275.00	75.00	–	–	–	–	–	प्रतिवर्ष 10,000 सिलोकोन डयोड्स, 1,300 टन ट्रां० फा० पत्तियां, 1,100 टन स्टैम्पिग्ज तथा 600 टन तांबा रेखण बनाने के लिए विशाखन।
				उड़ीसा					
37. मै० अलमोनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, जैपोर, जिला कोरापुट	श्री श्रीपति सिंघानिया, प्रबंध संचालक (जे० के० सिंघानिया ग्रुप)	1650.00	170.00 (अति०)	–	–	–	–	–	15,000 टन वार्षिक की दर से अलमोनियम धातु तथा 7,000 टन वार्षिक की दर से धातु पत्तियां बनाने के लिए संकलित कारखाना लगाना
38. मै० लक्ष्मी आटोसाईकल्स लि०, कोरापुट जिला कोरापुट	श्री ए० विश्वेश्वरराव अध्यक्ष तथा श्री ए० एल० कुमार, प्रस्तावित प्रबंध संचालक	129.74	75.00	–	10.00	–	–	–	50,000 वार्षिक की विस्थापित क्षमता से आटोसाइकलें बनाने के लिए।
39. मै० उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्ज लि०, चौदवार, जिला कटक	श्री प्रताप सिंह, प्रबंध संचालक	24.05	–	24.05 ज०मा०में	–	–	–	–	पश्चिमी जर्मनी से 3 शलाफहोर्स्ट स्वचालित कोन वाइंडर मशीनों का

*परियोजना में जीवन बीमा निगम द्वारा योगदान की राशी कम कर दी जायेगी।
@साधारण शेयरों में अभिदान।

परिशिष्ट 'ख' (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										आयात तथा स्विट-जरलैंड से 5 कम्बिंग मशीनों और संगलकों सहित 4 पिरन वायंडरों का आयात।
				राजस्थान						
40.	मै० दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लि०, कोटा	डा० भरत राम तथा श्री चरत राम, प्रबंध संचालक (श्रीराम ग्रुप)	7.67	–	5.60 ज०मा०में	–	–	–	–	अतिरिक्त पुर्जों अर्थात् अपकेन्द्रित तथा उच्च दाब यन्त्रों के आयात के लिए।
41.	मै० राजस्थान कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा	सहकारी इकाई	121.00	45.50	–	–	–	–	–	12,960 पूरक तकुओं वाले सूती कताई मिल की स्थापना के लिए।
42.	मै० राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि०, भीलवाड़ा	श्री एल० एन० झुनझुनवाला, प्रबन्ध संचालक	50.00	30.00 (अति०)	–	–	–	–	–	कुछ तकुओं को कपास और तन्तु रेशे से कृत्रिम रेशे के उत्पादन के लिए विशाखन योजना तथा वर्तमान फैक्टरी में रेशे तथा धागे रंगने के लिए रंगाई संयन्त्र लगाना।
				तमिलनाडु						
43.	मै० धरंगधरा कैमिकल वर्कस लि०, साहूपुरम, जिला तिरुनेलवेली	श्री श्रीअंश प्रसाद जैन, अध्यक्ष (श्रीअंश प्रसाद जैन ग्रुप)	18.57	–	5.56 ज०मा०में 6.82 फ्रा०फ्रा० में	–	–	–	–	उत्पादन व्यय को कम करने के लिए कुछ वर्तमान यन्त्रों के स्थान पर नये लगानेके लिए उनका आयात।
44.	मै० इनफिल्ड इण्डिया लि०, तिरुवोतियूर, मद्रास	श्री एस० संकरन, प्रबंध संचालक	30.87	30.00 (अति०)	–	–	–	–	–	एक शिफ्ट के आधार पर मोटर साइकलों/स्कूटरों को 11,000 वार्षिक से 16,000 वार्षिक उत्पादन बढ़ाने

									तथा पेन्ट करने एवं पुर्जे जोड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए।
45. श्री मीनाक्षी मिल्स लि०, मदुरई	श्री करुमुथु थियागराजा चेट्टियार, प्रबंध संचालक (थियागराजा ग्रुप)	68.50	55.00	–	–	–	–	–	मिल के कताई भाग–का आधुनिकीकरण।
46. मैं० मैट्टूर कैमिकल एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, मैट्टूरडैम, जिला सेलम	श्री आर० वी० रमानी प्रबंध संचालक (शेषसायी ग्रुप)	32.00	–	7.40 ज०मा०में	–	–	–	–	6,600 टन वार्षिक दर से रेयन स्तर के कास्टिक सोडे के बनाने के विस्तार योजना हेतु कुछ उपस्करों का आयात।
47. मैं० प्लास्टिक रेसिन्ज एण्ड कैमिकल्स लि०, साहूपुरम, जिला तिरुनेलवेली	श्री पी० सी० जैन, अध्यक्ष (श्रीअंश प्रसाद जैन ग्रुप)	210.99 (अति० व्यय)	35.00 (अति०)	–	–	–	–	–	14,000 टन वार्षिक की विस्थापित क्षमता से पी० वी०सी० रेसिन बनाने के लिए योजना के प्रति व्यय के कुछ यन्त्र को पूरा करने हेतु।
48. मैं० शक्ति पाइप्स लि०, इलावुर, मद्रास के पास, जिला चिंगलपुट	श्री ए० वेलिंगिरि, प्रबंध संचालक	40.00	–	–	5.00@	–	–	–	संयन्त्र की क्षमता को पूरा इस्तेमाल करने के लिए दूसरी शिफ्ट लागू करने की योजना।
49. मैं० शक्ति शुगर्स लि०, अपाकुडल, जिला कोयम्बतूर	श्री एन० महालिंगम, प्रबंध संचालक	75.00	37.00	–	–	–	–	–	20 लाख गैलन वार्षिक की दर से औद्योगिक अलकोहल बनाने के लिए आसवनीलगाना।
50. मैं० सेलम कोपरेटिव शुगर सेल्स लि०, मोहानूर, जिला सेलम	सहकारी इकाई	130.24	40.00 (अति०)	–	–	–	–	–	1,000 टन से 1,750 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार योजना।
				उत्तर प्रदेश					
51. मैं० जैन शुद्ध वनस्पति लि०, गाजियाबाद, जिला मेरठ	स/श्री आर० एन० जैन, जे० आर० जैन, एस० आर० जैन तथा एन० एल० जैन, प्रवर्तक	113.00	25.00	–	4.00	3.00	–	–	15,000 टन वार्षिक की दर से वनस्पति बनाने के लिए कारखाना लगाना।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	मै० जे० के० सातोह एग्री-कलचरल मशीन्ज लि०, सानचेंदी गांव जिला कानपुर	श्री पद्मपत सिंघानिया, अध्यक्ष (जे० के० सिंघानिया ग्रुप)	170.00	80.00	–	5.00	5.00	–	–	6,000 वार्षिक की दर से पावर टिलरों हैंड ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए कारखान लगाना
	@प्रत्यक्ष अभिदान	आगे ले जाया गया	17588.45	2386.49	372.69	106.51	46.39	200.00	42.35	
53.	मै० मोदी स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि०, मोदी नगर, जिला मेरठ	श्री जी० एम० मोदी, श्री के० एन० मोदी तथा चार अन्य संचालकों की प्रबंध समिति (मोदी ग्रुप)	5.83	–	0.92 जा०मा० में 4.91 (पौंड में)	–	–	–	–	कम्पनी के उत्पादन के अधिक भाग को सिलाई धागे से पक्के सिलाई धागे में बदलने के लिए कुछ सन्तुलन उपस्करों का आत।
54.	मै०राठी अलायज्ञ एण्ड स्टील लि०, गाजियाबाद, जिला मेरठ	श्री सी० आर० राटी, प्रस्तावित प्रबन्ध संचालक	75.50	39.50 –	–	1.50	5.75	–	–	20,000 टन वार्षिक की क्षमता से नरम इस्पात सिल्लियां तथा लोचदार इस्पात सिल्लियां बनाने के लिए कारखाना लगाना।
55.	मै० स्टार पेपर मिल्स लि०, सहारनपुर	श्री वी० पी० बजोरिया प्रबंध संचालक	171.04	–	51.05 जा०मा० में अति० 16.17 (पौंड में)	–	–	–	–	8,106 टन से 8,691 टन वार्षिक की दर से एम० एफ० लिखने तथा छपाई करने वाले कागज और 25,100 टन से 30,170 टन वार्षिक एम०जी० क्राफ्ट कागज का केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित तीव्र कार्यक्रम के अधीन उत्पादन करने की विस्तार योजना।

56. मै० स्वदेशी पोलिटेक्स लि०, गाजियाबाद, जिला मेरठ	श्री सीताराम जैपुरिया, संसद सदस्य, अध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक (जैपुरिया ग्रुप)	1098.88	50.00	100.00 जा०मा०में	20.00	–	–	–	6,100 टन वार्षिक की दर से पोलेस्टर रेशे का उत्पादन करने के लिए संयन्त्र लगाना।
57. मै० उत्तर प्रदेश स्टील्ज़ लि०, मुजफ्फर नगर	श्री ब्रह्म स्वरूप, अध्यक्ष	21.40	6.74 (अति०)	14.66	–	–	–	–	3 टन वाली भट्टी को उपलब्ध करना तथा लगाना।
			पश्चिमी बंगाल						
58. मै० अण्डमान टिम्बर इंड-स्ट्रीज़ लि०, (i) गनीपुर, जिला 24 परगना (ii) बम्बू फ्लैट, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अण्डमान	श्री बी० के० खैतान और ए० के० बोस, प्रबंध संचालक	10.00	10.00 (अति०)	–	–	–	–	–	कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर की फैक्टरियों में कुछ सन्तुलन सहायक उपकरणों को उपलब्ध करना तथा लगाना।
59. मै० गौंटरमैन पाइपर्ज (इण्डिया) लि०, डाकखाना अमगचिया, जिला 24 परगना	श्री एच० के० नाथानी, श्री डब्ल्यू० लोज, प्रबन्ध सचालक	18.14	7.50 (अति०)	–	–	–	–	–	3,000 टन से 3,600 टन वार्षिक दर से इस्पात चादरों के बनाने के लिए सन्तुलन उपकरणों का उपलब्ध करना।
60. मै० खास कजोरा कोल कम्पनी लि०, रानीगंज, जिला बर्दवान	श्री सीताराम बेरी-वाला और श्री जगन्नाथ बेरीवाला, प्रबंध संचालक	16.12	12.00 (अति०)	–	–	–	–	–	3.60 लाख टन से 5 लाख टन खानों से कोयला निकालने की क्षमता बढ़ाना।
61. मै० परसिया कोलरीज़ लि०, रानीगंज, जिला बर्दवान	श्री बी० एन० पोद्दार तथा श्री बी० के० पोद्दार, संयुक्त प्रबंध संचालक	31.82	20.00 (अति०)	–	–	–	–	–	कम्पनी को दिये गए 6 लाख टन वार्षिक की लाइ-सेंस क्षमता तक कोयला निकालने हेतु।
तीन कम्पनियों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा उप-ऋणों से रुपया ऋणों में परिवर्तन तथा पहले से मंजूर एक जर्मन मार्क उप-ऋण में वृद्धि के कारण अन्तर		–	16.28	0.70	–	–	–	–	
	कुल जोड़	19042.18	2548.51	561.10	128.01	52.14	200.00	42.35	

परिशिष्ट 'ग' (i)

30 जून, 1971 तक (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों के समायोजन के बाद) समस्त आर्थिक कार्यकलापों के अन्तर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकर के अनुसार विभिन्न प्रकार के उद्योग के लिए मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का विश्लेषण

(रुपये, लाखों में)

उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	रकम				
		ऋण	हामीदारियां	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	कुल का प्रतिशत
खाद्य निर्माण उद्योग, सिवाय पेय उद्योगों के —चीनी						
(i) चीनी	92	7219.89	49.00	—	7268.89	19.9
(ii) फलों तथा वनस्पति का परिरक्षण तथा डिब्बा बन्दी	1	—	3.90	—	3.90	—
सूती वस्त्र निर्माण —कताई, बूनाई और सूती वस्त्रों की फिनिशिंग	92	3632.67	197.50	278.21	4108.38	11.2
सूती वस्त्र निर्माण,—कताई, बुनाई और पटसन उत्पादन की फिनिशिंग	14	564.31	—	—	564.31	1.5
कृत्रिम रेशों का निर्माण	13	992.18	96.25	42.35	1130.78	3.1
काठ और कार्क निर्माण, सिवाय फर्नीचर निर्माण के	5	188.43	7.00	—	195.43	0.5
कागज और कागज उत्पादों का निर्माण	26	1603.07	159.07	551.16	2313.30	6.3
रबड़ उत्पादों का निर्माण	8	779.74	27.00	280.13	1086.87	3.0
मूल औद्योगिक रसायनों का निर्माण	17	1410.30	42.75	176.03	1629.08	4.5
उर्वरकों का निर्माण	6	760.60	224.43	1278.86	2263.89	6.2
विविध रसायनिक उत्पादों का निर्माण	22	1095.23	221.35	245.72	1562.30	4.3
वनस्पति और पशुजन्य तेल तथा स्नेहों का निर्माण	4	70.00	7.00	—	77.00	0.2
कांच और कांच उत्पादों का निर्माण	10	289.71	15.00	—	304.71	0.8
चीनी मिट्टी और अन्य प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का निर्माण	12	438.33	23.00	—	461.33	1.3
सीमेंट का निर्माण	26	1660.16	210.89	18.54	1889.59	5.2
मूल धातु उद्योग :—						
(i) लोहा और इस्पात	7	512.59	297.25	—	809.84	2.2
(ii) अलौह धातुएं	10	909.97	295.00	1945.65	3150.62	8.6
धातु उत्पादों का निर्माण, सिवाय मशीनरी और परिवहन उपस्कर के	53	1847.63	426.60	130.26	2404.49	6.6
मशीनरी का निर्माण, सिवाय बिजली मशीनरी के	21	1023·70	79·70	105·01	1208·41	3·3
बिजली की मशीनरी, उपस्करों, औजारों और पूर्ति साधनों का निर्माण	33	1168·17	140·24	—	1308.41	3.6
रेल-सड़क उपस्कर का निर्माण	3	72.25	1.50	—	73.75	0.2
मोटर गाड़ियों और उनके कल पुर्जो कर निर्माण	19	1020.17	200.00	26.95	1247.12	3.4
बाइसिकलों का निर्माण	3	189.63	—	—	189.63	0.5
बिजली, गैस और भाप, जल और सफाई सेवायें :—						
(i) बिजली प्रकाश और शक्ति : जनन, संचरण और वितरण	5	43.00	50.00	—	93.00	0.3
(ii) गैस निर्माण और वितरण	4	136.95	8.00	21.05	166.00	0.5
खनन और खदान उद्योग :—						
(i) कोयला	3	122.00	—	—	122.00	0.3
(ii) पत्थर के खदान-खनिज	1	—	10.00	—	10.00	—
(iii) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	1	—	350.00	—	350.00	0.9
होटल उद्योग	5	268.12	7.00,	93.00	368.12	1.0
विविध निर्माण उद्योग	11	206.17	—	—	206.17	0.6
जोड़	527	28224.97	3149.43	5192.92	36567.32	100.0

परिशिष्ट 'ग' (ii)

(रुपये, लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	इकाइयों की कुल संख्या	रकम				कुल का प्रतिशत
		ऋण	हामीदारीयां	मशीनरी की आस्थगित आदागियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	
आन्ध्र प्रदेश	32	1484.42	174.82	925.82	8255.06	7.1
असम	6	301.79	350.00	—	651.79	1.8
बिहार	25	1529.86	363.00	329.75	2222.61	6.1
गुजरात	42	2319.29	171.32	127.30	2617.91	7.2
हरियाणा	22	901.63	69.38	20.08	991.09	2.7
केरल	16	1041.95	19.50	172.47	1233.92	3.4
मध्य प्रदेश	15	657.82	223.25	39.82	920.89	2.5
महाराष्ट्र	113	6417·02	558.28	375.93	7351.23	20.1
मेघालय	1	95.00.	—	—	95.00	0.3
मैसूर	37	1797.99	195.50	221·52	2215.01	6.1
उड़ीसा	16	1020·17	95·00	—	1115·17	3·0
पंजाब	11	660.20	—	9.96	670.16	1.8
राजस्थान	13	830.64	15.50	757.35	1603.49	4.4
तमिलनाडु	61	3301.49	410.38	1238.50	4950.37	13.5
उत्तर प्रदेश	39	2381.53	196.25	322.31	2900.09	7·9
पश्चिमी बंगाल	71	3233.55	217.50	546.65	3997.70	10.9
दिल्ली	4	187.62	14.75	97.30	299.67	0.8
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	11.00	—	—	11.00	—
गोआ	1	—	75.00	—	75.00	0.2
पांडेचेरी	1	52.00	—	8.16	60.16	0.2
जोड़	527	28224.97	3149.43	5192.92	36567.32	100.0

परिशिष्ट 'घ'

30 जून, 1971 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का धनराशि के अनुसार वर्गीकरण

(प्रत्येक औद्योगिक संस्था के लिये मंजूर की गई रकमों के अनुसार)

(रुपये, लाखों में)

	सहकारी		पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां					जोड़				
	संस्थाओं की संख्या	ऋण	संस्थाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिये गारंटियां	जोड़	संस्थाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिये गारंटियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. रकमें, जो दस लाख रु० से अधिक न हों।	—	—	70	222.17	205.04	—	427.21	70	222.17	205.04	—	427.21
2. रकमें, जो 10 लाख रु० से अधिक पर 20 लाख रु० अधिक न हों।	—	—	48	539.61	209.38	—	748.99	48	539.61	209.38	—	748.99
3. रकमें जो 20 लाख रु० से अधिक पर 30 लाख रु० से अधिक न हों।	3	75.20	43	874.93	218.20	4.71	1097.84	46	950.13	218.20	4.71	1173.04
4. रकमें, जो 30 लाख रु० से अधिक पर 40 लाख रु० से अधिक न हों।	16	592.50	43	1293.71	219.25	43.32	1556.28	59	1886.21	219.25	43.32	2148.78

5. रकमें, जो 40 लाख रु० से अधिक पर 50 लाख रु० से अधिक न हों ।	6	275.00	41	1593.81	260.15	38.68	1892.64	47	1868.81	260.15	38.68	2167.64
6. रकमें, जो 50 लाख रु० से अधिक पर 60 लाख रु० से अधिक न हों ।	7	399.75	16	853.40	34.00	—	887.40	23	1253.15	34.00	—	1287.15
7. रकमें, जो 60 लाख रु० से अधिक पर 70 लाख रु० से अधिक न हों ।	6	388.00	18	1096.74	19.00	58.75	1174.49	24	1484.74	19.00	58.75	1562.49
8. रकमें, जो 70 लाख रु० से अधिक पर 80 लाख रु० से अधिक न हों ।	12	930.00	16	918.23	198.85	82.94	1200.02	28	1848.23	198.85	82.94	2130.02
9. रकमें, जो 80 लाख रु० से अधिक पर 90 लाख रु० से अधिक न हों ।	30	2653.31	11	895.34	62.50	—	957.84	41	3548.65	62.50	—	3611.15
10. रकमें, जो 90 लाख रु० से अधिक पर एक करोड़ रु० से अधिक न हो ।	2	192.00	9	839.20	21.00	10.60	870.80	11	1031.20	21.00	10.60	1062.80
11. रकमें, जो एक करोड़ रु० से अधिक हों ।	16	2224.89	75	11367.18	1702.06	4953.92	18023.16	91	13592.07	1702.06	4953.92	20248.05
	98	7730.65	390	20494.32	3149.43	5192.92	28836.67	188	28224.97	3149.43	5192.92	36567.32

परिशिष्ट 'ङ'

30 जून, 1971 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई निवल आर्थिक सहायता के उद्योगवार वितरण का विवरण

(क) ऋणों का बोधक है।
(ख) हामीदारियों का बोधक है।
(ग) मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों की गारंटियों का बोधक है।

(रुपये लाखों में)

उद्योग का प्रकार		आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरियाणा	केरल	मध्य प्रदेश	मेघालय	महाराष्ट्र	मैसूर
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
खाद्य निर्माण उद्योग,	(क)	785.00	60.00	186.50	405.50	106.00	180.00	80.00	—	2899.70	756.75
सिवाय पेय उद्योगों के—	(ख)	—	—	5.00	—	—	—	—	—	—	—
चीनी											
		785.00	60.00	191.50	405.50	106.00	180.00	80.00	—	2899.70	756.75
फलों और वनस्पति का डिब्बाबन्दी व परीरक्षण	(ख)	—	—	—	—	3.90	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	3.90	—	—	—	—	—
वस्त्र निर्माण—वस्त्रों की कताई,	(क)	236.07	26.17	84.70	513.13	141.13	27.50	252.14	—	507.61	245.57
बुनाई और फिनिशिंग	(ख)	27.50	—	8.00	3.00	7.50	2.50	12.00	—	5.00	30.00
	(ग)	6.87	—	—	—	10.60	11.68	39.82	—	—	39.52
		270.44	26.17	92.70	526.13	159.23	41.68	303.96	—	512.61	315.09
वस्त्र निर्माण—पटसन उत्पादों की कताई-बुनाई और फिनिशिंग	(क)	—	78.50	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	78.50	—	—	—	—	—	—	—	—

उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	दिल्ली	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	पांडीचेरी	गोआ	जोड़	इकाइयों की संख्या
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	
175.00	315.00	80.00	750.44	440.00	–	–	–	–	–	7219.89	
–	–	–	44.00	–	–	–	–	–	–	49.00	
175.00	315.00	80.00	794.44	440.00	–	–	–	–	–	7268.89	92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.90	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.90	1
120.48	148.89	219.50	373.00	433.33	216.45	35.00	–	52.00	–	3632.67	
5.00	–	7.50	45.00	15.00	19.50	–	–	–	–	197.50	
–	9.96	–	24.99	122.31	–	4.30	–	8.16	–	378.21	
125.48	158.85	227.00	442.99	570.64	235.95	39.30	–	60.16	–	4108.38	92
–	–	–	–	–	485.81	–	–	–	–	564.31	
–	–	–	–	–	485.81	–	–	–	–	564.31	14

परिशिष्ट 'ड जारी

30 जून, 1971 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम मंजूर की गई निवल आर्थिक सहायता के ऊद्योगवार वितरण का विवरण

(क) ऋणों का बोधक है ।
(ख) हामीदारीयों का बोधक है ।
(ग) मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों का बोधक है ।

(रुपये, लाखों में)

उद्योग का प्रकार		आन्ध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरियाणा	केरल	मध्य प्रदेश	मेघलय	महाराष्ट्र	मैसूर
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कृत्रिम रेशों का निर्माण	(क)	—	—	—	443.40	—	24.93	50.00	—	185.00	—
	(ख)	—	—	—	23.00	—	—	46.25	—	7.00	—
	(ग)	—	—	—	42.35	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	508.35	—	24.93	96.25	—	192.00	—
काठ और कार्क का निर्माण सिवाय फर्नीचर निर्माण के	(क)	—	100.74	—	—	—	56.69	—	—	—	—
	(ख)	—	—	—	7.00	—	—	—	—	—	—
		—	100.74	—	7.00	—	56.69	—	—	—	—
कागज और कागज से बनी चीजों का निर्माण	(क)	110.98	—	218.76	58.97	—	40.00	—	—	122.83	417.85
	(ख)	15.00	—	—	46.57	—	--	—	—	22.50	—
	(ग)	—	—	311.21	57.95	—	—	—	—	—	182.00
		125.98	—	529.97	163.49	—	40.00	—	—	145.33	599.85
रबर उत्पादों का निर्माण	(क)	—	—	—	—	—	31.33	—	—	104.00	—
	(ख)	—	—	—	—	—	2.00	—	—	—	—
	(ग)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	33.33	—	—	104.00	—

उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तामिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	दिल्ली	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	पांडीचेरी	गोआ	जोड़	इकाइयों की संख्या
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	
–	–	55.80	–	233.45	–	–	–	–	–	992.18	
–	–	–	–	20.00	–	–	–	–	–	96.25	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.35	
–	–	55.80	–	253.45	–	–	–	–	–	1130.78	13
–	–	–	–	–	20.00	–	11.00	–	–	188.43	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.00	
–	–	–	–	–	20.00	–	11.00	–	–	195.43	5
128.65	–	–	–	256.12	248.91	–	–	–	–	1603.07	
50.00	–	–	–	5.00	20.00	–	–	–	–	159.07	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551.16	
178.65	–	–	–	261.12	268.91	–	–	–	–	2313.30	26
–	–	–	277.99	53.34	313.08	–	–	–	–	779.74	
–	–	–	–	5.00	20.00	–	–	–	–	27.00	
–	–	–	28.35	–	251.78	–	–	–	–	280.13	
–	–	–	306.34	58.34	584.86	–	–	–	–	1086.87	8
479.13	373.85	362.80	1543.77	1583.55	1595.53	39.30	11.00	60.16	–	16671.86	251

परिशिष्ट 'ङ' (जारी)

30 जून, 1971 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई निवल आर्थिक सहायता के उद्योगवार वितरण का विवरण—जारी

(क) ऋणों का बोधक है।

(ख) हामीदारियों का बोधक है।

(ग) मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों की गारंटियों का बोधक है।

(रुपये, लाखों में)

उद्योग का प्रकार		आन्ध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरियाणा	केरल	मध्य प्रदेश	मेघालय	महाराष्ट्र	मैसूर
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
उर्वरक का निर्माण	(क)	—	—	—	200.00	—	306.00	—	—	—	—
	(ख)	84.43	—	—	20.00	—	—	—	—	—	—
	(ग)	878.86	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		963.29	—	—	220.00	—	306.00	—	—	—	—
मूल औद्योगिक रसायनों का निर्माण	(क)	140.00	36.38	—	214.66	—	—	—	—	111.71	—
	(ख)	—	—	—	6.25	—	—	—	—	6.50	5.00
	(ग)	40.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		180.09	36.38	—	220.91	—	—	—	—	118.21	5.00
वनस्पति और पशुजन्य तेल और स्नेहों का निर्माण	(क)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.50
	(ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.50
विविध रसायनिक उत्पादों का निर्माण	(क)	137.24	—	—	10.64	—	74.50	17.38	—	478.84	10.08
	(ख)	25.00	—	—	—	—	—	5.00	—	131.85	15.00
	(ग)	—	—	—	—	—	—	—	—	245.72	—
		162.24	—	—	10.64	—	74.50	22.38	—	856.41	25.08
कांच और कांच उत्पादों का निर्माण	(क)	20.00	—	84.93	3.79	—	5.00	—	—	33.83	1.50
	(ख)	5.00	—	—	—	—	—	—	—	10.00	—
		25.00	—	84.93	3.79	—	5.00	—	—	43.83	1.50

उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	दिल्ली	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	पांडीचेरी	गोआ	जोड़	इकाइयों की संख्या
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	
–	–	54.60	–	200.00	–	–	–	–	–	760.60	
–	–	–	–	45.00	–	–	–	–	75.00	224.43	–
–	–	200.00	–	200.00	–	–	–	–	–	1278.86	
–	–	254.60	–	445.00	–	–	–	–	75.00	2263.89	6
14.29	–	–	600.96	195.09	97.21	–	–	–	–	1410.30	
15.00	–	–	5.00	5.00	–	–	–	–	–	42.75	
–	–	–	100.08	–	35.86	–	–	–	–	176.03	
29.29	–	–	706.04	200.09	133.07	–	–	–	–	1629.08	17
–	–	–	–	27.50	–	–	–	–	–	70.00	
–	–	–	–	7.00	–	–	–	–	–	7.00	
–	–	–	–	34.50	–	–	–	–	–	77.00	4
–	–	–	123.67	39.75	203.13	–	–	–	–	1095.23	
–	–	–	27.00	12.50	5.00	–	–	–	–	221.35	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	245.72	
–	–	–	150.67	52.25	208.13	–	–	–	–	1562.30	22
–	–	–	–	20.65	120.01	–	–	–	–	289.71	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15.00	
–	–	–	–	20.65	120.01	–	–	–	–	304.71	10

परिशिष्ट 'ङ' (जारी)

30 जून, 1971 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम मंजूर की गई निवल आर्थिक सहायता के उद्योगवार वितरण का विवरण

(क) ऋणों का बोधक है।
(ख) हामीदरियों का बोधक है।
(ग) मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों की गारंटियों का बोधक है।

(रुपये, लाखों में)

उद्योग का प्रकार		आन्ध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरियाणा	केरल	मध्य प्रदेश	मेघालय	महाराष्ट्र	मैसूर
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		रु.	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
चीनी मिट्टी और अन्य प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का निर्माण	(क)	–	–	162.75	–	86.98	–	–	–	6.00	2.85
	(ख)	–	–	5.00	–	15.00	–	–	–	–	–
		–	–	167.75	–	101.98	–	–	–	6.00	2.85
सीमेंट का निर्माण	(क)	37.00	–	406.22	112.30	–	–	219.59	95.00	20.00	–
	(ख)	2.89	–	5.00	30.00	–	–	110.00	–	5.00	8.00
	(ग)	–	–	18.54	–	–	–	–	–	–	–
		39.89	–	429.76	142.30	–	–	329.59	95.00	25.00	8.00
मूल धातु उद्योग—लोहा	(क)	–	–	150.00	–	–	–	–	–	270.09	–
	(ख)	–	–	260.00	–	–	–	–	–	15.00	–
		–	–	410.00	–	–	–	–	–	285.09	–
अलौह धातुएं	(क)	–	–	–	–	–	134.00	–	–	63.69	90.00
	(ख)	–	–	–	–	–	10.00	–	–	–	125.00
	(ग)	–	–	–	–	–	160.79	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	304.79	–	–	63.69	215.00
धातु उत्पादों का निर्माण सिवाय मशीनरी परिवहन उपस्कर के	(क)	–	–	159.00	155.61	182.67	–	38.71	–	510.58	–
	(ख)	15.00	–	20.00	2.00	23.50	–	50.00	–	158.10	–
	(ग)	–	–	–	27.00	–	–	–	–	103.26	–
		15.00	–	179.00	184.61	206.17	–	88.71	–	771.94	–
मशीनरी का निर्माण सिवाय बिजली मशीनरी के	(क)	–	–	–	67.07	71.36	–	–	–	282.08	53.00
	(ख)	–	–	–	7.00	7.00	–	–	–	5.70	7.50
	(ग)	–	–	–	–	9.48	–	–	–	–	–
		–	–	–	74.07	87.84	–	–	–	287.78	60.50

उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	दिल्ली	अडंमान व निकोबार द्वीपसमूह	पांडीचेरी	गोआ	जोड़	इकाइयों की संख्या
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
56.75	—	—	—	—	123.00	—	—	—	—	438.33	
—	—	—	3.00	—	—	—	—	—	—	23.00	
56.75	—	—	3.00	—	123.00	—	—	—	—	461.33	12
100.00	—	125.00	545.05	—	—	—	—	—	—	1660.16	
—	—	—	50.00	—	—	—	—	—	—	210.89	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.54	
100.00	—	125.00	595.05	—	—	—	—	—	—	1889.59	26
53.00	—	—	—	39.50	—	—	—	—	—	512.59	
15.00	—	—	—	7.25	—	—	—	—	—	297.25	
68.00	—	—	—	46.75	—	—	—	—	—	809.84	7
170.00	—	111.00	100.00	—	241.28	—	—	—	—	909.97	
—	—	—	120.00	40.00	—	—	—	—	—	295.00	
—	—	557.35	968.50	—	259.01	—	—	—	—	1945.65	
170.00	—	668.50	1188.50	40.00	500.29	—	—	—	—	3150.62	10
127.00	—	—	169.19	135.33	369.54	—	—	—	—	1847.63	
—	—	—	27.00	20.50	110.50	—	—	—	—	426.60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.26	
127.00	—	—	196.19	155.83	480.04	—	—	—	—	2404.49	53
—	—	—	93.72	120.00	336.47	—	—	—	—	1023.70	
—	—	—	22.50	10.00	20.00	—	—	—	—	79·70	
—	—	—	95.53	—		—	—	—	—	105.01	
—	—	—	211.75	130.00	356·47	—	—	—	—	1208·41	21

परिशिष्ट 'ङ'——जारी

30 जून, 1971 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई निवल आर्थिक सहायता के उद्योगवार वितरण का विवरण—जारी

(क) ऋणों का बोधक है।
(ख) हामीदारियों का बोधक है।
(ग) मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों की गारंटियों का बोधक है।

(रुपये लाखों में)

उद्योग का प्रकार		आन्ध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरियाणा	केरल	प्रदेश मध्य	मेघालय	महाराष्ट्र	मैसूर
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
बिजली की मशीनरी, उपस्करों, औजारों और पूर्ती साधनों का निर्माण	(क)	–	–	12.00	92.37	65.00	162.00	–	–	322.45	165.39
	(ख)	–	–	–	15.00	12.48	5.00	–	–	48.63	5.00
		–	–	12.00	107.37	77.48	167.00	–	–	371.08	170.39
रेल-सड़क उपस्कर का निर्माण	(क)	–	–	15.00	2.25	–	–	–	–	–	–
	(ख)	–	–	–	1.50	–	–	–	–	–	–
		–	–	15.00	3.75	–	–	–	–	–	–
मोटरगाड़ियों और उनके कल-पुर्जों का निर्माण	(क)	11.79	–	–	–	188.06	–	–	–	352.01	2.50
	(ख)	–	–	50.00	–	–	–	–	–	90.00	–
	(ग)	–	–	–	–	–	–	–	–	26.95	–
		11.79	–	50.00	–	188.06	–	–	–	468.96	2.50
साइकलों का निर्माण	(क)	–	–	–	–	50.43	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	50.43	–	–	–	–	–
विविध उद्योग	(क)	6.34	–	–	–	10.00	–	–	–	64.10	10.00
		6.34	–	–	–	10.00	–	–	–	64.10	10.00
बिजली, गैस, जल और स्वास्थ्य सेवाएं :											
—बिजली उत्पादन और शक्ति उत्पादन, संचरण और वितरण	(क)	–	–	–	40.00	–	–	–	–	–	–
	(ख)	–	–	–	–	–	–	–	–	50.00	–
		–	–	–	40.00	–	–	–	–	50.00	–

उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	दिल्ली	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	पांडीचेरी	गोवा	जोड़	इकाइयों की संख्या
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	
–	62.59	184.74	12.00	–	59.63	30.00	–	–	–	1168.17	
–	–	8.00	28.88	–	2.50	14.75	–	–	–	140.24	
–	62.59	192.74	40.88	–	62.13	44.75	–	–	–	1308.41	33
–	–	–	–	–	55.00	–	–	–	–	72.25	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.50	
–	–	–	–	–	55.00	–	–	–	–	73.75	3
75.00	133.72	–	124.34	101.93	30.82	–	–	–	–	1020.17	
10.00	–	–	30.00	–	20.00	–	–	–	–	200.00	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.95	
85.00	133.72	–	154.34	101.93	50.82	–	–	–	–	1247.12	19
–	–	–	–	–	139.20	–	–	–	–	189.63	
–	–	–	–	–	139.20	–	–	–	–	189.63	3
–	–	–	98.63	5.10	12.00	–	–	–	–	206.17	
–	–	–	98.63	5.10	12.00	–	–	–	–	207.17	11
–	–	–	–	–	3.00	–	–	–	–	43.00	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.00	
–	–	–	–	–	3.00	–	–	–	–	93.00	5

परिशिष्ट 'ङ'--(जारी)

30 जून, 1971 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई निवल आर्थिक सहायता के उद्योगवार वितरण का विवरण—जारी

(क) ऋणों का बोधक है ।
(ख) हामीदारियों का बोधक है ।
(ग) मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों की गारंटियों का बोधक है ।

(रुपये लाखों में)

उद्योग का प्रकार		आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरियाणा	केरल	मध्य प्रदेश	मेघालय	महाराष्ट्र	मैसूर
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिजली, गैस, जल और स्वास्थ्य सेवाएं :											
—गैस निर्माण और वितरण	(क)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(ख)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(ग)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
खनन और खदान--कोयला	(क)	–	–	50.00	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	50.00	–	–	–	–	–	–	–
पत्थर की खदान खनिज	(ख)	–	–	10.00	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	10.00	–	–	–	–	–	–	–
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	(ख)	–	350.00	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	350.00	–	–	–	–	–	–	–	–
होटल उद्योग	(क)	–	–	–	–	–	–	–	–	82.50	–
	(ख)	–	–	–	–	–	–	–	–	3.00	–
	(ग)	–	–	–	–	–	–	–	–		–
		–	–	–	–	–	–	–	–	85.50	–
	(क)	1484.42	301.79	1529.86	2319.29	901.63	1041.95	657.82	95.00	6417.02	1797.99
	(ख)	174.82	350.00	363.00	171.32	69.38	19.50	223.25	–	558.28	195.50
	(ग)	925.82	–	329.75	127.30	20.08	172.47	39.82	–	375.93	221.52
जोड़		2585.06	651.79	2222.61	2617.91	991.09	1233.92	920.89	95.00	7351.23	2215.01
राज्यवार इकाइयों की संख्या		(32)	(6)	(25)	(42)	(22)	(16)	(15)	(1)	(113)	(37)

उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	दिल्ली	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	पांडीचेरी	गोआ	जोड़	इकाइयों की संख्या
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	
–	–	–	5.00	44.94	87.01	–	–	–	–	136.95	
–	–	–	4.00	4.00	–	–	–	–	–	8.00	
–	–	–	21.05	–	–	–	–	–	–	21.50	
–	–	–	30.05	48.94	87.01	–	–	–	–	166.00	4
–	–	–	–	–	72.00	–	–	–	–	122.00	
–	–	–	–	–	72.00	–	–	–	–	122.00	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.00	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.00	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	350.00	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	350.00	1
–	–	–	27.50	35.50	–	122.62	–	–	–	268.12	
–	–	–	4.00	–	–	–	–	–	–	7.00	
–	–	–	–	–	–	93.00	–	–	–	93.00	
–	–	–	31.50	35.50	–	215.62	–	–	–	368.62	5
1020.17	660.20	830.64	3301.49	2381.53	3233.55	187.62	11.00	52.00	–	28224.97	
95.00	–	15.50	410.38	196.25	217.50	14.75	–	–	75.00	3149.43	
–	9.96	757.35	1238.50	322.31	546.65	97.30	–	8.16	–	5192.92	
1115.17	670.16	1603.49	4950.37	2900.09	3997.70	299.67	11.00	60.16	75.00	36567.32	527
(16)	(11)	(13)	(61)	(39)	(71)	(4)	(1)	(1)	(1)	(527)	

परिशिष्ट 'च'

वर्ष 1970 के दौरान देश के चुने हुए उद्योगों की कुल संस्थापित क्षमता और औद्योगिक उत्पादन तथा उसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त औद्योगिक संस्थाओं का योगदान

उद्योग	उत्पादन इकाई	सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में			भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त औद्योगिक संस्थाओं के सम्बन्ध में		
		औद्योगिक संस्थाओं की संख्या	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	औद्योगिक संस्थाओं की संख्या	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. रसायन और रसायान उत्पाद							
—स्लफ्यूरिक एसिड	हजार टन में	67	1,930	1,199	7	410	273
—कास्टिक सोडा	"	28	367	357	7	134	137
—सोडा एश	"	4	471	446	2	255	251
—ब्लीचिंग, पाउडर	"	3	21	15	2	14	6
—क्लोरिन तरल	"	22	222	147	7	80	58
—फिनायल	"	3	18	10	1	10	8
—अटाडीन	"	1	7	4	1	7	4
—एसीटोन	"	4	19	8	2	17	5
—डाई-एसीटोन तरल	"	2	5	3	2	5	3
2. उर्वरक							
(क) नाइट्रोजन उर्वरक	"	13	978	631	3	290	187
—अमोनियम सल्फेट	"	2	96	34	1	16	9
—अमोनियम क्लोराइड	"	2	186	73	1	112	52
—अमोनियम फास्फेट	"	28	1,300	620	3	84	66
(ख) फास्फेटीय उर्वरक							
—सुपर फासफेट	"	50	17,360	14,034	10	10,690	8,526
3. सीमेंट	"	57	768	753	12	350	342
4. कागज और कागज बोर्ड							
5. रबर							
—आटोमोबाइल टायर	संख्या हजारों में	8	3,482	2,974	3	900	933
—अटोमोबाइल ट्यूब	"	8	3,482	2,663	3	900	906
—साइकल टायर	"	11	21,296	20,988	1	5,000	4,441
—साइकल ट्यूब	"	11	21,296	15,841	1	5,000	4,441
—औद्योगिक वी० बैल्ट और पंखों के पट्टे	"	6	3,850	1,400	1	960	1,091

6. इस्पात की ढलवां वस्तुएं	हजार टनों में	43	129	45	3	18	9
—इस्पात ट्यूब और नल	"	15	510	242	4	266	85
—बाल और रोलर बियरिंग	संख्या लाखों में	7	159	175	1	18	16
7. रिफ्रेक्ट्रियां	हजार टनों में	43	1,080	661	4	162	116
—सफाई भांड (सैनीटरी वेअर्स)	"	13	18	13	2	5	5
8. मशीनरी							
—शक्ति टिलर्स	संख्या इकाई में	1	3,000	327	1	3,000	327
—सिलाई मशीनें	संख्या हजारों में	5	493	178	1	300	152
—चाय उद्योग मशीनरी	मूल्य लाख रुपये में	6	230	140	1	48	43
—चीनी मिलों की मशीनरी	"	16	2,100	1,376	2	855	431
—औद्योगिक स्क्रीनें	"	6	226	85	1	41	41
9. बिजली की मशीनरी और सामान							
—बिजली की मोटरें	अश्वशक्ति हजारों में	20	2,569	3,194	2	425	577
—बिजली के पंखे	संख्या हजारों में	16	1,816	1,624	1	600	512
—बिजली के ट्रांसफारमर	किलोवाट एम्पियर हजारों में	23	6,265	7,518	2	1,000	900
—घरेलू प्रयोग के मीटर	संख्या हजारों में	8	1,905	2,057	2	915	669
10. रीमर	"	14	208	187	3	46	46
11. माइक्रो मीटर	"	1	12	9	1	12	9
12. आटोमोबाइल उद्योग							
—मोटरसाइकल —स्कूटर —तिपहिये स्कूटर	संख्या इकाई में	8	1,04,500	1,17,206	6	62,800	50,009
13. साइकल (पूर्ण)	संख्या हजारों में	9	2,105	2,073	2	900	844
14. चीनी							
—केन्द्रसरकारी क्षेत्र	लाख टनों में	137	22.85	24.29	6	1.35	1.13
—सहकारी क्षेत्र	"	74	13.68	12.50	47	9.72	8.76
15. सूती वस्त्र			178.76	9,650		12.60	770
—सूत	किलोग्राम लाखों में	*664	(करघे लाखों में)		@44	(करघे लाखों में)	
			2.09	78,490		0.09	2,221
—कपड़ा	मीटर लाखों में		(तकुए लाखों में)			(तकुए लाखों में)	

टिप्पणी:—1. खाना 6, 7 और 8 में दी गई सूचना उन औद्योगिक इकाइयों के बारे में है जिन से ऋण वसूल होना बाकी है; और इनमें वे इकाइयां शामिल नहीं है जिन्होंने ऋण की पूरी अदायगी कर दी है।

2. खाना 3, 4 और 5 में दी गई सूचना औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य, वाणिज्य पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालयों की रिपोर्टों पर आधारित है।

* इसमें 291 संयुक्त मिलें शामिल हैं। @ इसमें 11 संयुक्त मिलें शामिल हैं।

परिशिष्ट 'छ'

30 जून, 1971 को जिन संस्थाओं में निगम के संचालक, संचालक और अंशधारी के रूप में हितबद्ध है, उनके द्वारा देय ऋण

कम्पनियों/समितियों की क्रम संख्या	ऋण मंजूर होने की तारीख	मंजूर हुए ऋण की रकम	देय रकम		जोड़	कैफियत
			उन ऋणों की देय रकम जो सम्बन्धित संचालकों के निगम के संचालक होने अथवा ऋणी संस्था से हितबद्ध होने से पहले मंजूर किये गये थे	उन ऋणों की रकम जो सम्बन्धित संचालकों के निगम के संचालक रहते हुए मंजूर किये गये थे		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(क) जिन सहकारी समितियों में निगम के संचालक राज्य सरकारों या सहकारी बैंकों या सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के नामित व्यक्ति के रूप में हितबद्ध हैं, उनके द्वारा देय ऋण					
	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं		
	(ख) जिन संस्थाओं में निगम के संचालक केवल अंशधारियों के रूप में हितबद्ध हैं उनके द्वारा देय ऋण					
1.	28-1-61 29-3-61	8,26,000	9,45,907			
	27-5-65	12,00,000	15,13,718			
	28-1-61	79,48,348	98,97,609			
2.	30-5-63	19,59,187	8,84,661			
3.	29-9-64	36,01,070	22,89,562			
4.	28-3-69	53,34,427	42,49,433			
5.	30-4-64	1,00,00,000	85,00,000			
6.	26-11-56	25,00,000	6,38,000			
7.	30-12-65	2,00,00,000	—	1,80,00,000		
8.	27-1-65	50,00,000	40,00,000			
9.	31-10-68	20,65,000	—	20,65,000		
	31-10-68	12,32,088	—	10,74,588		
	7-10-70	3,00,000	—	3,00,000		
10.	29-8-63	27,22,764	25,27,659			
	29-8-63	7,96,000	6,56,000			
	28-9-66	4,51,000	—	4,51,000		
	28-7-66	....	....	7,24,000		
11.	30-5-63	34,09,098	21,46,343			
	30-5-63	29,88,345	8,95,345			

12.	30-4-64	41,89,000	37,28,000		
	28-12-64	4,39,000			
	30-4-64 28-12-64	38,88,883	27,80,694		
	30-4-64 28-12-64	47,17,684	36,00,804		
	27-1-67	75,00,000	—	59,00,000	
13.	28-9-62	1,50,00,000	1,42,50,000		
	28-7-66	50,00,000	—	50,00,000	
14.	25-5-61	2,79,000	1,12,250		
	25-5-61	6,53,756	2,78,506		
	29-8-63	7,50,000	3,60,000		
15.	28-12-64	6,88,435	3,10,435		
	22-11-66	23,22,000	—	16,78,988	
16.	28-11-60	12,00,000	7,50,000		
	30-1-69	80,00,000	—	80,00,000	
17.	25-3-65	42,82,645	28,65,145		
	'ख' का जोड़	13,12,43,730	6,81,80,571	4,31,93,576	11,13,74,147

ग. जिन संस्थाओं में निगम के संचालक, संचालकों के रूप में हितबद्ध हैं, उनके द्वारा देय ऋण

1.	27-6-58	20,00,000	4,00,000		
	29-8-68	35,00,000	33,50,000		
	25-11-65	5,00,000	3,48,617		
	28-2-63	15,17,500	4,87,162		
	28-2-63	16,32,195	6,66,910		
	31-1-63 30-7-64	22,05,000 4,70,000	23,80,134		
		1,06,558	1,00,653		
2.	24-2-66	50,00,000	22,05,000		
	30-11-67	6,95,000	4,19,405		
3.	28-11-68	40,00,000	—	40,00,000	
	25-2-71	6,95,000	—	15,00,000	
4.	29-12-66	50,00,000	—	29,00,000	
	'ग' का जोड़	2,81,26,253	1,03,93,881	84,00,000	1,87,93,881
'क', 'ख' और 'ग' का जोड़		15,93,69,983	7,85,74,451	5,15,93,576	13,01,68,028

परिशिष्ट 'ख'

लोक वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पात्र, जिलों/क्षेत्रों की समेकित सूची

राज्य	चुने हुए जिले
1. आन्ध्र प्रदेश	नलगोंडा, मेढक, महबूबनगर, करीमनगर, वारांगल, खमाम, चित्तूर, अनन्तपुर, करनूल और निजामाबाद।
2. असम	गोलपारा*, कछार, नवगंग, कामरूप, मिकिर हिल्स जिला* तथा मिजो हिल्स जिला।
3. बिहार	संथल परगना, भागलपुर*, पालामाऊं, चम्पारन, सारन, दरभंगा*, पुरणियां, मुजफ्फरपुर और सहर्ष।
4. गुजरात	पंचमहल*, कच्छ, अमरेली, सबरकण्ठ, बंसकण्ठ, बड़ौच, भावनगर, मेहसाना और सुरेन्द्रनगर।
5. हरियाणा	महिन्द्रगढ़*, हिसार तथा जींद।
6. हिमाचल प्रदेश	चम्बा, कन्नौर, कांगड़ा*, कुल्लू तथा लाहौल और स्पीति।
7. जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर,* अनन्तनाग, बारामुला, जम्मू*, कथुआ, उधमपुर, डोडा, लद्दाख, पुन्छ तथा राजौरी।
8. केरल	अलेप्पी,* त्रिवेन्द्रम, कन्नौर, त्रिचूर तथा मालापुरम।
9. मध्य प्रदेश	बस्तर, मांडला, सरगुजा, स्योनी, बिलासपुर, झलुआ, बालाघाट, सिन्धी, बेतूल रायगढ़, रायपुर, धार, टिकमगढ़, राजगढ़, खरगांव, साजपुर, शिवपुरी, चिंदवाड़ा, रीवा, पन्ना, देवस, मंदसौर, छत्तरपुर, गुना, दतिया, मोरेना, विदिशा, नरसिंहपुर, रायसेन, हुसंगाबाद, देमोह, भिंड तथा सागर।
10. महाराष्ट्र	भीर, उसमानाबाद, भन्डारा, रत्नागिरी,* औरंगाबाद, योतमल, चान्दा, धूलिया, बुल्डाना, नान्देद, प्रभांडी, जलगांव तथा कोलाबा।
11. मेघालय	संयुक्त खासी तथा जैन्तिया हिल्स के दोनों जिले* तथा गारो हिल्स*।
12. मैसूर	बेलगांव, बिदार, बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्ग, हसन, मैसूर, उत्तरी कनारा, रायचूर दक्षिणी कनारा तथा टुंकुर।
13. नागालैंड	कोहिमा,* मोकोचंग* तथा तेनसंग।
14. उड़ीसा	बोलंगिर, मयूरभंज,* धेनकनल, कालाहांडी*, बालासोर, क्योनझर, कोरापुट तथा फुलबानी।
15. पंजाब	होशियारपुर,* भटिंडा, गुरदासपुर तथा संगरूर।
16. राजस्थान	जैलोर, बंसवाड़ा, डुंगरपुर, नागौर, चुरू, अलवर,* टौंक, उदयपुर, जोधपुर, झुनझुनु, शिकर, शिरोही, भिलवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर, तथा बाड़मेर।
17. तमिलनाडु	दक्षिणी अरकोट, तिरुचिरापल्ली*, मुदुरई,* रामनाथापुरम,* कन्याकुमारी, उत्तरी अरकोट, तंजावुर तथा धर्मापुरी।
18. उत्तर प्रदेश	अलमोड़ा, आजमगढ़, बढ़ैच, बांदा, बलिया, बधायं, चमोली, फतेहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, पीलीभीत, जालौन, जौनपुर, झांसी,* मैनपुरी, पिथोरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, टेहरी, गढ़वाल, उन्नाव, उत्तरकाशी, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, फैजाबाद, गोंडा, मथुरा, फरुखाबाद, मुरादाबाद, शाहजहांनपुर तथा देवरिया।
19. पश्चिमी बंगाल	पुरुलिया*, बांकुरा, मिदनापुर, दार्जिलिंग, मालदा, कूचबिहार, पश्चिमी दिनाजपुर तथा मुर्शिदाबाद।

केन्द्र प्रशासित क्षेत्र

अंडमान और निकोबार द्वीपसमह*	सम्पूर्ण क्षेत्र
दादरा और नगर हवेली*	सम्पूर्ण क्षेत्र
गोआ, दमन और दिउ*	सम्पूर्ण क्षेत्र
लकादीव, अमीनदीव और मिनीकाय द्वीपसमूह*	वासित द्वीपसमूह
नेफा*	सम्पूर्ण क्षेत्र
पांडिचेरी*	सम्पूर्ण क्षेत्र
त्रिपुरा*	सम्पूर्ण क्षेत्र
मणीपुर*	सम्पूर्ण क्षेत्र

*ये जिले/क्षेत्र केन्द्रीय सरकार की निवेश आर्थिक सहायता के पात्र हैं।

टिप्पणियां : (i) तमिलनाडु में रामानाथापुरम, मदुकुलातर, शिवगंगा, परमकुडी, तिरुवदनई के उपतालुकाओं सहित उपतालुके तथा रामनाथापुरम जिले का रामानाथापुरम विकास जिले सहित तिरुपतुर, मेलूर (जिला मदुरई) और तिरुमयम, अलंगुडी तथा कुलातूर (जिला तिरुचेरापली) केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता के पात्र हैं।

(ii) क्रम संख्या 1 से 7 के केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में उनकी राजधानियों की नगरपालिका सीमाओं के भीतरी भाग को छोड़ कर सम्पूर्ण जिला और मणिपुर की नगरपालिका सीमा के भीतरी भाग को छोड़कर सम्पूर्ण क्षेत्र केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता के लिए पात्र है।

परिशिष्ट 'ग'

केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में औद्योगिक परियोजनाओं को रियायती दर पर उपलब्ध वित्तीय सहायता का विवरण

(i) **ब्याज की दर :**

वर्तमान ब्याज की दर 9 प्रतिशत (ब्याज तथा मूलधन की किस्तें समय पर अदा करने से 1/2 प्रतिशत की छूट) से कम ब्याज दर अर्थात् 7 1/2 प्रतिशत (1/2 प्रतिशत की छूट) होगी।

(ii) **ऋणों की अदायगी में आरम्भिक रियायत अवधि :**

निगम की सामान्य पद्धति रही है कि सहायता प्राप्त संस्था को ऋण अदायगी में मूलधन की प्रथम क़िस्त अदा करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाता है। पिछड़े क्षेत्रों में यह अवधि ऋण के प्रथम संवितरण की तारीख से दी जाएगी।

(iii) **ऋणों के लिए परिशोधन अवधि :**

ऋण अदायगी के लिए सामान्यतः 10 से 12 वर्षों के स्थान पर यह अवधि 15 से 20 वर्षों तक बढ़ा दी जाएगी।

(iv) **प्रतिभूति की सीमा :**

निगम की वर्तमान प्रवृत्ति 50 प्रतिशत का अन्तर रखने की है, जो 30/35 प्रतिशत तक घटा दी जाएगी, अर्थात् इक्विटी: ऋण अनुपात 1:2 में स्वीकार्य होगा।

(v) **प्रवर्तकों का योगदान :**

परियोजना की लागत में प्रवर्तकों से सामान्य आवश्यकताओं से भिन्न निगम कम योगदान स्वीकार कर लेगा।

(vi) **साधारण और अधिमान पूंजी में साझेदारी :**

प्रत्येक मामले के गुण-दोषों को देखते हुए निगम हामीदारी अथवा अन्य तरीके से अन्य क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्र/राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई के लिए शेयर पूंजी में अधिक साझेदारी पर विचार करने के लिए प्रस्तुत रहेगा।

(vii) **अन्य प्रभारों में कटौती :**

निगम के सामान्य प्रभारों, हामीदारी कमीशन, वचनबद्धता प्रभार, आवेदनों की जांच के लिए अप्रतिदेय शुल्क, विधिक प्रभारों में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी जाएगी।

सामान्यतः रियायतें उन परियोजनाओं पर लागू होंगी जिनकी परियोजना लागत एक करोड़ रुपए से अधिक न हो, बड़ी परियोजनाओं को रियायती वित्त देने के लिए चयनात्मक आधार पर विचार किया जाएगा।

पिछड़े प्रान्तों/क्षेत्रों में स्थित परियोजनायें केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार अनुदान/आर्थिक सहायता प्राप्त करने पर भी औद्योगिक वित्त निगम से रियायतें को प्राप्त कर सकेगी, जो परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक हो सकती है, बशर्ते परियोजना लागत 50 लाख रुपए से अधिक न हो।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

निगम के अधिकारी

प्रधान कार्यालय

मुख्य अधिकारी

चरन दास खन्ना—अध्यक्ष

बलदेव पसरीचा—महाप्रबन्धक

तपेन्द्र मोहन सेन—विधि सलाहकार

एस० एन० पाई—सहायक महाप्रबन्धक

एल० सीतारामम्—उप-महाप्रबन्धक

पी० एस० गुरुंग—मुख्य तकनीकी अधिकारी

आर० बी० माथुर—मुख्य लेखापाल

अन्य अधिकारी

पी० एस० गोपालाकृष्णन	परियोजना
इन्द्र सेन नांगिया	परियोजना
देवेन्द्र नाथ डावर	परियोजना
एम० पी० चक्रवर्ती	परियोजना
विश्वनाथ कपूर	परियोजना
एम० एल० चोपड़ा	परियोजना
ए० के० घोष (उप मुख्य विधि अधिकारी)	विधि
आर० रामाचन्द्र राव	बोर्ड एवं समन्वय
डी० जी० रामैया	प्रशासन
बी० एस० आर० के० सास्ती	सांख्यिकी विभाग
एस० के० जैन	विदेशी मुद्रा ऋण
एम० आर० गनपति राव	आर्थिक विभाग

दिल्ली मण्डल

एच० एस० रस्तोगी	प्रबन्धक
शंकर लाला मिश्रा	विधि अधिकारी

बम्बई कार्यालय

एम० एस० नागरथ	प्रबन्धक
एल० डी० मुन्दकर	विधि अधिकारी

कलकत्ता कार्यालय

एम० एन० खन्ना	प्रबन्धक
एम० रामकृष्ण राव	विधि अधिकारी
बी० एम० धर	

मद्रास कार्यालय

आर० एन० साहू	प्रबन्धक
पी० एस० बालासुब्रह्मणियम	विधि अधिकारी

अहमदाबाद कार्यालय

एस० के० भट्टाचार्य	प्रबन्धक
सी० पी० भान	विधि अधिकारी

गौहाटी उप-कार्यालय

एच० पी० गुप्ता	प्रभारी अधिकारी

STATE BANK OF INDIA

Central Office

NOTICE

Bombay, the 3rd November 1971

In pursuance of Regulation 76(1) of the State Bank of India General Regulations, 1955, the Executive Committee of the Central Board has empowered the Officer-in-Charge, Foreign Exchange Section at Moradabad Branch to exercise the following signing powers :—

"To endorse and transfer documents of title to goods, standing in the name of or held by the State Bank, to draw, accept and endorse bills of exchange and cheques, to issue confirm and transfer letters of credit, in the current and authorised business of the State Bank, and to sign all other letters, advices, accounts, receipts and documents connected with such business".

By order of the Executive Committee of the Central Board

T. R. VARADACHARY,
Managing Director

OFFICE OF THE PUNJAB WAKF BOARD

Ambala Cantt., the 31st July 1971

Delegation of powers

Resolution No. 9

In exercise of the powers conferred u/s 22 of the Wakf Act 1954, the Punjab Wakf Board, Ambala Cantt., *vide* its resolution No. 9, dated 31-7-1971 delegates its powers to the Property Officers, Field Inspectors and Rent Collectors as under :—

To authorise the Property Officers, Field Inspectors and also the Rent Collectors, jointly and severally to take possession of all the wakf properties on behalf of the Wakf Board in execution petitions filed by the Board and also to recover the amounts decreed by the court. They will be entitled to execute the decrees passed by any court or officers and accompany the court bailiffs for this purpose.

They are also authorised to pass valid receipts for taking possession of wakf properties and for obtaining the decretal amounts from the judgment debtors.

Note :—One copy of the resolution pasted on Notice Board.

The 4th October 1971

Delegation of powers

Resolution No. 10

In exercise of the powers conferred under section 22 of the Wakf Act 1954, the Punjab Wakf Board, Ambala Cantt., *vide* its resolution No. 10 dated 4-10-71 delegates the following powers to its Secretary.

1. To appear, persue, file written reply, any application and reply to any application or to make statement on oath or otherwise and to compromise the case filed by Shri Hassan Ahmed Raza, Ex-Rent Collector against the Board before the Labour *Cum* Conciliation Officer and now pending in the Labour Court, Haryana.
2. To file any appeal, Revision or review application in any court or office against any interim order as well as against the final order and to defend any of the same.
3. To authorise Shri Mohan Lal Gupta, M.A.,LL.B. or any other employee of the Board to represent the case on behalf of the Board.
4. The reply filed and any other action taken by the Secretary so far in the said proceedings is ratified and approved.

One copy of the resolution pasted on Notice Board.

GHAZANFAR ALI KHAN
Secretary,
Punjab Wakf Board,
Ambala Cantt.

DAMODAR VALLEY CORPORATION

Calcutta, the 22nd November 1971

No. 89, dated 14-10-71.—In exercise of the powers conferred by section 60 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948 (14 of 1948), the Corporation hereby makes, with the previous sanction of the Central Government, the following further amendments to the Damodar Valley Corporation Service Regulations, published with the Damodar Valley Corporation Notification No. 5, dated the 28th January 1957, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Damodar Valley Corporation Service (18th Amendment) Regulations, 1971.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 6th November, 1970.

2. In the Damodar Valley Corporation Service Regulations, after regulation 108A, the following regulation shall be inserted, namely :—

"Regulation 108B.—Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, the benefits admissible to the Central Government servants under the Central Civil Service (Extra-Ordinary Pension) Rules of the Government of India as amended from time to time, shall be admissible in the case of employees of the corresponding categories of the Damodar Valley Corporation."

Explanatory Memorandum

The employees of the Damodar Valley Corporation other than those covered by the definition of workmen as given in the Workmen's Compensation Act were not so far eligible to any compensation in case of accident, while on duty resulting in death or injury invalidating out of service.

Central Civil Service (Extra-ordinary Pension) Rules provide for such benefits to all Central Government Civil Servants who entered service under Central Government on or after 1-4-1937.

D.V.C. in general adopts Central Government service rules and regulations by making new regulations or amending existing regulations from time to time as per procedure laid down in DVC Act.

There had been representations from different sections of Corporation employees that the benefits under the Central Civil Services (Extra-ordinary Pension) Rules should be extended to them.

After careful consideration, DVC felt that such benefits should also be extended to its employees as applicable to the Central Government employees and in the Corporation Meeting held on 6-11-70 passed the resolution approving the proposal for adoption of the Central Civil Services (Extra-Ordinary Pension) Rules of the Government of India in respect of the employees of the Corporation.

It is intended to give effect to the amendment of the DVC Service Regulation incorporating the provision of the above Government of India Rules with effect from 6-11-70, the date of approval of the proposal by the Corporation.

It is confirmed that by giving retrospective effect to the above no employee will be affected prejudicially.

D. MOOKERJEA
General Manager & Secretary

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 23rd November 1971

THE UNIT SCHEME, 1971

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), the Board of the Unit Trust of India hereby makes the following unit scheme :

1. *Short title and commencement.*—(1) This scheme shall be called the Unit Scheme, 1971.

(2) It shall come into force on the 1st October 1971.

(3) The Scheme shall be applicable to savers participating in the Unit-Linked Insurance Plan 1971 only.

2. *Definitions.*—In this scheme, unless the context otherwise requires—

(a) the "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963;

(b) "acceptance date' with reference to an application made by an applicant to the Trust or its agent duly authorised in this behalf for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust or its authorised agent, as the case may be, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(c) "initial sale period" means the period during which the Trust in pursuance of the proviso to sub-clause (1) of clause (8), sells units at the price of ten rupees per unit.

(d) "body corporate" includes a society registered under the Societies Registration Act, 1860, such society being hereinafter referred to as "a society";

(e) "number of units in issue" means the aggregate of the number of units sold and outstanding;

(f) "recognised stock exchange" means a stock exchange, which is, for the time being, recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(g) "unit" means one undivided share of the face value of Rupees Ten in the unit capital of this Scheme;

(h) all other expressions not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them by the Act.

3. *Face value of each unit.*—The face value of each unit shall be ten rupees.

4. *Applications for units.*—(1) Applications for units may be made by the following classes of persons :—

(i) An individual or individuals, none of whom is a minor;

(ii) A company or other body corporate singly or along with another company or body corporate or an individual or individuals, none of whom is a minor;

(iii) A guardian on behalf of a minor.

(2) An individual may make an application in his personal capacity or in his capacity of an officer of a Government or of a Court.

(3) An application shall not be made jointly on behalf of a minor and another person.

(4) Applications shall be made in such form as may be approved by the Chairman of the Trust and, subject to the provisions of sub-clause (3), the total number of applicants in each case shall not exceed four.

(5) The number of units applied for shall, in all cases, be a multiple of ten.

(6) (a) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him along with the application in cash, cheque, draft, postal order, money order, mail transfer or credit transfer, including the cost of realising the cheque, draft or postal order, as the case may be.

(b) If the payment is made by cheque or draft, the acceptance date will, subject to such cheque or draft being realised, be the date on which the cheque or draft, as the case may be, is received by the Trust or its authorised agent. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for and other amounts and charges payable by the applicant, he shall be issued the number of units, being a multiple of ten, nearest to the number applied for by him and the balance, if any, due to him shall be refunded to him at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(c) A unit certificate will be sent by registered post with or without acknowledgement due to the address given by the applicant; and the Trust will not incur any liability for loss, damage, mis-delivery or non-delivery of the unit certificate, so sent.

5. *Purchase may be made through a banker etc.*—Any person may make arrangements with a banker or any other institution, empowering it, in accordance with law, to purchase units from the Trust on his behalf, from time to time.

6. *Sale of units.*—The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust or its agent, as the case may be, shall, as soon thereafter as possible, send the applicant an acknowledgement therefor. As soon as possible thereafter, the Trust shall issue to the applicant one unit certificate representing the units sold to him.

7. *Repurchase of units.*—(1) The Trust shall, at any time during the currency of this scheme on receipt by it of a unit certificate, with the form on the reverse thereof duly filled in, repurchase all or any part of the units comprised in the certificate, being always a multiple of ten; the certificate so received shall be retained by the Trust for cancellation. The Trust shall, in the case of repurchase of a part of the units comprised in the certificate issue a new certificate for the balance of the units held by the unit holder. Provided that (i) no person shall be entitled to sell to the Trust part only of the units comprised in a unit certificate if such sale would result in his becoming the holder of less than ten units; (ii) on sale of part of the units comprised in a unit certificate, the Trust will issue to the seller a certificate for the balance of the units held by him.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-clause (1) :

(a) the Trust shall not sell or repurchase units during such period as the Reserve Bank may in writing direct;

(b) the Trust shall not be under an obligation to sell or repurchase units—

(i) on such days as are not working days;

(ii) during the period when the register of unit holders is closed in connection with (as notified by the Trust) the annual closing of the books and accounts; and

(c) the Trust shall not be under an obligation to repurchase units during the initial sale period or during the period of three months immediately following the initial sale period or during the period during which, in pursuance of the second proviso to sub-clause (1) of clause (8) the Trust sells units at such fixed price as may be determined by it.

Explanation.—For the purposes of this scheme, the term "working day" shall mean a day which has not been either (i) notified under the Negotiable Instruments Act 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other states where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

(3) (i) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. (ii) Where an application by an applicant for repurchase of units from him has been accepted by the Trust, the Trust shall as soon thereafter as possible, send the applicant an acknowledgement therefor.

(4) Payment for the units repurchased by the Trust shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in his application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

8. Sale or repurchase to be as on the acceptance date.

(1) Every sale or repurchase of units by the Trust shall be as on the acceptance date at the respective prices prevailing on that day :

Provided that during such period, as may be determined by the Trust, from the date on which this Scheme comes into force, the Trust shall sell units at Rs. 10/-.

Provided further that during such period, as may be determined by the Trust, immediately following the date of the reopening of the register of unit holders after its closure in connection with (as notified by the Trust) the annual closing of the books and accounts, the Trust may sell units at such fixed price as may be determined by it.

(2) The price at which a unit will be sold by the Trust, hereinafter referred to as the sale price, and the price at which a unit will be repurchased by the Trust, hereinafter referred to as the repurchase price, shall be determined by the Trust on every Monday (or, the next working day, if a Monday happens to be a holiday), and shall apply to sales and repurchases between the opening of business on the next day and the close of business on the succeeding Monday (or the next working day if that Monday is a holiday).

(3) The sale price shall be arrived at by dividing the value (determined as hereinafter indicated) as at the close of business on the working day immediately preceding the day on which the sale price is determined, of the assets, reduced by liabilities pertaining to this Scheme not being contingent liabilities or liabilities in respect of the unit capital including reserves, if any, as at the close of business on the said working day, by the number of units in issue as at the close of business on the said day, adding thereto such sum as in the opinion of the Trust is adequate to cover brokerage, commission, taxes, if any, stamp duties, other charges in relation to the acquisition of investments by the Trust and management expenses, and adjusting upwards the resulting price by not more than 5 paise per unit.

(4) The repurchase price at which a unit will be repurchased by the Trust on any day shall be arrived at by dividing the value (determined as hereinafter indicated) as at the close of business on the working day immediately preceding the day on which the repurchase price is determined, of the assets reduced by liabilities pertaining to this Scheme, not being contingent liabilities or liabilities in respect of the unit capital including reserves, if any, as at the close of business on the said working day, by the number of units in issue as at the close of business on the said day, deducting therefrom such sum as in the opinion of the Trust is adequate to cover brokerage, commission, taxes, if any, stamp duties, and other charges in relation to the realisation of investments by the Trust, and adjusting downwards the resulting price by not more than 5 paise per unit.

(5) The sale price or the repurchase price of a unit shall be arrived at on the basis of the material available with the Trust on the day on which the sale price, or the repurchase price, as the case may be, is arrived at.

(6) Notwithstanding anything to the contrary in sub-clauses (2) (3) (4) and (5), when the Trust is satisfied that, in the interest of the Trust and of the unit holders, it is necessary or expedient to do so, it may vary the sale price or the repurchase price or both, as arrived at under sub-clause (3), or as the case may be, sub-clause (4) to such extent as it may deem fit.

9. *Publication of sale price and repurchase price.*—The Trust shall, as early as possible after the determination of the sale and the repurchase prices, publish in such manner as it may deem fit, the sale and the repurchase prices of units.

10. *Valuation of assets pertaining to this Scheme.*—(1) For the purposes of valuation of the assets under sub-clauses (3) and (4) of clause (8), the assets shall be classified into (A) Cash, (B) Investments and (C) Other Assets.

(2) *Investments shall be valued by taking.*—I. (a) the closing prices on the stock exchange, as on the working day, preceding the day on which the valuation is made, of the securities held by the Trust pertaining to this Scheme.

Provided where a security is quoted on more than one stock exchange, the manner of determining the price of such security shall be decided by the Trust,

(b) where any investment was not during the relevant period, dealt in, or quoted on any recognised stock exchange, such value, as the Trust may, in the circumstances consider to be the fair value of such investment; and

II. adding thereto

(a) in the case of interest earning deposits, interest accrued but not taken credit for;

(b) in the case of Government securities and debentures, interest accrued but not taken credit for; and

(c) in the case of preference shares and equity shares quoted ex-dividend, any dividend declared but not received.

(3) Other assets shall be valued at their book value.

11. *Form of unit certificate.*—Unit certificates shall be in Form A annexed hereto. Each unit certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the certificate and the name of the unit holder.

12. *Unit certificate.*—A unit certificate may represent any denomination of units, being a multiple of ten.

13. *Manner of preparation of unit certificate.*—The unit certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Trust. Every such signature shall be autographic until such time as an arrangement is authorised by the Trust adopting some method of mechanical signature; thereafter, all such signatures will be effected by the method so adopted. No unit certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person, whose signature appears thereon, may have ceased to be a person authorised to sign unit certificates on behalf of the Trust.

14. *Trusts not to be recognised regarding unit certificates.*—The person who is registered as the holder and in whose name a unit certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the unit holder and as having any right, title or interest in or to such unit certificate and the units which it represents; and the Trust may recognise such holder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take notice of the execution of any Trust, or, save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise and trust or equity or other interest affecting the title to any unit certificate or the units thereby represented.

15. *Holding by societies.*—(1) A unit certificate issued by the Trust to a society shall be made out in the name of the society.

(2) Where units are transferred to a society, the transfer shall be to the society by its name.

16. Exchange of unit certificates and procedure when certificate is mutilated, defaced, lost etc. (1) Subject to the provisions of this scheme, every unit holder shall be entitled to exchange any or all of his unit certificates for one or more unit certificates of such denominations as he may require, representing the same aggregate number of units. While applying for such exchange, the unit holder shall surrender to the Trust the unit certificate or certificates to be exchanged and shall pay to the Trust all moneys (if any payable thereunder) in respect of the issue of the new unit certificate or certificates.

(2) In case any unit certificate shall be mutilated or defaced, the Trust in its discretion may issue to the person entitled a new unit certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or defaced unit certificate. In case any unit certificate should be lost, stolen or destroyed, the Trust may, in its discretion issue to the person entitled a new unit certificate in lieu thereof. No such new unit certificate shall be issued unless the applicant shall previously have

(i) furnished to the Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, defacement, loss, theft or destruction of the original unit certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or defacement) produced and surrendered to the Trust the mutilated or defaced unit certificate; and

(iv) furnished to the Trust such indemnity as it may require.

The Trust shall not incur any liability for issuing such certificate in good faith under the provisions of this clause.

(3) Before issuing any unit certificate under the provisions of this clause, the Trust may require the applicant for the unit certificate to pay a fee of one rupee per unit certificate issued by it, together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover the stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such certificate. Provided that no fee, stamp duty or postal registration charges shall be payable in respect of such issue of unit certificate in the following cases, *viz.*

(i) When a unit certificate issued under clause 6 to an applicant or issued under clause 21(7) to a transferee is tendered for the first time for sub-division.

(ii) When consolidation of unit certificates is suggested by the Trust and such a suggestion is accepted by the unit holder.

17. *Register of unit holders.*—The following provisions shall have effect with regard to the registration of unit holders :—

(1) A register of the unit holders shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register :

(a) the names and addresses of the unit holders;

(b) the distinctive number of the unit certificate or certificates and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which such person became the holder of the units standing in his name.

(2) No application for registration as a unit holder shall be entertained unless the application relates to a number of units being a multiple of ten;

Provided that where, on the death of a unit holder any other person becomes entitled to a number of units not being a multiple of ten, such person may be registered as a unit holder in respect of such number of units :

Provided further that the Trust may, on application by such person in the appropriate form, sell to or repurchase from such person, such minimum number of units as may be necessary to make the units held by him a multiple of ten :

Provided however that such person shall, within six months from the date of his being so registered, purchase or sell units so as to make the number of units held by him a multiple of ten.

(3) If any unit certificate stands registered in the names of two or more persons, such persons shall be deemed to hold the unit certificate jointly and a discharge by the person first named in the register of unit holders shall, as regards receipt of amount due in respect of such units, discharge the Trust inrespect of such amounts.

(4) Where two or more individuals, none of them being a minor, apply, whether in pursuance of a transfer of units to them or otherwise, for issue of unit certificate in their favour and, in such application or otherwise, request in writing that any one of them should be permitted to deal with the units represented by the certificate, the Trust shall record in its books, suitable entries to take note of such request; and when a unit certificate has been issued in such circumstances, then, notwithstanding anything to the contrary in sub-clause (3), any one or more of the holders shall be entitled to deal with the units represented by such certificate, and a discharge by anyone or more of such persons shall, as regards receipt of amounts due in respect of such units, discharge the Trust in respect of such amounts.

(5) Any change of name or address on the part of any unit holder shall be notified to the Trust which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(6) Except when the register is closed in accordance with the provision in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any unit holder, without charge.

(7) The register will be closed at such times and for such periods as the trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 30 days in any one year; the Trust shall give notice of such closure by advertisement in such newspapers as the Board may direct.

(8) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

18. *Receipt by unit holder to discharge Trust.*—The receipt of the unit holder for any moneys paid to him in respect of the units represented by the certificate shall be a good discharge to the Trust.

19. *Death of joint holder of unit certificate.*—(1) In case of death of any one of the joint holders of a unit certificate, the survivors or survivor shall be the only person recognised by the Trust as having any title to or interest in the units represented by the certificate and to any money payable in respect of such units.

Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivors or survivor in respect of the said units or such money.

(2) The executors or administrators of a deceased sole unit holder or a holder of succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the unit and to any money payable in respect thereof.

(3) Any person becoming entitled to a unit in consequence of the death or bankruptcy of any sole unit holder or of the survivors or survivor of joint unit holders may subject as hereinafter provided, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, either be registered as the holder of such unit upon giving to the Trust notice in writing of his desire to the effect, or transfer such unit to some other person. All the limitations, restrictions and provisions of this scheme relating to transfers shall be applicable to any such notice or transfer as if the death or bankruptcy had not occurred and such notice or transfer were a transfer executed by the unit holder.

(4) The Trust may retain any moneys payable by it in respect of any unit of which any person is entitled to be registered as the unit holder or which any person under these provisions is entitled to transfer until such person be registered as the holder of such unit or shall duly transfer the same.

20. *Application by and registration of bodies corporate, minors etc.*—(1) A body corporate may be registered as a unit holder or one of joint unit holders.

(2) A minor may not be registered as a unit holder. An adult, being the lawful guardian of a minor, may, in his capacity as such lawful guardian, be registered as a unit holder. Such adult shall furnish to the Trust in such manner as it may specify the age of the minor and proof to the satisfaction of the Trust, that the age furnished is correct, and that such adult is the lawful guardian of the minor.

(3) Applications by companies or other corporate bodies shall be accompanied by the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and Articles, Bye-laws etc., an authorised copy of the resolution by the managing body, and a copy of the requisite power of attorney.

(4) A firm or other association of persons (not being incorporated) as such, shall not be registered as a unit holder.

(5) Not more than four persons may be joint holders.

(6) An individual applying for units in his official capacity shall be issued units in his official name.

21. *Transfer of units.*—(1) Every unit holder shall be entitled to transfer the units or any of the units held by him by an instrument in writing in a form approved by the Chairman of the Trust provided that no transfer shall be registered if the registration thereof would result in the transferor or the transferee being a holder of a number of units not being a multiple of ten :

Provided further that no transfer shall be made except to the persons in the classes mentioned in clause 4;

Provided no transfer except a transfer in favour of, or by, a banking institution shall be registered until the 30th September 1972.

Provided, however, the Board may, in its discretion, register any transfer even before the expiry of 30th September 1972.

(2) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of the units transferred until the name of the transferee is entered in the register in respect thereof;

(3) Every instrument of transfer shall be duly stamped (if under the law it requires to be stamped) and left with the Trust for registration along with the relative unit certificate or certificates and such other evidence as the Turst may require in support of the title of the transferor or his right to transfer the units. The Trust may dispense with the production of any unit certificates which shall have become lost, stolen or destroyed, upon compliance by the transferor with the like requirements to those arising in the case of an application by him for the replacement thereof.

(4) When the units are issued in the official name, they shall be deemed to be transferred without any

instrument of transfer from each holder of the office to the succeeding holder of the office on and from the date on which the latter takes charge of the office.

(5) When the holder of the office transfers the units so held to a person not being his successor in office, the transfer shall be made by an instrument of transfer signed by the holder of the office and the name of the office.

(6) All instruments of transfer, which may be registered, shall be retained by the Trust.

(7) Where units have been transferred the Trust shall issue to the transferee, whose name has been entered in the register, a fresh unit certificate in the respect of the units transferred to him; where the transferor has transferred only a portion of the units covered by a certificate, the Trust shall issue to the transferor a fresh certificate for the units not transferred by him. Before issuing any certificate for the units transferred to the transferee, the Trust may require the transferee to pay a fee of Rupee one per certificate, together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover the stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such certificate.

22. *Applications and transfer forms signed by attorneys.*—If any application or transfer form is signed by a person holding a power of attorney empowering him to do so, the original power of attorney or a notarially certified copy of the same, should be submitted along with the application or the transfer form, as the case may be, unless the power of attorney has already been registered in the books of the Trust.

23. *Distribution of Income.*—(i) The distribution of the income pertaining to the Unit Scheme 1971 shall be in the following manner :

(i) The income allocated to the Unit Scheme 1971 in any year reduced by the interest and amount of other expenses charged to this Scheme for that year shall be distributed to the Unit holders under the Scheme in such manner and at such percentage of the income so reduced as the Board of Trustees may determine.

(ii) The interest payable for any year for any borrowings by the Trust and the total amount of other expenses incurred by the Trust in that year for the purpose of the Unit Scheme 1971 shall be charged to the Unit Capital of that Scheme in such manner and to such extent as the Board may, with the previous approval of the Reserve Bank, determine.

(iii) For purposes of sub-clause (ii) above, where expenses are incurred in common by the Trust in relation to more than one Unit Scheme, such expenses may be allocated to the different schemes to such extent and in such manner as the Board may, with the previous approval of the Reserve Bank, determine, having regard to the nature and purposes of the expenses and other relevant factors.

24. *Payments to unit holders.*—(1) The income distributable to the unit holders shall be paid, as soon as may be, after the closing of the annual accounts, as on the September 30 of each year.

(2) It shall be lawful for a unit holder to receive and retain any income declared by the Trust in respect of units of which he is such holder, notwithstanding that the units have already been transferred by him for consideration unless the transferee who claims the income from the transferor has within fifteen days of the date on which the income became due, lodged the certificate and all other documents relating to the transfer which may, under the provisions of Clause 21 or otherwise, be required by the Trust, for being registered in his name.

Explanation : The period specified in this sub-clause shall be extended—

(i) in case of death of the transferee, by the actual period taken by his legal representative to establish his claim to the income;

(ii) in case of loss of the transfer deed by theft or any other cause beyond the control of the transferee, by the actual period taken for the replacement thereof; and

(iii) in case of delay in the lodging of any certificate and other documents relating to the transfer connected with transit through the post, by the actual period of the delay.

(3) Nothing contained in sub-clause (2) shall affect the right of the Trust to pay to the unit holder any income, which has become due, in respect of units of which he is such a holder.

(4) No interest shall be payable by the Trust on such income distributable among the unit holders.

(5) The income distributable among the unit holders or any other money payable in respect of the units shall be paid by cheque or warrant drawn on the Trust's bankers at the places where its offices are situated, or, at the option of the unit holder, by a bank draft or money order, the charges for such bank draft or money order, being borne by the unit holder.

25. *Publication of accounts.*—The Trust shall as soon as may be after the 30th September of each year cause to be published in such manner as the Board may specify accounts showing the working of the scheme during the period ending on the 30th September. The Trust shall, on a request in writing received from a unit holder, furnish him a copy of the accounts so published.

26. *Additions and amendments to scheme.*—The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment thereof will be notified in the official Gazette.

27. *Scheme to be binding on unit holders.*—The terms of this scheme, including any amendments thereof from time to time, shall be binding on each unit holder and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding.

28. The provisions of this Scheme shall, in respect of any units acquired or held in accordance with any plan or plans formulated by the Board, pursuant to clause (cc) of Sub-Section (1) of Section 19 of the Act for acquisition of an interest in units, apply and be read subject to the provisions of said plan or plans.

29. *Copy of scheme to be made available.*—A copy of this scheme incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Trust at all times during its business hours and may be supplied by the Trust to any person on application.

FORM A

UNIT TRUST OF INDIA, BOMBAY

(Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963)

Unit Scheme, 1971

(Clause 11)

Unit Certificate No. No. of Units

This is to certify that the person/s named in this Certificate is/are the Registered Holder(s) of.....

..... Units, each of the face value of Rupees Ten, subject to the provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 63), the Regulations framed thereunder and the Unit Scheme, 1971.

Name/s

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

FOR THE UNIT TRUST OF INDIA

.....

Date..... .....

No transfer of the units comprised in this certificate or any portion thereof is valid unless registered with the office of the Unit Trust for which an application in the prescribed from should be made accompanied by this certificate.

FORM OF APPLICATION FOR REPURCHASE OF UNITS

Date.....

To

The Unit Trust of India

.....

.....

I/We .....

.. ..

am/are the registered holder(s) of..... units of the Unit Trust of India and am/are desirous of selling to the Trust all the said .....

..... units

..... units out of the said ..... units and accordingly offer the same for repurchase by the Unit Trust at the repurchase price on the Acceptance Day in respect of this application.

The price of the units may be paid to me by* cash/cheque/bank draft/postal or money order at my cost.

I/We may be issued a unit certificate for the balance of ..... units and the said unit certificate may be sent by registered post at my/our cost to Shri..... at the address given below.

Signature/s of holder (s)

.....

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Signature of Witness

Occupation :

Address :

.....

Signature of Witness

Occupation :

Address :

For the use of the office Acceptance Date.

---

*Delete words inapplicable.

PROVISIONS OF THE

Children's Gift Plan—1970

In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963), the Board of the Unit Trust of India hereby makes the following plan under which a person may acquire an interest in units.

1. This plan shall be called the "Children's Gift Plan, 1970".

2. The Plan shall be applicable to units issued under the Unit Scheme, 1964, as also under any other scheme or schemes, which the Trust may make hereafter and to which it may make the Plan, applicable.

3. An individual, not being a minor, shall be eligible to participate in the Plan.

4. Every individual, desirous of participating in the Plan, shall make an application, in the form prescribed by the Unit Trust, for issue of units in favour of a child who has not completed 15 years of age on the date of application.

5. Application for issue of units under paragraph 4 above should be in multiples of ten, and for as a minimum, not less than fifty units.

6. Payments to the Trust shall be by bank draft, cheque, money order or cash or in any other manner as may be specified by the Trust in this behalf. Cheques or bank drafts shall be drawn in the name of "Unit Trust of India" and made payable at Bombay or at such place as the Trust may specify in this behalf. Cheques and bank drafts may be crossed "account payee".

7. The issue of units under this Plan shall be deemed to have been effected on the acceptance date, and the price at which units are issued, shall be the sale price ruling on the date of such acceptance.

8. Upon the conclusion of the sale in terms of paragraph 7, the Trust shall issue to the applicant one unit certificate representing the units issued in favour of the child. Each such certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the certificate and the name of the child who alone is entitled to the units comprised in the certificate. The certificate will bear the legend "Children's Gift Plan, 1970" and such certificate shall not be transferable.

9. It should be clearly understood that the rights to units issued under the Plan will vest only with the child in whose name the relevant unit certificate has been issued by the Trust and that the units are issued by the Trust and to be held by the child, only in accordance with the terms of this Plan. The applicant, at whose instance the units have been issued in favour of the child, will not have any rights whatsoever, to these units.

10. Further, the child, in whose name the unit certificate has been issued can deal with the units comprised therein only from the date on which he or she completes the age of 21.

11. Till the completion of the age of 21, income distribution due on the units comprised in the certificate and on the units deemed to have been allotted under paragraph 12 herein below shall be deemed to have been automatically reinvested in further units by the Trust in accordance with the provisions of the Plan.

12. The entire amount of income distribution shall be deemed to have been applied towards purchase of units, including fractional units, at the sale price ruling on the date of commencement of sale of units in the new accounting year beginning in July.

13. No unit certificate shall, however, be issued with respect to units deemed to have been allotted under paragraph 12 except as provided for in paragraphs 16 and 17.

14. When the child reaches the age of 21, on his surrendering to the Trust the unit certificate issued in terms of paragraph 8, the Trust shall repurchase (i) the units comprised in the certificate, and (ii) the units deemed to have been allotted from out of the income distribution in terms of paragraph 12, at the ruling repurchase price of units, on the date the child has completed the age of 21.

15. Where, however, the child, who has attained the age of 21, desires to hold all units including units deemed to have been allotted under paragraph 12 or part thereof, he can, in the case of the Unit Scheme 1964, do so only with respect to such number of units as is a multiple of ten nearest to the whole number of units or part thereof, as the case may be and in the case of any other unit scheme, in accordance with similar provisions thereof, if any, the balance of units, if any, being repurchased by the Trust at the ruling repurchase price on the date the child has completed the age of 21.

16. The Trust shall issue a fresh unit certificate with respect to units desired to be held in accordance with paragraph 15 above and the provisions of this Plan shall cease to be applicable to the units comprised in the certificate.

17. In the event of the child dying before the completion of age of 21, the executors or administrators of the deceased or holder of a succession certificate issued under the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units comprised in the certificate issued in favour of the deceased child and the units deemed to have been allotted under paragraph 12. On the certificate being surrendered, the Trust shall.

(a) issue to the persons so entitled a unit certificate covering the units comprised in the certificate surrendered as well as the units deemed to have been allotted, up to the nearest multiple of 10 and

(b) re-purchase the balance of units (including fractional units), if any, deemed to have been allotted at the ruling re-purchase price on the date of the death of the child.

The provisions of this Plan shall not apply to the units comprised in the certificate issued under this paragraph.

18. Once a year, shortly before the child's birthday, the Trust shall forward to the applicant a statement setting out, among other things, the number of units issued to the child, the number of units deemed to have been allotted from out of the income distribution in pursuance of paragraph 12 and their cash value at current prices. In the event of death of the applicant, the said statement shall be sent to the person nominated by the applicant in this behalf.

19. The provisions of the Plan shall come into force from July 1, 1970 and shall be in operation till amended or terminated as provided hereafter.

20. The Trust may amend this Plan in such manner and to such extent as it may consider expedient, without however, altering the fundamental basis of the Plan, whereupon the Plan as amended will govern also the units issued or deemed to have been issued. Any such amendment shall be published in not less than four daily newspapers circulating in India.

21. The Trust may terminate the Plan as a whole by publishing a notice in not less than four daily newspapers circulating in India. Such notice shall specify the date on which the termination shall take effect.

APPLICATION FORM CHILDERN'S GIFT PLAN 1970

To,

THE UNIT TRUST OF INDIA,
'Engineering Centre',
9, Mathew Road,
Bombay-4.

Dear Sirs,

1. I am interested in participating in the Children's Gift Plan, 1970.
2. I request you to issue——————————units
(in words) (in figures)

of the Unit Scheme 1964 in accordance with the terms of the above Plan in favour of the child, detail of whom are given below.

3. I am not a minor.
4. I am a resident of India.
5. Details regarding the minor

(a) Full Name — Shri / Shrimati..... / Kumari

(b) Residence Status — Resident in India..... / Shri..... / ..... / .....

(c) Father's name

(d) Address of the Minor

(e) Age* .....Date of Birth* .....
*Birth certificate or a certificate from a Magistrate should accompany the application.

6. The statement referred to in paragraph 18 of the plan may be sent to me at the address given below and, in the event of my death to Shri / Kumari / Shrimati ..... (name)
.....
(address)

Signature of Applicant.....
Applicant's full name.....
Applicant's Full Adress.....
Place.....
Date.....

Unit-Linked Insurance Plan-1971

Provisions of the Plan

In exercise of the powers conferred by Section 19(1) (cc) of the Unit Trust of India Act 1963, the Board o Trustees of the Unit Trust of India hereby make th following Plan.

1. This Plan shall be called 'The Unit Linked Insurance Plan, 1971'.

2. The Plan shall be applicable to units issued unde the Unit Scheme 1971, as also under any other scheme which the Trust may make hereafter and to which it ma make the Plan applicable.

3. An individual who, as of the date of application, ha completed 18 years of age, but not 45 years of age, i eligible for participation in the Plan.

4. Women are eligible for participation provided the have (i) regular income of their own; and (ii) they ar not pregnant at the time of admission to the Plan.

5. Every person desirous of participating in the Plan shall :

(a) complete the application form specified by the Trust;

(b) furnish evidence of age, in the manner prescribed by the Trust, along with the application; and

(c) furnish evidence of good health by making a declaration in the manner specified by the Trust in this behalf.

6. Normally, applicants who are unable to complete the form of declaration of good health to the Trust's satisfaction will not be admitted into the Plan.

7. The period of saving under this Plan shall be ten years from the date of admission by a member.

8. Contributions under the Plan shall be made by a member every half-year, or annually at his option as agreed upon before commencement of his participation in the Plan.

9. Each intending member shall make a contribution at the time of admission into the Plan. Minimum contribution by a member shall be Rs. 150 for half-yearly and Rs. 300 for annual payments.

10. Contributions above the minimum shall be in multiples of five and shall be subject to a maximum of Rs. 600 for half-yearly and Rs. 1,200 for annual payments.

11. Contributions to the Trust shall be made by bank draft, cheque or money order, or cash, or in any other manner as may be specified by the Trust in this behalf. Cheques or bank drafts shall be drawn in the name of the Unit Trust of India and made payable at such place as the Trust may specify in this behalf. Cheques and Bank drafts should be crossed 'Account Payee'.

12. In the case of half-yearly contributions, a member shall pay his contribution once in every alternate quarter of the accounting year of the Trust beginning from July each year (*viz.* July—September, October—December, January—March and April—June). Payments in the case of annual contributions should be made in the relevant quarter once every year. The Trust shall advise a member, in advance, with respect to each of the contribution due from him.

13. The last date by which contributions should reach the Trust is as follows :

Periodicity of the contribution	Last date for receipt of contribution
(i) *Half-Yearly*	
For those joining during—	
July-September	10th July and
January-March	10th January
October-December	10th October and
April-June	10th April
(ii) *Annual*	
For those joining during—	
July-September	10th July
October-December	10th October
January-March	10th January
April-June	10th April

14. The Trust shall, as soon as possible, advise each member of his admission into the Plan along with his membership number and the receipt of his initial contribution made in accordance with paragraph 9 above. In all his correspondence with the Trust, a member shall quote his membership number.

15. A suitable acknowledgement or receipt will be issued by the Trust in the case of subsequent contributions sent through cheques, bank drafts or money orders. In the case of a contribution tendered in cash over the counter at the office/s of the Trust also, an acknowledgement shall be made.

16. Contributions received from members reduced by amounts payable to the Life Insurance Corporation of India shall be utilised towards allotment of units to them in accordance with the provisions of this Plan.

17. Out of the initial contribution made by a member, as many units, including fractional units, shall be allotted, as could be purchased at the ruling sale price of units on the date payment is received by the Trust in cash, cheque or draft.

18. Allotment of units, including fractional units, from out of the subsequent contributions shall be made on the 15th (or, if it happens to be a holiday, the next working day of the Trust's office in Bombay) of July, October, January and April for contributions relating to, respectively, the July—September, the October—December, the January—March and the April—June quarters, at the ruling sale price of the units on that day.

19. The whole of the Income distributions on the units allotted under the Plans, as also in respect of other units acquired under it, as long as a member continues to participate in the Plan, shall be applied by the Trust for reinvestment in units, including fractional units, in accordance with the provisions of this Plan.

20. No unit certificate shall be issued to a member with respect to the units acquired under this Plan except as provided for in paragraphs 21 and 26 below.

21. On completion of the ten year period of saving, a member will be issued a unit certificate, with respect to the units to his credit, fractions, if any, being rounded off to the nearest whole number.

22. However, if the member so desires and makes a specific request to the Trust in this behalf, he shall be paid, on completion of his Plan period, cash equivalent of all the units to his credit, calculated by applying the repurchase price ruling the date the Plan was completed.

23. In the event of death of the member within the plan period, the executors or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act 1925 (39 of 1925) shall alone be entitled to receive from the Trust :

(a) all the units purchased and held by the Trust to the credit of the deceased member, and

(b) the amount payable by the Life Insurance Corporation of India on the life of the deceased member, detailed in paragraph 24 below.

24. Under this plan, subject to what is stated in paragraph 25 below, the amount or insurance on the life of a member payable by the Life Insurance Corporation of India on the death of the member within the ten year period of saving is the sum which is equal to the difference between the *total* amount of contributions to be made by the member under the plan over the ten year period and the contributions actually made, including contributions due but not made, till the death of the member.

25. In the event of death of the saver occurring at any time during the first two years from the date of

commencement of his participation in the plan, the amount of insurance cover will be limited as follows :

Period since the commencement of membership	Insurance benefit of Death
(i) Less than one year	Refund of insurance premiums paid upto the date of death.
(ii) 1 year or more, but less than 1½ years.	25% of the cover described in paragraph 24 above.
(iii) 1½ years or more but less than 2 years.	50% of the sum assured.

However, in the event of death due to accident, the foregoing restrictions will not apply and the full amount of the cover will become payable.

26. Any person becoming entitled to the benefits under the plan, in the event of death of the member, in terms of paragraph 23 above, may, upon providing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be (a) issued a unit certificate in his name, with respect to the units to the credit of the deceased member, fractions, if any, being rounded off to the nearest whole number and (b) paid the amount of insurance on the life of the deceased member. However, in respect of (a), the Trust may pay the cash equivalent of *all* the units, if so desired by the applicant.

27. The Trust shall issue a fresh unit certificate with respect to units desired to be held in accordance with paragraph 26 above and the provisions of this Plan shall cease to be applicable to the units comprised in the certificate.

28. Contributions by members should reach the Trust by the dates specified in paragraph 13. A period of fifteen days as a grace period may be allowed by the Trust, at its discretion. With respect to these contributions received after the due date, units shall be allotted at the sale price ruling on the date the contribution was received in the Trust's office. Where the contribution from a member is in default even after the expiry of the grace period, the member whose contribution is in default shall cease to participate in the plan, forthwith. Insurance cover on the life of the member will also terminate simultanously.

29. A member whose participation in the Plan stands terminated in terms of paragraph 28 above, may revive his participation, not later than one year from the due date of the first instalment of contribution in default, subject to such terms and conditions as may be prescribed by the Trust in consultation with the Life Insurance Corporation. Erstwhile members desirous of reviving their membership in the Plan should contact the Trust's offices.

30. A member can terminate his participation in the Plan by giving notice of not less than a month, in writing to the Trust.

31. In the event of termination of membership in terms of paragraph 28 or 30 above, the erstwhile member will be issued a unit certificate with respect to the units to his credit, fractions, if any, being rounded off to the nearest whole number. Before doing so, however, the Trust shall be entitled to recover, towards administrative charges, a sum not exceeding Rs. 50.

32. The Trust shall send to each member, as soon as possible, after the close of the accounting year, a statement as at the end of the accounting year, setting out for the period to which it relates :

(i) Units purchased and outstanding at the commencement of the period,

(ii) Particulars of contributions received during the period,

(iii) Particulars of units purchased during the period,

(iv) Income distribution on the units issued and reinvested, and

(v) Unit issued and outstanding at the end of the period.

33. The provisions of the plan shall come into force from October 1, 1971, and shall be in operation till amended or terminated as provided hereafter.

34. The Trust may amend this plan in such menner and to such extent as it may consider expedient, without, however, altering the fundamental basis of the Plan. Any such amendment shall be published in not less than four daily newspapers circulating in India.

35. The Trust may discontinue the plan as a whole in respect of new entrants by publishing a notice in not less than four daily newspapers circulating in India. Such notice shall specify the date on which the termination shall take effect.

APPLICATION FORM FOR UNIT-LINKED INSURANCE PLAN 1971

To,

THE UNIT TRUST OF INDIA,

Dear Sirs,

I am interested in participating in the Unit-Linked Insurance Plan, 1971.

2. I have read the provisions of the Plan and agree to abide by them.

3. I wish to join the Plan for a sum of Rs.———— (in figures) ———— (in words) and I hereby agree to make half-yearly/annual contributions of Rs. ———— per contribution, in accordance with the provisions of the Unit-Linked Insurance Plan, 1971. My first half-yearly/annual contribution of Rs. ———— is sent herewith.

4. I am not a minor.

5. My age is ————; and date of birth ———— I furnish herewith, as proof. Municipal Certificate of Birth/Certificate of Baptism/Original horoscope/School or College Certificate/Extract from service record of the employer provided the employer admits age on the basis of a standard proof/Letter from the Life Insurance Corporation certifying the date as that admitted by it.

6. I am a resident of India.

7. I am/am not a member of the Plan.

8. My membership No. is ———— and my annual contribution is Rs. ————.

Yours faithfully,

Date :

Place : Signature of Applicant

Applicant's full name :
Occupation :
Applicant's full address :

UNIT-LINKED INSURANCE PLAN, 1971

Form of Declaration of Health :

1. Are you at present in sound health ?

2. Have you ever suffered from any of the following :

(i) Tuberculosis (ii) Cancer (iii) Paralysis (iv) Insanity (v) Any disease of the heart and lungs (vi) Kidney disease (vii) Any disease of the brain (viii) Diabetes (ix) Hypertension (x) Any other serious disease.

For female applicants

I hereby declare that I am not pregnant now/* and all earlier deliveries have been normal and gone full time.

* Where applicable.

For all applicants (including female applicants)

I hereby declare that I am in good health and free from disease, that I have not had any serious illness or major operation for the last five years and that no proposal of insurance on my life to the Life Insurance Corporation of India has ever been adversely treated.

I further declare that to the best of my knowledge the foregoing statements and answers are true and correct in every particular and the said statements and this declaration shall be the basis for my admission to the Unit Trust's Unit-Linked Insurance Plan.

Date :

Place :

(Signature of the Applicant)

(To be completed by an Officer of the UTI or an authorised agent of UTI)

The applicant has completed and signed the above declaration in my presence. From his appearance and to the best of my judgment I find that he is in good health and has a sound constitution. His date of birth is—— ———— according to the *———— ———— submitted in proof of the age of the applicant.

The applicant has been introduced to me by ———— ———— whose signature is appended below :

Date :	Signature of the Officer or authorised agent of U. T. I.
Place :	Designation :
	Signature of the witness identifying the applicant
	Name : (BLOCK CAPITALS)
Date :	Occupation :
Place :	Address :

* The nature of proof should be stated by the Officer completing the declaration. The date of birth should be recorded on the basis of a standard proof such as (i) Municipal Certificate of birth (ii) Certificate of Baptism (iii) Original Horoscope (iv) School or College Certificate (v) Extract from service record of the employer provided the employer admits age on the basis of a standard proof or (vi) Letter from the Life Insurance Corporation certifying the date as that admitted by it.

MEMBERSHIP CERTIFICATE

(Issued under and in accordance with the provisions of Unit-Linked Insurance Plan, 1971).

1.	Name of Member	
2.	Membership No.	
3.	Period of Saving	Ten years
4.	Target Amount	Rs.
5.	Mode of contribution	Half-yearly/Annual
6.	Amount per contribution	Rs.
7.	Age nearer birthday at commencement	
8.	Date of expiry of membership	
9.	Benefit under the Plan	

On the completion of the ten year period of savings, a member shall be entitled to all the units accumulated to his credit under the provisions of this Plan (clauses 21 and 22 of the Plan).

In the event of the member's death *within* the period of the Plan, the successors to the deceased member are entitled to (a) all the units accumulated to the credit of the deceased member till his death and (b) the amount payable by the Life Insurance Corporation of India on the life of the deceased member.

The amount of insurance on the life of a member participating in the Plan, payable by the Life Insurance Corporation of India at any time, is equal to the difference between the total amount of contributions to be made to the Unit Trust of India by the member over the entire period (10 years) of the Plan and the contributions actually made, including contributions due but not made till the death of the member, subject to a maximum of Rs. 12,000.

However, in the event of death of the member occurring at any time during the first two years from the date of his participation in the Plan, the amount payable by the Life Insurance Corporation is limited as follows :

(i) Less than one year	Refund of premium paid to the Life Insurance Corporation.
(ii) One year or more, but less than 1-1/2 years.	25 per cent of the insurance cover detailed in the preceeding paragraph.
(iii) 1-1/2 years or more, but less than 2 years.	50 per cent of the insurance cover detailed in the preceeding paragraph.

However, in the event of death due to accident, the foregoing restrictions will not apply and the full amount of the cover will become payable.

Note : This certificate is issued only for the information of the member and is not a legal document conferring any right or title on the member. It cannot be assigned, mortgaged, transferred or dealt with in any way.

Place :

Date :

For *the Unit Trust of India*

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 22nd November 1971

No. INS. I.22(1)1/71(8).—In pursuance of the powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director-General has fixed the 28th November, 1971 as the date from which the medical benefit as laid down in the said Regulation 95-A and the Madras Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954, shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

I. The area within the limits of revenue village of :— Pandaravadai Perumandi in Kumbakonam Taluk of Thanjavur district.

II. The areas within the revenue villages of :—

(1) Mela Thiruvengadanathapuram (2) Thiruvengadanathapuram (3) Suthamalli (4) Kunnathur (5) Thenpathu (6) Kandiaperi (7) Vilagam (8) Keela Thiruvengadanathapuram (9) Tharuvai (10) Munnirpallam (11) Karungadu and (12) Karuppanthurai in Tirunelveli Taluk of Tirunelveli District.

No. INS.I.22(1)1/71(9).—In pursuance of the powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director-General has fixed the 26th December, 1971 as the date from which the medical benefit as laid down in the said Regulation 95-A and the Mysore Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958, shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of Mysore namely :—

Sl. No.	District	Taluk	Hobli	Name of the village
1.	Bangalore	Bangalore South Tq.,	Krishna-rajapuram	White-Field
2.	Bangalore	Bangalore South Tq.,	Krishna-rajapuram	Sadaramangala
3	Bangalore	Hoskote	Bidarahalli	Kadugodi
4.	Bangalore	Hoskote	Bidarahalli	Belthur

No. INS.I.22(1)1/71(10).—In pursuance of the powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director-General has fixed the 26th December, 1971 as the date from which the medical benefit as laid down in the said Regulation 95-A and the Assam Employees's State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958, shall be extended to the families of insured namely :—

The areas comprised within the Revenue villages of :—

I. Chotatingrai T. E. Upper Assam Tea Co., Ltd., Grant No. 54 F.5. in Tipling Mauza in Lakhimpur District;

II. Hengaluguri and Bazaltoli Goan in the Ranpagar Mauza in Lakhimpur District.

V. N. KAUL
Deputy Insurance Commissioner

No. 6(1)/69-Estt.III.—In surance of Section 25 of the Employees's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 and in continuation of Corporation's Notification of even Number dated the 28th July, 1971, the Chairman, Employees' State Insurance Corporation is pleased to nominate the following employers and employees additional representatives on the Regional Board, Tamil Nadu Region.

Now, therefore, the following further additions are made in the Corporation's Notification of even number dated the 28th July, 1971 :—

After the entry No. 9, the following entries shall be added, namely :—

"10. Shri M. M. Muthiah, Managing Director, Messrs Carborandum Universal Ltd., Madras.	Employers' additional representative nominated by the Chairman, E. S. I. Corporation.
11. Shri M. A. Alagappan, Director M/s. Ambadi Enterprises Pvt. Ltd., 11/12, North Beach Road, Madras-1.	Do.
12. Shri R. Subramanyam, Personal Manager, Carborundum Universal Ltd., 11/12 North Beach Road, Madras-1.	Do.
13. Shri M. S. Ramchandran, I.N.T.U.C. 107,-New Jail Road,	Do.
14. Shri K. M. Sundaram, General Secretary, Tamil Nadu, A.I.T.U.C. 157-Broadway, Madras.	Do.
15. Shri K. C. Narayanan, Secretary, Madras Labour Union, 136, Stranhans Road, Perambur Barracks P. O Madras-12.	Do.

T. C. PURI
Director-General

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

NEW DELHI

NOTICE

Notice is hereby given that the TWENTY-THIRD ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA will be held on Monday, the 27th September, 1971, at 4.00 P.M. (Standard Time) at Hotel mperial, Janpath, New Delhi, to transact the following business :

(1) To read and consider the Balance Sheet of the Corporation and the Profit and Loss Account for the year ended the 30th June, 1971, together with the Report by the Board on the working of the Corporation throughout the year and the Auditors' Report on the said Balance Sheet and Accounts.

(2) To elect a Director in place of Shri N. Ramanand Rao, being a Director elected to represent shareholders referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, who retires, but is eligible for re-election under Section 11 of the Act.

(3) To elect a Director in place of Shri N. V. Nayudu, being a Director elected to represent shareholders referred to in clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, who retires, but is eligible for re-election under Section 11 of the Act.

(4) To elect a Director in place of Shri P. S. Rajagopal Naidu, being a Director elected to represent shareholders referred to in clause (e) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, who retires, having served two full consecutive terms of 4 years each, and is therefore not eligible for re-election in accordance with the third proviso to sub-section (2) of Section 11 of the Act.

(5) To elect under Section 34 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, one Auditor duly qualified to act as Auditor of Companies under Section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) by the parties mentioned in sub-section (3) of Section 4 of the Industrial Finance Corporation Act, namely scheduled banks, insurance companies, investment trusts and other like financial institutions, and co-operative banks, in place of Messrs. S. B. Billimoria and Company, Bombay, who retire but are eligible for re-election.

14th July, 1971

BALDEV PASRICHA
General Manager

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

Board of Directors

C. D. Khanna	*Chairman*
G. Ramanujam	Nominated by the Industrial Development Bank of India.
F. K. F. Nariman	
Dr. Samuel Paul	
Dr. V. V. Bhatt	
B. B. Lal	Nominated by the Central Government.
M. K. Venkatachalam	
N. Ramanand Rao	Elected to represent Scheduled Banks.
S. J. Utamsing	
Sardar Santokh Singh	Elected to represent Insurance concerns, Investment Trusts and other like financial institutions.
N. V. Nayudu	
P. S. Rajagopal Naidu	Elected to represent Co-operative Banks.
N. A. Kalyani	

Central Committee

C. D. Khanna	*Chairman*
B. B. Lal	Elected by the nominated Directors.
M. K. Venkatachalam	
N. A. Kalyani	Elected by the elected Directors.
Sardar Santokh Singh	

Bankers

RESERVE BANK OF INDIA

Auditors

M/s. S. B. Billimoria & Co.	*Chartered Accountants*
M/s. Walker Chandiok & Co.	*Chartered Accountants*

MEMBERS OF THE ADVISORY COMMITTEES

Chemical Process & Allied Industries

C. D. Khanna, *Chairman*
N. A. Kalyani
Sardar Santokh Singh
D. S. Seth
S. K. Mukherjee
C. J. Dadachanji
G. P. Kane
Jayant J. Mehta
R. V. Ramani
A. Seetharamaiah
L. Kumar
V. N. Kasturirangan

SUGAR

C. D. Khanna, *Chairman*
P. S. Rajagopalan Naidu
N. A. Kalyani
S. N. Gundu Rao
J. K. Bhosale
A. Das
S. V. Sampath
M. M. K. Wali
N. S. Jain

ENGINEERING

C. D. Khanna, *Chairman*
N. A. Kalyani
S. J. Utamsing
K. C. Maitra
Pranlal Patel
P. R. Deshpande
B. N. Khosla
A. K. Sen
B. D. Kalelkar
K. B. Rao
Hari Bhushan

TEXTILES

C. D. Khanna, *Chairman*
P. S. Rajagopal Naidu
G. Ramanujam
Sardar Santokh Singh
N. Mazumder
B. Raha
K. Sundaram
C. S. Ramachary
S. A. Kher
K. Kishore
I. B. Dutt
A. Das
M. M. Wali

MISCELLANEOUS INDUSTRIES

C. D. Khanna, *Chairman*
S. J. Utamsing
F. K. F. Nariman
K. C. Maitra
R. Chakravarthy
G. P. Kane
B. N. Raman
A. Seetharamiah

JUTE

C. D. Khanna, *Chairman*
N. Ramanand Rao
S. J. Utamsing
S. Paul
Hari Shankar Singhania
S. L. Mehta
S. P. Mukherjee
B. D. Kumar
R. Mahadvan

OUTLINE OF THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

Incorporation and purpose

The I.F.C. was established in 1948 under an Act of the Indian Parliament, with the object of making medium and long-term credits to industrial concerns in India.

Capital

Fifty per cent of the paid-up capital now standing at Rs. 8.35 crores is held by the Industrial Development Bank of India (I.D.B.I.), which is a wholly-owned subsidiary of the Reserve Bank of India. The remaining 50% is held by scheduled banks, co-operative banks, insurance concerns and investment trusts, etc.

Management

The Board of Directors consists of a whole-time Chairman appointed by the Central Government after consultation with the I.D.B.I. and twelve directors. Six directors are elected by share-holders other than the I.D.B.I. Four directors are nominated by the I.D.B.I. and two by the Central Government.

Functions and Lending Policies

Any public limited company or co-operative society incorporated and registered in India which is engaged, or proposes to engage itself in the manufacture, preservation or processing of goods, or in the shipping, mining or hotel industry or in the generation or distribution of electricity or any other form of power, is eligible for financial assistance. Public sector projects, which are set up as public limited companies, can also receive assistance from the I.F.C. on the same basis as industrial projects in the private sector. Financial assistance, on concessional terms, is available for setting up industrial projects in certain industrially less developed districts in the States/Union Territories notified by the Central Government.

Assistance may take the shape of long-term loans—both rupee and foreign currency; underwriting of equity, preference and debenture issues; subscribing to equity, preference and debenture capital; guaranteeing of deferred payments in respect of machinery imported from abroad or purchased in India and guaranteeing of loans raised in foreign currency from foreign financial institutions as also those raised in rupees from scheduled banks or State Co-operative Banks or floated in the public market. The resources of the I.F.C. are available for the setting up of new industrial projects as also for renovation, modernisation, expansion or diversification of existing ones.

Sources of Funds

The main sources of funds of the I.F.C., other than its own capital, retained earnings, repayment of loans and sale of investments, are borrowings from the market by the issue of bonds, loans from the Central Government and foreign credits.

HIGH LIGHTS OF OPERATIONS

	As on 30-6-70	As on 30-6-71	
	Rupees in crores	Rupees in crores	U. S. equivalent in million
Capital and Reserves			
Paid-up Capital	8·35	8·35	11·13
Reserves	12·65	14·24	19·00
Total	21·00	22·59	30·13
Sanctions (Net)			
—Rupee loans	213·30	238·67	318·23
—Foreign currency loans	37·97	43·58	58·11
—Underwritings	25·68	29·01	38·68
—Direct subscriptions	2·01	2·48	3·31
—Guarantees for deferred payments	28·04	28·46	37·94
—Guarantees for foreign loans	23·47	23·47	31·29
Total	330·47	365·67	487·56

Disbursements			
—Rupee loans	196·43	209·61	279·48
—Foreign currency loans	32.37	35.47	47.29
—Underwritings	19·84	20·57	27·42
—Direct subscriptions	1·99	2·13	2·84
—Guarantees for deferred payments issued	27·45	27·65	36·87
—Guarantees for foreign loans issued	23·33	23·33	31·11
Total	301·41	318·76	425·01
Outstandings			
—Rupee loans	128·06	133·32	177·76
—Foreign currency loans	25·16	26·09	34·79
—Underwritings	15·29	15·61	20·81
—Direct subscriptions	2·48	2·41	3·21
Guarantees for deferred payments issued	8·24	7·05	9·40
—Guarantees for foreign loans issued	16·15	13·65	18·20
Total	195·38	198·13	264·17
Number of industrial units financed	499	527	
Earning for the year			
—Gross income	12·82	13·46	17·95
—Gross profit before taxation	4·33	4·47	5·96
—Provision for taxation	2·37	2·37	3·16
—Net Profit	1·96	2·10	2·80

Notes : 1. Figures of net sanctions and number of industrial units financed as on 30-6-1970 do not coincide with those given in the Annual Report for that year due to certain cancellations/adjustments made during the current year in respect of financial assistance sanctioned upto 30-6-1970.

2. The number of industrial units financed is the number of units to which financial assistance, of one or more types on one or more occasions, has been sanctioned. In point of fact, many of these industrial units have received from the Corporation assistance of more than one kind and many have received assistance more than once.

SUMMARY OF FINANCIAL OPERATIONS

(Crores of Rupees)

	Upto 30-6-1970			During the year ended 30-6-1971			Total as on 30-6-1971			Amount out-standing as on 30-6-71
	Sanctions (net)		Amount disbursed	Sanctions (net)		Amount disbursed	Sanctioned (net)		Amount disbursed	
	No.	Amount		No.	mount		No.	Amount		
1. **Loans**										
—Rupees	639	213.30	196.43	45	25.37	13.18	684	238.67	209·61	133.32
—Foreign currency	135	37·97	32·37	22	5·61	3·10	157	43·58	35·47	26·09
TOTAL	774	251·27	228·80	67	30·98	16·28	841	282·25	245·08	159·41
2. **Underwritings**										
—Equity shares	121	10·31	7·68	9	0·91	0·11	130	11·22	7·79	6·64
—Preference shares	96	6·64	4·58	7	0·42	0·62	103	·06	5·20	4·42
—Debentures	20	8·73	7·58	1	2·00	—	21	1·73	7·58	4·73
TOTAL	237	25·68	19·84	17(a)	3·33	0·73	254(c)	29·01	20·57	15·61
3. **Direct Subscriptions**										
—Equity shares	5	0·17	0·15	8	0·37	0·11	13	0·54	0·26	0·75(d)
—Preference shares	1	0·02	0·02	3	0·10	0·03	4	0·12	0·05	0·29(d)
—Debentures	1	1·82	1·82	—	—	—	1	1·82	1·82	1·37
TOTAL	7	2·01	1·99	11(b)	0·47	0·14	18	2·48	2·13	2·41
Total of 1 to 3	1018	278·96	250·63	95	34·78	17·15	1113	313·74	267·78	177·43
4. **Deferred payment guarantees**	41	28·04	27·45	1	0·42	0·20	42	28·46	27·65	7·05
5. **Guarantees for foreign loans**	5	23·47	23·33	—	—	—	5	23·47	23·33	13·65
TOTAL of 1 TO 5	1064	330·47	301·41	96	35·20	17·35	1160	365·67	318·76	198·13

(a) Sanctions in respect of equity and preference shares in 7 cases have been accounted for separately.
(b) Sanctions in respect of equity and preference shares in 2 cases have been accounted for separately.
(c) Sanctions in respect of equity and preference shares in 75 cases have been accounted for separately.
(d) Includes Rs. 0.67 crore being part of the outstanding loans of 4 companies converted into share and Rs. 0.06 crore of convertible debentures of another company converted into equity shares.

NOTE : Figures on 30-6-1970 do not coincide with those given in the Annual Report for that year due to certain cancellations/adjustments made during the current year in respect of financial assistance sanctioned upto 30-6-1970.

THE YEAR IN BRIEF

During the year ended June 30, 1971, the Corporation approved financial assistance of Rs. 35.32 crores (gross) for 61 industrial projects compared to assistance of Rs. 19.38 crores for 49 projects approved during the previous year.

The aggregate cost of the 61 projects for which assistance was sanctioned during 1970-71 is estimated at about Rs. 190 crores. Of the projects assisted, 24 were new projects accounting for about 50% (Rs. 20.87 crores) of the total sanctions for the year.

The projects assisted during the year 1970-71 covered a wide range of industries, including priority industries like alloy steels, tractors, cement and aluminium. Other industries which claimed substantial assistance were sugar, synthetic fibres, iron & steel, electrical machinery, cotton textiles, and metal products. The sanctions, in respect of 61 projects, were spread over 13 States. Eleven approved projects in 7 States would be located in districts notified by the Central Government as backward or industrially less developed. Financial assistance extended to such projects aggregated Rs. 8.32 crores, accounting for about 24% of the total sanctions for the year.

As in the previous year, during 1970-71 also, sugar and textile co-operatives claimed sizeable assistance, which was of the order of Rs. 9.15 crores being about 26% of the total sanctions. The Corporation sanctioned assistance for 8 sugar co-operatives and 2 textile co-operatives; four sugar co-operatives and one textile co-operative, are located in notified industrially less developed districts.

Pursuance to the new policy of public sector undertaking eligible for assistance from the all-India financial institutions, two public sector projects were sanctioned loans for projects involving the manufacture of tele-communication cables and electrical equipment.

The working results for the year disclose a higher income of Rs. 13.46 crores, compared with Rs. 12.82 crores for the year 1969-70. The gross profit of Rs. 4.47 crores registered an increase of Rs. 0.14 crore over the previous year. After making provision for taxation to the extent of Rs. 2.37 crores, the net profit, of Rs. 2.10 crores, was higher by Rs. 0.14 crore compared to previous year. Additions made to reserves were to the extent of Rs. 1.69 crores, bringing the total reserves of the Corporation to Rs. 14.24 crores, which exceed the paid-up capital by Rs. 5.90 crores.

With a view to meeting the existing and future commitments on rupee loans, as also to reducing its dependence on borrowings from the Central Government, the Corporation made in November, 1970, a Bond issue for Rs. 4.50 crores. Including the permissible 10% of the amount issued, the Corporation was able to raise subscriptions to the extent of Rs. 4.95 crores.

During the year, a further line of credit for DM 10 million from the Kreditanstalt of West Germany was allocated to the Corporation. An allocation of £ 1 million under the UK/India Capital investment Loan, 1969 was also made to the Corporation. Documentation in connection with a further allocation of UK credit to the extent of £ 1 million under the UK/India Capital Investment Loan, 1971 is expected to be completed shortly.

During the year, the Corporation raised its leading rates. The effective rate of interest on rupee loans was raised from 8% to 8½% p.a. with effect from the 5th December, 1970. The effective rate of interest on sub-loans to foreign currencies was increased from 8½% to 9% p.a. with effect from the 27th February, 1971.

A sub-office of the Corporation started functioning at Gauhati with effect from the 17th May, 1971. A Branch of the Corporation was opened at Ahmedabad on the 18th August, 1971. Arrangements are under way for opening additional offices of the Corporation at Hyderabad, Bangalore, Kanpur, Patna, Bhubaneshwar and Bhopal. It is hoped that with the opening of additional offices, the Corporation would be able to render better service to its existing and prospective clients

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA —1970-71

The Board of Directors present herewith their Twenty-third Report on the working of the Corporation, together with the Audited Statement of Accounts, for the year ended the 30th June, 1971.

REVIEW OF THE CORPORATION'S OPERATIONS DURING THE YEAR

2. The following table indicates the financial assistance sanctioned and disbursed during the year :

TABLE 1

(Crores of Rupees)

	Assistance sanctioned (Gross)		Assistance disbursed
	Number of applications	Amount	Amount
(i) Rupee loans	46(45)	25·49(25·37)	13·18
(ii) Foreign currency loans	22	5·61	3·10
(iii) Underwritings	10 (a)	3·33	0·73(c)
(iv) Direct subscriptions	9 (b)	0·47	0·14
Total of (i) to (iv) :	87(86)	34·90 (34·78)	17·15
(v) Guarantees for deferred payments for plant & machinery	1	0·42	0·20(d)
Total of (i) to (v) :	88(87)	35·32 (35·20)	17·35

Note : Figures within brackets denote net effective sanctions, i.e., gross sanctions *minus* sanctions subsequently cancelled during the year.

(a) 7 cases cover both equity and preference shares.

(b) 2 cases cover both equity and preference shares.

(c) Amount called-up and paid-up on shares which devolved on the Corporation.

(d) Guarantees actually issued.

Industrial finance Corporation of India

3. The bulk of the assistance sanctioned during the year, *viz.* Rs. 25.49 crores was, as usual, in the form of rupee loans Sanctions for the year of Rs. 35.32 crores were higher by nearly 82% compared with the sanctions for the previous year of Rs. 19.38 crores.

Assistance disbursed during the year, of Rs. 17.35 crores, was somewhat lower compared to disbursement of Rs. 18.05 crores in the previous year. The slight decline in disbursements confined mostly to rupee loans is due to the lower quantum of assistance sanctioned during the previous year. Disbursements under foreign currency loans actually showed a rise from Rs. 1.69 crores in 1969-70 to Rs. 3.10 crores in 1970-71.

Cash disbursements during the year aggregated Rs. 17.15 crores as against Rs. 17.71 crores in the previous year. The details of cash disbursements are as under :—

	(Crores of Rupees)
(i) Rupee loans	13.18
(ii) Foreign currency loans	3.10
(iii) Investments in shares in pursuance of underwriting obligations/direct subscriptions	0.87
Total :	17.15

4. As on the 30th June, 1970, 51 applications from 34 concerns were pending with the Corporation for an aggregate amount of Rs. 127.99 crores including 17 applications from 9 concerns involving Rs. 113.29 crores of assistance which was intended to be extended jointly with other institutions. During the year under review 96 fresh applications were received from 70 concerns, covering rupee and foreign currency loans, underwriting of share and debenture issues and guarantees for deferred payments. In all, 88 applications from 61 concerns for a total assistance of Rs. 35.32 crores were sanctioned. 4 applications for assistance could not be sanctioned. 20 applications from 16 concerns were withdrawn either because the applicant concerns modified, postponed or abandoned their schemes or failed to comply with the conditions relating to the grant of financial assistance. Further, the processing of 29 applications (from 29 concerns) could not be taken up as the applicant concerns had not furnished all the requisite information and data.

At the end of the year, 41 applications from 28 concerns for assistance for an aggregate amount of Rs. 94.40 crores were pending disposal. These included 9 applications from 4 concerns for assistance aggregating Rs. 77.88 crores, intended to be provided jointly with other institutions; applications from two fertiliser projects alone accounted for an aggregate amount of Rs. 73.23 crores. These could not be processed because some of the basic aspects of the projects remained to be sorted out before these could be considered ripe for appraisal. Amongst the pending applications, there were 10 from sugar co-operatives for assistance aggregating Rs. 10.27 crores and one from a co-operative spinning mill for Rs. 1.00 crore. Some of the applications from sugar co-operative could not be taken up for appraisal because they had not been able to collect adequate share capital, because by the very nature the collection of share capital in their case is a gradual process.

A detailed statement showing the number and amount of applications pending at the beginning of the year, applications received, sanctioned, rejected or withdrawn, and the amount disbursed, during the year to industrial units in the different States is attached as Appendix 'A' to the Report.

Rupees Loans

5. During the year, 46 rupee loans for an aggregate amount of Rs. 25.49 crores were sanctioned, two applications were declined, and thirteen applications were treated as withdrawn. Disbursements during the year amounted to Rs. 13.18 crores.

FOREIGN CURRENCY LOANS

6. Foreign currency loans for an aggragate amount equivalent to Rs. 5.61 crores were sanctioned during the year in respect of 22 applications. The currency-wise distribution of these loans is shown in Table 2.

TABLE 2

Currency	Number of subloans	Foreign currency (In-Million)	Rupee equivalent (In Lakhs)
West German Marks	21	25·90	530·78
£Sterling	3	0·12	21·51
French Francs	2	0·65	8·81
TOTAL ..	26		561·10

Letters of Credit in foreign currencies for an aggregate amount equivalent to Rs. 2.40 crores were issued in favour of foreign machinery suppliers. Under the French Credit available with the Corporation, Letters of Commitment were issued in favour of Banque Francaise du Commerce Exterieur, Paris (BFCE), relating to two equipment contracts for an aggregate amount equivalent to Rs. 17.83 lakhs (FF 1.32 million).

Disbursements during the year amounted to DM 12.18 million (Rs. 249.49 lakhs), US $ 0.57 million (Rs. 42.79 (lakhs) and FF 1.29 million (Rs. 17.48 lakhs).

UNDERWRITING OPERATIONS

7. During the year, sanction was accorded in respect of 10 underwriting applications for an aggregate amount of Rs. 333.15 lakhs, comprising equity shares of Rs. 91.00 lakhs, preference shares of Rs. 42.15 lakhs and debentures of Rs. 200.00 lakhs.

Ten issues (including two approved during the previous year) underwritten by the Corporation for equity and preference shares of the amount of Rs. 79.00 lakhs and Rs. 39.90 lakhs respectively were placed on the market. The devalution in respect of them amounted to equity shares of Rs. 10.28 lakhs and preference shares of Rs. 34.89 lakhs. Of the 10 cases in respect of which underwriting operations were completed, one equity issue underwritten by the Corporation to the extent of Rs. 20 lakhs was fully subscribed by the public, in respect of 3 others involving underwriting by the Corporation to the extent of Rs. 47.50 lakhs in equity shares and Rs. 17.65 lakhs in preference shares the equity portion was fully subscribed. The break-up of amounts underwritten and devolved on the Corporation in respect of the 10 underwriting operations completed during the year may be seen in the following table :—

TABLE 3

(Lakhs of Rupees)

	Amount underwritten	Amount devolved on the Corporation
Equity shares	79·00	10·28
Preference shares	39·90	34·89
TOTAL ..	118·90	45·17

The Corporation approved during the year direct subscriptions including Rights Issues to equity and preference shares to the extent of Rs. 37.01 lakhs and Rs. 9.99 lakhs respectively in respect of 9 companies.

GUARANTEES FOR DEFERRED PAYMENTS IN RESPECT OF PLANT AND MACHINERY

8. During the year, one application for an amount of Rs. 42.35 lakhs was sanctioned. Guarantees issued during the year amounted to Rs. 19.79 lakhs.

INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED

9. The industry-wise distribution of financial assistance sanctioned during the year under review is shown in table 4. It will be seen that coverage of industries has been quite comprehensive and many of them constitute key segments of the country's economy. The principal beneficiaries were, in order of size, the sugar industry, synthetic fibres, iron and steel, electrical machinery, cotton textiles, metal products, motor vehicles and non-ferrous metals.

The assistance of Rs. 8.29 crores sanctioned to the sugar industry was accounted for by eight units in the co-operative sector. In the case of cotton textiles, [illegible] spinning co-operative claimed Rs. 85.50 lakhs (i.e., 31.5%) of the total assistance of Rs. 2.73 crores sanctioned to this industry. These two spinning units represent the first spinning enterprises to be set up in the co-operative sector in Madhya Pradesh and Rajasthan; the one in Rajasthan has been located in a notified industrially backward district. Assistance sanctioned to sugar and textile co-operative aggregated Rs. 9.15 crores, which constituted about 26% of the total assistance sanctioned during the year.

Nylon filament yarn and polyester staple fibre among synthetic fibres, alloy steels transformers and tele-communication equipment, metal products, tractors and power tillers and aluminium in the non-ferrous metals group, were notable industries which received assistance during the year. Other industries assisted by the Corporation were manufacture of machinery, cement, chemicals, vegetable oil, coal, dehydration of vegetables, paper, hotel, wood and cork, etc.

TABLE 4

(Lakhs of Rupees)

Industry	Loans	Underwritings	Guarantees for deferred payments	Total	% of the whole	Number of Units
Sugar	829·00	—	—	829·00	23·5	8
Synthetic Fibres	435·00	55·00	42·35	532·35	15·1	5
Iron & Steel	211·50	267·25	—	478·75	13·6	4
Electrical Machinery	289·39	9·40	—	298·79	8·5	6
Cotton Textiles	268·06	5·00	—	273·06	7·7	9
Metal Products	233·80	10·60	—	244·40	6·9	7
Motor Vehicles	229·54	10·00	—	239·54	6·8	3
Non-ferrous Metals	170·00	—	—	170·00	4·8	1
Machinery	83·15	12·00	—	95·15	2·7	3
Paper	70·22	—	—	70·22	2·0	1
Misc. Chemical Products	70·00	—	—	70·00	2·0	2
Basic Industrial Chemicals	56·78	—	—	56·78	1·6	3
Cement	50·00	—	—	50·00	1·4	1
Vegetable and Animal Oil and Fats	25·00	7·00	—	32·00	0·9	1
Coal	32·00	—	—	32·00	0·9	2
Food Mfrs. Canning & Preserving of Vegetables and fruits	12·00	3·90	—	15·90	0·4	1
Hotel	15·00	—	—	15·00	0·4	1
Wood and Cork	10·00	—	—	10·00	0·3	1
Electricity, Gas & Steam	8·99*	—	—	8·99	0·2	—
Fertilisers	5·60	—	—	5·60	0·2	1
Bicycles	4·58	—	—	4·58	0·1	1
TOTAL :	3109·61	380·15	42·35	3532·11	100·0	61

*Amount sanctioned by way of conversion of part of the foreign currency loan sanctioned earlier.

Assistance of the order of Rs. 20.87 crores (about 59% of the total) was sanctioned to 24 new units, while the balance of Rs. 14.45 crores was sanctioned for expansion, diversification and modernisation of existing undertakings. The total estimated capital cost of the projects in respect of which the Corporation sanctioned assistance during the year aggregated Rs. 190.42 crores; the Corporations assistance in relation to the total cost amounted to about 18.6%.

STATE-WISE DISTRIBUTION OF FINANCIAL ASSISTANCE

10. Table 5 shows the State-wise distribution of the financial assistance sanctioned by the Corporation during the year.

The total financial assistance approved to the extent of Rs. 35.32 crores was in respect of 61 projects in 13 States. Except for 3 States, all others were beneficiaries of substantial assistance from the Corporation Industrial projects in 6 industrially less developed States, *viz.* Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh were sanctioned assistance to the extent of Rs. 15.22 crores, representing 43% of the total. The projects in these States related to the manufacture of sugar, cotton textiles, paper, synthetic fibres and yarn, power alcohol, alloy steel, aluminium, power tillers and hand tractors, auto-cycles, etc.

Maharashtra claimed the largest share of assistance (21.8%), mainly because of the assistance sanctioned to 3 sugar co-operatives aggregating Rs. 3.24 crores and Rs. 3.00 crores to 3 other units in the State for expansion of capacity for the manufacture of roller bearing, dry battery cells and nylon filament yarn. Assistance of the order of Rs. 4.49 crores was sanctioned to projects in Gujarat for the manufacture of nylon yarn, sugar and ball bearings. Mysore's share of Rs. 2.60 crores (7.4%) went to sugar, cotton textiles and electrical machinery. Projects in Tamil Nadu were in the cotton textiles, sugar and chemical industries. The principal beneficiary in Haryana was a project for the manufacture of agricultural tractors. The balance assistance of Rs. 1.56 crores (4.4%) was sanctioned to projects in other States.

The names of concerns in each State to whom financial assistance was sanctioned with particulars of the relative projects assisted are shown in Appendix 'B' of the Report.

TABLE 5

(Lakhs of Rupees)

State	Loans	% of the total loans	Under-writings	Guarantees for deferred payments	Total	% of the whole	Number of units
Maharashtra	752·08	24·2	17·02	—	769·10	21·8	14
Bihar	225·00	7·2	260·00	—	485·00	13·7	4
Gujarat	383·61	12·3	23·00	42·35	448·96	12·7	3
Uttar Pradesh	397·94	12·8	44·25	—	442·19	12·5	7
Orissa	269·05	8·7	100·00	—	279·05	7·9	3
Mysore	260·28	8·4	—	—	260·28	7·4	3
Tamil Nadu	216·78	7·0	5·00	—	221·78	6·3	8
Andhra Pradesh	185·00	5·9	5·00	—	190·00	5·4	3
Haryana	143·57	4·6	10·88	—	154·45	4·4	6
Kerala	105·00	3·4	—	—	105·00	3·0	1
Rajasthan	81·10	2·6	—	—	81·10	2·2	3
West Bengal	49·50	1·6	—	—	49·50	1·4	4
Mad hya Pradesh	40·00	1·3	5·00	—	45·00	1·3	2
Pun jab	0·70*	—	—	—	0·70	—	—
TOTAL	3109·61	100·0	380·15	42·35	3532·11	100·0	61

*Increase in the DM sub-loan sanctioned earlier.

PRIORITY PROJECTS ASSISTED DURING THE YEAR

Project of National Importance
alloy steel

It is well-known that for the industrial development of the country, alloy steel is of paramount importance. In participation with other all-India term-lending institutions, *viz.* IDBI, ICICI, LIC and UTI, the Corporation sanctioned a rupee loan of Rs. 150 lakhs and extended assistance of underwriting and direct subscription to the share capital to the extent of Rs. 60 lakhs to Bihar Alloy Steels Ltd. The plant, to be set up at Patratu, near Ranchi, Bihar, will manufacture carbon and alloy construction steels, ball bearing steels, alloy tool and high speed steels in technical and financial collaboration with two companies belonging to the Schneider Group of France.

Engineering

A rupee loan of Rs. 100 lakhs was sanctioned to Anti-friction Bearings Corporation Ltd., which is engaged in the manufacture of Tapered and Cylindrical Roller Bearings and Ball Thrust Bearings. The Corporation's assistance is meant for the expanison of the manufacturing capacity of the Company's existing plant at Lonavala, Maharashtra, from 4.6 lakh nos. to 10 lakh nos. per annum of Cylindrical and Tapered Roller Bearings. With the growth of the engineering and transport industries, the demand for Roller Bearings is on the increase and the Company's products would help meet the shortfall in this regard.

Another unit in the ball bearing industry, for which financial assistance was approved, was Precision Bearings India Ltd. The Company was sanctioned a rupee loan of Rs. 85 lakhs and a sub-loan in DM equivalent to Rs. 5.61 lakhs. The financial assistance is for the implementation of an expansion scheme aimed at increasing the production of Ball and Roller Bearings at the Company's plant at Baroda. The concern is already manufacturing 67 types of Ball and Roller Bearings and, under the expansion scheme, it proposes to take up the manufacture of another 28 types of sophisticated nature which are at present being imported.

Agricultural Machinery

It has been recognised that there is an imperative need for increasing the production of tractors, a large number of which are being imported at present. In participation with IDBI, ICICI and USAID, the Corporation sanctioned to Escorts Tractors Ltd., a rupee loan of Rs. 60 lakhs and a sub-loan in DM equivalent to Rs. 63.84 lakhs for a new project to be located at Faridabad, Haryana, aimed at the manufacture of 6,000 nos. of 46 H.P. tractors. The Company has been promoted by Escorts Ltd., a concern already assisted by the Corporation, in technical and financial collaboration with the Ford Motor Company of U.S.A., who are entering into such a venture, for the first time, in this country. The Company's products will help bridge a vital gap in the economy. A notable feature of the project is that the Company would also be setting up centres for servicing and maintenance of tractors, thus providing considerable opportunities for employment of technical personnel in the field. Besides, the Company would be procuring about 69% of the components from small and ancillary industries which would again provide employment for technically qualified persons.

Another projects of importance to the agricultural sector, assisted by the Corporation, which aims at the manufacture of 6,000 nos. of power tillers per annum is that of J.K. Satoh Agricultural Machines Ltd., Kanpur. the Corporation sanctioned to the Company, a rupee loan of Rs. 80 lakhs and an underwriting of Rs. 5 lakhs each of equity and preference shares. The project envisages technical and financial collaboration with the well-known Japanese firms of Satoh Agricultural Machine Manufacturing Co. Ltd., and Sumitomo Shoji Kaisha Ltd.. The Company would manufacture power tillers/hand tractors of smaller H.P. (7.5 H.P. and 8 to 11 H.P.) capable of using attachments and accessories for versatile applications. The tillers would be suitable for dry and wet land tilling, ploughing, ridging, pudding, levelling and haulage operations. As light-weight equipment, they are expected to be popular for use in small land holdins. The project also envisages the setting-up of ancillary industries for manufacturing various components. A programme for the development of small scale industry has already been drawn up and a good number of qualified unemployed engineers are intended to be absorbed. The Company has also set up a training school for training operating personnel and technical staff for after-sales service.

Synthetic Fibres

With inadequate production of cotton in the country in relation to requirements and changes in tastes and habits of consumers, the demand for man-made fibres for clothing has increased considerably in recent years. The manufacture of synthetic or non-cellulosic fibres is also considered desirable to the extent it would obviate the imports of cotton. During the year, the Corporation assisted, in participation with other all-India financial institutions, a new project to be set up by Swadeshi Polytex Ltd., at Ghaziabad, U.P., for the manufacure of

6,100 tonnes/annuma of ployster fibre in technical collaboration with Vickers-Zimmer of West Germany. The Corporation approved for this project a rupee loan of Rs. 50 lakhs and sub-loan of DM equvalent to Rs. 100 lakhs and the facility of underwriting to the extent of Rs. 20 lakhs.

In the field of manufacture of nylon-6, the Corporation assisted two projects, one being new. A sub-loan in DM equivalent to Rs. 100 lakhs was approved for Garware Nylons Ltd., for implementing a scheme of expanision. In the other case, the Corporation approved a rupee loan of Rs. 50 lakhs, a sub-loan in DM equivalent to Rs. 100 lakhs, underwriting of equity and preference shares to the extent of Rs. 8 lakhs and Rs. 15 lakhs respectively and a guarantee for deferred payments to the extent of Rs. 42.35 lakhs for a new nylon project undertaken by Gujarat Polyamides Ltd., at Uddhana, near Surat in Gujarat.

Public sector Undertakings

An important project in the public sector for which assistance was approved during the year relates to the manufacture of paper insulated tele-communication cables with an installed capacity of 1,000 kilometres per annum, by Traco Cable Co, Ltd., a Kerala Government undertaking. The Company is engaged since 1965 in the manufacture of PVC insulated armoured and unarmoured heavy duty electric cables including flexibles upto 1.1 K.V. with copper/aluminium conductors, PVC insulated wires and flexibles and bare aluminium conductors like AAC and ACSR. The project located at Irimpanam, Ernakulam District, envisages diversification of the lines of manufacture as mentioned above. It would help relieve the existing shortage of telephone cables in the country and would help the installation of more telephones by Government, thus enabling communication facilities being developed in the rural and urban areas.

The Corporation sanctioned a loan of Rs. 75 lakhs (as part of the loan assistance of Rs. 250 lakhs applied for by the Company from all-India financial institutions) to NGEF Ltd., Bangalore, a company promoted by the State Government of Mysore and engaged in the manufacture of switchgears and boards, transformers and electric motors. The project aims at setting up a plant for diversifving its production by taking up the manufacture of 10,000 nos. of silicon diodes (for rectifiers) per annum and also production for captive consumption of transformer laminations 1,300 metric tonnes per annum, motor stampings with a capacity of 1,100 metric tonnes per annum and copper wire drawing with a capacity of 600 metric tonnes per annum. The scheme also aims at acquisition of certain balancing equipment for strengthening the existing lines of production. NGEF is one of the important undertakings of the State Government and has been set up with technical collaboration of AEG-Telefunken of West Germany, who have also participated in the Company's equity. The Company has also received substantial loan assistance under the KFW line of credit available with Government. This Company is exporting its products, viz. switchgears, transformers and electric motors to several countries including West Germany and has large export orders awaiting execution. The scheme, when implemented, would help meet the gap in the manufacture of an important product, viz. high rated power diodes for the electrical industry, apart from serving the interests of a variety of other industries, where the Company's products are used.

Projects in Industrially less developed Districts/Areas

A project of high national priority, for which assistance was approved during the year, would be located in Jeypore in the backward district of Koraput, Orissa. The project is being taken up by the Aluminium Corporation of India Ltd. (a company already assisted by the Corporation), to whom the Corporation has sanctioned a rupee loan of Rs. 170 lakhs. The project envisages the setting-up of a new integrated aluminium plant with an annual installed capacity of 15,000 tonnes of metal, of which 7,000 tonnes will be converted into aluminium rods. Location of the project in Koraput would not only provide employment to about 2,400 persons in that less developed area, but also would lead to the growth of infrastructure facilities. It will further lead to the establishment of several ancillary-industries, which may come up after the plant goes on stream.

Another project worthy of note is that of Lakshmi Auto Cycles Ltd., for which a loan of Rs. 75 lakhs and the facility of underwriting of equity shares to the extent of Rs. 10 lakhs was approved during the year. The project aims at the setting-up of a plant for the manufacture of autocycles with an installed capacity of 50,000 nos. per annum in Koraput, a notified backward district in Orissa. The project has been virtually promoted by two professional engineers, who will look after the day-to-day operations. A notable feature of the project is that it would not depend on any foreign know-how for the the manufacture of autocycles (Mopeds) and the product would be low priced so as to be within the reach of consumers in the lower middle class. The project also envisages the establishment of a number of ancillary industries, which would be engaged in the manufacture of components required for the autocycle. The scheme is thus considerably employment oriented.

Note may also be taken of the assistance approved during year for the first co-operative spinning venture in the State of Rajasthan being located in Bhilwara, a notified backward district in the State. The Corporation has sanctioned a rupee loan of Rs. 45.50 lakhs to the Rajasthan Co-operative Spinning Mills Ltd., promoted by the cotton growers of Bhilwara District and adjoining districts in Rajasthan. The project envisages the seting-up of a cotton spinning mill with a complement of 12,960 spindles for the manufacture of cotton yarn. This co-operative society has been promoted with the active support and guidance of the State Government with a view to enabling the cotton growers of the area to get a better return for the produce and to induce them to increase the area under cultivation and yield of cotton.

As part of the larger assistance approved by IDBI and the State Bank of India, a rupee loan of Rs. 26.63 lakhs, a sub-loan in DM equivalent to Rs. 3.37 lakhs and the facility of direct subscription to equity shares to the extent of Rs. 5 lakhs was sanctioned to the Textile Corporation of Marathwada Ltd. (TEXCOM), promoted by the Marathwada Development Corporation Ltd. (MDC), a wholly-owned enterprise of the Maharashtra Government, set up to promote the economic development of the under-developed Marathwada region of the State. MDC has sponsored a composite project for the manufacture of bleached, dyed and printed varieties of cotton textiles. The project involves the setting-up of 2,304 powerlooms, a pre-weaving unit and a processing unit. The pre-weaving and the processing units are being put up at Nanded, an under-developed district. The powerlooms would be operated by 24 co-operative societies (each owning 96 power-looms) of local weavers, spread over five districts (viz. Aurangabad, Parbhani, Nanded, Bhir and Osmanabad).

Projects sponsored by new Entrepreneurs and Technologists

Mention may be made of the assistance approved during the year for Premier Synthetic Processors Ltd., Bombay, a company promoted by a qualified textile technologist. The project envisages the setting-up of a processing plant near Bombay for finishing and dyeing of about 8,200 metres/day of grey synthetic woven and knitted fabrics. With several new plants coming up in the coun-

try for the manufacture of nylon and polyester fibre, consumption of synthetic fibres is expected to increase considerably. Establishment of a unit for processing synthetic fabrics, particularly in a textile centre like Bombay, is a step in the right direction.

The Corporation also sanctioned a rupee loan of Rs. 10 lakhs, a guarantee for deferred payments to the extent of Rs. 4.71 lakhs and the facility of underwriting of equity and preference shares to the extent of Rs. 5 lakhs and Rs. 2 lakhs respectively to the Excelsior Plants Corporation Ltd., a company promoted by a few young technicians for setting-up a factory at Faridabad (Haryana) for fabrication of plants for the manufacture of mechanised bricks, ceramics and special types of tiles with an installed capacity of 25 plants per annum. The project is being implemented in technical collaboration with industrial Export, Rumania. The brick and the making plants fabricated by the company would enable the units installing the same to produce by modern methods high quality bricks and tiles for building construction and other industrial uses. The Company has plans to undertake turn-key jobs of installing brick making plants as required by its customers and would also place at their disposal trained technical personnel to ensure smooth operations; thus, the project is employment-oriented as well.

TOTAL OPERATIONS FROM THE 1ST JULY, 1948 TO THE 30TH JUNE, 1971

11. Statistics relating to the aggregate financial assistance sanctioned and disbursed by the Corporation since its inception in July, 1948, have been given on page 9. The total net assistance sanctioned upto the 30th June, 1971 amounted to Rs. 365.67 crores covering in all 1160 applications and 527 industrial projects. Disbursements up to the said date added upto Rs. 318.76 crores, of which cash disbursement were of the order of Rs. 267.78 crores. The total amount of assistance outstanding as at the close of the year under review was Rs. 198.13 crores.

The following table shows at a glance the number of applications approved, net sanctions and the amount disbursed during the last 23 years as also the assistance outstanding as on the 30th June, 1971.

TABLE 6

(Crores of Rupees)

	(Net) Sanctions		Assistance disbursed	Assistance outstanding as on 30-6-1971
	Number of applications	Amount	Amount	Amount
1. Loans				
—Rupees	684	238·67	209·61	133·32
—Foreign currency	157	43·58	35·47	26·09
TOTAL	841	282·25	245·08	159·41
2. Underwritings				
—Equity shares	130	11·22	7·79	6·64
—Preference shares	103	7·06	5·20	4·24
—Debentures	21	10·73	7·58	4·73
TOTAL	254 (a)	29·01	20·57	15·61
3. Direct subscriptions				
—Equity shares	13	0·54	0·26	0·75(d)
—Preference shares	4	0·12	0·05	0·29(b)
—Debentures	1	1·82	1·82	1·37
TOTAL	18	2·48	2·13	2·41
TOTAL of 1 to 3 :	1113	313·74	267·78	177·43
4. Guarantees for deferred payments	42	28·46	27·65(c)	7·05
5. Guarantees for loans from foreign financial institutions	5	23·47	23·33(c)	13·65
TOTAL of 1 to 5 :	1160	365·67	318·76	198·13

(a) Sanctions in respect of equity and preference shares in 75 cases have been accounted for separately.

(b) Includes Rs. 0·67 crore being part of outstanding loans of 4 companies converted into shares and Rs. 0·06 crore of convertible debentures of another concern converted into equity shares.

(c) Guarantees actually issued.

NET FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED AND DISBURSED YEAR-WISE FROM THE 1ST JULY, 1948 TO THE 30TH JUNE, 1971.

12. The net total financial assistance sanctioned and disbursed by the Corporation during each of the last twenty-three years, classified according to the Five-Year Plans, is shown in the following table :

TABLE 7

(Crores of Rupees)

Year ended 30th June	Net financial assistance sanctioned during the year				Amount disbursed during the year			
	Loans	Under-writings	Guaran-tees	Total	Loans	Under writings	Guaran-tees	Total
PERIOD PRIOR TO THE FIRST PLAN :								
1949	3·25	—	—	3·25	1·33	—	—	1·33
1950	2·90	—	—	2·90	2·08	—	—	2·08
1951	1·98	—	—	1·98	2·38	—	—	2·38
TOTAL	8·13	—	—	8·13	5·79	—	—	5·79
THE FIRST PLAN PERIOD :								
1952	3·20	—	—	3·20	1·78	—	—	1·78
1953	0·53	—	—	0·53	2·50	—	—	2·50
1954	4·10	—	—	4·10	2·82	—	—	2·82
1955	5·13	—	—	5·13	1·64	—	—	1·64
1956	14·06	—	—	14·06	2·20	—	—	2·20
TOTAL :	27·02	—	—	27·02	10·94	—	—	10·94
THE SECOND PLAN PERIOD :								
1957	9·15	—	—	9·15	9·78	—	—	9·78
1958	5·93	0·75	1·82	8·50	8.33	—	—	8·33
1959	2·77	0·87	0·27	3·91	7·48	0·66	—	8·14
1960	12·62	0·10	6·06	18·78	8·41	0·17	2·09	10·67
1961	18·58	1·84	8·29	28·71	6·62	0·48	13·02	20·12
TOTAL :	49·05	3·56	16·44	69·05	40·62	1·31	15·11	57·04
THE THIRD PLAN PERIOD :								
1962	17·84	0·73	0·48	19·05	10·92	0·24	0·41	11·57
1963	19·82	4·63	10·62	35·07	15·05	3·99	3·18	22·22
1964	23·61	4·30	13·16	41·07	16·94	1·96	6·39	25·29
1965	19·61	3·55	3·92	27·08	19·79	3·36	14·65	37·80
1966	21·60	3·96	1·35	26·91	23·99	4·48	2·17	30·64
TOTAL :	102·48	17·17	29·53	149·18	86·69	14·03	26·80	127·52
ANNUAL PLAN PERIOD :								
1967	12·35	1·87	4·00	18·22	29·52	2·90	5·64	38·06
1968	15·86	1·48	0·85	18·19	23·35	1·06	2·61	27·02
1969	23·93	2·42	0·40	26·75	15·03	1·68	0·28	16·99
TOTAL :	52·14	5·77	5·25	63·16	67·90	5·64	8·53	82·07
THE FOURTH PLAN PERIOD :								
1970	12·46	1·19	0·29	13·94	16·86	0·85	0·34	18·05
1971	30·97	3·80	0·42	35·19	16·28	0·87	0·20	17·35
TOTAL :	43·43	4·99	0·71	49·13	33·14	1·72	0·54	35·40
GRAND TOTAL :	282·25	31·49*	51·93	365·67	245·08	22·70	50·98	318·76

*Includes direct subscription of Rs. 2.48 crores.

Note : The figures given in the table do not tally with those given in the Annual Reports for the previous years on account of cancellations/adjustments subsequently made in the figures for the previous year.

FACILITY-WISE REVIEW OF ASSISTANCE SANCTIONED (CUMULATIVE) UPTO THE 30TH JUNE, 1971

Rupee Loans

13. The net effective total sanctions of rupee loans as on the 30th June, 1971 amounted to Rs. 238.67 crores against which the amount disbursed stood at Rs. 209.61 crores, constituting about 87.8% of the total.

Foreign Currency Loans

14. Upto the 30th June, 1971, foreign currency loans sanctioned by the Corporation amounted to equivalent of Rs. 43.58 crores. The Corporation had opened Letters of Credit for DM 76.77 million and US $ 26.86 million (total Rs. 35.32 crores) in favour of foreign machinery suppliers upto the said date. Besides, down payments for FF 0.19 million equivalent to Rs. 2.76 lakhs had been made to the BFCE (Paris) and 13 Letters of Commitment to the extent of FF 12.11 million (Rs. 1.66 crores) had been issued to them. Currency-wise, disbursements made upto the 30th June, 1971 amounted to DM 70.27 million, US $ 26.76 million and FF 11.33 million (total Rs. 35.47 crores).

The cumulative position relating to foreign currency loans upto the 30th June, 1971 is summarised in following table.

TABLE 8

Currency	Net Sanctions			Letters of Credit/ Commitments issued		Amount Disbursed	
	Number of sub-loans	Foreign currency (million)	Rupee equivalent (lakhs)	Foreign currency (million)	Rupee equivalent (Lakhs)	Foreign currency (Million)	Rupee equivalent (lakhs)
Deutsche Marks	103	105·04	2139·48	76·77	1560·15	70·27	1426·97
U.S. Dollars	57	26·92	1976·52	26·86	1971·55	26·76	1964·72
French Francs	11	12·97	177·48	12·11	165·60	11·33	155·18
Pound Sterling	3	0·12	21·50	—	—	—	—
TOTAL :	174*		4314·98**		3697·30		3546·87

Notes : *The sub-loans sanctioned were in respect of 157 applications.

**Does not include a sum of Rs. 43.05 lakhs, in respect of two concerns, which is not to be availed of or likely to be converted into other facilities.

Underwriting operations and direct subscriptions to capital

15. Upto the 30th June, 1971, the Corporation had sanctioned 179 applications for the underwriting of equity shares, preference shares and debentures for a net aggregate amount of Rs. 29.01 crores. Equity shares accounted for Rs. 11.22 crores, preference shares for Rs. 7.06 crores, and debentures for Rs. 10.73 crores. In addition, 14 applications for firm subscription for Rs. 66.09 lakhs (Rs. 53.60 lakhs in equity shares and Rs. 12.49 lakhs in preference shares)—including Rights Issues which had devolved in pursuance of underwriting obligations assumed by the Corporation earlier—had been sanctioned upto the 30th June, 1971.

The Corporation had signed underwriting agreements in 174 cases for an aggregate sum of Rs. 26.67 crores. Operations in 173 cases for Rs. 26.44 crores had been completed upto the 30th June, 1971. 12 issues underwritten by the Corporation for Rs. 2.36 crores were fully subscribed by the public. As for the remaining 161 issues involving an aggregate commitment of Rs. 24.08 crores, the Corporation was called upon to take up shares and debentures to the extent of Rs. 20.65 crores; the devolution on the Corporation in aggregate terms was about 78%.

The position in respect of the issues finalised upto the 30th June, 1971 is shown in Table 9.

Upto the 30th June, 1971, the Corporation had directly subscribed to a debenture issue to the extent of Rs. 1.82 crores.

TABLE 9

(Lakhs of Rupees)

	Amount underwritten	Amount devolved on the Corporation	Percentage of (3) to (2)
1	2	3	4
Equity shares	1089·05	776·22	71·3
Preference shares	682·29	531·03	77·8
Debentures	873·00	758·20	86·8
	2644·34	2065·45	78·1

Guarantees for deferred payments for Plant and Machinery

16. The net amount of guarantees for deferred payments sanctioned upto the 30th June, 1971 amounted to Rs. 28.46 crores in respect of 42 applications. The total amount of guarantees actually issued upto the 30th June, 1971 was Rs. 27.65 crores.

Guarantees for Foreign Currency Loans from Financial institutions abroad

17. After accounting for cancellations and withdrawals, the sanctions of guarantes for foreign currency loans, in respect of 5 applications, amounted to Rs. 23.47 crores. Guarantees actually issued upto the 30th June, 1971 totalled Rs. 23.33 crores.

PURPOSE-WISE DISTRIBUTION OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED UPTO THE 30TH JUNE, 1971

18. The purpose-wise classification of net financial assistance sanctioned upto the 30th June, 1971 alongwith the total cost of the projects financed by the Corporation is shown in the following table :

TABLE 10

(Crores of Rupees)

Purpose of financial assistance	Total cost of the Projects	Net financial assistance sanctioned				Percentage of (6) to (2)
		Loans	Underwritings and direct subscriptions	Guarantees for deferred payments for machinery & for foreign loans	Total	
1	2	3	4	5	6	7
New undertakings	1003·43	169·88	21·14	42·26	233·28	23·3
Existing undertakings for :						
(i) Expansion of existing lines of production	474·65	87·25	7·17	7·07	101·49	21·4
(ii) Modernisation and rehabilitation	103·59	11·55	2·76	0·53	14·84	14·3
(iii) Diversification into new lines of production	30·82	11·34	0·82	2·07	13·83	44·9
TOTAL :	1612·49	280·02	31·49	51·93	363·44	22·5
Loans sanctioned for other purposes, e.g. working capital	—	2·23	—	—	2·23	—
GRAND TOTAL :	1612·49	282·25	31·49	51·93	365·67	

The industry-wise and state-wise distribution of the net financial assistance sanctioned upto the 30th June, 1971 is given in Appendices 'C(i)' and 'C(ii)' respectively to this Report. In Appendix 'D', the net financial assistance has been classified according to the amounts sanctioned to various industrial concerns. Appendix 'E' shows the industry-wise distribution of the net financial assistance sanctioned in each State, as on the 30th June, 1971.

Of the total net assistance aggregating Rs. 365.67 crores sanctioned by the Corporation upto the 30th June, 1971, assistance of the order of Rs. 233.28 crores was extended to new undertakings and the balance assistance of Rs. 132.39 crores to existing units for expansion, modernisation or diversification into other lines of production. The total cost of the 527 projects for which the Corporation has so far extended financial assistance has been of the order of Rs. 1612 crores, which is an index of the over-all resources, mobilised for the completion of the projects.

ASSISTANCE TO INDUSTRIAL CO-OPERATIVES

19. In accordance with the objectives laid down in the successive Plans and in pursuance of Central Government's policies, the Corporation has extended sizeable assistance to industrial co-operatives, engaged particularly in the manufacture of sugar and cotton textiles.

Upto the 30th June, 1971, financial assistance had been sanctioned to 98 industrial co-operatives amounting to Rs. 77.31 crores, distributed over 74 sugar co-operatives (Rs. 65.87 crores), 22 cotton spinning co-operatives (Rs. 1043 crores, one co-operative jute mill (Rs. 78.50 lakhs) and a co-operative unit for the extraction of vegetable oil (Rs. 22.50 lakhs). Disbursements aggregated Rs. 65.59 crores.

The state-wise and industry-wise distribution of industrial co-operatives financed by the Corporation upto the 30th June, 1971, is shown in Table 11.

It will be seen that Maharashtra occupied the foremost position so far as assistance to industrial co-operatives is concerned, followed by Mysore, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and Uttar Pradesh.

It will be of interest to note that the financial assistance sanctioned to industrial co-operatives represents about 32% of the total rupee loan assistance sanctioned by the Corporation.

TABLE 11

(Lakhs of Rupees)

State	Sugar		Cotton Spinning		Others		Total sanctions		Total disbursements	Loans outstanding
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	Amount	Amount
Andhra Pradesh	6	635·00	3	110·00	...	...	9	745·00	557·00	362·07
Assam	1	60·00	—	—	1*	78·50	2	138·50	138·50	85·00
Bihar	1	115·00	1	24·70	...	—	2	139·70	114·70	131·55
Gujarat	6	405·50	2	170·00	...	—	8	575·50	425·50	324·08
Haryana	2	106·00	...	...	—	—	2	106·00	106·00	—
Kerala	2	180·00	—	...	...	—	2	180·00	180·00	232·69
Madhya Pradesh	1	80·00	1	40·00	—	—	2	120·00	60·00	60·00
Maharashtra	28	2794·70	8	382·50	—	—	36	3177·20	2806·70	1604·20
Mysore	8	677·75	2	79·00	1**	22·50	11	779·25	608·75	442·38
Orissa	2	175·00	1	31·00	...	—	3	206·00	181·00	149·57
Punjab	4	315·00	...	—	...	...	4	315·00	315·00	217·03
Rajasthan	1	80·00	1	45·50	—	...	2	125·50	79·00	82·25
Tamil Nadu	7	583·00	1	35·00	...	—	8	618·00	576·00	364·26
Uttar Pradesh	5	380·00	2	125·00	...	...	7	505·00	411·00	191·84
TOTAL	74	6586·95	22	1042·70	2	101·00	98	7730·65	6559·15	4226·92

*Jute Co-operative.

**Vegetable oil extraction.

The Corporation's assistance to the cooperative sector has to be seen in the broader perspective of encouraging industrial co-operatives which has been accepted as a national policy. The impact of the Corporation's financial assistance to industrial co-operatives on the economy, as a whole, can be gauged from the fact that it has been instrumental in mobilising resources of the order of Rs. 160.74 crores, being the aggregate estimated project cost of 98 co-operative units, the Corporation's share of assistance being as high as—48.1%. The extent to which savings in the agricultural sector have been mobilised for productive purposes is evident from the fact that in respect of 74 co-operative sugar factories, producer members had contributed a sum of about Rs. 34.41 crores as share capital, contribution from others (viz. non-producer members, co-operative institution and the rest) amounted to Rs. 3.52 crores and the assistance by way of share capital from the State Governments totalled Rs. 17.09 crores. In addition, a sum of Rs. 19.78 crores had been collected by co-operative sugar factories, which have gone into production, by way of non-refundable deposits out of the price of sugarcane payable to the growers.

With continuing accent on the promotion of industrial co-operatives, the Corporation is expected to assume still larger responsibilities in the development of this sector of the economy as an agency for providing long-term financial assistance.

ASSISTANCE TO INDUSTRIALLY LESS DEVELOPED STATES/AREAS

20. In recent years, attention has been focused on the removal of regional imbalances in the economy and on the need for fostering industrial growth in less developed States/areas. The Corporation has already extended sizeable financial assistance to industrial undertakings in the States/areas generally considered to be industrially less developed. Of the total assistance of the order of Rs. 365.67 crores sanctioned for 527 projects upto the end of the year under review, roughly 33.3% of the assistance, *i.e.*, Rs. 121.80 crores, spread over 149 industrial units, was accounted for by Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Madhya Pradesh, Meghalaya, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh, Andaman & Nicobar Islands

and Goa, which have been classified as less developed or backward States/areas.

Industrial Finance Corporation of India

It has been recognised that for bringing about balanced regional development, attention has to be directed to selected districts/areas, rather than a State as a whole. Accordingly, the Central Government has notified, in consultation with the State Governments and the Planning Commission, certain districts in the States/areas as qualifying for the concessions extended by the all-India term-lending financial institutions to industrial projects that may be located in them. The districts/areas notified by the Central Government upto the 30th June, 1971 are shown in Appendix 'H' The financial assistance sanctioned by the Corporation to 103 industrial projects set up/proposed to be set up in the districts/areas, that have now been notified by the Central Government, aggregated Rs. 74.33 crores, covering in all 57 districts and 3 Union Territories. It may be mentioned that the concessions offered by the Corporation are applicable to new projects that may be set up in the notified districts/areas. The concessions that have already been announced by the Corporation on the 23rd July, 1970, are shown in Appendix 'I'.

ASSISTANCE TO NEW ENTREPRENEURS AND TECHNOLOGISTS

21. The Corporation has continued to give special attention to industrial concerns which are promoted by new entrepreneurs and technologists. Over the years, the Corporation has assisted quite a number of industrial projects promoted by new entrepreneurs and technologists in industries such as engineering, textiles, chemicals, sugar, cement, paper and paper boards, rubber products, glass, hotels, etc.

ASSISTANCE TO PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

22. As was mentioned in last year's Report, the Central Government, has authorised the Corporation to entertain applications for financial assistance from public sector undertakings (irrespective of the extent of Government's shareholdings in them) on the same basis as applications from private sector concern. Public sector undertakings, which are incorporated as public limited companies, are thus eligible to apply to the Corporation for financial assistance for expansion, modernisation, or diversification or for the setting-up of new projects.

During the year under review, the Corporation sanctioned financial assistance aggregating Rs. 1.80 crores to two public sector undertakings. Taking into account, also the financial assistance extended to public sector undertakings in the previous years (with the specific approval of Government in each case), the net sanctions to 5 concerns (in which the Central/State Government's participation in equity capital is above 51%) upto June 30, 1971 totalled Rs. 6.42 crores.

CRITERIA AND PROCEDURE ADOPTED FOR GRANT OF FINANCIAL ASSISTANCE

23. Under the IFC Act, the Corporation, in the discharge of its functions, is required to act on business principles, due regard being had to the interests of industry, commerce and the general public.

As the industrial projects seeking assistance are in the nature of business risks, the Corporation examines them in the light of several factors involved, *viz.* the relative industrial and national priority of the project in the economy of the country, the technical, financial and economic viability of the project, the experience and probity of the promoters and their own financial contribution to the project cost, the quality of management, and the adequacy and competence of the technical, financial and administrative personnel, during the construction and operation of the project.

The Corporation's approach is project-oriented and as such, the technical, the financial, the managerial and the economic aspects of a project require detailed evaluation.

In examining the technical aspects, for example, such aspects as the feasibility of the technical process selected, the location of the project, the specifications of plant and equipment and the reputation and experience of the machinery suppliers, arrangements for securing the technical know-how and training of personnel and labour, plant layout, arrangements for utilities required and a review of the projected construction schedule, are carefully considered. A scrutiny of the financial aspects of a project involves an assessment of its cost, an appraisal of the working capital required, the sources of finance such as share capital, long-term loans, arrangements for meeting the foreign exchange cost, deferred payments for plant and machinery and internal accruals, in the case of existing undertakings. Again, it is necessary to ensure that the project has a satisfactory equity : debt ratio, the promoters' contribution to the project costs is adequate and the projections of profitability are realistic so that the long-term debts can be properly serviced and a reasonable return is assured to the shareholders.

The study of the managerial aspects aims at ensuring that the concern has a proper management set-up and has a competent Board of Directors as also the required qualified and experienced technical and administrative personnel. The economic and social aspects of a project such as the market outlook, the employment potential and the capacity to create a climate for industrialisation in a relatively under-developed or backward area are also taken note of.

24. After a detailed technical-cum-financial appraisal of the project has been made by the technical and financial staff of the Corporation, the views of the appropriate Advisory Committee, which consists of experts drawn from the public and private sectors having specialised knowledge of the particular industry, are invited. Thereafter, the Board of Directors of the Corporation takes a decision on each case after taking into account the recommendations of the Advisory Committee. A reference to the Advisory Committee, is however, dispensed with, where assistance is required not for any new project, as such, but for acquisition of plant and machinery by way of modernisation, balancing equipment or marginal expansion. In the case of large projects involving joint financing with other all-India financial institutions such as, the IDBI, the ICICI, the LIC, and the UTI, mutual consultations are held at regular intervals at inter-institutional meetings or at special conferences. To expedite processing of requests for financial assistance in such cases, generally, joint technical and financial appraisals are carried out by teams of officers of participating institutions.

25. It will be recalled that pursuant to the recommendations of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee, the Central Government decided in February, 1970 to make certain changes in the policy in regard to assistance from public financial institutions. With the acceptance of the joint-sector concept in principle, it was decided that there should be a greater degree of participation in management, particularly at policy levels, in the case of the major projects involving substantial assistance from public financial institutions. Government also decided that public financial institutions should also, as part of their financial assistance arrangements, exercise option for converting loans given and debentures issued in future, either wholly or partly, into equity within a specified period of time. As for loans and debentures given in the past, the financial institutions concerned

should have discretion to negotiate conversion in cases of default.

The Central Government have recently issued detailed guidelines on Government decisions on the recommendations of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee in regard to policies to be followed by the long-term financial institutions for conversion of loans into equity and for nomination of directors on the boards of the assisted concerns. These guidelines have been issued to the all-India financial institutions, *viz.* Industrial Development Bank of India (IDBI), Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. (ICICI), Life Insurance Corporation of India (LIC), Unit Trust of India (UTI) and the Industrial Finance Corporation of India (IFCI).

In terms of these guidelines, it has become obligatory on the financial institutions to normally stipulate a condition for option to convert a portion of the loan into equity in all cases where the aggregate financial assistance exceeds Rs. 50 lakhs. In all cases where the aggregate financial assistance to an industrial concern exceeds Rs. 25 lakhs but does not exceed Rs. 50 lakhs, the condition for incorporation of the convertibility clause may be stipulated at the discretion of the financial institutions. In exercising the discretion, all material factors will have to be taken into consideration besides the normal commerical ones, such as whether the assisted concern forms part of the 'core sector' as classified by the Government from time to time, or is a defence-oriented industry, or an industry producing essential items of mass consumption. In cases where the aggregate financial assistance to one industrial concern does not exceed Rs. 25 lakhs, condition for conversion of a part of the loan into equity need not be written as a measure of policy unless the financial institutions themselves so decide on commercial grounds.

The condition for conversion of the whole or part of the loan into equity will not apply to sub-loans in foreign currency granted by the Indian financial institutions to industrial concerns out of foreign currency lines of credit made available by foreign institutions directly to Indian financial institutions for sub-lending. However, the convertibility clause shall apply to all appropriate loan agreements/debenture issues covering rupee assistance from the financial institutions to industrial concerns to enable the latter to purchase foreign exchange from foreign lines of credit operated by the Government of India or from any other source abroad.

The terms of conversion of loans/deventures into equity capital such as, the quantum of the loan to be converted, the issue price of the share, the stage or stages at which conversion option might be exercised, the period during which the option would remain open, the period of notice if any, to be given for exercise of the option, etc., will be negotiated in each case and will be incorporated in the loan agreement. In settling the terms, due consideration will be given to factors such as nature and importance of the industry, the likely gestation period of the project, the debt-equity gearing, the projected profit potential, the prospects of expansion, etc. In the case of existing companies with reserves created out of past profits, in fixing the issue price of the share, consideration will be given to factors such as market value of the share, the break-up value of the share, dividend record, current and projected profitability, etc.

Where the convertibility clause is stipulated, the Company concerned has to obtain the approval of its shareholders and of Central Government to the terms of conversion under the provisions of Section 81(3) of the Companies Act.

During the financial year of the Corporation ended the 30th June, 1971, the Corporation has stipulated a condition for conversion of loan equity at the option of the Corporation in respect of 21 concerns to whom rupee loans were sanctioned during the year. Out of the 21 concerns mentioned above, the terms and conditions of the conversion have been finalized in 16 cases.

Under the aforesaid guidelines, the all-India financial institutions including the Corporation are required to nominate their respresentatives, officials and non-officials, on the Boards of all assisted concerns where substantial financial assistance has been sanctioned and where the convertibility clause has been incorporated in the agreements for financial assistance.

26. After financial assistance is sanctioned by the Board of Directors of the Corporation, a Letter of Intent is issued to the applicant communicating the sanction, in principle, of the facility applied for and also indicating broadly the main terms and conditions governing the same. Thereafter, the borrower is required to execute a Loan Agreement and other documents of security, which have been standardised and printed.

Disbursements start only after completion of legal formalities and on compliance with conditions precedent to disbursement loans as incorporated in the relative. Loan Agreement. The legal formalities have, however, been considerably simplified to minimise delays. Subsequent disbursements are made according to the requirements of the project after verification of the progress made in its implementation and utilization of earlier releases of loan, etc.

Both during the construction period of a project and after its implementation, the Corporation maintains proper follow-up. An assisted concern is required to submit regular progress reports in the prescribed forms as also its audited balance sheets. The officers of the Corporation inspect the project from time to time to verify its physical and financial progress, and to offer the guidance that may be required. After the project has gone on stream, inspections at regular intervals by the technical and financial officers of the Corporation continue.

RESOURCES

Bonds

27. In November, 1970, with a view to augmenting its resources, the Corporation placed on the market a Bonds Issue for Rs. 4.50 crores with a maturity period of 12 years. The Bonds were issued, at par, and the rate of interest offered was 5¾% p.a. Including the permissible 10% of the amount of the issue, the total amount of the Bonds allotted was Rs. 4.95 crores. With this issue, the aggregate amount of Bonds outstanding at the end of the year was Rs. 57.69 crores.

Borrowings from the Central Government

28. As on the 30th June, 1970, loans outstanding from the Central Government stood at Rs. 79.61 crores. During the year under review, no amount was borrowed from Government while a sum of Rs. 2.29 crores was repaid, the balance outstanding at the end of the year being Rs. 77.32 crores. This amount represents the loans raised from the Central Government between the years 1959-60 and 1968-69. As in the previous year, no budgetary allocation of funds was made for the Corporation for the year 1970-71.

Borrowings from the Reserve Bank of India

29. As in the past, borrowings from the Reserve Bank of India were availed of for temporary periods during the year, when considered necessary. As on the 30th June, 1971, the outstandings under this head amounted to Rs. 1.24 crores, which have since been cleared. Following the increase in Bank Rate from 5 to 6% with effect from the 8th January, 1971, the rate of interest on these borrowings was 6% per annum.

Borrowings in Foreign Currencies

30. In October, 1970, a further loan of DM 10 million, being the 9th line of credit, was allocated to the Corporation under an Inter-Governmental Agreement signed on the 19th November, 1970, between the Governments of the Federal Republic of Germany and India. The relative agreement between the Corporation and the Kreditanstalt was signed on the 22nd June, 1971. As at the close of the year, the total amount of West German credit available with the Corporation amounted to DM 112.5 million, against which the Corporation had sanctioned sub-loans to the extent of DM 105.04 million. DM lines of credit are now fully convertible, that is, they can be utilised for the import of capital goods, engineering know-how and services, etc., from countries such as the USA, the UK, Italy, France, Norway, Sweden, Denmark, Japan, etc., in addition to West Germany, except certain countries specifically excluded.

Under the UK/India Capital Investment Loan, 1969, the Government of India allocated to the Corporation in September, 1970, £ 1 million to enable it to finance the import of capital goods from the UK by eligibile industrial concerns. Against this line of credit, sub-loans for an aggregate amount of £ 0.12 million (Rs. 21.50 lakhs) have been sanctioned. Documentation in connection with a further allocation of UK Credit to the extent of £ 1 million under the UK/India Capital Investment Loan, 1971 is expected to be completed shortly.

The total value of the French credit available to the Corporation from Banque Francaise du Commerce Exterieur, Paris, amounted to FF 15 million and sub-loans sanctioned there against totalled FF 12.97 million. The two lines of credit aggregating $ 26.88 million that the United States Agency for International Development had extended to the Corporation have been fully committed.

Upto the 30th June, 1971, the Corporation had repaid DM 10.58 million in respect of the first two loans of DM 15 million and DM 25 million from the Kreditanstalt, US $ 14.35 million in respect of the two USAID loans and FF 3.32 million in respect of the BFCE credit.

Sources from which assistance given has been financed

31. As mentioned in para 11, disbursements on loans and amounts paid on shares and debentures, upto the 30th June, 1971, aggregated Rs. 267.78 crores. This amount was financed from the following sources :

	(Crores of Rupees)
Paid-up capital	8·35
Reserves	14·24
Borrowings from the market by issue of bonds	57·69
Borrowings from the Central Government	77·32
Borrowings from the Reserve Bank of India	1·24
Foreign credits	35·47
Repayment of rupee and sale of investments, etc.	73·47
Total:	267·78

SOURCES AND USES OF FUNDS FOR THE PAST THREE YEARS

32. The following table shows the position regarding sources and uses of funds for the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71.

(Crores of Rupees)

	1968-69	1969-70	1970-71
A. SOURCES OF FUNDS :			
1. Opening cash and bank balances	2·67	8·42	6·89
2. Gross profit for the year	3·92	4·33	4·47
3. Borrowings from Government	10·00	—	—
4. Net Borrowings from Reserve Bank of India	—	—	1·24
5. Borrowings from the market by the issue of bonds	8·33	5·50	4·95
6. Borrowings from foreign credit institutions	1·41	1·69	3·10
7. Sale of investments	0·73	1·10	1·16
8. Sale of investments in Government securities	—	1·30	2·01
9. Redemption of debentures/preference shares	0·50	0·01	0·70
10. Repayment of loans by borrowers—			
(a) Rupee loans	7·55	10·34	9·48
(b) Foreign currency loans	1·25	1·97	2·46
11. Recoveries in respect of obligations met under guarantees	0·03	0·04	—
Total :	36·39	33·70	35·46
B. USES OF FUNDS :			
1. Disbursement of assistance by way of—			
(a) Loans—			
(i) Rupee loans	12·91	15·01	13·16
(ii) Foreign currency loans	1·41	1·69	3·10
(b) Subscription to shares/debentures of industrial concerns in pursuance ofunderwriting obligations	1·62	0·82	0·73
(c) Direct subscriptions	0·05	0·03	0·14
(d) Obligations under guarantees met by the Corporation	0·76	0·16	0·02
	16.75	17.71	17.15

	1968-69	1969-70	1970-71
2. Repayment of loans from Government	0·86	1.77	2.29
3. Repayment of loans from foreign credit institutions	2·15	2.09	2.26
4. Redemption of bonds	4·38	—	
5. Provision for taxation	2·22	2·37	2·37
6. Dividend	0·21*	0·25	0·42
7. Investment in Government securities	0·80	2·51	...
8. Others	0·60	0·11	1·79
9. Closing cash and bank balances	8·42	6·89	9·18
Total :	36·39	33·70	35·46

Note : *The amount in the cash payment, exclusive of the amount of dividend payable to the IDBI, transferred to Special Reserve Fund under Section 32A of the IFC Act.

It will be seen from the table that the disbursements of financial assistance, in cash, amounted to Rs. 17.15 crores as compared with Rs. 17.71 crores in the preceding year. Thus the level of disbursements was more or less maintained in spite of lower sanctions to the extent of Rs. 19.38 crores in the previous year. The provision for taxation for the year under review was Rs. 2.37 crores. For financing its operations, the Corporation did not borrow, for the second year in succession, any funds from the Central Government and raised Rs. 4.95 crores from the market by an issue of Bonds.

PROGRESS OF REPAYMENTS

33. Tables 12 and 13 show the amounts which were due by way of interest on loans and instalments of principal and the amounts that were realised during each of the last five years. They also show the amounts in default at the end of each of those years. The interest in default of Rs. 550.75 lakhs and the principal in default of Rs. 498.03 lakhs as on the 30th June, 1971, amounted to 3.45% and 3.13% respectively of the total outstanding loans of Rs. 159.41 crores.

TABLE 12

Interest

(Lakhs of Rupees)

Year ended 30th June	Loans outstanding at the beginning of the year*	Arears of interest outstanding at the beginning of the year	Amount of interest due during the year	Total of columns 3 & 4	Amount of interest received during the year	Defaults of interest at the end of the year**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1967	9960·69	61·42	801·69	863·11	721·98	116·82
1968	12120·37	116·82	940·19	1057·01	830·57	202·81
1969	13552·04	202·81	1026·64	1229·45	917·78	311·67
1970	14207·50	311·67	1084·89	1396·56	1023·84	372·72
1971	14998·54	372·72	1161·08	1533·80	983·05	550·75

*Excluding amounts due on account of defaulted deferred payment instalments guaranteed and met by the Corporation and interest due thereon which are shown separately in table 15.

**Excluding amounts for which extension of time was granted. Technically, such cases are not treated as defaults.

TABLE 13

Principal

(Lakhs of Rupees)

Year ended 30th June	Loans outstanding at the beginning of the year*	Arrears of principal outstanding at the beginning of the year	Amount of principal due during the year	Total of columns 3 & 4	Amount of principal received during the year	Defaults of principal outstanding at the end of the year**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1967	9960·69	38·83	784·13	822·96	723·24	80·02
1968	12120·37	80·02	928·16	1008·18	801·11	149·32
1969	13553·04	149·32	944·90	1094·22	811·99	256·51
1970	14207·50	256·51	1163·86	1420·37	1004·24	313·21
1971	14998·54	313·21	1354·43	1667·64	1151·66	498·03

*Excluding amounts due on account of defaulted deferred payment instalments guaranteed and met by the Corporation and interest due thereon which are shown separately in table 15.

**Excluding amounts for which extension of time was granted. Technically, such cases are not treated as defaults.

34. The industry-wise break-up of defaults, as on the 30th June, 1971, along with the comparative figures for the previous year is given in the following table :

TABLE 14

(Lakhs of Rupees)

Industry	Defaults as on 30-6-70			Defaults as on 30-6-71		
	No. of Concerns	Principal	Interest	No. of Concerns	Principal	Interest
Sugar	5	24·50	56·40	7	39·00	82·05
Textiles	14	115·66	138·62	21	180·33	186·88
Paper	3	12·45	62·35	3	15·65	87·86
Basic Industrial Chemicals	1	15·00	17·95	2	19·73	22·53
Ceramics & Refractories	4	37·18	46·74	5	54·48	62·30
Iron & Steel	1	2·45	0·01	—	—	—
Wood & Cork	1	56·25	13·10	1	75·00	23·09
Metal Products	9	14·62	17·91	10	15·17	19·53
Machinery	3	9·60	5·25	5	31·85	10·57
Electrical Machinery & Appliances	3	14·91	7·88	2	19·23	22·30
Motor Vehicles & Ancillaries	1	2·12	2·48	1	5·30	8·88
Miscellaneous Manufacturing Industries	2	3·42	0·98	2	8·63	1·06
Miscellaneous Chemicals	2	4·00	1·06	2	23·06	12·16
Hotels	1	1·05	1·80	1	3·15	4·33
Bicycles	1	—	0·19	1	2·00	—
Glass	—	—	—	2	3·92	1·24
Rubber	—	—	—	2	1·53	5·97
Total :	51	313·21	372·72	67	498·03	550·75

35. The number of cotton textile concerns in default rose from 14 to 21 during the year. The amount in default recorded a further increase because most of the concerns, which were in default during the previous year, were again unable to meet their commitments during the current year. In keeping with the unfavourable conditions prevailing in the cotton textile industry, these concerns failed to improve their performance. It is well-known that profitability in the cotton textile industry in the country during the past few years has been adversely affected by a steep rise in the cost of the raw materials and manufacturing costs without a commensurate increase in the sales realisation. Apart from other difficulties such as over-runs in the project costs due to delays in implementation, shortage of working capital, inefficient management and labour troubles, operations of some of the units were affected by lack of adequate and regular power supply. Necessary relief was granted to some of the concerns by way of rescheduling and postponing payments of instalments of principal. At the same time, follow-up action was intensified in the form of more frequent inspections and dialogues with the promoters and exchange of view with other financial institutions and commercial banks in order to have better appreciation of the deficiencies or difficulties of these concerns. In a few cases, recourse had to be taken to law against some of the concerns in order to safeguard the interests of the Corporation.

36. Though the output of sugar in the country during the crushing season 1970-71 was around 37 lakh tonnes as compared with the peak production of 42.62 lakh tonnes registered during 1969-70, the working results of some of the sugar factories were affected by accumulation of large stocks of sugar held by them with consequent pressure on their liquid resources. The number of defaulting concerns, therefore, went up from 5 to 7, the interest in default from Rs. 56.40 lakhs to Rs. 82.05 lakhs and the amount of principal in default from Rs. 24.50 lakhs to Rs. 39.00 lakhs.

37. The profitability of the paper industry as a whole continued to be satisfactory in the wake of de-control of prices, which came about in 1968 and 1969. Some of the concerns assisted by the Corporation, however, continued to be in default for reasons peculiar to the units. Reference was made in the last year's report to efforts in rehabilitating one of the projects in which the Corporation has a large stake. The concern has since approached the all-India long-term financial institutions for financial assistance for implementing a scheme of expansion, which is under the active consideration of the institutions. In another case, legal action has resulted in a commissioner for mortgaged properties being appointed and further steps are being taken for realisation of the Corporation's dues by sale of its assets.

38. Ceramics and refractories fared better during the year as a result of rise in the tempo of demand from steel and other industries. Though the units assisted by the Corporation also recorded some improvement in their working results, they failed to clear, the arrears of instalments of interest and principal. In one case, though a small amount was paid to the Corporation towards arrears, it would take quite some time before the undertaking could be regarded to have recovered completely from the effects of recession. In another case, the Company is under liquidation the Corporation has taken legal action and under the orders of the Court, assets have been put on sale.

39. The concern engaged in the manufacture of hard board to which reference was made in the last year's report continued to be in default during the year, though it recorded an improvement in its sales, both domestic and export. The Company continued to experience difficulties in marketing its products due to transport difficulties. Some further relief may have to be considered to enable the Company to retrieve its position.

40. The number of assisted concerns in the engineering industry which failed to meet their commitments to the Corporation during the year increased from 10 to 12. Though, there has been some revival in the engineering industry, some of the assisted concerns engaged in the manufacture of machinery, machine tools, steel structurals and small tools continued to have unsatisfactory operations. A few others, including some large ones in the Eastern region, closed down mainly due to labour trouble, high cost of production and stringency of working capital. The state of affairs of all these units is constantly under review and measures are being taken toward their rehabilitation and/or realisation of the Corporation's dues through sale of mortgaged assets.

41. As on the 30th June, 1971, the amounts of outstanding defaults in respect of deferred payments guaranteed by the Corporation stood at Rs. 316,83 lakhs as against Rs. 293.84 lakhs as at the close of the previous year. The bulk of defaults under

deferred payments guarantees were accounted for by 3 projects in the paper industry and 2 in the textile industry. Reference was made in the last report to proposals for rehabilitation of one of the projects in which the Corporation had a large financial stake. Some progress was registered in this direction during the year and it is hoped that the scheme of financial reconstruction and rehabilitation under contemplation would come to be implemented, thereby enabling the Corporation to realise a substantial portion of its dues. In the case of another assisted company in the paper industry, the Corporation's stake is quite large, the proposals for rehabilitation as part of the scheme of arrangement approved by the High Court have already been finalised. The company has now approached the all-India financial institutions including the Corporation for financial assistance for undertaking a scheme of expansion. The Company's application is being actively considered. In the case of the third unit in the paper industry, which committed defaults in meeting its liabilities under deferred payments, though the unit is in production and has recorded better results during the year, the defaults have yet to be cleared; suitable rescheduling of the liabilities is contemplated with the necessary streamlining of the management of the Company.

In one of the concerns engaged in the textile industry, which had defaulted in meeting its commitments to the Corporation, a scheme of rehabilitation and financial reconstruction has been before the Court and it is hoped that with this scheme being approved and suitable changes in management being made as contemplated, there would be improvement in the Company's operations.

From the observations made in the above paragraphs in respect of some of the defaulting concerns, it will be seen that in handling cases of persistent defaults, the Corporation has always tried to probe into the root causes of the malaise affecting an enterprise and to find a constructive solution for bringing about an improvement in the working results of the concern by suggesting a scheme of financial reconstruction, by strengthening and/or change of existing managerial control, by providing reliefs in the form of rescheduling of existing loans or conversion of loans into equity or short-term obligations into long-term liabilities, etc., with a view to placing the undertaking on a sound footing and improving its financial viability.

42. The position of defaults in the payment of instalments of deferred payments guaranteed and met by the Corporation and interest and other charges due thereon for the last five years is shown in Table 15.

TABLE 15

Defaults in the payment of instalments of deferred payments guaranteed and met by the Corporation and interest, etc., due hereon

(Lakhs of Rupees)

Year ended 30th June	Amount of arrears due at the beginning of the year	Defaults during the year	Total of columns 2 & 3	Recoveries during the year	Amount of arrears outstanding at the end of the year
1	2	3	4	5	6
1967	239·34	95·77	335·11	—	335·11
1968	335·11	80·41	415·52	0·47	415·05
1969	415·05	116·27	531·32	3·89	527·43
1970	527·43	52·24	579·67	285·83*	293·84
1971	293·84	25·71	319·55	2·72	316·83

*This amount included instalments in default aggregating Rs. 279·44 lakhs, which have been converted into new loans and extension of time was granted for the same.

General review of Industries particularly in the fields in which the Corporation has rendered financial Assistance.

43. Reviewing the performance during the year of industries assisted by the Corporation, it is observed that there was a notable improvement in the utilisation of existing capacity. Full capacity was utilised in the case of electrical equipment industries such as transformers, electrical motors, batteries, house service meters, electrical measuring instruments and high tension insulators and in the non-electrical machinery group such as ball and roller bearings, twist drills, etc. A greater degree of utilisation was also noticed in the case of cables and wires, machine tools and accessories, grinding wheels, etc. Industries like aluminium, caustic soda, soda ash, synthetic fibres, paper and paper board, automobile tyres and tubes also showed better performance in the matter of utilisation of capacity. In the case of coal, a levelling-off of demand, coupled with difficulties in movement, resulted in lower utilisation of capacity.

The cotton textile industry continued to be under stresses and strains of various adverse factors such as a steep rise in prices of cotton without a commensurate increase in sales realisation of yarn and cloth, rise in wages, lack of satisfactory power supply, shortage of working capital, etc. To mitigate the difficulties created by cotton shortage, Government made arrangements to import one million bales of cotton, including staple fibre. The Cotton Corporation of India has been established to canalise imports and also to enter the domestic market if and when considered necessary with a view to holding the price level and ensuring better distribution. Recently, Government have announced some concessions to the industry by way of reduction in the custom duty from 100% to 30% *ad valorem* on imports of cellulosic staple fibre. Government have also recognised the need for modernisation of export-oriented units in the industry. A scheme for providing financial assistance to textile units has been formulated by Government whereunder such assistance will be channelled through the Corporation on concessional terms. These measures, it is hoped, will help improve the profitability of the industry and also give a fillip to exports.

As regards the jute industry, though in the earlier months, there was a fall in demand for carpet backing in the USA market, some improvement, in this regard, was noticed towards the end of 1970. With the steep fall in exports from Pakistan owing to recent political events and better availability of jute in India, it is hoped, that the jute industdy would record better results. There is, no doubt, however, that the industry still requires modernisation on a substantial scale.

The performance of the sugar industry could, on the whole, be regarded as satisfactory, though the industry was often afflicted with the problem of large stocks causing tightness in working capital, though the position has lately improved. During the year, the percentage of levy sugar was reduced from 70 to 60, following the increase in the production of sugar. Later in may, 1971, the Central Government announced decontrol of prices, distribution and movement of sugar. The releases of sugar from the factories for sale to whole-salers will, however, continue to be regulated so as to maintain prices and ensure sugar availbility throughout the year. In place of two rates of duty of 25% *ad valorem* for levy sugar and 37.5% *ad valorem* for free sale sugar, Government has since fixed one uniform rate of duty, *i.e.* 30% *ad valorem* on all vacuum pan sugar.

The engineering industry, which was severely hit by the recession during 1965-68 showed signs of revivial. Though, there has been noticeable improvement in the demand for such products an spun pipes, steel castings, steel forgings, steel structurals, machine tools, fuller capacity could not be achieved because of shortage of steel. However, Government are fully seized of the importance of alleviating steel shortage in the country. As a measure of immediate relief, the Government arranged for imports of steel. The commissioning of the Bokaro Steel Plant and the expansion of Bhilai Steel Plant will improve the situation though it will take time. As a long-term plan, the establishment of 3 new steel plants in the South and the implementation of the programme for setting up several 'mini steel' plants are also expected to relieve to some extent shortage of steel and allied products. With the planned increase in steel production the prospects of the refractory industry have also brightened.

With regard to the paper industry, the policy of removal of controls on prices and distribution, which was announced in 1968 and 1969, has resulted in appreciable improvement in profitability and output. The country, however, is faced with acute shortage of paper. To reach the Fourth Plan target of an installed capacity of 10.20 lakh tonnes, additional capacity of the order of 2.32 lakh tonnes will have to be created. A crash programme for the expansion of capacity of some of the existing paper units is already under implementation and is expected to bring about some increase in output. Paper industry is, however, highly capital intensive. Its development and growth is dependent in a large measure on the availability of suitable raw materials such as, bamboo, bagasse, and hard woods.

The increase in the production of fertilisers was, more or less, of the same order as in the previous year. However, the production of fertilisers in the country has not been able to match the demand. The programmes in the public sector were hampered by the shortage of steel, delay in the supply of indigenously fabricated equipment, interruption in power supply and labour problems. Difficulties in arranging foreign exchange resources/foreign collaboration posed a problem to fertiliser projects in the private sector. The manufacture of fertilisers is again a highly capital intensive industry. Though some new units have already been planned, it would be some time before they go on stream and fill the gap between demand and supply.

The cement industry showed some improvement in its performance during the year, though profitability was affected by rise in wage costs and interruptions in power supply.

The man-made fibre industry has acquiring increasing significance ont only because of its versatile uses but also because of shortage of cotton in the country. The existing production of synthetic fibres in the country is very much short of demand. By the end of the Fourth Five-Year Plan, demand for nylon filament yarn (including industrial yarn) has been placed around 29,000 tonnes, whereas the capacity available would be of the order of 16,750 tonnes. To bridge the gap between the increasing demand for the synthetic fibres and its availability, efforts are necessary to put up additional capacity.

A statement outlining the installed capacity and industrial production in the country during the year 1970 in respect of some selected industries where the Corporation has rendered financial assistance as also the contribution thereto made by the concerns assisted by the Corporation appears as Appendix 'F'.

Rate of Interest

44. With prior approval of the Industrial Development Bank of India, the Corporation raised, with effect from the 5th December, 1970, the rate of interest on its rupee loans from 8½ to 9% per annum, subject to the usual rebate of ¼% annum for punctual payment of instalments of principal and interest. However, the revised rate of interest is not applicable to the rupee loans on concessional terms sanctioned/to be sanctioned to small and medium sized projects in districts/territories notified by the Central Government as industrially less developed. The rate of interest on sub-loans in foreign currencies was also raised, with effect from the 27th February, 1971, from 9 to 9¼% per annum, subject to usual rebate of ¼% per annum.

Distribution of shares

45. There has been no change in the distribution of shares of the Corporation held by the various categories of shareholders during the year under report. The distribution of shares as on the 30th June, 1971 was as under :

	Number of shares held	*Percentage in the total*
Industrial Development Bank of India	8346	50
Scheduled Banks	3405	20
Insurance Concerns, etc.	3586	22
Co-operative Banks	1355	8
	16692	100

ACCOUNTS

PROFIT AND LOSS STATEMENT FOR THE YEAR

(Lakhs of Rupees)

	This year	Previous year
46. The year's working shows a gross income of	1345·95	1281·57
After deducting from gross income :—		
Interest paid on bonds and other borrowings	820·34	793·56
Other expenses	78·35	55·19
And after providing for :—		
Taxation	237·00	237·00
The net profit for the year is :—	210·26	195·82

The net profit of Rs. 210·26 lakhs has been appropriated as under :—	₹	₹
(i) Transfer to General Reserve Fund	74·54	96·19
(ii) Transfer to Special Reserve Fund (Under Section 36 (1) (viii) of the Income-tax Act, 1961)	50·00	45·00
(iii) Transfer to Reserve for Doubtful Debts	42·99	30·00
(iv) Transfer to staff welfare fund	1·00	—
(v) Payment of dividend @ 5% on the paid-up share capital of Rs. 8·35 crores for the year	41·73	24·63
	210·26	195·82

General reserve fund

47. A sum of Rs. 74.54 lakhs has been transferred, out of the current year's profits, to the General Reserve Fund which now stands at Rs. 834.60 lakhs.

In addition to the General Reserve Fund, there are the following Special Reserve Funds aggregating Rs. 435.78 lakhs.

	(Lakhs of Rupees)
(1) Special Reserve Fund under Section 32A of the Industrial Finance Corporation Act.	100·00
(2) Special Reserve Fund under Section 36 (1) (viii) of the Income-tax Act, 1961.	335·78
	435·78

The General and Special Reserve Funds aggregate Rs. 1270.38 lakhs.

There is, in addition, a Reserve for Doubtful Debts amounting to Rs. 153.82 lakhs. The sum total of the reserves held by the Corporation adds upto Rs. 1424.20 lakhs, which exceeds the paid-up capital by Rs. 589.60 lakhs.

SPECIAL RESERVE FUND UNDER SECTION 36 (1)(VIII) OF THE INCOME TAX ACT, 1961

48. A sum of Rs. 50.00 lakhs has been transferred from the profits of the current year on the basis of 10% of the assessable income as Special Reserve Fund under Section 36(1)(VIII) of the Income-tax Act, 1961. This raises the balance to the credit of the fund to Rs. 335.78 lakhs.

Reserve for doubtful debts

49. A review of the loan accounts as at the end of the year shows a satisfactory position. In view, however, of the large size of the operations of the Corporation, and the fact that schemes for rehabilitation of certain projects may take time to mature, the Directors have decided, as a measure of prudence, to transfer an amount of Rs. 42.99 lakhs to the Reserve for Doubtful Debts from the profits of the year under report.

Provision for Income-tax

50. As the assessment proceedings in respect of tax payable by the Corporation for the accounting year ended the 30th June, 1970 (assessment year 1971-72) were not finalised by the close of the annual accounts, no adjustments in respect thereof have been made in the year's accounts. In respect of the accounting year ended the 30th June, 1971, a sum of 237.00 lakhs has been provided in the accounts for taxation.

WORKING RESULTS FOR THE LAST FIVE YEARS

51. A summary of the profit and loss account of the Corporation for the last five years is given in the following table :—

TABLE 16

(Lakhs of Rupees)

	For the year ended 30th June				
	1967	1968	1969	1970	1971
Interest earned	858·33	1009·90	1086·78	1200·34	1257·84
Other income	103·68	71·24	107·03	81·23	88·11
Total income :—	962·01	1081·14	1193·81	1281·57	1345·95
Interest paid	569·55	670·63	739·24	793·56	820·34
Discount and brokerage on bonds	12·60	16·97	17·87	1·37	1·17
Establishment expenses, inclusive of medical fees & expenses and interest on employees' provident fund	22·72	23·49	29·35	35·03	48·24
Other expenses	11·65	13·63	15·24	18·79	28·94
Total expenditure :	616·52	724·72	801·70	848·75	898·69
Gross profit :	345·49	356·42	392·11	432·82	447·26
Provision for taxation	180·69	198·25	221·79	237·00	237·00
Net profit :	164·80	158·17	170·32	195·82	210·26
To reserves	140·17	133·54	145·69	171·19	168·53
To dividend	24·63	24·63	24·63	24·63	41·73

The total income of the Corporation for the year under report amounted to Rs. 1345.95 lakhs as against Rs. 1281.57 lakhs in the previous year. The gross profit increased from Rs. 432.82 lakhs to Rs. 447.26 lakhs. After providing Rs. 237.00 lakhs for taxation (the same amount as provided last year), the net profit increased from Rs. 195.82 lakhs to Rs. 210.26 lakhs. The appropriations to reserves amounted to Rs. 168.53 lakhs as compared to Rs. 171.19 lakhs last year.

With the tranfer of Rs. 74.54 lakhs to the General Reserve Fund out of profits for the year, the Fund became equal to the paid-up share capital of the Corporation as on the 30th June, 1971. Therefore, as permissible under Section 32 of the IFC Act, the Corporation has declared a higher dividend of 5% on its paid-up capital in respect of the year ended the 30th June, 1971. It is for the first time that it has been possible to declare dividend at the maximum rate provided under the IFC Act. The total dividend for the year comes to Rs. 41.73 lakhs compared with Rs. 24.63 lakhs for the previous year.

Schedule attached to the balance sheet

52. The schedule attached to the Balance Sheet gives particulars in respect of loans and advances oustanding as on the 30th June, 1971.

(i) *Debts secured only by court-decrees.*—The outstanding amount which aggregated Rs. 0.67 lakh (Item 'e') was due from one concern.

(ii) *Interest of directors in loanee concerns.*—A statement showing an analysis of the figure shown against item (f) of the schedule is given in Appedix 'G'.

There was no concern (vide Section 'A' of the statement) in which any director of the Corporation had interest as a nominee director of a State Government or of a Co-operative Bank or of a Registrar of Co-operative Societies.

Of the loans aggregating Rs. 1113.74 lakhs due from concerns in which some of the Corporation's directors were interested as share-holders only, loans for Rs. 681.81 lakhs were sanctioned prior to the dates on which the concerned directors became directors of the Corporation or acquired interest in the loanee concerns. Debts due from concerns in which the directors of the Corporation were interested as directors and which were sanctioned financial assistance after they became directors of the Corporation aggregated Rs. 84 lakhs, constituing, about 0.5% of the total oustanding loans of Rs. 159.42 crores (vide Section 'C' of the statement).

Out of the overdue amounts of instalments of principal and interest totalling Rs. 1365.61 lakhs, a sum of Rs. 98.09 lakhs relates to a concern in which a director of the Corporation was interested as a shareholder.

Meetings of the Board, Central committee and other committees

53. Eleven Meetings of the Board were held during the year, seven at New Delhi, and one each at Bangalore, Bombay, Chandigarh and Shillong.

The Central Committee met twice during the year. 9 meetings of other Committees of the Board were also held during the year.

Advisory Committees

54. The names of the members of the six Advisory Committees have been shown elsewhere in the Report. The number of meetings of the various Advisory Committees held during the year is given below :

Name of the Advisory Committee	*No. of meetings held*
Chemical Process & Allied Industries	8
Engineering	8
Sugar	8
Textiles	5
Jute	Nil
Miscellaneous Industries	Nil

These meetings considered applications for various types of financial assistance from 44 concerns.

The Corporation continued to maintain a panel of technical experts and consultants for various industries to have the benefit of their special expertise and to co-opt them where necessary, on the appropriate Committees as members, depending upon the needs of the occassion, the complexity and nature of the case to be considered and the field of spcialisation of the expert concerned.

Board of Directors

55. During the year under report, the following changes took place in the composition of the Board :

In terms of Section 10 (1) (aa) of the IFC Act, 1948, the Industrial Development Bank of India nominated Shri F.K.F. Nariman, Dr. Samuel Paul and Dr. V. V. Bhatt, as Directors in place of Shri Charat Ram, Dr. R. N. Bhargava and Shri S. L. N. Simha, respectively.

In terms of Section 10 (1) (b) of the IFC Act, 1948, the Central Government nominated Shri B. D. Pande, Secretary to the Govt. of India, Department of Industrial Development, Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, in place of Shri T. Swaminathan. Shri B. D. Pande, consequent upon his transfer from the Ministry of Industrial Development, tendred his resignation from the Board of Directors of the Corporation. Shri B. B. Lal, Secretary to the Government of India, Ministry of Industrial Development, has been nominated in his place with effect from the 17th August, 1971.

At the Annual General Meeting held on the 30th September, 1970, Shri N. V. Nayudu, Managing Director, Life Insurance Corporation of India, was elected to represent insurance companies, investment trusts and other like financial institutions in the casual vacancy caused by the resignation of Shri S. D. Srinivasan.

The Board place on record their appreciation of the valuable services rendered by Shri Charat Ram, Dr. R. N. Bhargava, Shri S. L. N. Simha, Shri T. Swaminathan, Shri B. D. Pande and Shri S. D. Srinivasan.

Other Committees

56. The Corporation has recently taken steps to constitute Local Advisory Committees at the places where it has already established offices with a view to rendering more effective service to its clients and also to have first-hand knowledge of the industrial environments in the respective areas served by its offices, opportunities for investment, general impression of the public about the working of the Corporation, measures for popularising the activities of the Corporation, etc. The membership comprises, besides one or two Director of the Corporation, the representatives of the financial institutions at the State level, important Chambers of Commerce & Industry, nationalised bank functioning in the area of jurisdiction of the Committee, and the concerned State Government and a few prominent industrialists

Opening of officers of the Corporation

57. The Board of Directors of the Corporation have, in addition to the existing branches at Bombay, Calcutta and Madras, approved of the opening of three new branches at Ahmedabad, Hyderabad and Bangalore, and five sub-offices of the Corporation at Kanpur, Patna, Bhubaneshwar, Bhopal and Gauhati. The sub-office at Gauhati started functioning with effect from the 17th May, 1971. The office is intended to serve the States of Assam, Nagaland, Meghalaya and also the Union Territories of Manipur, N.E.F.A. and Tripura. A branch was opened at Ahmedabad on the 18th August, 1971. Arrangements are under way for opening Branches at Hyderabad and Bangalore and sub-offices at other places

Auditors

58. M/s. Walker Chandiok & Company, New Delhi, were appointed by the Industrial Development Bank of India as Auditors of the Corporation for the year ended the 30th June, 1971. At the Annual General Meeting of the shareholders of the Corporation, held on the 30th September, 1970, M/s. S. B. Billimoria & Company, Bombay, were re-elected Auditors by the shareholders, other than the Industrial Development Bank of India, for the same period. M/s. S. B. Billimoria & Company will retire but are eligible for re-election.

Acknowledgement of assistance received

59. The Board wish to place on record their appreciation of the co-operation and assistance received from the various Ministries and Departments of the Government of India and the Industrial Development Bank of India. The Board are grateful to the members, who have served on the various Advisory Committees of the Corporation, for their valuable assistance and advice, and also to the non-officials, who have served as the Corporation's nominees on the Boards of Directors of the various assisted concerns. The Board also wish to express their appreciation for the loyal and devoted service put in by the officers and staff of the Corporation during the year.

On behalf of the Directors

C. D. KHANNA
Chairman

INDUSTRIAL FINANCE

NEW

Balance Sheet as at

Previous Year	Capital and Liabilities			This Year
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
	1. AUTHORISED CAPITAL :			
10,00,00,000	20,000 shares of Rs. 5,000 each.			10,00,00,000
	ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL.			
5,00,00,000	10,000 Shares of Rs. 5,000 each fully paid-up, (Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend at 2½% under Section 5 of the Industrial Finance Corporation Act).		5,00,00,000	
2,00,00,000	4,000 (Second Series) shares of Rs. 5,000 each fully paid-up. (Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend at 4% under Section 5 of the Industrial Finance Corporation Act).		2,00,00,000	
1,34,60,000	2,692 (Third Series) shares of Rs. 5,000 each fully paid-up. (Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend at 4% under Section 5 of the Industrial Finance Corporation Act).		1,34,60,000	8,34,60,000
8,34,60,000				
	2. RESERVES AND RESERVE FUND.			
	(i) General Reserve Fund (under Section 32).			
6,63,87,453	Balance as per last Balance Sheet.	7,60,05,737		
96,18,284	Transferred from Profit & Loss Account.	74,54,263	8,34,60,000	
7,60,05,737				
	(ii) Special Reserve Fund (under Section 32A).			
1,00,00,000	Balance as per last Balance Sheet.		1,00,00,000	
	(iii) Special Reserve Fund (under Section 36(1) (viii) of the Income-tax Act, 1961).			
2,40,78,362	Balance as per last Balance Sheet.	2,85,78,362		
45,00,000	Transferred from Profit and Loss Account.	50,00,000	3,35,78,362	
2,85,78,362				
11,45,84,099				
8,34,60,000	Carried over		12,70,38,362	8,34,60,000

CORPORATION OF INDIA,

DELHI.

30th June, 1971.

Previous Year	Property and Assets			This Year
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
	1. CASH AND BANK BALANCES :			
9,177	(i) In hand at Head Office and at Branches.		38,769	
	(ii) With Banks (under Section 19).			
85,82,307	(a) Reserve Bank of India.	49,15,209		
5,92,86,840	(b) Scheduled Banks.	8,42,86,407		
10,00,000	(c) State Co-operative Banks.	26,00,000		
20,466	(d) Outside India.	8,811	9,18,10,427	9,18,49,196
6,88,89,613				
6,88,98,790				
	2. INVESTMENTS AT COST :			
	(i) Under Section 20.			
2,00,70,000	(a) Securities of the Government of India.	—		
—	(b) Securities of the State Government.	—		
21,00,000	(c) Initial Capital of Unit Trust of India.	21,00,000	21,00,000	
2,21,70,000				
	(ii) Under Section 23(1)(f)			
65,91,150	(a) Shares.	94,80,693		
—	(b) Application money paid on Shares.	8,75,000	1,03,55,693	
65,91,150				
	(iii) Under Section 23(1)(h)			
—	(a) Stocks.	—		
10,33,16,613	(b) Shares.	10,85,49,285		
9,73,250	(c) Application money apaid on shares & debentures.	2,17,750		
—	(d) Bonds.	—		
4,86,29,600	(e) Debentures.	4,73,14,600	15,60,81,635	
15,29,19,463				
	(iv) Under Section 23(1)(i)			
1,82,00,000	Debentures.		1,37,35,000	18,22,72,328
19,98,80,613				
	[Rs. 13,33,86,090 (Quoted) Rs. 12,99,08,245 (Market Value). Rs. 4,88,86,238 (Unquoted.)]			
	3. LOANS AND ADVANCES :			
153,22,17,265	Total loans outstanding (as per schedule annexed).			159,41,19,564
1,80,09,96,668	Carried over			1,86,82,41,088

BALANCE

Previous Year	Capital and Liabilities			This Year
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
8,34,60,000	Brought Forward			8,34,60,000
11,45,84,099	RESERVES & RESERVE FUND (*Contd.*)		12,70,38,362	
	(iv) Reserve for Doubtful Debts.			
89,45,478	Balance as per last Balance Sheet.	1,19,45,478		
—	*Less* : Bad Debt written off,	8,63,019		
89,45,478		1,10,82,459		
30,00,000	Transferred from Profit & Loss Account.	42,99,175	1,53,81,634	
1,19,45,478				
	(v) Staff Welfare Fund			
—	Transferred from Profit & Loss Account.		1,00,000	14,25,19,996
12,65,29,577				
	3. PROVISION FOR TAXATION :			
5,98,60,717	Balance as per last Balance Sheet.		4,56,78,698	
2,37,00,000	*ADD* : Provision for the year.		2,37,00,000	
8,35,60,717			6,93,78,698	
3,78,82,019	*LESS* : Adjustments during the year (Net.)		2,15,91,727	
4,56,78,698			4,77,86,971	
61,07,118	*LESS* : Tax deducted at source.	61,40,537		
2,08,14,602	Advance tax paid,	2,38,12,581	2,99,53,118	1,78,33,853
2,69,21,720				
1,87,56,978				
	4. BONDS AND DEBENTURES :			
5,48,86,900	(i) 4% Bonds (Unsecured) redeemable in 1971. (Guaranteed by the Government of India under Section 21).		5,48,86,900	
6,00,33,100	(ii) 4½% Bonds (Unsecured redeemable in 1974. (Guaranteed by the Government of India under Section 21).		5,00,33,100	
4,45,50,000	(iii) 4½% Conversion Bonds (Unsecured) redeemable in 1976. (Guaranteed by the Government of India under Section 21.)		4,45,50,000	
6,58,48,100	(iv) 4½% Bonds (Unsecured) reedeemabe in 1976. (Guaranteed by the Government of India under Section 21).		6,58,48,100	
22,53,18,100				
22,87,46,535	Carried over		22,53,18,100	24,38,13,849

SHEET (*Contd.*)

Previous Year	Property and Assets			This Year
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
1,80,09,96,668	Brought Forward			1,86,82,41,088
1,05,90,811	4. SUB-BORROWERS COMMITMENT TOWARDS DEFERRED FRENCH CREDIT ON ACCOUNT OF PRINCIPAL.			1,08,16,648
	5. DIVIDEND DEFICIT ACCOUNT :			
—	Balance as per last Balance Sheet.		—	
—	*LESS* : Balance of Profit transferred from Profit & Loss Account.		—	—
	6. PREMISES AT COST :			
—	Balance as per last Balance Sheet.		—	
—	Additions during the year.		—	
—			—	
—	*LESS* : Depreciation upto last year.	—		
—	Depreciation for the year.	—	—	—
	7. MOTOR CARS, CYCLES, FURNITURE, FIXTURES, FITTINGS, ETC. AT COST :			
7,68,879	Balance as per last Balance Sheet.		8,63,576	
1,05,749	Additions during the year.		4,96,869	
8,74,628			13,60,445	
11,052	*LESS* : Cost of assets sold/discarded.		6,725	
8,63,576			13,53,720	
2,97,306	*LESS* : Depreciation upto last year.	3,54,367		
67,274	Depreciation for the year.	1,13,870		
3,64,580		4,68,237		
10,213	*DEDUCT* : Depreciation on assets sold/discarded.	3,239	4,64,998	8,88,722
3,54,367				
5,09,209				
	8. OTHER ASSETS :			
	Interest accrued :			
1,19,02,283	(i) On loans and advances.	1,42,76,886		
15,96,814	(ii) On debentures.	15,47,802		
18,97,876	(iii) On deposits with banks.	20,05,095		
1,53,96,973				
1,81,20,96,688	Carried over	1,78,29,783		1,87,99,46,458

BALANCE

Previous Year	Capital and Liabilities			This Year
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
22,87,46,555	Brought Forward			24,38,13,849
22,53,18,100	BONDS AND DEBENTURES (*Contd.*)		22,53,18,100	
2,00,00,000	(v) 5½% Bonds (Unsecured) redeemable in 1977. (Guaranteed by the Government of India under Section 21).		2,00,00,000	
6,12,90,000	(vi) 5¾ % Bonds (Unsecured) redeemable in 1978. (Guaranteed by the Government of India under Section 21).		6,12,90,000	
8,24,86,700	(vii) 5¾ % Bonds (Unsecured) redeemable in 1979. (Guaranteed by the Government of India under Section 21).		8,24,86,700	
8,33,30,800	(viii) 5¾ % Bonds (Unsecured) redeemable in 1980 (Guaranteed by the Government of India under Sectin 21).		8,33,30,800	
5,50,00,000	(ix) 5¾ % Bonds (Unsecured) redeemable in 1981.(Guaranteed by the Government of India under Section 21).		5,50,00,000	
—	(x) 5¾ % Bonds (Unsecured) redeemable in 1982. (Guaranteed by the Government of India under Section 21).		4,95,00,000	
—	(xi) % Debentures (Unsecured) redeemable in (Guaranteed by the Government of India under Section 21).		—	57,69,25,600
52,74,25,600				
	5. FIXED DEPOSITS :			
—	(Under Section 22).			
	6. BORROWINGS :			
	(i) From Reserve Bank of India:—			
	(a) Secured by pledge of Government Securities of the face value of Rs.—[under Section 21 (3)(a)].			
—	(b) Secured by Bonds and Debentures issued by the Corporation of the face value of Rs. 3·25 crores. [under Section 21 (3) (b)].	1,24,10,000	1,24,10,000	
—				
—	(ii) From Industrial Development Bank of India. [under Section 21 (4)].			
79,61,48,180	(iii) From Government of India [under Section 21(4)].		77,32,05,415	
20,62,91,583	(iv) In Foreign Currency.		21,47,49,369	1,00,03,64,784
1,00,24,39,763				
1,05,90,811	7. DEFERRED FRENCH CREDIT ON ACCOUNT OF PRINCIPAL.			1,08,16,648
	8. SUBVENTION PAID BY GOVERNMENT OF INDIA.			
	On account of dividend under Section 4 read with Section 32.			
—	Balance as per last Balance Sheet.			
—	*LESS* : Paid to Government of India.			—
—				
1,76,92,02,729	Carried over			1,83,19,20,881

SHEET (*Contd.*)

Previous Year	Property and Assets			This Year
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
1,81,20,96,688	Brought Forward			1,87,99,46,458
1,53,96,973	OTHER ASSETS (Contd.)	1,78,29,783		
1,86,389	(iv) On investment in Government Securities.	—		
39,124	(v) On advances to staff.	68,871		
288	(vi) On Rental Deposits.	288	1,78,98,942	
1,56,22,774				
11,23,960	Commitment and charges accrued.		8,46,232	
2,839	Commitment & other charges accrued on Foreign Currency Loans availed.		—	
38,71,934	Sundry Debtors.		42,82,422	
4,66,624	Advances to staff.		7,70,395	
90,501	Stocks of stationery.		95,673	
55,186	Telephone Deposits.		72,019	
	Cheques lodged for collection or in hand pending collection			
93,16,304	per contra.		97,99,110	
51,689	Prepaid Expenses.		53,844	
3,28,746	Difference in Exchange.		2,58,344	
18	Stamps on hand.		18	
3,09,30,521				3,40,76,999
24,39,66,816	9. GUARANTEES PER CONTRA.			20,70,51,508
12,50,000	10. UNDERWRITING CONTRACTS PER CONTRA.			23,00,000
2,08,82,44,025	Carried over			2,12,33,74,965

BALANCE

Previous Year	Capital and Liabilities			This Year
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
1,76,92,02,729	Brought Forward			1,83,19,20,881
	9. OTHER LIABILITIES :			
	Interest accrued and accruing :-			
1,52,82,212	(a) On borrowings from Government of India under Section 21(4).	1,48,88,796		
69,14,830	(b) On industrial Finance Corporation Bonds.	73,25,956		
13,01,429	(c) On borrowings in Foreign Currency.	11,94,169		
447	(d) On Sundry Deposits.	487	2,34,09,408	
2,34,98,918				
10,12,797	Advance Garantee Commission.		8,94,204	
1,02,05,992	Sundry Creditors.		1,03,62,206	
2,34,52,773	Interest held in Suspense.		2,91,68,158	
5,32,414	Commitment Charges held in Suspense.		4,33,270	
24,717	Incidental Charges held in Suspense.		38,681	
4,20,572	Guarantee Commission held in Suspense.		4,20,572	
68,900	Legal Charges Suspense.		74,200	
28,27,255	Industrial Finance Corporation Employees' Provident Fund Account.		33,23,363	
438	Unclaimed Dividend.		614	
93,16,304	Cheques received for collection per contra.		97,99,110	
—	Commitment Charges accrued on Foreign Currency Loans availed.		5,790	7,79,29,576
7,13,61,080				
	10. CONTINGENT LIABILITIES :			
8,24,21,131	(a) Guarantees given. [under Section 23(1)(b) per contra].	7,05,29,601		
16,15,45,685	(b) Foreign loan Guarantees given. [under Section 23 (1)(c) per contra.]	13,65,21,907	20,70,51,508	
24,39,66,816				
12,50,000	(c) Underwriting contracts. [under Section 23 (1) (d) per contra].		23,00,000	20,93,51,508
24,52,16,816				
2,08,57,80,625	Carried over			2,11,92,01,965

SHEET *(Contd.)*

Previous Year	Property and Assets			This Year
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
	Brought Forward			2,12,33,74,965

2,08,82,44,025	Carried over	2,12,33,74,965

BALANCE

Previous Year	Capita and Liabilities			This Year
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
2,08,57,80,625	Brought Forward			2,11,92,01,965
	II. PROFIT & LOSS ACCOUNT :			
24,63,400	Balance as per last Balance Sheet.	24,63,400		
24,63,400	*LESS* : Dividend for 1969-70.	24,63,400	—	
—				
1,95,81,684	*ADD* : Profit for the year as per Profit & Loss Account.		2,10,26,438	
45,00,000	*LESS* : Transferred to Special Reserve Fund (under section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961).	50,00,000		
30,00,000	Transferred to Reserve for Doubtful Debts.	42,99,175		
96,18,284	Transferred to General Reserve Fund.			
—	Transferred to Staff Welfare Fund.	1,00,000	1,68,53,438	41,73,000
1,71,18,284				
24,63,400				
2,08,82,44,025				2,12,33,74,965

Contingent Liabilities : (a) Partly paid-up shares held as investment under Section 23(1)(f) and Section 23(1)(h)—Rs. 34,91,593/-.

(b) Interest under Deferred French Credit—Rs. 25,74,787/-.

Baldev Pasricha
General Manager

C. D. Khanna
Chairman

As per our report attached.

S.B. BILLIMORIA & Co.

WALKER, CHANDIOK & Co.

Chartered Accountants

Shri N. Ramanand Rao
Shri G. Ramanujam
Dr. V. V. Bhatt
Dr. Samuel Paul
} *Directors*

Shri S. J. Utamsing
Sardar Santokh Singh
Shri P. S. Rajagopal Naidu
} *Directors*

SHEET (*Contd.*)

Previous Year	Property and Assets			This Year
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
2,08,82,44,025	Brought Forward			2,12,33,74,965
2,08,82,44,025				2,12,33,74,965

NOTES: (1) Investments under Section 23(1)(h) include a sum of Rs. 1,97,900/- in the equity share capital of a company which has gone into voluntary liquidation. The Corporation is not likely to realise the full amount invested.

(2) Loans and advances include a sum of Rs. 81,63,841/- due from an industrial concern which is considered doubtful of recovery. No specific provision has been made against this amount because of adequate provision existing under the heads "Interest held in Suspense Account" and "Reserve for Doubtful Debts".

(3) Loans and advances during the previous year included Rs. 23,75,000/- on account of arrears of instalments of interest due from two concerns. During the year, the Corporation adjusted arrears of interest by accepting equity shares of the borrower companies of the same face value as part of a rehabilitation scheme. The market value of these shares is considered below the face value.

(4) Commitment and other charges accrued include:

(a) Rs. 1,41,567/- due from two concerns, the payment of which is disputed. No specific provision has been made against this amount which is considered doubtful of recovery.

(b) Rs. 4,33,270/- due from a concern, which is considered dubtful of recovery and held in suspense.

(5) Sundry Debtors include:—

(a) Rs. 9,87,641/- being balance of purchase consideration, fully secured, recoverable from a company on account of assets of a borrower concern sold to them.

(b) Rs. 2,76,729/- being balance of purchase consideration and interest thereon (security Rs. 2,58,000/-) recoverable from a company on account of assets of a borrower concern sold to them.

(c) Rs. 7,87,975/- on account of additional liability of certain sub-borrowers in respect of instalments of principal, repaid by them prior to the devaluation of the rupee, which is in dispute and considered doubtful of recovery.

(d) Rs. 1,97,525/- being the amount of application and allotment moneys invested in a company. The Corporation filed a suit holding the allotment of shares void, as certain Stock Exchanges refused to list the shares, and claiming refund of the application and allotment amount paid. The allotment has since been held valid by Supreme Court. There are however certain other connected issued pending before the High Court and pending settlement the amount is continued to be held in Sundry Debtors Account.

(6) No provision has been made in respect of liability for gratuity payable (amount unascertainable) in accordance with the Payment of Gratuity to Employees Regulations, 1968.

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA
NEW DELHI

Scheduled showing particulars in respect of Loans and Advances referred to in the Balance Sheet as at the 30th June, 1971.

	Rs.
(a) Debts considered good in respect of which the Corporation is fully secured. Out of this :-	130,81,66,142
(i) Loans amounting to Rs. 65,61,31,075 are also secured by the personal guarantees of Directors and/or former Managing Agents and/or former Secretaries and Treasurers of borrower concerns. (Of these loans aggregating Rs. 82,00,000 are further secured by the guarantees of the Central and/or State Governments and loans aggregating Rs. Nil are guaranteed by the Scheduled or Co-operative Banks).	
(ii) Loans amounting to Rs. 40,23,99,322 are also secured by the guarantees of the Central and/or State Governments.	
(iii) Loans amounting to Rs. Nil are also secured by the guarantees of Scheduled and/or State Co-operative Banks.	
(b) Debts previously fully secured but now secured to the extent of Rs. 10,52,99,000 only. (Out of Rs. 15,45,71,894/ loans amounting to Rs. 2,65,28,146 are also secured by the guarantees of the Central and State Governments.)	15,45,71,894
(c) Debts secured only by the gurantees of the Central and/or State Governments.	4,52,32,197
(d) Debts secured only by the gurantees of the Scheduled and/or Co-operative Banks.	8,60,82,584
(e) Debts secured only by Court Decrees.	66,747
Total of (a), (b), (c), (d) & (e)	159,41,19,564
(f) Debts due by concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Directors and Shareholders.	13,01,68,028
Of these :-	
(i) Debts aggregating Rs. Nil are due by Co-operative Societies in which the Directors of the Corporation are interested as nominees of State Government or Co-operative Banks or Registrar of Co-operative Societies.	
(ii) Debts aggregating Rs. 11,13,74,147 are due by concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Shareholders only.	
(iii) Debts aggregating Rs. 1,87,93,881 are due by concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Directors.	
(g) Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Directors and Shareholders.	1,13,48,901

		Rs.
(h) (i)	Total amount of instalments whether of principal or interest of which default was made at any time during the year.	5,44,59,234
(ii)	Total amount of instalments whether or principal of interest overdue at the end of the year.	13,65,60,680
(iii)	Total amount of instalments whether of principal or interest overdue by concerns in which Directors of the Corporation are interested as shareholders only.	98,08,886

Note:—The schedule includes defaults committed by six concerns in payment of the instalments of deferred payments to the machinery suppliers met by the Corporation under Deferred Payment Guarantee and treated as loans.

BALDEV PASRICHA
General Manager

C. D. KHANNA
Chairman

S. B. BILLIMORIA & CO.

WALKER, CHANDIOK & CO.

Chartered Accountants

INDUSTRIAL FINANCE

NEW

Profit Loss Account for the

Previous Year			This Year
Rs.		Rs.	Rs.
7,93,55,581	To Interest on Bonds, Debentures, etc.		8,20,34,017
	,, Salaries, Allownaces, Provident Fund Contributions and Gratuity :		
50,622	(a) Chairman.	46,457	
36,719	(b) General Manager.	29,325	
32,27,364	(c) Others.	46,06,686	
1,79,733	(d) Provident Fund Contributions.	2,10,110	
39,735	(e) Gratuity.	2,250	
35,34,174		48,94,828	
2,11,050	*LESS* : Amount recovered from assisted concerns for legal work done by the Corporation.	2,81,700	46,13,128
33,23,123			
11,750	To Directors' Fees.		11,350
3,250	,, Commitee Members' Fees (Other than Directors).		4,350
91,989	,, Directors' Travelling and Other allowances.		1,00,711
48,314	,, Committee Members' (Other than Directors) Travelling and other allowances.		44,988
8,71,785	,, Rent, Taxes, Insurance and Lighting.		11,16,601
1,41,764	,, Postage, Telegrams, Stamps and Telephones.		1,62,185
1,70,006	,, Printing, Stationery and Advertisement.		2,67,020
7,764	,, Repairs.		6,187
39,785	,, Law Charges.		32,854
20,000	,, Audit Fees.		20,000
67,274	,, Depreciation.		1,13,870
	To other Expenses :		
5,500	Agency Charges.	4,950	
15,000	Books and Newspapers.	19,047	
37,091	Medical Fees and Expenses.	42,749	
1,46,658	Travelling Expenses.	1,79,650	
11,985	Halting Allowances.	16,739	
20,083	Maintenance of Motor Cars.	25,587	
2,36,317			
8,41,52,385	Carried Over	2,88,722	8,85,27,261

CORPORATION OF INDIA,
DELHI

Year ended the 30th June, 1971

Previous Year				This Year
Rs.			Rs.	Rs.
12,00,33,727	By	Interest.		12,57,83,668
28,37,627	„	Commission.		25,81,615
—	„	Rent.		—
5,53,835	„	Profit on sale of Investments.		12,22,356
5,233	„	Profit on sale of Assets.		1,132
26,29,767	„	Dividend on Shares.		34,39,754
18,45,351	„	Commitment Charges.		13,36,427
—	„	Premia on premature repayments.		—
—	„	Bad Debts recovered.		
2,51,062	„	Miscellaneous Income.		2,40,105
12,81,56,602		Carried Over		12,45,95,027

PROFIT & LOSS

Previous Year				This Year
Rs.			Rs.	Rs.
8,41,52,385		Broutght Forward		8,85,27,261
2,37,317	To	Other Expenses (*Contd.*)	2,88,722	
4,800		Listing fees	6,000	
20,253		Bank Charges.	26,648	
97,610		Expenses not Enumerated.	1,81,773	
1,43,151		Interest of Employees' Provident Fund.	1,67,672	6,72,815
5,02,131				
83,106	To	Commitment Charges on Foreign Currency Loans.		1,41,091
1,37,091	„	Brokerage on Bonds.		1,16,756
..	„	Discount on Bonds.		—
..	„	Bad Debts written off.		—
—	„	Income tax deducted on sale of securities.		—
—	„	Provisions for doubtful debts.		—
—	„	Loss on sale of Investments.		4,00,000
206	„	Assets written off.		482
—	„	Loss on sale of Assets.		184
2,37,00,000	„	Provision for Taxation.		2,,37,00,000
1,95,81,684	„	Balance of Profit carried to Balance Sheet.		2,10,26,438
12,81,56,602				12,45,95,027

Baldev Pasricha
General Manager

C. D. Khanna
Chairman

As per our report attached.

S. B. BILLMORIA & CO.
WALKER, CHANDIOK & CO.

Chartered Accountant

Shri N. Ramanand Rao
Shri G. Ramanujam
Dr. V. V. Bhatt
Dr. Samuel Paul
} *Directors*

Shri S. J. Utamsing
Sardar Santokh Singh
Shri P. S. Rajagopal Naidu
} *Directror*

ACCOUNT (*Contd.*)

Previous Year		This Year
Rs.		Rs. Rs.
12,81,56,602	Brought Forward	13,45,95,027
12,81,56,602		13,45,95,027

Notes : 1. Interest includes Rs. 3123/- recovery of the arrears originally held in Suspense Account.

2. Interest does not include Rs. 57,92,340/- considered doubtful of recovery and held in Suspense Account.

3. Interest has not been charged in one account as it is considered doubtful of recovery.

4. Commission on one account amounting to Rs. 1,73,493/- has not been taken into account as the interpretation of the clause in the relative agreement, relating to the basis of computation of the amount, is under correspondance.

5. Commitment Charges include Rs. 68,240/- recovery of the arrears originally held in Suspene Account.

6. "Miscellaneous Income" does not include Rs. 13,965/- on account of Incidental Chargesal considered doubtful of recovery and held in Suspense Account.

7. Salaries and allowances include Rs. 3,75,293/- on account of revision of pay scales of workmen employees and adjustment allowance to officers in respect of previous year.

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA
REPORT OF THE AUDITORS

TO THE SHAREHOLDERS

OF THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

We, the undersigned Auditors of the Industrial Finance Corporation of India, do hereby report to the Shareholders upon the Balance Sheet and Accounts of the Corporation as at 30th June, 1971.

We have examined the attached Balance Sheet with the Accounts and Vouchers relating thereto and the audited returns from the Branches, which returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where we have called for explanations and information, such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion, the Balance Sheet together with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and properly drawn up in accordance with the Act and the Rules of the Corporation so as to exhibit a true and correct view of the State of the affairs of the corporation according to the best of our information and explanations given to us and as shown by the books of the Corporation.

S. B. BILLIMORIA & CO.
WALKER CHANDIOK & CO.
Chartered Accountants

TRIVANDRUM
Dated, 26th August, 1971

CONTENTS

	Appendix
Statement showing the state-wise distribution of the number and amount of applications pending at on 1,7,1970, as also those received, rejected, withdrawan and sanctioned and the amount disbursed during the year ended the 30th June, 1971, and applications pending as on the 30th June, 1971	"A"
Statement of financial assistance sanctioned from 1-7-70 to 30-6-1771	"B"
Analysis of the net financial assistance sanctioned for various types of industries as per the International Standard Industrial Classification of all economic activities as on the 30th June, 1971	"C"(*i*)
State/Temporary-wise distribution of net financial assistance sanctioned as on the 30th June, 1971	"C"(*ii*)
Statement showing the classification of net financial assistance sanctioned as on the 30th June, 1971, according to amounts sanctioned for each industrial concern.	"D"
Statement showing industry-wise distribution of net financial assistance sanctioned up to the 30th June, 1971 in each State.	"E"
Statement showing the total installed capacity and industrial production in the country in seected industries during the year 1970 and the contribution thereto by concerns assisted by I.F.C.	"F"
Debts due by concerns in which the Directors of the Corporation are interested.	"G"
Consolidated list of districts/territories notified by the Central Government as qualifying for concessional finance from public financial instiutions.	"J"
Details of concessions on financial assistance for industrial projects that may be located in districts/areas notified by the Central Government.	"I"

APPENDIX "A"

STATEMENT SHOWING STATE-WISE DISTRIBUTION OF THE NUMBER AND AMOUNT OF DRAWN AND SANCTIONED AND THE AMOUNT DISBURSED DURING THE YEAR ENDED

(a) represents loans. (b) represents underwritings. (c) represents guarantees for deferred payments on machinery and for foreign loans.

State/Territory		Applications pending at the beginning of the year (1-7-70)*		Applications received during the year (1-7-70 to 30-6-71)		Applications rejected during the year (1-7-70 to 30-6-71)	
		No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Andhra Pradesh	(a)	1	60·00	2	340·00	—	—
	(b)	—	—	1	5·00	—	—
Assam	(a)	—	—	—	—	—	—
Bihar	(a)	2	221·46	3	475·00	—	—
	(b)	1	2000·00	2	500·00	—	—
Gujarat	(a)	2	3823·00	8	699·60	—	—
	(b)	—	—	1	23·00	—	—
	(c)	—	—	1	64·40	—	—
Haryana	(a)	6	643·00	6	121·73	—	—
	(b)	1	3·90	4	23·48	—	—
Kerala	(a)	1	20·00	5	390·00	—	—
	(b)	1	7·50	2	110·00	—	—
	(c)	1	10·00	—	—	—	—
Madhya Pradesh	(a)	1	40·00	—	—	—	—
	(b)	—	—	—	—	—	—
Maharashtra	(a)	11	921·10	18	1067·39	1	200·00
	(b)	3	195·00	3	21·42	1	120·00
Mysore	(a)	2	3050·00	4	382·28	—	—
	(b)	1	700·00	—	—	—	—
Orissa	(a)	—	—	4	1109·05	—	—
	(b)	—	—	2	15·50	—	—
Punjab	(a)	2	311·68	1	60·00	1	275·68
	(b)	2	226·80	—	—	1	220·00
Rajasthan	(a)	—	—	4	122·10	—	—
Tamil Nadu	(a)	1	55·00	9	370·78	—	—
	(b)	—	—	2	15·00	—	—
	(c)	—	—	—	—	—	—
Uttar Pradesh	(a)	7	418·90	7	297·12	—	—
	(b)	3	37·25	4	50·00	—	—
West Bengal	(a)	2	54·72	3	37·50	—	—
	(b)	—	—	—	—	—	—
Delhi	(a)	—	—	—	—	—	—
	(b)	—	—	—	—	—	—
Goa, Daman & Diu	(a)	—	—	—	—	—	—
TOTAL :	(a)	38	9618·86	74	5472·55	2	475·68
	(b)	12	3170·45	21	763·40	2	340·00
	(c)	1	10·00	1	64·40	—	—
GRAND TOTAL :		51	12799·31	96	6300·35	4	815·68
		(34)		(70)		(2)	
Of which joint financing with other financial institutions:**		17	11328·89	17	3226·90	4	815·68
		(9)		(8)		(2)	

Note : *The number and amount of applications pending at the beginning of the year may not tally with the figures shown in the Annual Report for the previous year due to certain changes made subsequently by the applicant concerns.

**Figures in brackets denote the number of concerns.

†Including 6 cases of re-allocation for Rs. 27·35 lakhs sanctioned in earlier years.

APPLICATIONS PENDING AS ON 1-7-1970 AS ALSO THOSE RECEIVED, REJECTED, WITH THE 30TH JUNE, 1971 AND APPLICATIONS PENDING AS ON THE 30TH JUNE, 1971.

(Lakhs of Rupees)

Applications withdrawn during the year (1-7-70 to 30-6-71)		Applications sanctioned (Gross amount) during the year (1-7-70 to 30-6-71)		Amount disbursed during the year (1-7-70 to 30-6-71)	Applications pending as on 30-6-1971	
No. (8)	Amount (9)	No. (10)	Amount (11)	Amount (12)	No. (13)	Amount (14)
1	60·00	2	185·00	80·00		—
—	—	1	5·00	9·95	—	—
—	—	—	—	18·50	—	—
2	221·46	3	225·00	66·45	—	—
—	—	3	260·00	5·93	—	—
1	43·99	6	383·61	44·52	4	4098·00
—	—	1	23·00	—	—	—
—	—	1	42·35	—	—	—
3	135·25	5	143·57	52·02	4	114·00
—	—	3	10·88	8·62	3	18·50
1	20·00	1	105·00	36·46	4	285·00
1	7·50	—	—	—	2	110·00
1	10·00	—	—	—	—	—
—	—	1	40·00	21·46	—	—
—	—	1	5·00	4·24	—	—
3	71·10	18	752·08	584·93	9	761·00
1	5·00	4	17·02	6·24	—	—
—	—	4	260·28	121·32	2	2972·00
—	—	—	—	0·76	1	700·00
—	—	4	269·05	123·73	—	—
—	—	1	10·00	—	1	5·50
1	60·00	—	0·70	9·02	1	36·00
—	—	—	—	—	1	6·80
—	—	3	81·10	4·00	1	36·00
1	9·00	7	216·78	139·77	2	85·00
—	—	1	5·00	7·24	1	10·00
—	—	—	—	19·79	—	—
2	156·28	10	297·94	135·35	3	165·50
1	6·00	4	44·25	7·84	2	37·00
1	42·72	4	49·50	160·66	—	—
—	—	—	—	0·92	—	—
—	—	—	—	30·00	—	—
—	—	—	—	5·78	—	—
—	—	—	—	29·20	—	—
16	819·80	68†	3109·61	1628·19	30	8552·50
3	18·50	19†	380·15	86·72	11	887·80
1	10·00	1	42·35	19·79	—	—
20	848·30	88	3532·11	1734·70	41	9440·30
(16)		(61)			(28)	
2	221·46	19	1269·19		9	7787·50
(1)		(10)			(4)	

APPENDIX "B"

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM THE IST JULY, 1970 TO THE 30TH JUNE, 1971

(Lakhs of Rupees)

S. No.	Name of the concern and location of the factory	Name of the Managing Directors/ Chairman/President of the Board of Directors/Secretaries and Treasurers	Capital cost of the project	Amount of financial assistance sanctioned						Particulars of the project or purpose of assistance sanctioned
				Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Guarantees for deferred payments on machinery	
						Equity	Preference	Debentures		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ANDHRA PRADESH						
1.	M/s. Andhra Foundry & Machine Co. Ltd., Maula Ali, Hyderabad.	Shri Harish Chandra Prasad, Proposed Managing Director.	30·00	—	—	2·50@	2·50@	—	—	Acquisition and installation of certain balancing equipment and replenishment of working capital and meeting other pressing liabilities.
2.	M/s. Hindustan Polymers Ltd., Visakhapatnam.	Shri Kasturbhai Lalbhai, Chairman.	249·17 (over-run)	35·00 (addl.)	—	—	—	—	—	For meeting a part of the second over-run in the cost of the project envisaging manufacture of 10,000 tonnes of styrene monomer, 7,500 tonnes of polystyrene per annum with a captive alcohol distillery having a capacity of 2·2 million gallons per annum.
3.	M/s. West Godavari Co-op. Sugars Ltd., Surappagudem, Dist. West Godavari.	Co-operative Unit.	260·00	150·00*	—	—	—	—	—	Setting up a sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
				BIHAR						
4.	M/s. Bihar Alloy Steels Ltd., Patratu, Ranchi.	Dr. B. C. Jain, Proposed Managing Director, (Birla Group)	2431·58	150·00	—	50·00	10·00	—	—	Setting up a factory for the manufacture of carbon alloy and constructional steels, spring steels, austenitic and heat resisting steels, tool and high speed steels with an installed capacity of 40,000 tonnes per annum.
5.	M/s. Kalyanpur Lime & Cement Works Ltd., Banjari, Distt. Sahabad.	Shri S. P. Sinha, Managing Director,	101·40	50·00 (addl.)	—	—	—	—	—	Renovation and balancing scheme for achieving and stabilising the production of cement at the rated capacity of 4 lakh tonnes per annum.

6.	M/s. Purnea Co-op. Sugar Factory Ltd., Banmankhi, Distt. Purnea.	Co-operative Unit.	59·60 (over-run)	25·00 (addl.)	—	—	—	—	—	For meeting the over-run in the cost of the project of setting up a sugar factory with a crushing capacity of 1,000 tonnes of sugar-cane per day.
7.	M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., Jamshedpur, Distt. Singhbhum.	Shri J. R. D. Tata, Chairman and Shri S. K. Nanavati, Managing Director, (Tata Group)	5800·00	—	—	—	—	200·00	—	For financing the replacement, modernisation and diversification programm of the company.
					GUJARAT					
8.	M/s. Amreli Sahakari Krishi Khand Udyog Ltd., Govadka, Distt. Amreli.	Co-operative Unit.	249·95	140·00*	—	—	—	—	—	Setting up a sugar factory with a crushing capacity of 1250 tonnes of sugar-cane per day.
9.	M/s. Gujarat Polyamides Ltd., Udhana, Distt. Surat.	H. H. Fateshinhrao P. Gaekwad, Chairman.	1100·00	50·00	100·00 (in DM)	8·00	15·00	—	42·35	Setting up a plant for the manufacture of Nylon-6 textile yarn with an installed capacity of 1,800 tonnes per annum.
10.	M/s. Precision Bearings India Ltd., Maneja, Distt. Baroda.	Shri K. G. Krishnamoorthy, Vice-President (Technical), Shri K. M. S. Wadia, Vice-President (Commercial).	168·89	85·00	5·61 (in DM)	—	—	—	—	Expansion and balancing of the existing plant so as to increase the production of ball and roller bearings from 23.53 lakh nos. to 28·82 lakhs nos. per annum.
					HARYANA					
11.	M/s. Atlas Cycle Industries Ltd., Sonepat, Distt. Rohtak.	Shri B. D. Kapur, and Shri J. D. Kapur, Principal Executive Officers.	6·45	—	4·15 (in DM) (addl.) 0·43 (in £)	—	—	—	—	Replacement of certain worn-out machines and introduction of semi-automatic processes in the manufacture of components for bicycles.
12.	M/s. Beco Engg. Co. Ltd., Ballabgarh, Distt. Gurgaon.	Shri Yayant H. Shah, Managing Director, (Bajaj Group)		—	3·15 (in DM) (addl.)	—	—	—	—	Import of a gear grinding machine from West Germany.
13.	M/s. Depro Foods Ltd., Rai, Near Sonepat, Distt. Rohtak.	Shri M. P. Mittal, Managing Director.	36·88	12·00**	—	2·50	1·40	—	—	Setting up a vegetable dehydration plant with the capacity to process 12 to 15 tonnes of prepared raw vegetables per day.
14.	M/s. Escorts Tractors Ltd., Faridabad, Distt. Gurgaon.	Shri H. P. Nanda, Chairman.	991·82	60·00	63·84 (in DM)	—	—	—	—	Manufacture of 16 H.P. tractors, replacement of parts and related accessory equipments with an installed capacity of 6,000 nos. p. a.

@Direct subscription.
*To be reduced to the extent LIC participates in the project.

APPENDIX "B" (*contd.*)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	M/s. Excelsior Plants Corporation Ltd., Distt. Gurgaon.	Shri J. N. Raina, Managing Director.	—	—	—	2·00@	—	—	—	Setting up a factory for the manufacture of mechanical brick plants as also plants for the manufacture of ceramic and special types of tiles with an installed capacity of 25 plants. n.a.
16.	Telefunken (India) Ltd., Ballabgarh, Distt. Gurgaon.	Mr. Felix Herringer, Chairman and Shri Ravi P. Gupta, Managing Director.	25·00	—	—	2·49@	2·49@	—	—	Increasing the production of radio sets to 3 lakh nos. per annum as also to take up the manufacture of 40,000 nos. of record players per annum.
					KERALA					
17.	M/s. Traco Cable Co. Ltd., Irimpanam, Distt. Ernakulam. (Kerala Govt. Undertaking).	Shri K. P. Viswanathan Nair, Chairman.	₹149·10	105·00	—	—	—	—	—	Diversification scheme for the manufacture of paper insulated telecommunication cables with an installed capacity of 1,000 kms. per annum.
					MADHYA PRADESH					
18.	M/s. Co-op. Spg. Mills Ltd., Burhanpur, Distt. Khandwa.	Co-operative Unit.	110·09	40·00	—	—	—	—	—	Setting up a spinning mill with a complement of 12,312 spindles.
19.	Shree Synthetics Ltd., Ujjain.	M/s. Bangur Bros., Ltd., Secretaries. (Bangur Group)	—	—	—	5·00@ @	—	—	—	Setting up a plant for the manufacture of Nylone-9 filament yarn with an installed capacity of 1,100 tonnes per annum.
					MAHARASHTRA					
20.	M/s. Antifriction Bearings Corpn., Ltd., Lonavla, Poona.	Sri C. C. Desai, Chairman.	323·86	100·00	—	—	—		—	Expansion scheme envisaging an increase in the production capacity of roller beatings from 4.64 lakh nos. to 10 lakhs nos. per annum.
21.	M/s. Ashok S. S. K. Ltd., Ashok Nagar, Distt. Ahmedanagar.	Co-operative Unit	163·90	100·00 (addl.)	—	—	—	—	—	Expansion scheme for increasing the crushing capacity from 1500 to 2600 tonnes of sugarcane per day.
22.	Bombay Malleable Iron Castings & Allied Industries Ltd. Ambernatha, Bombay.	Shri H. M. Patel Chairman.	20·00	10·0 (addl.)	—	0·60@	—	—	—	For acquisition of certain additional equipments, purchase of land and construction of buildings and partly for meeting the working capital requirements.

23.	M/s Emco Transformers Ltd., Thana.	Shri H. V. Gandhi, Chairman.	8·00	7·40 (addl.)	—	—	—	—	—	Acquisition of additional equipments for achieving optimum production in the manufacture of transformers.
24.	M/s Estrella Batteries Ltd., Bombay	Shri Shantilal Choonilal and Shri Harshad Choonilal, Directors.	179·06	91·62	8·38 (in DM)	—	—	—	—	Expansion in the production capacity for the manufacture of dry cells from 70 million to 130 million cells per annum and manufacture of special tuboplast jackets for making leak-proof batteries with an installed capacity of 100 tonnes per annum.
25.	M/s Gangapur S.S.K. Ltd., Raghunathnagar, Distt. Aurangabad.	Co-operative Unit.	150·57	74·00	—	—	—	—	—	For purchasing the sugar factory with a crushing capacity of 1,000 tonnes of Sugarcane per day belonging to M/s Gangapur Sugar Mills Ltd.
26.	M/s Garware Nylons Ltd., Pimpri, Poona.	Shri B.D. Garware, Chairman & Managing Director	583·63	—	100·00 (in DM)	—	—	—	—	Expansion scheme for increasing the capacity for the manufacture of Nylon-6 filament yarn from 756 to 2,000 tonnes per annum and production of 330 tonnes of plastic ships per annum.
27.	M/s Mahindra Ugine Steel Co. Ltd., Khopoli, Distt. Kolaba.	Shri K. Ramachandran, Executive Director. (Mahindra & Mahindra Group)	87·00	—	22·00 (in DM)	—	—	—	—	Acquisition of certain balancing equipments for steel melting shop, forge shop, heat treatment and finishing strip and laboratory, etc.
28.	M/s Poona Industrial Hotels Ltd., Poona.	Shri S.L. Kirloskar, Chairman. (Kirloskar Group)	29·05 (Over-run)	15·00 (addl.)	—	—	—	—	—	For meeting the over-run in the cost of the project of setting up a four star hotel at Poona.
29.	M/s Premier Synthetic Processors Ltd., Thana, Bombay.	Shri B.K. Jhunjhunwala, Promoter-Director.	60·00	33·34	1·66 (in DM)	5·00	2·00	—	—	Setting up a processing Plant for finishing and dyeing of about 8,200 meters per day of grey synthetic woven and knitted fabrics.
30.	M/s Ruby Mills Ltd., Bombay.	Shri M.C. Shah, Managing Director.	2·40	—	2·40 (in DM) (addl.)	—	—	—	—	Import of one Peerless Shearing machine to enable the company to improve the quality of cloth.

* Cost of the project accounted for earlier.
** Since cancelled.
@ Direct subscription under IDBI's underwriting obligation. Cost of the project accounted for in 1969-70.
≡ To be reduced to Rs. 55·00 lakhs consequent upon the IDBI's agreeing to participate in the project with a loan of Rs. 50·00 lakhs.
@@ Firm allotment in lieu of the right of conversion to the extent of 10% of the rupee loan of Rs. 50 lakhs sanctioned earlier. Cost of the project accounted for in 1969-70.
+Direct subscription to rights issue.

APPENDIX "B" (*Contd.*)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	M/s Shree Datta Shetkari S.S.K. Ltd., Shirol, Distt. Kolhapur.	Co-operative Unit.	250·00	150·00*	—	—	—	—	—	Setting up a sugar factory with an installed crushing capacity of 1,250 tonnes of Sugarcane per day.
32.	M/s Tata Merlin & Gerin Ltd., Thana, Bombay.	Shri R.F.S. Talyarkhan, Chairman. (Tata Group)	68·21	—	1·99 (in FF)	4·42@	—	—	—	Expansion scheme envisaging the manufacture of 66 KW current and potential transformers as also the balancing of the plant for the existing products.
33.	M/s. Textile Corporation of Marathwada Ltd., Distt. Nanded.	Shri Arvind N. Marathal, Chairman. Promoted by Marathwada Development Corporation Ltd. (An undertaking wholly owned by Maharashtra State Government).	383·00	26·63	3·37 (in DM)	—	5·00 (Direct subscription)	—	—	For financing the project for the manufacture of bleached, dyed and printed varieties of cotton textiles involving the setting up of a pre-weaving unit and a processing unit at Nanded and 2,304 power-looms to be operated by 24 weaver co-operative societies spread over five districts of Aurangabad, Parbhani, Nanded, Bhir and Osmanabad.
					MYSORE					
34.	M/s. Davangere Cotton Mills Ltd., Davangere, Distt. Chitradurga.	Shri R. R. Sreenivasamoorthy and Shri R. L. Sreenivasa Gupta, Managing Directors.	108·21	29·00	6·28 (in DM)	—	—	—	—	Modernisation and renovation of the Company's Davangere unit to achieve diversification of cotton fabrics, man-made fibre fabrics or blended fabrics.
5.	Shri Doodhganga Krishna S.S.K. Niyamit, Nanadi, Distt. Belgaum.	Co-operative Unit.	260·00	150·00*	—	—	—	—	—	Setting up a sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
36.	M/s. NGEF Ltd., Bangalore. (Mysore Government Undertaking)	Shri Sachidananda Moorthy, I.A.S., Managing Director.	275·00	75·00	—	—	—	—	—	Diversification and cost rationalisation programmes for the manufacture of 10,000 nos. of silicon diodes, 1,300 tonnes of transformer laminations, 1,100 tonnes of stampings and 600 tonnes of copper wire drawing per annum.

					ORISSA					
37.	M/s. Aluminium Corpn. of India Ltd., Jeypore, Distt. Koraput.	Shri Shripati Singhania, Manag ng Director. (J.K. Singhania Group)	1650·00	170·00 (addl.)	—	—	—	—	—	Setting up an integrated aluminium plant of the capacity of 15,000 tonnes per annum of alumunium metal together with rod fabrication capacity of 7,000 tonnes per annum.
38.	M/s. Lakshmi Auto Cycles Ltd., Koraput, Distt. Koraput.	Shri A. Visweswara Rao, Chairman and Shri A.L. Kumar, Proposed Managing Director.	129·74	75·00	—	10·00	—	—	—	Manufacture of auto-cycles with an installed capacity of 50,000 nos. per annum.
39.	M/s. Orissat Texile Mills Ltd., Chowdwar, Distt. Cuttack.	Shri Pratap Singh, Managing Director.	24·05	—	24·05 (in DM)	—	—	—	—	Import of 3 Schlafhorst automatic cone winders from West Germany and 5 combing machines and 4 pirn winders with accessories from Switzerland.
					RAJASTHAN					
40.	M/s. Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd., Kota.	Dr. Bharat Ram & Shri Charat Ram, Managing Directors, (Shriram Group)	7·67	—	5·60 (in DM)	—	—	—	—	For import of stand-by equipment viz. a centrifing and high pressure clearing apparatus.
41.	M/s. Rajasthan Coop. Spg. Mills Ltd., Gulabpura, Distt. Bhilwara.	Co-operative Unit.	121·00	45·50	—	—	—	—	—	Setting up a spinning mill with a complement of 12,960 spindles.
42.	M/s. Rajasthan Spg. & Wvg. Mills Ltd., Bhilwara.	Shri L.N. Jhunjhunwala, Managing Director.	50·00	30·00 (Addl.)	—	—	—	—	—	Diversification scheme envisaging diversion of a part of the spindleage from the production of cotton and staple yarn to synthetic yarn as also the installation of a fibre and yarn dyeing plant at its existing factory.
					TAMIL NADU					
43.	M/s. Dhrangadhra Chemical Works Ltd., Sahupuram, Distt. Thirunelveli.	Shri Shriyans Prasad Jain, Chairman, (Shriyans Prasad Jain Group)	18·57	—	5·56 (in DM) 6·82 (in FF)	—	—	—	—	Import of certain equipments for replacing the existing ones to effect economy in the cost of production.

*Th be rejuced to the extent L.I.C. participates in the project.

+Subscription to rights issue.

APPENDIX "B" (*Contd.*)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	M/s. Enfield India Ltd., Tiruvottiyur, Madras.	Shri S. Sankaran, Managing Director	30·87	30·00 (Addl.)	—	—	—	—	—	Increasing the production of motor cycles/scooters from 11,000 nos. p.a. to 16,000 nos. p.a. on single shift basis, and also improving the efficiency of painting and assembly operations.
45.	Shree Meenakshi Mills, Ltd., Madurai.	Shri Karumuthu Thiagarajan Chettiar, Managing Director, (Thiagaraja Group)	68·50	55·00	—	—	—	—	—	Modernisation of the spinning section of the mill.
46.	M/s. Mettur Chemical & Industrial Corpn., Ltd., Mettur Dam, Distt. Salem.	Shri R.V. Ramani, Managing Director (Seshasayee Group)	32.00	—	7·40 (in DM)	—	—	—	—	Import of certain balancing equipments in connection with the Company's expansion scheme to increase the production of rayon grade caustic soda by 6,600 tonnes per annum.
47.	M/s. Plastic Resins & Chemicals Ltd., Sahupuram, Distt. Tirunelveli.	Shri P. C. Jain, Chairman, (Shriyans Prasad Jain Group)	210·99 (over-run)	35·00 (addl.)	—	—	—	—	—	For meeting a part of the over-run in the cost of the Company's project envisaging the manufacture of PVC resin with an annual installed capacity of 14,000 tonnes.
48.	M/s. Sakthi Pipes Ltd., Elavur, Near Madras, Distt. Chingleput.	Shri A. Vellingiri, Managing Director.	40·00	—	—	5·00@	—	—	—	Implementing a scheme envisaging the introduction of second shift operation with a view to utilising the plant capacity more fully.
49.	Sakthi Sugars Ltd., Appakudal, Distt. Coimbatore.	Shri N. Mahalingam, Managing Director.	75·00	37·00	—	—	—	—	—	Setting up a distillery for the manufacture of industrial alcohol with an installed capacity of 2 million gallons per annum.
50.	M/s. Salem Co-op. Sugar Mills Ltd., Mohanur, Distt. Salem.	Co-operative Unit.	130·24	40·00 (Addl.)	—	—	—	—	—	Expansion scheme for increasing the crushing capacity of sugarcane from 1,000 tonnes to 1,750 tonnes per day.
		UTTAR PRADESH								
51.	M/s. Jain Shudh Vanaspati Ltd., Ghaziabad, Distt. Meerut.	S/Shri R. N. Jain, J. R. Jain, S. R. Jain and N. L. Jain, Promoters.	113·00	25·00	—	4·00	3·00	—	—	Setting up a factory for the manufacture of 15,000 tonnes vanaspati per annum.

52.	M/s. J. K. Satoh Agricultural Machines Ltd., Sanchendi Village, Distt. Kanpur.	Shri Padampat Singhania Chairman, (J. K. Singhania Group)	170·00	80·00	—	5·00	5·00	—	—	Setting up a factory for the manufacture of power tillers hand tractors with an installed capacity of 6,000 nos. per annum.
53.	M/s. Modi Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd., Modinagar, Distt. Meerut.	Committee of Management consisting of Shri G. M. Modi, Shri K. N. Modi and four other Directors. (Modi Group)	5·83	—	0·92 (in DM) 4·91 (in £)	—	—	—	—	Import of certain balancing equipments to enable the Company to convert a major part of its production of sewing yarn into sewing thread.
54.	M/s. Rathi Alloys & Steel Ltd., Ghaziabad, Distt. Meerut.	Shri C.R. Rathi, Proposed Managing Director.	75·50	39·50	—	1·50	5·75	—	—	Setting up a factory for the manufacture of mild steel ingots and spring steel ingots with an installed capacity of 20,000 tonnes per annum.
55.	M/s. Star Paper Mills, Ltd., Saharanpur.	Shri B. P. Bajoria, Managing Director.	171·04	—	51·05 (in DM) (addl.) 16·17 (in £)	—	—	—	—	Expansion scheme envisaging an increase in the capacity for the manufacture of M.F. writing and printing paper from 8·106 tonnes to 8,691 tonnes per annum and of M.G. Kraft paper from 25,100 tonnes to 30,170 tonnes per annum under the crash programme sponsored by the Govt. of India.
56.	M/s. Swadeshi Polytex Ltd., Ghaziabad, Distt. Meerut.	Shri Sitaram Jaipuria, M.P. Chairman and Managing Director, (Jaipuria Group)	1098·88	50·00	100·00 (in DM)	20·00	—	—	—	Setting up a plant for the manufacture of polyester staple fibre with an installed capacity of 6,10. tonnes per annum.
57.	M/s. Uttar Pradesh Steels Ltd., Muzaffarnagar.	Shri Brahma Swarup, President.	21·40	6·74 (Addl.)	14·66	—	—	—	—	For acquiring and installing a 3 tonne induction furnace.
			WEST BENGAL							
58.	M/s. Andaman Timber Industries Ltd., (*i*) Ganipur, Distt. 24-Parganas (*ii*) Bamboo Flat, Port Blair, South Andaman.	Shri B. K. Khaitan and Shri A. K. Bose, Managing Directors.	10·00	10·00 (Addl.)	—	—	—	—	—	Acquisition and installation of balancing/ancillary equipment at its Calcutta and Port Blair factories.
59.	M/s. Gontermann Peipers (India) Ltd., P.O. Amgachia, Distt. 24, Parganas.	Shri H. K, Nathani, Shri W. Lotz., Managing Directors.	18·14	7·50 (Addl.)	—	—	—	—	—	Acquisition of certain balancing equipments for increasing the machinery and material handling capacity from 3,000 tonnes to 3,600 tonnes of steel rolls per annum.

@Direct subscription.

APPENDIX "B" (*Contd.*)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	M/s. Khas Kajora Coal Co. Ltd., Rani ganj, Distt. Burdwan.	Shri Sitaram Beriwala & Shri Jagannath Beriwala, Managing Directors.	16·12	12·00 (Addl.)	—	—	—	—	—	Increasing the coal raising capacity of the Company's mines from 3·60 lakhs tonnes to 5 lakhs tonnes per annum.
61.	M/s. Parasea Collieries Ltd., Raniganj, Distt. Burdwan.	Shri B. N. Poddar & Shri V. K. Poddar Jt. Managing Directors.	31·82	20·00 (Addl.)	—	—	—	—	—	For increasing the coal raising capacity of the Company's mines to the presently licensed capacity of 6 lakhs tonnes per annum.
	Amounts sanctioned by way of conversion of foreign currency sub-loans to rupee loans in respect of three concerns and increase in the DM sub-loan of another sanctioned earlier.		—	16·28	0·70	—	—	—	—	
		TOTAL	19042·18	2548·51	561·10	128·01	52·14	200·00	42·35	

APPENDIX "C" (i)

ANALYSIS OF THE NET FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED FOR VARIOUS TYPES OF INDUSTRIES AS PER THE INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ALL ECONOMIC ACTIVITIES AS ON THE 30TH JUNE, 1971

(After adjustment of cancellations/withdrawals)

(Lakhs of Rupees)

Type of Industry	No. of units	Amount				% of the whole
		Loans	Under-writings	Guarantees for deferred payments on machinery & for foreign loans	Total	
Food Manufacturing Industries except Beverage Industries—						
(*i*) Sugar	92	7219·89	49·00	—	7268·89	19·9
(*ii*) Canning & Preserving of Fruits & Vegetables	1	—	3·90	—	3·90	—
Manufacture of Textiles—						
(*i*) Spg., Wvg. & Finishing of Cotton Textiles	92	3632·67	197·50	278·21	4108·38	11·2
(*ii*) Spg., Wvg. & Finishing of Jute Manufactures	14	564·31	—	—	564·31	1·5
Manufacture of Synthetic Fibres	13	992·18	96·25	42·35	1130·78	3·1
Manufacture of Wood & Cork except manufacture of Furniture	5	188·43	7·00	—	195·43	0·5
Manufacture of Paper & Paper Products	26	1603·07	159·07	551·16	2313·30	6·3
Manufacture of Rubber Products	8	779·74	27·00	280·13	1086·87	3·0
Manufacture of Basic Industrial Chemicals	17	1410·30	42·75	176·03	1629·08	4·5
Manufacture of Fertilisers	6	760·60	224·43	1278·86	2263·89	6·2
Manufacture of Miscellaneous Chemical Products	22	1095·23	221·35	245·72	1562·30	4·3
Manufacture of Vegetable & Animal Oil & Fats	4	70·00	7·00	—	77·00	0·2
Manufacture of Glass & Glass Products	10	289·71	15·00	—	304·71	0·8
Manufacture of Pottery, China & Earthenware	12	438·33	23·00	—	461·33	1·3
Manufacture of Cement	26	1660·16	210·89	18·54	1889·59	5·2
Basic Metal Industries—						
(*i*) Iron & Steel	7	512·59	297·25	—	809·84	2·2
(*ii*) Non-Ferrous Metals	10	909·97	295·00	1945·65	3150·62	8·6
Manufacture of Metal Products except Machinery & Transport Equipment	53	1847·63	426·60	130·26	2404·49	6·6
Manufacture of Machinery except Electrical Machinery	21	1023·70	79·70	105·01	1208·41	3·3
Manufacture of Electrical Machinery, Apparatus, Appliances & Supplies	33	1168·17	140·24	—	1308·41	3·6
Manufacture of Rail-Road Equipment	3	72·25	1·50	—	73·75	0·2
Manufacture of Motor Vehicles and Ancillaries	19	1020·17	200·00	26·95	1247·12	3·4
Manufacture of Bicycles	3	189·63	—	—	189·63	0·5
Electricity, Gas & Steam, Water & Sanitary Services—						
(*i*) Electric Light & Power : Generation, Transmission & Distribution	5	43·00	50·00	—	93·00	0·3
(*ii*) Gas Manufacture & Distribution	4	136·95	8·00	21·05	166·00	0·5
Mining & Quarrying—						
(*i*) Coal	3	122·00	—	—	122·00	0·3
(*ii*) Stone Quarrying-Minerals	1	—	10·00	—	10·00	—
(*iii*) Petroleum & Natural Gas	1	—	350·00	—	350·00	0·9
Hotel Industry	5	268·12	7·00	93·00	368·12	1·0
Miscellaneous Manufacturing Industries	11	206·17	—	—	206·17	0·6

APPENDIX "C" (II)

STATE/TERRITORY-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED AS ON THE 30TH JUNE, 1971

(After adjustment of cancellations/withdrawals)

(Lakhs of Rupees)

State/Territory	No. of units	Amount				% of the whole
		Loans	Under-writings	Guarantees for deferred payments on machinery & for foreign loans	Total	
Andhra Pradesh	32	1484·42	174·82	925·82	2585·06	7·1
Assam	6	301·79	350·00	—	651·79	1·8
Bihar	25	1529·86	363·00	329·75	2222·61	6·1
Gujarat	42	2319·29	171·32	127·30	2617·91	7·2
Haryana	22	901·63	69·38	20·08	991·09	2·7
Kerala	16	1041·95	19·50	172·47	1233·92	3·4
Madhya Pradesh	15	657·82	223·25	39·82	920·89	2·5
Maharashtra	113	6417·02	558·28	375·93	7351·23	20·1
Meghalaya	1	95·00	—	—	95·00	0·3
Mysore	37	1797·99	195·50	221·52	2215·01	6·1
Orissa	16	1020·17	95·00	—	1115·17	3·0
Punjab	11	660·20	—	9·96	670·16	1·8
Rajasthan	13	830·64	15·50	757·35	1603·49	4·4
Tamil Nadu	61	3301·49	410·38	1238·50	4950·37	13·5
Uttar Pradesh	39	2381·53	196·25	322·31	2900·09	7·9
West Bengal	71	3233·55	217·50	546·65	3997·70	10·9
Delhi	4	187·62	14·75	97·30	299·67	0·8
Andaman & Nicobar Islands	1	11·00	—	—	11·00	—
Goa	1	—	75·00	—	75·00	0·2
Pondicherry	1	52·00	—	8·16	60·16	0·2
TOTAL	527	28224·97	3149·43	5192·92	36567·32	100·0

APPENDIX "D"

STATEMENT SHOWING CLASSIFICATION OF NET FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA AS ON THE 30TH JUNE, 1971

(According to amounts sanctioned for each industrial concern)

(Lakhs of Rupees)

	Co-operatives		Public Limited Companies					Total				
	No. of concerns	Loans	No. of concerns	Loans	Underwritings	Guarantees for deferred payments on machinery & for foreign loans	Total	No. of concerns	loans	Underwritings	Guarantees for deferred payments on machinery & for foreign loans	Total
1. Amounts not exceeding Rs. 10 lakhs	—	—	70	222·17	205·04	—	427·21	70	222·17	205·04	—	427·21
2. Amounts exceeding Rs. 10 lakhs but not exceeding Rs. 20 lakhs	—	—	48	539·61	209·38	—	748·99	48	539·61	209·38	—	748·99
3. Amounts exceeding Rs. 20 lakhs but not exceeding Rs. 30 lakhs	3	75·20	43	874·93	218·20	4·71	1097·84	46	950·13	218·20	4·71	1173·04
4. Amounts exceeding Rs. 30 lakhs but not exceeding Rs. 40 lakhs	16	592·50	43	1293·71	219·25	43·32	1556·28	59	1886·21	219·25	43·32	2148·78
5. Amounts exceeding Rs. 40 lakhs but not exceeding Rs. 50 lakhs	6	275·00	41	1593·81	260·15	38·68	1892·64	47	1868·81	260·15	38·68	2167·64
6. Amounts exceeding Rs. 50 lakhs but not exceeding Rs. 60 lakhs	7	399·75	16	853·40	34·00	—	887·40	23	1253·15	34·00	—	1287·15
7. Amounts exceeding Rs. 60 lakhs but not exceeding Rs. 70 lakhs	6	388·00	18	1096·74	19·00	58·75	1174·49	24	1484·74	19·00	58·75	1562·49
8. Amounts exceeding Rs. 70 lakhs but not exceeding Rs. 80 lakhs	12	930·00	16	918·23	198·85	82·94	1200·02	28	1848·23	198·85	82·94	2130·02
9. Amounts exceeding Rs. 80 lakhs but not exceeding Rs. 90 lakhs	30	2653·31	11	895·34	62·50	—	957·84	41	3548·65	62·50	—	3611·15
10. Amounts exceeding Rs. 90 lakhs but not exceeding Rs. 1 crore	2	192·00	9	839·20	21·00	10·60	870·80	11	1031·20	21·00	10·60	1062·80
11. Amounts exceeding Rs. 1 crore	16	2224·89	75	11367·18	1702·06	4953·92	18023·16	91	13592·07	1702·06	4953·92	20248·05
TOTAL	98	7730·65	390	20494·32	3149·43	5192·92	28836·67	488	28224·97	3149·43	5192·92	36567·32

APPENDIX "E"

STATEMENT SHOWING INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL UPTO 30TH JUNE, 1971 IN EACH STATE

(*a*) represents loans
(*b*) represents underwritings
(*c*) represents gurantees for deferred payments on machinery and for foreign loans

Type of Industry		Andhra Pradesh	Assam	Bihar	Gujarat	Haryana	Kerala	Madhya Pradesh	Megha-laya	Mahara-shtra	Mysore
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Food manufacturing industries except beverage industries :											
—Sugar . .	(a)	785·00	60·00	186·50	405·50	106·00	180·00	80·00	—	2899·70	756·75
	(b)	—	—	5·00	—	—	—	—	—	—	—
		785·00	60·00	191·50	405·50	106·00	180·00	80·00	—	2899·70	756·75
—Canning & preserving of fruits & vegetables . .	(b)	—	—	—	—	3·90	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	3·90	—	—	—	—	—
Manufacture of textiles :											
—Spinning, weaving & finishing of cotton textiles . .	(a)	236·07	26·17	84·70	513·13	141·13	27·50	252·14	—	507·61	245·57
	(b)	27·50	—	8·00	13·00	7·50	2·50	12·00	—	5·00	30·00
	(c)	6·87	—	—	—	10·60	11·68	39·82	—	—	39·52
		270·44	26·17	92·70	526·13	159·23	41·68	303·96	—	512·61	315·09
—Spinning, weaving & finishing of jute manufactures .	(a)	—	78·50	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	78·50	—	—	—	—	—	—	—	—
Manufacture of synthetic fibres .	(a)	—	—	—	443·00	—	24·93	50·00	—	185·00	—
	(b)	—	—	—	23·00	—	—	46·25	—	7·00	—
	(c)	—	—	—	42·35	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	508·35	—	24·93	96·25	—	192·00	—
Manufacture of wood & cork except manufacture of furniture	(a)	—	100·74	—	—	—	56·69	—	—	—	—
	(b)	—	—	—	7.00	—	—	—	—	—	—
		—	100·74	—	7·00	—	56·69	—	—	—	—
Manufacture of paper & paper products .	(a)	110·98	—	218·76	58·97	—	40·00	—	—	122·83	417·85
	(b)	15·00	—	—	46·57	—	—	—	—	22·50	—
	(c)	—	—	311·21	57·95	—	—	—	—	—	182·00
		125·98	—	529·97	163·49	—	40·00	—	—	145·33	599·85
Manufacture of rubber products	(a)	—	—	—	—	—	31·33	—	—	104·00	—
	(b)	—	—	—	—	—	2·00	—	—	—	—
	(c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	33·33	—	—	104·00	—
Manufacture of fertilizers . .	(a)	—	—	—	200·00	—	306·00	—	—	—	—
	(b)	84·43	—	—	20·00	—	—	—	—	—	—
	(c)	878·86	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		963·29	—	—	220·00	—	306·00	—	—	—	—
	C/o	2144·71	265·41	814·17	1830·47	269·13	682·63	480·21	—	3853·64	1671·69

APPENDIX "E"

ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA,
(After adjustment of cancellations/withdrawals)

(Lakhs of Rupees)

Orissa	Punjab	Rajas-than	Tamil Nadu	Uttar Pradesh	West Bengal	Delhi	Andaman & Nicobar slands	Pondi-cherry	Goa	Total	No. of units
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
175·00	315·00	80·00	750·44	440·00	—	—	—	—	—	7219·89	
—	—	—	44·00	—	—	—	—	—	—	49·00	
175·00	315·00	80·00	794·44	440·00	—	—	—	—	—	7268·89	92
—	—	—	—	—	—	—	—	—		390	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·90	1
120·48	148·89	219·50	373·00	433·33	216·45	35·00	—	52·00	—	3632·67	
5·00	—	7·50	45·00	15·00	19·50	—	—	—	—	197·50	
—	9·96	—	24·99	122·31	—	4·30	—	8·16	—	278·21	
125·48	158·85	227·00	442·99	570·64	235·95	39·30	—	60·16	—	4108·38	92
—	—	—	—	—	485·81	—	—	—	—	564·31	
—	—	—	—	—	485·81	—	—	—	—	564·31	14
—	—	55·80	—	233·45	—	—	—	—	—	992·18	
—	—	—	—	20·00	—	—	—	—	—	96·25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42·35	
—	—	55·80	—	253·45	—	—	—	—	—	1130·78	13
—	—	—	—	—	20·00	—	11·00	—	—	188·43	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·00	
—	—	—	—	—	20·00	—	11·00	—	—	195·43	5
128·65	—	—	—	256·12	248·91	—	—	—	—	1603·07	
50·00	—	—	—	5·00	20·00	—	—	—	—	159·07	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	551·16	
178·65	—	—	—	261·12	268·91	—	—	—	—	2313·30	26
—	—	—	277·99	53·34	313·08	—	—	—	—	779·74	
—	—	—	—	5·00	20·00	—	—	—	—	27·00	
—	—	—	28·35	—	251·78	—	—	—	—	280·13	
—	—	—	306·34	58·34	584·86	—	—	—	—	1086·87	8
—	—	54·60	—	200·00	—	—	—	—	—	760·60	
—	—	—	—	45·00	—	—	—	—	75·00	224·43	
—	—	200·00	—	200·00	—	—	—	—	—	1278·86	
—	—	254·60	—	445·00	—	—	—	—	75·00	2263·89	6
479·13	473·85	617·40	1543·77	2028·55	1595·53	39·30	11·00	60·16	75·00	18935·75	257

APPENDIX "E" (*Contd.*)

STATEMENT SHOWING INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL UPTO 30TH JUNE, 1971 IN EACH STATE

(a) represents loans

(b) represents underwritings

(c) represents guarantees for deferred payments on machinery and for foreign loans

Type of Industry		Andhra Pradesh	Assam	Bihar	Gujarat	Haryana	Kerala	Madhya Pradesh	Megha-laya	Maha-rashtra	Mysore
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	B/f	2144·71	265·41	814·17	1830·47	269·13	682·23	480·21	—	3853·64	1671·69
Manufacture of basic industrial chemicals	(a)	140·00	36·38	—	214·66	—	—	—	—	111·71	—
	(b)	—	—	—	6·25	—	—	—	—	6·50	5·00
	(c)	40·09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		180·09	36·38	—	220·91	—	—	—	—	118·21	5·00
Manufacture of vegetable & animal oil & fats	(a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42·50
	(b)	—	—	—	—x	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	42·50
Manufacture of miscellaneous chemical products	(a)	137·24	—	—	10·64	—	74·50	17·38	—	478·84	10·08
	(b)	25·00	—	—	—	—	—	5·00	—	131·85	15·00
	(c)	—	—	—	—	—	—	—	—	245·72	—
		162·24	—	—	10·64	—	74·50	22·38	—	856·41	25·08
Manufacture of glass & glass products	(a)	20·00	—	84·93	3·79	—	5·00	—	—	33·83	1·50
	(b)	5·00	—	—	—	—	—	—	—	10·00	—
		25·00	—	84·93	3·79	—	5·00	—	—	43·83	1·50
Manufacture of pottery, china & earthenware	(a)	—	—	162·75	—	86·98	—	—	—	6·00	2·85
	(b)	—	—	5·00	—	15·00	—	—	—	—	—
		—	—	167·75	—	101·98	—	—	—	6·00	2·85
Manufacture of cement	(a)	37·00	—	406·22	112·30	—	—	219·59	95·00	20·00	—
	(b)	2·89	—	5·00	30·00	—	—	110·00	—	5·00	8·00
	(c)	—	—	18·54	—	—	—	—	—	—	—
		39·89	—	429·76	142·30	—	—	329·59	95·00	25·00	8·00
Basic metal industries—iron & steel	(a)	—	—	150·00	—	—	—	—	—	270·09	—
	(b)	—	—	260·00	—	—	—	—	—	15·00	—
		—	—	410·00	—	—	—	—	—	285·09	—
—Non-ferrous metal industry	(a)	—	—	—	—	—	134·00	—	—	63·69	90·00
	(b)	—	—	—	—	—	10·00	—	—	—	125·00
	(c)	—	—	—	—	—	160·79	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	304·79	—	—	63·69	215·00
	C/o	2551·93	301·79	1906·61	2208·11	371·11	1066·92	832·18	95·00	5251·87	1971·62

APPENDIX "E" (*Contd.*)

ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA,

(*After adjustment of cancellations/withdrawals*)

(Lakhs of Rupees)

Orissa	Punjab	Rajas-than	Tamil Nadu	Uttar Pradesh	West Bengal	Delhi	Andaman & Nicobar Islands	Pondi-cherry	Goa	Total	No. of units
Rs..	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
479·13	473·85	617·40	1543·77	2028·55	1595·53	39·30	11·00	60·16	75·00	18935·75	257
14·29	—	—	600·96	195·09	97·21	—	—	—	—	1410·30	
15·00	—	—	5·00	5·00	—	—	—	—	—	42·75	
—	—	—	100·08	—	35·86	—	—	—	—	176·03	
29·29	—	—	706·04	200·09	133·07	—	—	—	—	1629·08	
—	—	—	—	27·50	—	—	—	—	—	70·00	
—	—	—	—	7·00	—	—	—	—	—	7·00	
—	—	—	—	34·50	—	—	—	—	—	77·00	4
—	—	—	123·67	39·75	203·13	—	—	—	—	1095·23	
—	—	—	27·00	12·50	5·00	—	—	—	—	221·35	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245·72	
—	—	—	150·67	52·25	208·13	—	—	—	—	1562·30	22
—	—	—	—	20·65	120·01	—	—	—	—	289·71	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15·00	
—	—	—	—	20·65	120·01	—	—	—	—	304·71	10
56·75	—	—	—	—	123·00	—	—	—	—	438·33	
—	—	—	3·00	—	—	—	—	—	—	23·00	
56·75	—	—	3·00	—	123·00	—	—	—	—	461·33	12
100·00	—	125·00	545·05	—	—	—	—	—	—	1660·16	
—	—	—	50·00	—	—	—	—	—	—	210·89	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18·54	
100·00	—	125·00	595·05	—	—	—	—	—	—	1889·59	26
53·00	—	—	—	39·50	—	—	—	—	—	512·59	
15·00	—	—	—	7·25	—	—	—	—	—	297·25	
68·00	—	—	—	46·75	—	—	—	—	—	809·84	7
170·00	—	111·00	100·00	—	241·28	—	—	—	—	909·97	
—	—	—	120·00	40·00	—	—	—	—	—	295·00	
—	—	557·35	968·50	—	259·01	—	—	—	—	1945·65	
170·00	—	668·35	1188·50	40·00	500·29	—	—	—	—	3150·62	10
903·17	473·85	1410·75	4187·03	2422·79	2680·03	39·30	11·00	60·16	75·00	28820·22	365

APPENDIX "E" (*Contd.*)

STATEMENT SHOWING INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL UPTO 30TH JUNE, 1971 IN EACH STATE

(a) represents loans
(b) represents underwritings
(c) represents guarantees for deferred payments on machinery and for foreign loans

Type of Industry		Andhra Pradesh	Assam	Bihar	Gujarat	Haryana	Kerala	adhya Pradesh	Megha-laya	nha-rashtra	Mysore
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	B/f	2551·93	301·779	1906·61	2208·11	371·11	1066·92	832·18	95·00	5251·87	197162
Manufacture of metal products except machinery & transport ment	(a)	—	—	159·00	155·61	182·67	—	38·71	—	510·58	—
	(b)	15·00	—	20·00	2·00	23·50	—	50·00	—	158·10	—
	(c)	—	—	—	27·00	—	—	—	—	103·26	—
		15·00	—	179·00	184·61	206·17	—	88·71	—	771·94	—
Manufacture of machinery except electrical machinery.	(a)	—	—	—	67·07	71·36	—	—	—	282·08	53·00
	(b)	—	—	—	7·00	7·00	—	—	—	5·70	7·50
	(c)	—	—	—	—	9·48	—	—	—	—	—
		—	—	—	74·07	87·84	—	—	—	287·78	60·50
Manufacture of electrical machinery, apparatus, appliance & supplies	(a)	—	—	12·00	92·37	65·00	162·00	—	—	322·45	165·39
	(b)	—	—	—	15·00	12·48	5·00	—	—	48·63	5·00
		—	—	12·00	107·37	77·48	167·00	—	—	371·08	170·39
Manufacture of rail-road equipment	(a)	—	—	15·00	2·25	—	—	—	—	—	—
	(b)	—	—	—	1·50	—	—	—	—	—	—
		—	—	15·00	3·75	—	—	—	—	—	—
Manufacture of motor vehicles & ancillaries	(a)	11·79	—	—	—	188·06	—	—	—	352·010	2·50
	(b)	—	—	50·00	—	—	—	—	—	90·00	—
	(c)	—	—	—	—	—	—	—	—	26·95	—
		11·79	—	50·00	—	188·06	—	—	—	468·96	2·50
Manufacture of bicycles	(a)	—	—	—	—	50·43	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	50·43	—	—	—	—	—
Misc. manufacturing industries	(a)	6·34	—	—	—	10·00	—	—	—	64·10	10·00
		6·34	—	—	—	10·00	—	—	—	64·10	10·00
Electricity, gas, water & sanitary services: —Electric light & Power:generation, transmission & distribution	(a)	—	—	—	40·00	—	—	—	—	—	—
	(b)	—	—	—	—	—	—	—	—	50·00	—
		—	—	—	40·00	—	—	—	—	50·00	—
—Gas manufacture & distribution	(a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mining & quarrying —coal	(a)	—	—	50·00	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	50·00	—	—	—	—	—	—	—
Stone quarrying —minerals	(b)	—	—	10·00	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	10·00	—	—	—	—	—	—	—
Petroleum & natural gas	(b)	—	350·00	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	350·00	—	—	—	—	—	—	—	—
Hotel industry	(a)	—	—	—	—	—	—	—	—	82·50	—
	(b)	—	—	—	—	—	—	—	—	3·00	—
	(c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	85·50	—
	(a)	1484·42	301·79	1529·86	2319·29	901·63	1041·95	657·82	95·00	6417·02	1797·99
	(b)	174·82	350·00	363·00	171·32	69·38	19·50	223·25	—	558·28	195·50
	(c)	925·82	—	329·75	127·30	20·08	172·47	39·82	—	375·93	221·52
Total		2585·06	651·79	2222·61	2617·91	991·09	1233·92	920·89	95·00	7351·23	2215·01
No. of units State-wise:		(32)	(6)	(25)	(42)	(22)	(16)	(15)	(1)	(113)	(37)

APPENDIX "E" (*Contd.*)

ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA,
(*After adjustment of cancellations of withdrawals*)

(Lakhs of Rupees)

Orissa	Punjab	Rajas-than	Tamil Nadu	Uttar Pradesh	West Bengal	Delhi	Andaman & Nicobar Islands	Pondi-cherry	Goa	Total	No. of units
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	5
903·17	473·85	1410·75	4187·03	2422·79	2680·03	39·30	11·00	60·16	75·00	28820·22	36
127·00		—	169·19	135·33	369·54	—	—	—	—	1847·63	
—	—	—	27·00	20·50	110·50	—	—	—	—	426·60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130·26	
127·00	—	—	196·19	155·83	480·04	—	—	—	—	2404·49	53
—	—	—	93·72	120·00	336·47	—	—	—	—	1023·70	
—	—	—	22·50	10·00	20·00	—	—	—	—	79·70	
—	—	—	95·53	—	—	—	—	—	—	105·01	
—	—	—	211·75	130·00	356·47	—	—	—	—	1208·41	21
—	62·59	184·74	12·00	—	59·63	30·00	—	—	—	1168·17	
	—	8·00	28·88	—	2·50	14·75	—	—	—	140·24	
	62·59	192·74	40·88	—	62·13	44·75	—	—	—	1308·41	33
—	—	—	—	—	55·00	—	—	—	—	72·25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1·50	
—	—	—	—		55·00	—	—	—	—	73·75	3
75·00	133·72	—	124·34	101·93	30·82	—	—	—	—	1020·17	
10·00	—	—	30·00	—	20·00	—	—	—	—	200·00	
—	—	—	—	—		—	—	—	—	26·95	
85·00	133·72	—	154·34	101·93	50·82	—	—	—	—	1247·12	19
	—	—	—	—	139·20	—	—	—	—	891·63	
—		—	—		139·20	—	—	—	—	189·63	3
—		—	98·63	5·10	12·00	—	—	—		206·17	
	—		98·63	5·10	12·00			—	—	206·17	11
—	—	—	—	—	3·00	—	—	—	—	43·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50·00	
—	—	—	—	—	3·00	—	—	—	—	93·00	5
—	—	—	5·00	44·94	87·01	—	—	—	—	136·95	
—		—	4·00	4·00	—	—	—	—	—	8·00	
—	—	—	21·05		—	—	—	—		21·05	
—	—	—	30·05	48·94	87·01	—	—	—	—	100·00	4
—	—	—	—	—	72·00	—	—		—	122·00	
—	—	—	—		72·00	—	—	—	—	122·00	3
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10·00	
—	—		—	—	—	—	—	—	—	10·00	1
—	—		—	—	—	—	—	—		350·00	
—	—		—	—	—	—	—	—		350·00	1
—	—	—	27·50	35·50	—	122·62		—	—	268·12	
—	—	—	4·00	—	—	—	—	—	—	7·00	
		—	—	—	—	93·00	—	—	—	93·00	
—	—	—	31·50	35·50	—	215·62	—	—	—	368·12	5
1020·17	660·20	830·64	3301·64	2381·53	3233·55	187·62	11·60	52·00		28224·97	
95·00		15·50	410·38	196·25	217·50	14·75			75·00	3149·43	
	9·96	757·35	1238·50	322·31	546·65	97·30	—	8·16	—	5192·92	
1115·17	670·16	1603·49	4950·37	2900·09	3997·70	299·67	11·60	60·16	75·00	36567·32	527
(16)	(11)	(13)	(61)	(39)	(71)	(4)	(1)	(1)	(1)	(527)	

APPENDIX "F"

STATEMENT SHOWING THE TOTAL INSTALLED CAPACITY AND INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE COUNTRY IN SELECTED INDUSTRIES DURING THE YEAR 1970 AND THE CONTRIBUTION THERETO BY CONCERNS ASSISTED BY I. F. C.

Industry	Output unit	*Total for the country*			*In respect of concerns assisted by I.F.C.*		
		No. of concerns	Installed capacity	Actual production	No. of concerns	Installed capacity	Actual production
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Chemicals & Chemical products							
—Sulphuric Acid	M.T.-Thousands	67	1,930	1,199	7	410	273
—Caustic Soda	—do—	28	367	357	7	134	137
—Soda Ash	—do—	4	471	446	2	255	251
—Bleaching Powder	—do—	3	21	15	2	14	6
—Chlorine Liquid	—do—	22	222	147	7	80	58
—Phenol	—do—	3	18	10	1	10	8
—Butadiene	—do—	1	7	4	1	7	4
—Acetone	—do—	4	19	8	2	17	5
—Di-acetone Alcohol	—do—	2	5	3	2	5	3
2. Fertilisers							
(a) Nitrogenous Fertilisers							
Ammonium Sulphate	—do—	13	978	631	3	290	187
,, Chloride	—do—	2	96	34	1	16	9
,, Phosphate	—do—	2	186	73	1	112	52
(b) Phosphatic Fertilisers							
—Superphosphate	—do—	28	1,300	620	3	84	66
3. Cement	—do—	50	17,360	14,034	10	10,690	8,326
4. Paper & Paper Board	—do—	57	768	753	12	350	342
5. Rubber							
—Automobile Tyres	No. Thousands	8	3,482	2,974	3	900	933
,, Tubes	—do—	8	3,482	2,663	3	900	906
—Bicycle Tyres	—do—	11	21,296	20,988	1	5,000	4,441
,, Tubes	—do—	11	21,296	15,841	1	5,000	4,441
—Industrial V Belts and Fan Belts	—do—	6	3,850	1,400	1	960	1,091
6. Steel Castings	M.T. Thousands	43	129	45	3	18	9
—Steel Tubes & Pipes	—do—	15	510	242	4	266	85
—Ball and Roller Bearings	No. Lakhs	7	159	175	1	18	16
7. Refractories	M.T. Thousands	43	1,080	661	4	162	116
—Sanitarywares	—do—	13	18	13	2	5	5
8. Machinery							
—Power Tillers	Nos.	1	3,000	327	1	3,000	327
—Sewing Machines	No. Thousands	5	493	178	1	300	152
—Tea Processing Machinery	Value in Lakhs of Rupees	6	230	140	1	48	43
—Sugar Mill Machinery	—do—	16	2,100	1,376	2	855	431
—Industrial Screens	—do—	6	226	85	1	41	41
9. Electrical Machinery & Appliances							
—Electric Motors	H.P.—Thousands	20	2,569	3,194	2	425	577
—Electric Fans	No.—Thousands	16	1,816	1,624	1	600	512
—Electric Transformers	KVA—Thousands	23	6,265	7,518	2	1,000	900
—House Service Meters	No.—Thousands	8	1,905	2,057	2	915	669
10. Reamers	—do—	14	208	187	3	46	46
11. Micro Meters	—do—	1	12	9	1	12	9
12. Automobile Industry							
—Motor Cycles —Scooters —3 Wheelers	Nos.	8	1,04,500	1,17,206	6	62,800	50,009
13. Bicycles (complete)	No.—Thousands	9	2,105	2,073	2	900	844
14. Sugar							
—Private Sector	M.T.—Lakhs	137	22,85	24·29	6	1·35	1·13
—Co-operative Sector	—do—	74	13·68	12·50	47	9·72	8·76
15. Cotton Textiles							
—Yarn	Kgs.—Lakhs	*664	178·76 (Lakh spindles)	9,650	@44	12·60 (Lakh spindles)	770
—Cloth	Metres—Lakhs		2·09 (Lakhs looms)	78,490		0·09 (Lakh looms)	2,221

Note : 1. Information in columns 6, 7 and 8 is in respect of industrial units from whom loans are due and outstanding and excludes those which have fully repaid the loans.

2. Information in columns 3, 4 and 5 is based on the Reports of the Ministries of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, Petroleum and Chemicals.

*Includes 291 composite mills.

@Includes 11 composite mills.

APPENDIX "G"

DEBTS DUE BY CONCERNS IN WHICH THE DIRECTORS OF THE CORPORATION ARE INTERESTED AS DIRECTORS AND SHAREHOLDERS AS ON THE 30TH JUNE, 1971

No. of Companies/ Societies	Date of Sanction of loan	Amount of loan sanctioned	Amount Due		Total	Remarks
			In respect of loans sanctioned *prior* to the dates on which the concerned directors became directors of the Corporation or acquired interest in the loanee concerns	In respect of loans sanctioned when the concerned directors were directors of the Corporation		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	A. Debts due by Co-operative Societies in which the Directors of the Corporation are interested as nominees of State Governments or Co-operative Banks or Registrar of Co-operative Societies.					
	Nil	Nil	Nil	Nil		
	B. Debts due by concerns in which the Directors of the Corporation are interested as shareholders only.					
1.	28·1·61 29.3.61	8,26,000	9,45,907			
	27·5·65	12,00,000	15,13,718			
	28·1·61	79,48,348	98,97,609			
2.	30·5·63	19,59,187	8,84,661			
3.	29·9·64	36,01,070	22,89,562			
4.	28·3·69	53,34,427	42,49,433			
5.	30·4·64	1,00,00,000	85,00,000			
6.	26·11·56	25,00,000	6,38,000			
7.	30·12·65	2,00,00,000	...	1,80,00,000		
8.	27·1·65	50,00,000	40,00,000			
9.	31·10·68	20,65,000	—	20,65,000		
	31·10·68	12,32,088	—	10,74,588		
	7·10·70	3,00,000	...	3,00,0000		
10.	29·8·63	27,22,764	25,27,659			
	29·8·63	7,96,000	6,56,000			
	28·9·66	4,51,000	—	4,51,000		
	28·7·66	—	—	7,24,000		
11.	30·5·63	34,09,098	21,46,343			
	30·5·63	29,88,345	9,85,845			
12.	30·4·64	41,89,000	37,28,000			
	28·12·64	4,39,000				
	30·4·64 28·12·64	38,88,883	27,80,694			
	30·4·64 28·12·64	47,17,684	37,00,804			
	27·1·67	75,00,000		59,00,000		
13.	28·9·62	1,50,00,000	1,42,50,000			
	28·7·66	50,00,000	—	50,00,000		
14.	25·5·61	2,79,000	1,12,250			
	25·5·61	6,53,756	2,78,506			
	29·8·63	7,50,000	3,60,000			
15.	28·12·64	6,88,435	3,10,435			
	22·11·66	23,22,000	—	16,78,988		
16.	28·11·60	12,00,000	7,50,000			
	30·1·69	80,00,000	—	80,00,000		
17.	25·3·65	42,82,645	28,65,145			
	Total of 'B':	13,12,43,730	6,81,80,571	4,31,93,576	11,13,74,147	
	C. Debts due by concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Directors.					
1.	27·6·68	20,00,000	4,00,000			
	29·8·68	35,00,000	33,50,000			
	25·11·65	5,00,000	3,84,617			
	28·2·63	15,17,500	4,87,162			
	28·2·63	16,32,195	6,66,910			
	31·1·63	22,05,000				
	30·7·64	4,70,000	23,80,134			
		1,06,558	1,00,653			
2.	24·2·66	50,00,000	22,05,000			
	30·11·67	6,95,000	4,19,405			
3.	28·11·68	40,00,000	—	40,00,000		
	25·2·71	15,00,000	...	15,00,000		
4.	29·12·66	50,00,000	...	29,00,000		
	Total of 'C':	2,81,26,253	1,03,93,881	84,00,000	1,87,93,881	
	Total of 'A', 'B' & 'C':	15,93,69,983	7,85,74,451	5,15,93,576	13,01,68,028	

APPENDIX "H

Consolidated list of Districts/territories notified by the Central Government as qualifying for Concessional Finance from Public Financial Institutions.

States	Selected Districts
1. Andhra Pradesh	Nalgonda, Medak, Mehbubnagar, Karimnagar, Warangal, Khammam, Chittoor, Anantapur, Kurnool and Nizamabad.
2. Assam	Goalpara*, Cachar, Nowgong, Kamrup, Mikir Hills district* and Mizo Hills district.
3. Bihar	Santhal Parganas, Bhagalpur,* Palamau, Champaran, Saran, Darbhanga,* Purnea, Muzaffarpur and Saharasa.
4. Gujarat	Panchmahals,* Kutch, Amreli, Sabarkantha, Banaskantha, Broach, Bhavnagar, Mehsana and Surendranagar.
5. Haryana	Mohindergarh,* Hissar and Jind.
6. Himachal Pradesh	Chamba, Kannaur, Kangra*, Kulu and Lahaul & Spiti.
7. Jammu & Kashmir	Srinagar*, Anantnag, Baramula, Jammu*, Kathua, Udhampur, Doda, Ladakh, Poonch and Rajouri.
8. Kerala	Alleppey*, Trivandrum, Cannanore, Trichur and Malapuram.
9. Madhya Pradesh	Bastar, Mandla, Surguja, Seoni, Bilaspur, Jhalua, Balaghat, Sindhi, Betul, Raigarh, Raipur, Dhar, Tikamgarh, Rajgarh, Khargone, Shajapur, Shivpuri, Chhindwara, Rewa, Panna, Dewas, Mandsaur, Chhatarpur, Guna, Datia, Morena, Vidisha, Narsimhapur, Raisen, Hoshangabad, Demoh, Bhind and Sagar.
10. Maharashtra	Bhir, Osmanabad, Bhandara, Ratnagiri*, Aurangabad, Yeotmal, Chanda, Dhulia, Buldhana, Nanded, Parbhandi, Jalgaon and Colaba.
11. Meghalaya	Both the districts of United Khasi and Jaintia —Hills* and Garo Hills*.
12. Mysore	Belgaum, Bidar, Bijapur, Dharwar, Gulbarga, Hassan, Mysore, North Kanara, Raichur, South Kanara and Tumkur.
13. Nagaland	Kohima*, Mokokchung and Tuensang.
14. Orissa	Bolangir, Mayurbhanj,* Dhenkanal, Kalahandi*, Balasore, Keonjhar, Koraput and Phulbani.
15. Punjab.	Hoshiarpur*, Bhatinda, Gurdaspur and Sangrur.
16. Rajasthan	Jalore, Banswara, Dungarpur, Nagaur, Churu, Alwar*, Tonk, Udaipur, Jodhpur, Jhunjhunu, Sikar, Sirohi, Bhilwara, Jhalwar, Jaisalmer and Barmer.
17. Tamil Nadu	South Arcot, Thiruchirapalli*, Madurai*, Ramanathapuram*, Kanyakumari, North Arcot, Thanjavur, and Dharamapuri.

APPENDIX "H" (*Contd.*)

18. Uttar Pradesh	Almora, Azamgarh, Baharaich, Banda, Ballia*, Badaun, Chamoli, Fatehpur, Garhwal, Ghazipur, Hamirpur, Hardoi, Pilibhit, Jalaun, Jaunpur, Jhansi*, Mainpuri, Pithoragarh, Pratapgarh, Rae Barcli, Sultanpur, Tehri-Garhwal, Unnau, Uttar Kashi, Barabanki, Basti, Bulandshahr, Etah, Etawah, Faizabad, Gonda, Mathura, Farrukhabad, Muradabad, Shajahanpur and Deoria.
19. West Bengal	Purulia*, Bankura, Midnapur, Darjeeling, Malda, Cooch-Behar, West Dinajpur and Murshidabad.
Union Territories	
1. Andaman & Nicobar Islands*	Entire area
2. Dadra & Nagar Haveli*	Entire area
3. Goa, Daman & Diu*	Entire area
4. Laccadive, Amindive & Minicoy Islands.*	The inhabited Islands.
5. NEFA*	Entire area
6. Pondicherry*	Entire area
7. Tripura*	Entire area
8. Manipur*	Entire area

*These district/area are eligible for the Central Government's capital investment subsidy.

Notes : (*i*) In Tamil Nadu, talukas, inclding sub-talukas, of Ramanathapuram, Madukulathur, Sivaganga, parmakudi, Thiruvadanai and Thirupathur constituting the East Ramanathapuram development District of Ramanathapuram District. Melur (District Madurai) and Thirumayam, Alangudi and Kulathur (District Thiruchirapalli) are eligible for the Central Government's subsidy.

(ii) In respect of Union Territories Nos. 1 to 7, the entire district, excluding the area within the municipal limits of their capitals, and in respect of Manipur, the whole territory excluding the area within the municipal limits of the capital, are eligible for the Central Government's subsidy.

APPENDIX "I"

Details of Concessions on Financial Assistance for Industrial Projects that may be located in Districts/areas notified by the Central Government.

(i) *Rate of interest*:

As against the current rate of interest at 9% (with a rebate of ½ % for punctual payment of instalments of principal and interest), a lower rate of interest, i.e. 7½% (with a rebate of ½% will be charged.

(ii) *Initial grace period for commencement of repayment of loans*:

The Corporation's normal practice is to allow 3 years' moratorium to any assisted concern for the first repayment of the principal amount of the loan. In the case of undertakings in backward area, this period would be extended to five years from the date of the first disbursement of the loan.

(iii) *Amortisation period for loans*:

As against the normal period of 10 to 12 years for the repayment of a loan, this period would be extended to 15/20 years.

(iv) *Margin of security* :

The present practice of the Corporation is to aim at a margin of 50%. This would be reduced to 30/35%. In other words, an equity, debt ratio of 1:2 would be acceptable.

(v) *Promoters' contribution*:

The Corporation would be prepared to accept a lower contribution from the promoters to the cost of the project than its normal requirements.

(vi) *Participation in equity and preference capital* :

Depending on the merits of each case, the Corporation would be prepared to consider participation by way of underwriting or otherwise in the share capital of an industrial concern located in a backward district to a greater extent as compared to projects located elsewhere.

(vii) *Reduction in other charges*:

50% reduction will be made on the Corporation's normal charges in respect of underwriting commission, commitment charge, non-refundable examination fee for processing of applications and legal charges.

The concessions will normally be applicable to cases where the total project cost dose not exceed Rs. 1·00 crore; concessional finance for larger projects would be considered on a selective basis.

Assistance on concessional terms from the Corporation will be in addition to the grant/subsidy for projects in backward district/areas upto 10% of the project cost (provided it does not exceed Rs. 50 lakhs), which may be availed of under the Central Government's scheme.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971